विशेष रिपोर्ट

स्वस्थ भारत (न्यास) का सातवां स्थापना दिवस

मौसम ने बर्बाद की फसलें

महंगाई से राहत कोशिश है, पूरी नहीं

मूल्य 30/-

जून, 2022

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की राह

क्वाड में भारत की कूटनीति का दिखा असर

समय की कसौटी पर

इस्लाम और इतिहास

Career Magazine

DIALOGUEINDIA

... Dialogue for Change in Education

Portal for Current News & Analysis :
www.dialogueindia.in

राजनीतिक पत्रिका

डायलॉग इंडिया

★★★★★★★★★★ परिवर्तन की चाह - संवाद की राह

Portal for Career & Competition
www.dialogueindiaacademia.com

6th DIALOGUE INDIA Academia Conclave 2022

New Education Policy and Prospects of Internationalization of India Higher Education

11th DIALOGUE INDIA National Ranking (For Private Higher Education Institutions in India) 2022

8th DIALOGUE INDIA International Academia Awards (For Private Higher Education Institutions in India) 2022

Awards

BEST Colleges

1st Week of August, 2022 at New Delhi (India)

INTERNATIONAL AWARD CATEGORIES

- Engineering
- Medical
- Dental
- Law
- Management
- Hotel Management
- Fashion & Design
- Fine Arts
- Pharmacy
- Mass Comm.

Best Colleges / Universities of all categories on Overall / Infrastructure / Placement / Research & Innovation / Upcoming wise.

Best V.C. / Director / Principal of Universities / Institutes / Colleges of India.

Best College / Universities : State / Zone / National wise.

Editor Choice Education Excellency Award.

To Participate in Survey Please log on to our website
dialogueindiaacademia.com

For Business Enquiry Please Contact
dialogueindiaacademia@gmail.com (#08860787583)

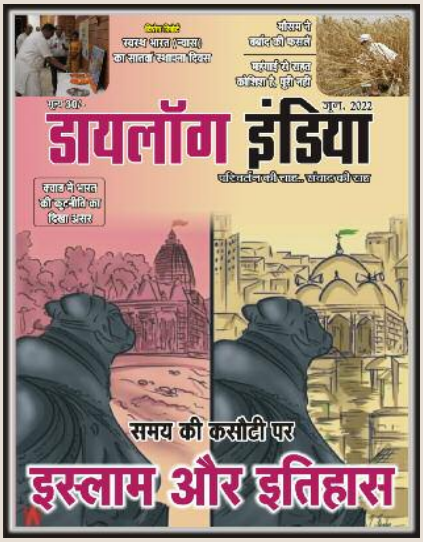

विषय सूची

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की वाह संवाद की राह

जून, 2022

06
मौसम ने बर्बाद की फसलें

08
क्वाड में भारत की कूटनीति का दिखा असर

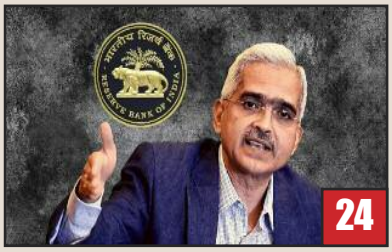
24
महंगाई से राहत कोशिश है, पूरी नहीं

32
मोदी सरकार : आठ साल

41
गृह-शांति के लिये आतंक से लड़ाई का सन्देश

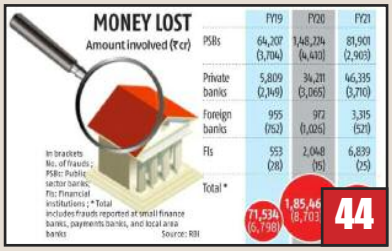

44
भारतीय बैंकों मे व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था

52
समय की कसौटी पर इस्लाम और इतिहास

74
स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका पर हुआ अमृत मंथन

84
ऑर्गेज्म चरम सुख बनाम चरित्रहीन स्त्रियां ऑर्गेज्म

हमारे बारे में
डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की चाह संवाद की राह

वर्ष- 13 अंक- 10

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल
प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल
विशिष्ट संपादक
अमित त्यागी
विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, डॉ. अर्चना पाटिल
आदित्य गोयल, डॉ. यशवंत चौधरी
उप संपादक
नेहा जैन
मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)
सम्यक अग्रवाल
मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार
जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा
ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
उत्तराखंड - रूपक कुमार
बिहार - नंद शर्मा
महाराष्ट्र - तेजेन्द्र सिंह
दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी
गौतमबुद्ध नगर - मनीष गुप्ता
गाजियाबाद - घनश्याम शर्मा
डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक, रजत
मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : www.dialogueindia.in
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित
© सर्वाधिकार सुरक्षित
जून, 2022 माह के लिए प्रकाशित
- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

एक वैश्विक आंदोलन सनातनता व अस्तित्व के लिए

भारत का आम हिंदू जन व्यथित है। यह होना स्वाभाविक भी है। न्यायालय के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने व उसके कूप आदि शिव के शिवलिंग होने के तथ्य व वीडियो सामने आ रहे हैं उसके साथ ही देश में तथाकथित 'गंगा-जमुना तहज़ीब' और 'हिंदू-मुस्लिम भाईचारे' व 'धर्मनिरपेक्षता' जैसे जुमलों की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। सबसे वीभत्स व झझकोर देने वाला तथ्य यह है कि इस्लामिक आक्रांताओं के कुकृत्यों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुस्लिम समाज उस स्थान का प्रयोग 'बजूखाने' (कुल्ला करने व हाथ धोने) के लिए करता था। स्वयं आदिदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग का ऐसा घोर अपमान निश्चित रूप से हिंदुओं को अपमानित करने व नीचा दिखाने के लिए ही किया जाता रहा है। कल्पना कीजिए अगर ऐसा अपमान किसी अन्य धर्म के भगवान का किया जाता तो कैसी हिंसक प्रतिक्रिया होती? और अब जैसे जैसे एक एक कर देश की प्रमुख मस्जिदों सहित हजारों मस्जिदों के पूर्व में मंदिर होने व लाल किला, कुतुब मीनार व ताजमहल सहित सभी मुगलकालीन इमारतों के निर्माण हिंदू राजाओं द्वारा करवाने के दावे व तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद भारत में इस्लाम व इतिहास दोनो की विश्वसनीयता पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं। ब्रिटिश भारत के लिए तो सोचा जा सकता था कि उन्होंने देश को गुलाम बनाए रखने के लिए 'बांटो व राज करो' की नीति अपनाई व अनावश्यक रूप से व अतिरंजित तरीके से इस्लाम को बढ़ावा दिया व झूठा इतिहास लिखा, किंतु आजादी के बाद भारत की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने मुगलों व अंग्रेजों द्वारा किए कुकृत्यों को बदलने की जगह वामपंथी इतिहासकारों की मदद से उनको छिपाने व मुगल राजाओं को महिमामंडित करने की साजिश की। महान सनातन संस्कृति, अत्यंत उन्नत भारतीय सभ्यता व उसके मान बिंदुओ को क्रमिक रूप से नष्ट कर लालच, स्वार्थ, शोषण, हिंसा, लूट व दमन पर आधारित ब्रिटिश राज्य की तथाकथित आधुनिक लोकतांत्रिक बाज़ार अर्थव्यवस्था को भारत पर थोपने की निरंतर साजिश की गयी व आज भी की जा रही है। हजारों वर्षों से समग्रता व संतुष्टि से अपनी भौतिक व आंतरिक उन्नति में रत भारतीय जनमानस की सत्य सनातन

व्यवस्थाओं को तोड़ने व छिन्न भिन्न करने के जो षड्यंत्र हुए उसमें जो लोग भी शामिल हुए उनके खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए व जो भी व्यवस्थाएं व भवन नष्ट किए गए हों या उनका स्वरूप नष्ट हुआ हो उनको अपनी मौलिक अवस्था में पुन: स्थापित करने का विशाल अभियान सरकार व समाज द्वारा आरंभ किया जाना चाहिए। इसमें जो भी ताकत विरोध करे उसको हर संभव तरीके से समझाना व सत्य तक लाना सरकार व समाज दोनो की जिम्मेदारी है। मौलिक भारत की भारत सरकार से निम्न मांग की गई हैं जो समर्थन योग्य हैं –

1) पूरे देश में जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदे बनाई गयीं उनको वापस भव्य मंदिर बनाया जाए।
2) ऐसी मस्जिदों के लिए अलग जगह दी जा सकती है।
3) जिस भी किसी व्यक्ति ने जानते बुझते हुए भी मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों में कुरान के विरुद्ध नवाज़ पढ़ता है व हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है उनकी पहचान कर उनको देश निकाला दिया जाए।

सनातन के प्रति हमारा आग्रह किसी भावना के वशीभूत नहीं है। सत्य यही है कि सनातन सभ्यता और संस्कृति व उस पर आधारित जीवन शैली ही हर उस समस्या का समाधान देती है जो पिछले तीन चार सौ वर्षों में पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति ने दुनिया के सामने पैदा की हैं। उपभोगवाद व भोग की पश्चिमी संस्कृति के कारण दुनिया में संसाधनों का संकट खड़ा हो गया है व प्रकृति के अत्यधिक दोहन व जीवाश्म ईंधन के अतिशय प्रयोग ने प्रकृति के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग से उपजे जलवायु परिवर्तन हर दिन जीवन को अधिक असामान्य बना रहा है और वैज्ञानिक व नीतिकार हर कुछ वर्षों के अंतराल पर ही 'न्यू नोर्मल' की अवधारणायें गड़ रहे हैं। यह पूर्णत: असामान्य है और एक हो व्यक्ति के जीवन में अब प्रकृति इतने ज़्यादा बार परिवर्तित हो रही है कि उसे कई 'न्यू नोर्मल' दौरों से गुजरना पड़ रहा है और उसका शरीर व मान इसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। असामान्य मौसम से उपजी असामान्य व कम उपज ने विश्व स्तर पर खाद्य संसाधनों की होड़ तो बढ़ा ही दी है, सूखे, बाढ़, तूफ़ान व चक्रवात वैश्विक जीडीपी, आधारभूत ढांचे को अतिशय नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, सप्लाई चैन बिखर रही है व मंदी, बेरोजगारी, विस्थापन व महंगाई हमें घेरती जा रही है। ऐसे में आशंकित लोग व सरकारें मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो आपसी संघर्षों में घिरते जा रहे है व दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने व नष्ट होने के कगार पर आ खड़ी हुई है।

इतना सब हो जाने के बाद भी और पर्यावरणवादियों द्वारा लाखों चेतावनी देने कि अगले कुछ दशकों में ही पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी व हमारे से अगली पीढ़ी शायद ईद युग की अंतिम पीढ़ी हो, दुनिया की सरकारें, कारपोरेट व वैश्विक संस्थान बातों से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। उनका जीडीपी आधारित विकास के मॉडल से मोह भंग नहीं हो रहा और वो नित दुनिया को गर्त में धकेलते जा रहे हैं। यह सभी को ज्ञात है कि सनातन सभ्यता का माडल ही शाश्वत माडल है, वे अपने तात्कालिक नुकसान होने के डर से उसे अपनाने से भाग रहे हैं। ऐसे में समाज को ही आगे आना होगा और एक वैश्विक आंदोलन कर ऐसी सभी शक्तियों को समाप्त या अप्रासंगिक करना होगा जो सनातन सभ्यता व संस्कृति की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की विरोधी हैं। क्योंकि अब प्रश्न अस्तित्व का है हमारे भी और प्रकृति के भी।

अनुज अग्रवाल
संपादक

मौसम ने बर्बाद की फसलें

● पूनम गौड़

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी की है कि दुनिया के पास सिर्फ 10 हफ्तों का ही गेहूं शेष है। साल 2008 के बाद यह अपने सबसे निचले स्तर पर है। गेहूं का संकट यूक्रेन-रूस युद्ध के साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से भी पैदा हुआ है। हालात के मद्देनजर भारत को इस साल गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों की चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया को एक चौथाई गेहूं की आपूर्ति करते हैं। रूस में इस साल गेहूं की अच्छी फसल हुई है, पर मौसम की वजह से यूरोप और अमेरिका में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।

भीषण गर्मी से भारत में भी गेहूं समेत रबी की बाकी फसलों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसका असर अनाज की कमी के रूप में दिखाई भी देने लगा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अब गेहूं समेत रबी की फसलों में ऐसी वरायटी चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से बढ़ती गर्मी में भी पर्याप्त उत्पादन दे सके। कई रिपोर्टें हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल गर्मी से इस बार बहुत प्रभावित हुई हैं। इन प्रदेशों में किसानों को 20 से 60 प्रतिशत तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्मी समय से महीने भर पहले ही शुरू हो गई तो गेहूं के दाने मोटे नहीं हो पाए, जिसके चलते मंडियों में इसका भाव गिर गया।

गौरतलब है कि लोगों के खाने का चक्र हर साल 21 से 37 प्रतिशत तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। यानी खाने का चक्र भी धरती को गर्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2022 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल फूड सिस्टम से होने वाला उत्सर्जन ही धरती को 1.5 डिग्री से अधिक तक गर्म करने के लिए काफी है। इस फूड सिस्टम में फसलों के उत्पादन से लेकर परिवहन तक शामिल है। दुनिया भर के 780 करोड़ लोगों के खाने की व्यवस्था हर साल 21 से 37 प्रतिशत तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार पेड़ कार्बन उत्सर्जन को सोखते हैं। खेत और चारागाहों के लिए रास्ता बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। खेतों में ज्यादातर डीजल का उपयोग हो रहा है। खाद और केमिकल भी जमकर चल रहे हैं। इन्हीं सबसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। खेती से होने वाले जलवायु परिवर्तन को कम करने को लेकर 2021 में ग्लास्गो में आयोजित कॉप-26 में भी चिंता जाहिर की गई थी। लेकिन खाना इंसान की जरूरत है। खाना तो कोई नहीं छोड़ सकता, पर क्या खाना बर्बाद करना भी नहीं छोड़ सकता?

संयुक्त राष्ट्र का फूड वेस्ट इंडेक्स-2021 बताता है कि हर भारतीय साल में 50 किलो खाना बर्बाद कर देता है। इस हिसाब से देश में हर साल करीब 6.88 करोड़ टन खाना बर्बाद हो रहा है। यह हाल तब है जब देश के 14 फीसदी लोग कुपोषण के शिकार हैं। दुनिया के 107 देशों की लिस्ट वाले इस इंडेक्स में भारत 94वें पायदान पर रहा था। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में 2019 के दौरान करीब 93.1 करोड़ टन भोजन बर्बाद किया गया। इससे 40 टन की क्षमता वाले करीब 2.3 करोड़ ट्रक भर जाएंगे और अगर इन्हें लाइन में खड़ा करें तो यह पृथ्वी के सात चक्कर पूरा कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 प्रतिशत भोजन हर साल कचरे में फेंक दिया जाता है।

एक तरफ भोजन का संकट है तो दूसरी तरफ खाने की बर्बादी। इन सबके ऊपर हैं सबकी हालत खराब करने वाले जलवायु परिवर्तन से उपजते सकंट। इस पर पक्ष विपक्ष में घंटों बातें की जा सकती हैं लेकिन एक बात बिल्कुल साफ दिखती है कि हम बैलेंस बनाने में चूक गए हैं। ना प्रकृति के साथ हमारा बैलेंस बन पाया है, और ना पेट की जरूरतों तथा अपनी आदतों के साथ।

फसलों की बर्बादी के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, गेहूं की कमी के लिए भारत को दोषी ठहराना ठीक नहीं

– राजेश सिन्हा

भारत दुनिया के बाकी हिस्सों को खिलाने के लिए अपने लोगों को भूखा नहीं रख सकता। हालांकि, इसने दुनिया को विशेष रूप से विकसित पश्चिमी देशों और अमेरिका को परेशानी में डाल दिया। सात देशों के समूह जी-7 ने भारत के फैसले पर निराशा व्यक्त की।

स्थिति पहले से बिल्कुल उलट गई है। अमेरिका और दूसरे पश्चिम देश जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को लेकर अपने दायित्वों को पूरा करने से भाग रहे हैं और वह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों से लड़ने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान नहीं कर रहे हैं। मगर अब वे दुनिया के सामने आने वाले संकट से निपटने के लिए भारत की मदद मांग रहे हैं। दुनिया कई संकटों से एक साथ जूझ रही है- युद्ध, खाद्य संकट, और जलवायु परिवर्तन जिससे मनुष्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पहले से ही अपना दुष्प्रभाव छोड़ रही थी, क्योंकि दुनिया भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। उसकी तीव्रता के साथ आवृति में भी बदलाव आ गया है। हाल में रूस के यूक्रेन पर हमले से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति बाधित हो गई है। दोनों देशों का वैश्विक गेहूं निर्यात में लगभग एक तिहाई का हिस्सा है।

नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में गेहूं की कमी हो गई है। वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में 60 फीसदी से अधिक की तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की स्थिति देख कर घोषणा की कि भारत गेहूं की आपूर्ति करके दुनिया के बचाव में आगे आएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हालांकि, इसकी अधिकांश उपज की खपत देश में ही हो जाती है और वैश्विक गेहूं निर्यात में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 7 फीसदी है। इस साल गेहूं का कम उत्पादन हुआ। बढ़ती रिटेल और खाद्य महंगाई के चलते प्रधानमंत्री को अपने वादे से पीछे हट कर गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा

तर्क स्पष्ट और निर्विवाद था

भारत दुनिया के बाकी हिस्सों को खिलाने के लिए अपने लोगों को भूखा नहीं रख सकता। हालांकि, इसने दुनिया को, विशेष रूप से विकसित पश्चिमी देशों और अमेरिका को परेशानी में डाल दिया। सात देशों के समूह जी-7 ने भारत के फैसले पर निराशा व्यक्त की। जर्मनी में जी-7 कृषि मंत्रियों की बैठक के बाद, जर्मन कृषि मंत्री केम ओजदेमिर ने कहा कि भारत का निर्यात पर प्रतिबंध 'संकट को और गंभीर बनाएगा।' ओजडेमिर ने शनिवार, 14 मई को स्टटगार्ट में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'अगर हर कोई निर्यात पर प्रतिबंध लगाना या बाजार को बंद करना शुरू कर देता है तो इससे संकट और बढ़ जाएगा।'

अमेरिका ने कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर 'पुनर्विचार' करेगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा, 'हम देशों को निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर भोजन की कमी को बढ़ा देगा। सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों में भारत भी होगा। हम हम आशा करते हैं कि भारत दूसरे देशों की चिंता को सुनकर गेहूं के निर्यात को रोकने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।

भारत पर नैतिक दबाव डालने के प्रयास किये गए

कुछ विश्लेषकों ने कहा कि भारत के निर्यात प्रतिबंध का प्रभाव कम आय वाले विकासशील देश ज्यादा महसूस करेंगे। प्रतिबंध के बाद एक नोट में नोमुरा ग्लोबल मार्केट्स रिसर्च ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अधिकांश एशियाई अर्थव्यवस्थाएं घरेलू खपत के लिए आयातित गेहूं पर निर्भर हैं और वैश्विक स्तर पर गेहूं की ऊंची कीमतों से जोखिम में हैं, भले ही वे सीधे भारत से आयात न करें। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है। वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रतिबंध तीन उद्देश्यों को पूरा करता है: i) देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, ii) संकट में पड़े लोगों की मदद करना; यदि कोई देश विशेष रूप से अनुरोध करता है तो भारत सरकार उसे गेहूं निर्यात करने पर निर्णय लेगी, और iii) एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की कोशिश मौजूदा अनुबंध को पूरा कर अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने की है।

'इसलिए, अगर हम कहते हैं कि लगभग 1.6 या 1.7 मिलियन टन गेहूं का अब तक निर्यात किया जा चुका है, तो हम अब भी क्रेडिट पत्र के साथ पूर्व बुक वैध आदेश को पूरा करने के लिए 2.5 मिलियन टन और गेहूं के निर्यात को अनुमति देने की स्थिति में हैं।' उन्होंने शनिवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा। कई बिन्दु हैं जिनको लेकर विकसित देश दूर भागते रहे है: विकास, गरीबी, वित्त, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के

जल-संकट गृहयुद्ध का कारण न बन जाये

पिछले कई दिनों से गंभीर जल संकट से दिल्ली की जनता परेशान है। परेशानी का सबब यह है कि पानी पहुंचाने वाले टैंकरों को कड़ी सुरक्षा में चलाया जा रहा है, ताकि पानी को लेकर हिंसा की नौबत न आ जाए। दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में पानी की कमी से जूझ रहे लोग पानी की टंकियों और हैंडपंपों से बूंद-बूंद पानी इकट्ठा कर रहे है और अपने-अपने पानी के डिब्बों को जंजीर से बांधकर रख रहे हैं। ऐसा ही नजारा मंगलवार को वसंत विहार के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में देखने को मिला। यह चिंताजनक इसलिए है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो यह जल संकट कभी भी जल संघर्ष एवं हिंसा में बदल सकता है। यह तो अक्सर देखने में आता ही रहा है कि पानी को लेकर लोग एक दूसरे की जान तक लेने में भी नहीं हिचकते। भीषण गर्मी और हरियाणा में नदी में कम पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली के जल-संकट को जल्दी-से-जल्दी दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी ही चाहिए।

दिल्ली में जल संकट वैसे तो हर वर्ष गर्मी की समस्या है, पर इसका दुष्प्रभाव साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से दिल्ली में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो यह बात काफी हद तक सच भी है। जैसे दिल्ली की जनसंख्या में बीते दो दशकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। परंतु केवल जनसंख्या में वृद्धि ही दिल्ली में साल दर साल गहराते जल संकट का कारण नहीं है। विश्व के किसी भी शहर एवं खासकर राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर इससे उपजने वाली विभिन्न समस्याओं एवं जल संकट का मूल आबादी की बजाय, आबादी द्वारा चुनी गई सरकार एवं उसके लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, जोकि जीवन के मूलभूत तत्वों एवं जीवन निर्वाह की मूल जरूरतों में से एक जल भी उपलब्ध नहीं करवा पाती है। यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है।

यह कैसी सरकार है जिसके शासन में एक-एक बाल्टी पानी के लिए लोग रात-रात भर जाग रहे हैं। जहां पानी पहुंच रहा है वहां लंबी-लंबी कतारें लगी हैं। जिनके पास पानी खरीदने को पैसे नहीं हैं, वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जो खरीद सकते हैं, वे मुंहमांगा दाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये हाल कुछेक इलाकों का है। आधी से ज्यादा दिल्ली पानी के लिए इसी तरह तरस रही है। यह हर साल का रोना है। लेकिन विडंबना यह है कि जल संकट के स्थायी समाधान के लिए क्या हो, इसकी फिक्र किसी को नहीं दिखती।

दिल्ली में जल-संकट का कारण राजनीति भी है। पानी को लेकर विवाद दूसरे राज्यों में भी होते रहते हैं। नदियों के पानी पर किसका और कितना हक हो, यह मुद्दा जटिल तो है ही, राज्यों की राजनीति ने इसे और पेचीदा बना डाला है। दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने को लेकर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ चर्चा करीब

तीन साल से चल रही है। हरियाणा सरकार के साथ भी लंबे समय से बात चल रही है। पर अब तीनों राज्यों ने अपनी मजबूरी जता दी है। मोटे तौर पर दिल्ली में पानी का संकट तब खड़ा होता है, जब यमुना में पानी कम हो जाता है। ताजा स्थिति यह है कि वजीराबाद बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर सामान्य से छह फीट नीचे चला गया है। यहां पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा तर्क यह दे रहा है कि पंजाब उसे उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा। यानी जब पंजाब हरियाणा को पानी देगा, तब वह दिल्ली को देगा। अगर वाकई ऐसा है तो यह बेहद गंभीर बात है। इससे तो यही लग रहा है कि पानी को लेकर सरकारें राजनीति कर रही हैं। गौरतलब है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा की। जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसी की सरकार पंजाब में है तो वह समस्या के समाधान के लिये तत्पर क्यों नहीं होती? पंजाब हरियाणा को पानी दे तो दिल्ली को पानी मिल सकता है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिये गंभीरता क्यों नजर नहीं आ रही है? क्यो जल पर राजनीति की जा रही है? क्यों जनता को पानी के लिये त्राहि-त्राहि करने पर विवश किया जा रहाहै?

ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राजनीतिज्ञ, जिन्हें सिर्फ वोट की प्यास है और वे अपनी इस स्वार्थ की प्यास को इस पानी से बुझाना चाहते हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का यह जल-विवाद आज हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दे उससे पूर्व आवश्यकता है तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रीय हित एवं जनता के हित के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये। जीवन में श्रेष्ठ वस्तुएं प्रभु ने मुफ्त दे रखी हैं- पानी, हवा और प्यार। और आज वे ही विवादग्रस्त, दूषित और झूठी हो गईं। बहुत हो चुका है। अब बस। 2022 दिल्ली के जन-संकट का समाधान का वर्ष हो।

भारत की नदियां शताब्दियों से भारतीय जीवन का एक प्रमुख अंग बनी हुई हैं। इन्हीं के तटों से ऋषियों-मुनियों की वाणी मुखरित हुई थी। जहां से सदैव शांति एवं प्रेम का संदेश मिलता था। इसमें तो पूजा के फूल, अर्घ्य और तर्पण गिरता था अब वहां निर्दोषों का खून गिरता है। हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं विविधता की एकता का संदेश इन्हीं धाराओं की कलकल से मिलता रहा है। जिस जल से सभी जाति, वर्ग के लोगों के खेत सिंचित होते हैं। जिनमें बिना भेदभाव के करोड़ों लोग अपना तन-मन धोते हैं। जो जल मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी की भी प्यास बुझाता है, उसमें अलगाव, भेदभाव, राजनीतिक स्वार्थ का जहर कौन घोल रहा है?

सभी इन राज्यों के अपने तकनीकी व अन्य कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वे उचित भी हों, लेकिन जिस तरह का रवैया दिल्ली

एवं पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारें दिखा रही हैं, उसे शायद ही कोई जायज ठहराएगा। हालांकि देखा यह भी जाना चाहिए कि इन राज्यों के पास अपने लिए कितना पानी है। दिल्ली की अपनी भौगोलिक स्थिति और अन्य मजबूरियां ऐसी हैं कि बिना दूसरे राज्यों से पानी मिले उसका गुजारा चल नहीं सकता। सारे राज्य एक ही देश के हैं, पड़ोसी हैं, सभी के नागरिक भी एक ही हैं। ऐसे में कोई राज्य किसी जरूरतमंद राज्य को पानी नहीं देकर संकट खड़ा करता है, तो यह गंभीर बात है, यह प्रदूषित राजनीति का द्योतक है।

देश की राजधानी में ही अगर इतना गंभीर जल संकट खड़ा हो जाता है और वह भी हर साल, तो सरकारों पर सवाल उठना लाजिमी है। जल-संकट के अलावा भी अन्य आम जनता से जुड़े अनेक संकट है जैसे प्रदूषण आदि। आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? दिल्ली की अपनी सरकार है। केंद्र सरकार भी यहां है। देश की सर्वोच्च अदालत भी यहां बैठती है। सत्ता और शक्ति का केंद्र होने के बावजूद लाखों लोग अगर पानी के लिए तरसते हैं तो निश्चित ही इसे व्यवस्था की नाकामी का नतीजा माना जाना चाहिए। नदियों ने विभिन्न प्रांतों को जोड़ा था पर राजनीतिज्ञ इसे तोड़ रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल एक अखण्ड राष्ट्र के उसी प्रकार हिस्से हैं जिस प्रकार मनुष्य शरीर के अंग हुआ करते हैं। कोई सरकार जनता की सुरक्षा एवं संरक्षण करने में असमर्थ है और दूसरी तरफ कोई सरकार अपनी कुर्सी को चमकाने के लिए जल विवाद का लाभ उठाना चाहते हैं। ये स्थितियां गृह युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं। जिस पर नियंत्रण पाना किसी अथॉरिटी के लिए सम्भव नहीं होगा। ये स्थितियां हमारे संवैधानिक ढांचे के प्रति भी आशंका पैदा कर रही हैं। 'नदी जल' के लिए कानून बना हुआ है। आवश्यक हो गया है कि उस पर पुनर्विचार कर देश के व्यापक हित में विवेक से निर्णय लिया जाना चाहिए।

- ललित गर्ग

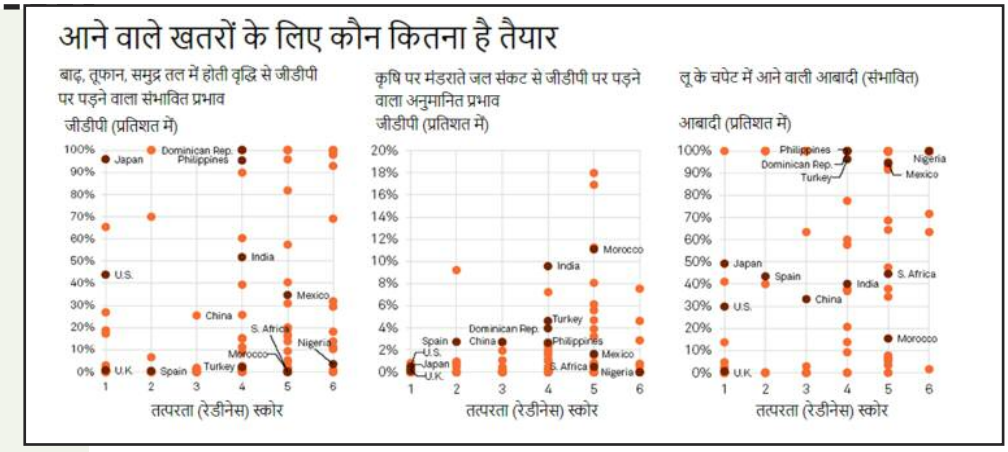

प्रभाव। जलवायु परिवर्तन से वर्तमान संकट और बढ़ गया है। जैसा कि कई अध्ययनों ने स्थापित किया है कि विकसित देशों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विकसित देश अब तक ऐतिहासिक रूप से 79 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, जापान और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश समृद्ध देशों में आज वैश्विक आबादी का सिर्फ 12 प्रतिशत हिस्सा रहता है, लेकिन 170 साल से जीवाश्म ईंधन और उद्योग से निकलने वाली सभी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका हिस्सा 50 फीसदी से ज्यादा है।

न्याय और निष्पक्षता जैसे मुद्दों को देखने के लिए एकमात्र हिस्सा ऐतिहासिक जिम्मेदारी ही नहीं है। एक और मापदंड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भी है। इसलिए उदाहरण के लिए इस साल दुनिया के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 7 प्रतिशत हिस्सा भारत का रहा जो लगभग यूरोपीय संघ और अमेरिका के लगभग आधे के बराबर है। लेकिन भारत में संयुक्त रूप से दोनों क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या कहीं ज्यादा है। फिर यहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। करोड़ों के पास बिजली नहीं है। नतीजतन, भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन आज बहुत कम है।

देश	2020 में कुल कार्बन उत्सर्जन (GtCo2 में)	प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (TCo2 में)
चीन	10.7	7.4
यूएसए	4.7	14.2
भारत	2.4	1.8
रूस	1.8	10.8
जापान	1.6	8.1
जर्मनी	0.7	7.7

स्रोत : ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट

अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जलवायु शिखर सम्मेलन में तर्क दिया कि भारत जैसे तेजी से औद्योगीकरण वाले देशों को ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। जबकि भारत ने हाल ही में 2070 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन की प्रतिज्ञा की है और इस बात पर जोर दे रहा है कि कोयले से वह स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है मगर इसके लिए उसे अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत है। भारत ने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऐतिहासिक उत्सर्जन में अपने छोटे हिस्से का भी हवाला दिया।

समृद्ध देशों को न सिर्फ अपने यहां उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करना चाहिए, बल्कि गरीब देशों को कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते पर ले जाने के लिए वित्त पोषण और तकनीक का हस्तांतरण भी करना चाहिए। साथ ही उन्हें जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए छोटे देशों का समर्थन करना चाहिए। गरीब देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और अमीर देशों से जलवायु परिवर्तन के खतरों को खत्म करने में मदद करने के लिए अमीर देशों से अधिक धन उपलब्ध कराने की मांग करते रहे हैं।

2009 में अमीर देशों ने कम आय वाले देशों में जलवायु को अनुकूल बनाने और ऐसी ही दूसरी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए सालाना 100 बिलियन डॉलर का वादा किया।

अतीत की यादों में समाएं तालाब व बावड़ी के लिए वरदान साबित होंगे अमृत सरोवर

(पूर्वजों की देन व पानी संरक्षण के लिए तालाब व बावड़ी के रूप में किया गया उनका बेहतर प्रयास आज अतीत की यादों में समां गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार की उदासीनता ही रही है।अमृत सरोवर योजना से सिंचाई का कार्य भी किया जाएगा और बरसाती पानी को संरक्षित भी किया जाएगा।)

गर्मियों में पूरे भारत में बड़े पैमाने पर जल संकट पैदा हो जाता है; इस समस्या को देखते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार ने अपने गांवों में अस्तित्व खोते जा रहे तालाब एवं जोहड़ों को बचाने के लिए राज्य के जोहड़ तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने पर जोर शोर से काम शुरू किया है। यह अमृत सरोवर जल संरक्षण के साथ-साथ किसानों के लिए भी एक वरदान साबित होंगे। इन अमृत सरोवर के पानी से सिंचाई करने का भी प्रावधान रखा जाएगा। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1650 तालाबों का अमृत सरोवर के रूप में 15 अगस्त 2023 तक विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुरूआती चरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के 111 अमृत सरोवरों की योजना का शुभारंभ किया।

पूर्वजों की देन व पानी संरक्षण के लिए तालाब व बावड़ी के रूप में किया गया उनका बेहतर प्रयास आज अतीत की यादों में समां गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार की उदासीनता ही रही है। जिससे इन सूखे तालाबों व बावड़ियों का प्रयोग लोग पानी के लिए नहीं होता। बल्कि इनके किनारे लगे छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर ताश खेलने के रूप में कर रहे हैं। दशकों से वीरान पड़े तालाबों के प्रति ग्रामीणों के दिल में भी बेरूखी घर कर गई है। बरसात के घटते दिन भी तालाब व बावड़ियों के लिए अभिशप्त साबित हुए है। यही वजह है कि आज देश भर के गांवों में तालाब और जोहड़ पानी के अभाव में सूखे पड़े है। जिससे इन जोहड़ व तालाबों तक न तो पशुओं की पदचाप सुनाई देती है और न मनुष्य इनकी राह पकड़ता दिखाई देता है।

इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2022 को अमृत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 1650 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रत्येक जिले में 75-75 तालाबों को अमृत सरोवर बनाया जाएगा। इस योजना से गांवों का सौन्दर्यकरण होगा और पानी को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। आज गांव के तालाबों की स्थिति काफी दयानीय है और तालाबों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है तथा बरसाती पानी का भी तालाब संरक्षण नहीं कर पाते। इन तमाम पहलुओं को जहन में रखते हुए ही अमृत सरोवर योजना को शुरू किया गया है। इस योजना से सिंचाई का कार्य भी किया जाएगा और बरसाती पानी को संरक्षित भी किया जाएगा।

भारत में पानी की कमी अपर्याप्त आपूर्ति से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद पानी के प्रबंधन के तरीके से आई है। कृषि भारत के 78 प्रतिशत पानी का उपयोग करती है, और इसका बहुत ही अक्षमता से उपयोग करती है। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला लगभग दो-तिहाई पानी भूजल से आता है। भूजल पंप करने के लिए किसानों के लिए भारी बिजली सब्सिडी और तथ्य यह है कि भूजल बड़े पैमाने पर अनियमित है, पिछले कई दशकों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल के उपयोग में लगातार विस्फोट हुआ है। मांग की कमी को पूरा करने के लिए बोरवेल की व्यापक खुदाई करके भूजल के बढ़ते लेकिन बेहिसाब उपयोग की ओर जाता है।

पानी के उपयोग में शहरी भारत की अक्षमता अपर्याप्त, पुराने और जीर्ण वितरण नेटवर्क, अक्षम संचालन, अपर्याप्त मीटरिंग, अपूर्ण बिलिंग और संग्रह, और खराब शासन की सामान्य स्थिति से उत्पन्न होती है। अक्षमता का एक अन्य स्रोत अपशिष्ट जल का उपचार न करने और बागवानी जैसे विशेष उपयोगों के लिए पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग करने और शौचालयों को फ्लश करने के लिए भी

आता है। शहरी जल का कम मूल्य निर्धारण भी व्यर्थ उपयोग में योगदान देता है। यदि किसी चीज की कीमत कम है, तो उपयोगकर्ता उसका अधिक उपयोग करेंगे।

भारत के पानी को बचाने की चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक राजनीतिक समझौते की आवश्यकता है। किसानों को धान, गन्ना और केला जैसी जल-गहन फसलों को उगाने से रोकने के लिए भी कई प्रयास नहीं किए गए हैं, जब यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि कृषि में 80 प्रतिशत मीठे पानी की खपत होती है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी का महत्व भगवान के समान है। यहां के ग्रामीण इस अनमोल संसाधन की एक-एक बूंद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं।

राजस्थान के नागौर जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी को संरक्षित करने का सबसे आसान माध्यम तालाब हैं। इन तालाबों के बारे में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इनमें से कई तालाब सदियों पुराने हैं और ग्रामीणों के प्रयास से ही अभी तक संरक्षित किए गए हैं। नागौर जिले से कोई नदी नहीं बहती है और भूजल भी पीने योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीणों ने बारिश के पानी के संरक्षण और उपयोग के प्रभावी तरीके खोज निकाले हैं। बारिश के पानी को बचाने के लिए घरों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए टैंक और सामुदायिक उपयोग के लिए तालाब बनाए गए हैं। आज भी ये तालाब नागौर के ग्रामीणों के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत हैं।

तालाबों के संबंध में हर निर्णय ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाता है। तालाबों के संरक्षण के लिए हर गांव ने कुछ नियमों को लागू किया है। तालाब में गंदगी फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है, जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने पर जोर दिया जाता है। तालाब में जूते पहनकर प्रवेश करना सख्त मना है। इसके अलावा तालाब में नहाना, कपड़े धोना, मवेशियों को नहलाना भी मना है। घर के लिए तालाब से पानी ले जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन तालाब से पानी बिक्री के लिए नहीं लिया जा सकता है।

देश भर के कुछ गांव को छोड़कर ज्यादातर ऐसे हैं जहां तालाबों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है और वे जल्दी सूख जाते हैं, जिससे वहां के निवासियों को अन्य स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब हरियाणा सरकार की अमृत सरोवर योजना ने वर्षों से खाली पड़े और सूखते तालाबों को संरक्षित करने में पूरे देश में एक नयी आस जगाई है और हरियां के ग्रामीणों को इस पर गर्व है। अपने जल स्रोतों की सुरक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी पानी की कमी वाले अन्य क्षेत्रों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है।

-सत्यवान 'सौरभ'

लेकिन नए अनुमानों के मुताबिक जलवायु और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक सालाना 6.9 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। उदाहरण के लिए अमेरिका और यूके ने अपने योगदान में वृद्धि की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 2024 तक विकासशील देशों के लिए अमेरिकी जलवायु वित्त को दोगुना करने का वचन दिया है। फिर भी राष्ट्रपति बाइडेन का अगले वर्ष का बजट ओबामा प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी पूरा नहीं कर रहा है और यह 2030 तक 8 अरब डॉलर से 800 अरब डॉलर की प्रतिज्ञा से फिलहाल काफी दूर है जिसकी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन को सही करने में कोई मदद नहीं मिल रही है

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि विकसित देशों ने 2018 में जलवायु के लिए लगभग 80 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराया। लेकिन यह पाया गया कि उस धन का केवल 21 फीसदी ही जलवायु प्रभावों को सही करने के लिए दिया गया किया गया। इसका बड़ा हिस्सा कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए दिया गया। जलवायु के लेकर विकसित देशों के अंशदान के आंकड़ों की विकासशील देश आलोचना कर रहे हैं। वह यह दिखा रहे हैं कि सामान्य सहायता वाला भुगतान भी इसी में शामिल कर दिया गया है। लेकिन कई विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं उनसे जलवायु परिवर्तन को सही करने में कोई मदद नहीं मिल रही है। 2020 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में 210 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

औद्योगिक क्रांति के बाद से विकसित देश वातावरण में ऊष्मा को समाहित यानी ट्रैप करने वाले उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका खामियाजा विकासशील देशों को तापमान में वृद्धि, ज्यादा हीट वेव, बाढ़, सूखे के रूप में झेलना पड़ रहा है। विकासशील देशों ने एक अलग फंड की मांग की है जिसका भुगतान अमीर देश करें ताकि उन्हें हो रही उस नुकसान की भरपाई हो सके जिसे वह रोक नहीं सकते। इस मुद्दे को 'लॉस एंड डैमेज' के रूप में उल्लेखित किया गया है। गरीब, विकासशील देश अमीर और विकसित देशों से 'नुकसान और क्षति' फंड की मांग कर रहे हैं। यह पैसा उन चीजों की भरपाई करेगा जो विलुप्त हो गए हैं या जिन्हें दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इस फंड का इस्तेमाल तूफानों के बाद पुनर्निर्माण, नष्ट फसलों की क्षति-पूर्ति या जोखिम में आए पूरे समुदाय को स्थानांतरित करने के काम आ सकता है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने नुकसान और क्षति की तुलना अमेरिका के 1990 के दशक में तंबाकू और सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से की जिनसे धूम्रपान के कारण लोगों को हो रही बीमारियों में खर्च के लिए अरबों डॉलर की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। औद्योगिक देश ऐसे काम के लिए पैसा देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कानूनी रूप से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस तरह से देखा गया कि जिन देशों के पास सब कुछ है वो गरीब देशों के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने को तैयार नहीं थे। मगर अब स्थिति कुछ हद तक उलट रही है। मगर इस स्थिति का अमीर देशों को अहसास कराने के लिए एक युद्ध की जरूरत पड़ी।

जलवायु परिवर्तन से बड़ा नुकसान, भारत में समय से पहले 30 गुना बढ़ा हीटवेव का खतरा

जलवायु परिवर्तन ने भारत के अलावा पाकिस्तान में मुश्किल बढ़ा दी है और इस वजह से समय से पहले 30 गुना हीटवेव का खतरा बढ़ गया है। उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान में हाल की गर्मी की लहर पर विशेष रूप से नजर रखने वाले और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापने वाले एक एट्रिब्यूशन अध्ययन में कहा कि लंबे समय तक लू चलने की संभावना 30 गुना अधिक है।

हीटवेव से हुआ ये नुकसान

सूना-सूना लग रहा, बिन पेड़ों के गांव ।
पंछी उड़े प्रदेश को, बांधे अपने पांव ।।

पक्षियों को पर्यावरण की स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक माना जाता है। क्योंकि वे आवास परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं और पक्षी पारिस्थितिकीविद् के पसंदीदा उपकरण हैं। पक्षियों की आबादी में परिवर्तन अक्सर पर्यावरणीय समस्याओं का पहला संकेत होता है। चाहे कृषि उत्पादन, वन्य जीवन, पानी या पर्यटन के लिए पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन किया जाए, सफलता को पक्षियों के स्वास्थ्य से मापा जा सकता है। पक्षियों की संख्या में गिरावट हमें बताती है कि हम आवास विखंडन और विनाश, प्रदूषण और कीटनाशकों, प्रचलित प्रजातियों और कई अन्य प्रभावों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

बदल रहे हर रोज ही, हैं मौसम के रूप ।
सर्दी के मौसम हुई, गर्मी जैसी धूप ।।
सूनी बगिया देखकर, 'तितली है खामोश' ।
जुगनूं की बारात से, गायब है अब जोश ।।

हाल ही की एक रिपोर्ट, 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स' के अनुसार, दुनिया भर में मौजूदा पक्षी प्रजातियों में से लगभग 48 प्रतिशत आबादी में गिरावट के दौर से गुजर रही है या होने का संदेह है। प्राकृतिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में पक्षियों का पारिस्थितिक महत्व है। पक्षी कीट और कृंतक नियंत्रण, पौधे परागण और बीज फैलाव प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों को ठोस लाभ होता है। कीट का प्रकोप सालाना करोड़ों डॉलर के कृषि और वन उत्पादों को नष्ट कर सकता है। पर्पल मार्टिंस लंबे समय से हानिकारक कीटनाशकों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लागत (आर्थिक लागत का उल्लेख नहीं) के बिना कीट कीटों की आबादी को काफी हद तक कम करने के एक प्रभावी साधन के रूप में जाना जाता है।

आती है अब है कहां, कोयल की आवाज ।
बूढ़ा पीपल सूखकर, ठूंठ खड़ा है आज ।।
जब से की बाजार ने, हरियाली से प्रीत ।
पंछी डूब दर्द में, फूटे गम के गीत ।।

पक्षी प्राकृतिक प्रणालियों में कीड़ों की आबादी को कम करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्वी जंगलों में पक्षी 98 प्रतिशत तक बुडवार्म खाते हैं और 40 प्रतिशत तक सभी गैर-प्रकोप कीट प्रजातियों को खाते हैं। इन सेवाओं का मूल्य 5,000 डॉलर प्रति वर्ष प्रति वर्ग मील वन पर रखा गया है, संभावित रूप से पर्यावरण सेवाओं में अरबों डॉलर में अनुवाद किया जा सकता है। पक्षियों और जैव विविधता के नुकसान का सबसे बड़ा खतरा आवासों का विनाश और क्षरण है। पर्यावास के नुकसान में प्राकृतिक क्षेत्रों का विखंडन, विनाश और परिवर्तन शामिल है, जिन्हें पक्षियों को अपने वार्षिक या मौसमी चक्र को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

फीके-फीके हो गए, जंगल के सब खेल ।
हरियाली को रौंदती, गुजरी जब से रेल ।।
नहीं रहे मुंडेर पर, तोते-कौवे-मोर ।
लिए मशीनी शोर है, होती अब तो भोर ।।

1800 के दशक के बाद से अधिकांश पक्षी विलुप्त होने के लिए आक्रामक प्रजातियां जिम्मेदार हैं, जिनमें से अधिकांश समुद्री द्वीपों पर हुई हैं। उदाहरण के लिए, अकेले हवाई में, आक्रामक रोगजनकों और शिकारियों ने 71 पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दिया है। कुछ पक्षियों का अवैध शिकार वाणिज्यिक और निर्वाह उद्देश्यों के लिए, भोजन के लिए, या उनके पंखों के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, कुछ प्रजातियों का अत्यधिक शिकार विलुप्त होने का प्रमुख कारण रहा है। स्थानीय स्तर पर निर्वाह के शिकार के परिणामस्वरूप शायद ही कभी प्रजातियों का विलोपन होता है। व्यावसायिक शिकार से किसी प्रजाति के मरने की संभावना अधिक होती है।

अमृत चाह में कर रहे, हम कैसे उत्थान ।
जहर हवा में घोलते, हुई हवा तूफान ।।
बेचारे पंछी यहां, खेलें कैसे खेल ।
खड़े शिकारी पास में, ताने हुए गुलेल ।।

जलवायु परिवर्तन से आवास के नुकसान और आक्रामक प्रजातियों के खतरों के साथ-साथ नई चुनौतियों का निर्माण करने का खतरा है, जिन्हें पक्षियों को दूर करना होगा। इसमें आवास वितरण में बदलाव और चरम खाद्य आपूर्ति के समय में बदलाव शामिल है जैसे कि पारंपरिक प्रवासन पैटर्न अब पक्षियों को नहीं रख सकते हैं जहां उन्हें सही समय पर होने की आवश्यकता होती है। अन्य मानव निर्मित संरचनाओं के साथ टकराव भी एक इनकी मौत का कारण है। उदाहरण के लिए, पावरलाइन पक्षियों के लिए एक खतरा पेश करती है, विशेष रूप से बड़े पंखों वाले, और हर साल 25 मिलियन पक्षियों की मौत का अनुमान है। संचार टावरों का अनुमान है कि हर साल 7 मिलियन पक्षियों की मौत हो जाती है और रात में प्रवास करने वाले पक्षियों के लिए एक विशेष खतरा पैदा होता है।

वाहन दिन भर दिन बढ़े, खूब मचाये शोर ।
हवा विषैली हो गई, धुआं चारों ओर ।।
बिन हरियाली बढ़ रहा, अब धरती का ताप ।
जीव-जगत नित भोगता, कुदरत के संताप ।।

कीटनाशक और अन्य विषाक्त पदार्थ के कारण यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस का अनुमान है कि हर साल लगभग 72 मिलियन पक्षी कीटनाशक विषाक्तता से मर जाते हैं। पक्षियों पर कीटनाशकों के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है- प्रदूषण और विषाक्त पदार्थ उप-घातक प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो सीधे पक्षियों को नहीं मारते हैं, लेकिन उनकी लंबी उम्र या प्रजनन दर को कम करते हैं। कीटनाशकों के अलावा, भारी धातुओं (जैसे सीसा) और प्लास्टिक कचरे सहित अन्य संदूषक भी पक्षियों के जीवन काल और प्रजनन सफलता को सीमित करते हैं। तेल और अन्य ईंधन रिसाव का पक्षियों, विशेष रूप से समुद्री पक्षियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तेल पक्षियों के पंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है है, जिससे पंख अपने जलरोधक गुणों को खो देता है और पक्षी की संवेदनशील त्वचा को अत्यधिक तापमान में झुलसा देता है।

जीना दूभर है हुआ, फैले लाखों रोग ।
जब से हमने है किया, हरियाली का भोग ।।
शहरी होती जिंदगी, बदल रहा है गांव ।
धरती बंजर हो गई, टिके मशीनी पांव ।।

दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों की रक्षा करें,महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पक्षी सर्वेक्षण करना,पक्षियों की रक्षा के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करें संरक्षण रणनीति में जनसंख्या बहुतायत और परिवर्तन का विश्वसनीय अनुमान लगाना शामिल है। अधिक कटाई वाले जंगली पक्षियों की मांग में कमी के लिए नए और अधिक प्रभावी समाधान बड़े पैमाने पर लागू किए गए। हरित ऊर्जा संक्रमणों की निगरानी करना जो अनुपयुक्त तरीके से लागू किए जाने पर पक्षियों को प्रभावित कर सकते हैं।

रोज प्रदूषण अब हरे, धरती का परिधान ।
मौन खड़े सब देखते, मुंह ढांके हैरान ।।
हरे पेड़ सब कट चले, पड़ता रोज अकाल ।
हरियाली का गांव में, रखता कौन ख्याल ।।

पक्षी पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अत्यधिक दृश्यमान और संवेदनशील संकेतक हैं, उनका नुकसान जैव विविधता के व्यापक नुकसान और मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरे का संकेत देता है। इस प्रकार, हमें तेजी से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की गति को कम करने के लिए प्रकृति पर बढ़ते मानव पदचिह्न को कम करने के लिए सरकार, पर्यावरणविदों और नागरिकों के समन्वित कार्यों की आवश्यकता है।

सच्चा मंदिर है वही, दिव्या वही प्रसाद ।
बंटते पौधे हों जहां, संग थोड़ी हो खाद ।।
पेड़ जहां नमाज हो, दरख्त जहां अजान ।
दरख्त से ही पीर सब, दरख्त से इंसान ।।

-सत्यवान 'सौरभ'

यह बात जलवायु पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। विश्लेषण के अनुसार, भारत और पाकिस्तान में लंबे समय से हीटवेव चल रही है, जिसने व्यापक मानव पीड़ा और वैश्विक गेहूं की आपूर्ति को प्रभावित किया है। मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण होने की संभावना लगभग 30 गुना अधिक थी।

इन देशों के वैज्ञानिकों ने किया रिसर्च में सहयोग

भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विटजरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, यूएसए और यूके के वैज्ञानिकों ने यह आकलन करने के लिए सहयोग किया कि मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने इस एट्रिब्यूशन अध्ययन में हीटवेव की संभावना और तीव्रता को किस हद तक बदल दिया। यूके मेट ऑफिस ने बदले में, भारत और पाकिस्तान में अप्रैल/मई के तापमान के 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना जताई है।

भारत में गर्मी ने तोड़ा 122 साल पुराना रिकॉर्ड

इस साल मार्च की शुरुआत से ही भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में समय से पहले ही गर्म हवाएं चलने लगी थीं, जिसका असर अब भी महसूस किया जा रहा है। रिसर्चर्स ने बताया कि भारत में इस साल मार्च सबसे गर्म रहा और 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड तापमान देखा गया।

अगले 28 वर्षों में भारत में 62 फीसदी कृषि पर पानी की कमी का असर

- ललित मौर्या

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग फर्म एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 28 वर्षों में भारत में 62 फीसदी कृषि पर पानी की कमी का असर पड़ सकता है

इसमें कोई शक नहीं की जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहे हैं उससे न केवल लोगों के जीवन और गुणवत्ता को खतरा है। साथ ही लोगों की आय पर भी इन बदलावों का भारी असर पड़ेगा। भारत भी इससे अलग नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जारी एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 28 वर्षों में भारत की जीडीपी में 15 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के अन्य देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगें। पता चला है कि 2050 तक दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इन खतरों से कहीं ज्यादा प्रभावित हो सकती है।

यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग फर्म एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है। यह फर्म देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य के आधार पर क्रेडिट स्कोर देती है।

जलवायु में आते बदलावों के चलते कहां किस देश में कितना पड़ सकता है असर

2050 तक पड़ने वाले इन प्रभावों की गणना जलवायु के आरसीपी4.5 परिदृश्य के तहत की गई है। यहां आंकड़े प्रतिशत में हैं।

भारत में वायु प्रदूषण से 16 लाख मौतें !

अब वह वक्त आ गया है, जब अकाल मौतों की संख्या को देखते हुए विश्व को यह तय करना होगा कि आधुनिक विकास मॉडल की विसंगतियों पर गंभीरता से विचार हो 7 आंकड़े आईना दिखा रहे हैं ,एक साल में नब्बे लाख लोग प्रदूषण के चलते मौत के मुंह में समा गए हैं। अकेले एक साल में भारत में वायु प्रदूषण से सोलह लाख से अधिक लोग एक साल में मारे गए हैं ।

चर्चित स्वास्थ्य पत्रिका लैंसेट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019 में प्रदूषण से जो नब्बे लाख मौतें हुई उसमें पिचहत्तर फीसदी मौतें वायु प्रदूषण से हुई हैं। साथ ही तेरह लाख लोगों की मौतें प्रदूषित पानी पीने से हुई। दुनिया में होने वाली हर छठी मौत का प्रदूषण से होना बताता है7 क्या यह दुनिया को आधुनिक विकास मॉडल की विसंगतियों पर नये सिरे से विचार करने का विषय नहीं है। जरुर है,प्राथमिकता के साथ दुनिया को विचार करना चाहिए कि आज जो औद्योगिक व रासायनिक प्रदूषण लाखों जिंदगियां लील रहा है उस पर अंकुश कैसे लगे ?

यह समस्या केवल भारत या विकासशील देशों की ही नहीं है, विकसित देश भी इस संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन संपन्न देश इस संकट से बचाव के उपायों को करने में सक्षम हैं। दरअसल, विकसित देशों की समृद्धि शेष दुनिया के संसाधनों के अनैतिक दोहन और पर्यावरण की चिंता किये बगैर हुई औद्योगिक क्रांति के जरिये ही आई है। जब विकासशील व गरीब मुल्कों ने अपनी विशाल जनता का पेट भरने को उद्योगों के विस्तार का निर्णय लिया तो पश्चिमी देशों ने पर्यावरण संकट का राग अलापना शुरू कर दिया। वहीं वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिये विकासशील देशों ने गरीब मुल्कों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिये उठाये जाने वाले कदमों के एवज में जो मदद का वायदा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया। यही वजह है कि टोक्यो समझौते, पेरिस समझौते से लेकर ग्लासगो घोषणापत्रों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। जबकि हकीकत यही है कि दुनिया के गरीब व विकासशील देश पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद और मुनाफे की लिप्सा की कीमत चुका रहे हैं।

मुनाफा कमाने की मानवीय होड़ ने बीसवीं सदी से ही प्रदूषण का जहर वातावरण में घोलना शुरू कर दिया था। कालांतर यही विकास मानव को विनाश की ओर ले जाने लगा। आज दुनिया का तापमान उस स्तर तक जा पहुंचा है कि ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कुदरत के कहर से मानव कराह रहा है। दरअसल, पर्यावरण के मानकों को ताक पर रखकर मुनाफा कमाने के लालच ने लाखों निर्दोष लोगों को प्रदूषण के जरिये मौत के मुंह में धकेल दिया है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कारखानों-फैक्ट्रियों से ही प्रदूषण पैदा हुआ है, वाहनों की बढ़ती होड़ भी इसमें बड़ा कारक बना है।

संपन्नता के चलते एक घर में तीन-चार कार रखने वालों की भी इसमें भूमिका है। वाहनों का प्रदूषण भी मानव जीवन के लिये एक चुनौती बन गया है। सरकारें हैं कि सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास करती नजर नहीं आ रही हैं। प्रदूषण का संकट मानवता के लिये बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है और देश व सरकारें गैरजरूरी मुद्दों में उलझी हुई हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध समेत दुनिया के अन्य युद्धों से पैदा होने वाला जहरीले बारूद का धुंआ भी इस संकट को और बढ़ा रहा है जिसके चलते वातावरण में जहरीली गैसों व रसायनों का घुलना बदस्तूर जारी है। उन लोगों के लिये यह संकट और बड़ा है जो इन उद्योगों में काम कर रहे हैं। लाखों लोग महज जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। सरकारों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को तरजीह देकर जहरीला धुआं उगलने वाले थर्मल पॉवर प्लांटों के विकल्पों के बारे में सोचना होगा। इससे पहले कि यह संकट और गहरा हो, सरकार व नागरिकों के स्तर पर इसे रोकने की सार्थक पहल हो। पर्यावरण संरक्षण पर प्रत्येक वर्ष होने वाले धनी देशों के सम्मेलन के आयोजन के बजाय गरीब मुल्कों की मदद के विकल्प पर ध्यान देना जरूरी है। गरीब देशों की समस्या यह है कि प्रदूषण से पहले उनकी प्राथमिकता अपने लोगों के पेट भरने की है, सभी देशों को पर्यावरण के अनुकूल रोजगार के स्रोत तलाशने होंगे।

जंगल की आग, बाढ़, तूफान, समुद्र तल में होती वृद्धि से जीडीपी पर पड़ने वाला संभावित प्रभावकृषि पर मंडराते जल संकट से जीडीपी पर पड़ने वाला अनुमानित प्रभावकृषि पर पड़ने वाला पानी की कमी का प्रभावलू के चपेट में आने वाली आबादी (संभावित)

बांग्लादेश	भारत	पाकिस्तान	श्रीलंका
90	52	20	5
0	10	17	5
0	62	81	73
21	40	48	100

Chart: ललित मौर्य Source: अंतराष्ट्रीय रेटिंग फर्म एसएंडपी ग्लोबल, अप्रैल 2022

Get the data Embed Download image Created with Datawrapper

रिपोर्ट में भारत सहित दुनिया के 135 देशों की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर बाढ़, सूखा, तूफान, समुद्र के जल स्तर में होती वृद्धि, जंगल में लगने वाली आग, हीटवेव और जल संकट जैसे खतरों का जीडीपी पर पड़ने वाले असर का आंकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में जलवायु के खतरों को तीन अलग-अलग परिदृश्यों के आरसीपी2.6, आरसीपी 4.5 और आरसीपी 8.5 तहत मापा है।

अनुमान है कि इन देशों में आने वाले कुछ दशकों में बाढ़, तूफान, दावाग्नि और समुद्र के बढ़ते जल स्तर का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, जो अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित

करेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि जलवायु अनुकूलन पर ध्यान न दिया गया तो कृषि के लिए पानी की कमी पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगी।

इतना है नहीं रिपोर्ट के मुताबिक यदि क्षेत्रीय तौर पर देखें तो दुनिया में इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इतना है नहीं रिपोर्ट के मुताबिक यदि क्षेत्रीय तौर पर देखें तो दुनिया में इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

जहां अनुकूलन के आभाव में यूरोप से 10 गुना ज्यादा असर पड़ेगा। अनुमान है कि जलवायु बदलावों के चलते जहां बाढ़, सूखा, तूफान, दावाग्नि और समुद्र के बढ़ते जलस्तर का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही बढ़ती गर्मी और लू पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो जाएगी, जो बार-बार दस्तक देगी।

भारत की 62 फीसदी कृषि पर पड़ सकता है जल संकट का असर

इतना ही नहीं दक्षिण एशिया के लिए रिपोर्ट में जो निष्कर्ष सामने आए हैं उनके अनुसार बाढ़, तूफान, दावाग्नि और बढ़ते समुद्री जल स्तर के चलते भारत की करीब 52 फीसदी जीडीपी पर असर पड़ता सकता है। वहीं बांग्लादेश की 90 फीसदी, पाकिस्तान की 20 फीसदी और श्रीलंका की 5 फीसदी जीडीपी पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

इसी तरह कृषि पर बढ़ते जल संकट की बात करें तो उसके चलते भारत की 10 फीसदी, पाकिस्तान की 17 और श्रीलंका की 5 फीसदी जीडीपी प्रभावित हो सकती है। अनुमान है कि जहां आने वाले वक्त में पाकिस्तान की 81 फीसदी कृषि पानी की कमी से त्रस्त होगी। वहीं श्रीलंका में 73 और भारत में 62 फीसदी पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

वहीं यदि लोगों पर लू के प्रकोप को देखें तो अगले 28 वर्षों में श्रीलंका की 100 फीसदी आबादी लू की चपेट में आ सकती है। वहीं पाकिस्तान की 48 फीसदी, भारत की 40 फीसदी और बांग्लादेश की 21 फीसदी आबादी लू का बढ़ता कहर झेलने को मजबूर होगी। हाल ही में भारत में लू को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा किए विश्लेषण से पता चला है कि इस साल देश के 15 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लू की चपेट में हैं जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है।

इन बदलावों से दुनिया में कोई नहीं होगा सुरक्षित

यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो जलवायु में आते इन बदलावों के चलते जीडीपी में 4 फीसदी की गिरावट आ सकती है। देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन कमजोर देशों को भुगतना होगा जो इन जलवायु बदलावों के लिए जिम्मेवार तक नहीं हैं। अनुमान है कि अमीर देशों की तुलना में निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में जीडीपी को औसतन 3.6 गुना ज्यादा नुकसान होने की संभावना है।

इसके साथ ही मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सहित उप-सहारा अफ्रीका के कई क्षेत्रों में भी इन बदलावों का बड़े पैमाने पर असर हो सकता है। इसी तरह पूर्वी एशिया और प्रशांत देश को भी उप-सहारा अफ्रीका के समान ही खतरों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जहां अफ्रीकी देशों में गर्मी, सूखे और लू का खतरा ज्यादा होगा वहीं इन क्षेत्रों को तूफान और बाढ़ के चलते कहीं ज्यादा हानि हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे द्वीपीय देशों और भूमध्य रखा के पास के देशों पर जोखिम सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही उन देशों पर ज्यादा प्रभाव की आशंका है जहां अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि पर ज्यादा निर्भर है।

गौरतलब है कि आईपीसीसी द्वारा जारी रिपोर्ट 'क्लाइमेट चेंज 2022: इम्पैटस, अडॉप्टेशन एंड वल्नेरेबिलिटी' में भी बढ़ते जलवायु के खतरों के बारे में आगाह किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो दुनिया में करीब 300 करोड़ लोग पानी की गंभीर समस्या से त्रस्त होंगें जबकि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 400 करोड़ के पार चला जाएगा।

इतना ही नहीं रिपोर्ट के मुताबिक तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ करीब 8 फीसदी भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी, जिसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा, आय और स्वास्थ्य पर पड़ेगा।

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ने भी गणना की है कि, पिछले 50 वर्षों में औसतन दुनिया के किसी न किसी देश में मौसम या जलवायु से जुड़ी आपदा ने लोगों को अपना निशाना बनाया है। इन आपदाओं में हर रोज 115 लोगों की मौत हो रही है। वहीं हर दिन 1,544 करोड़ रुपए के रूप में इसका खामियाजा अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है।

बीमा फर्म स्विस रे का भी अनुमान है कि पिछले 10 वर्षों में बाढ़, तूफान और दावाग्नि के चलते हर साल वैश्विक जीडीपी को 0.3 फीसदी का नुकसान हुआ है। अनुमान है कि अकेले 2021 में प्राकृतिक आपदाओं से करीब 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि 9,200 लोगों की गई जान इन आपदाओं ने ली थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक बदलती जलवायु के चलते हर साल 560 आपदाएं लोगों को अपना निशाना बनाएंगी।

हमारी धरती एक साझा विरासत है और यह खतरा ऐसा है जिससे कोई एक देश या शहर प्रभावित नहीं होगा। यदि तापमान बढ़ता है तो उसका खामियाजा सारी मानव जाति को उठाना होगा। ऐसे में यह हमें तय करना है कि हम अपने लिए कैसा भविष्य चुनते हैं। ■

क्वाड में भारत की कूटनीति का दिखा असर

● संपादन - अनुज अग्रवाल

रूस-यूक्रेन जंग के बीच वैश्विक स्तर पर किसी एक नेता के दूसरे नेता से मिलने के मायने काफी बढ़ गए हैं। कौन किससे मिल रहा और क्या बयान दिए जा रह हैं इस पर सभी देशों की नजर है। ऐसे वक्त में जब 3 महीने से अधिक समय से रूस-यूक्रेन की लड़ाई जारी है और क्वाड की बैठक होती है। इस बैठक पर कई देशों की नजर थी लेकिन सबसे अधिक किसी की नजर थी तो वह देश था चीन। बैठक से चीन को जो संदेश देना था वो दिया गया। वहीं इससे अलग भारत और अमेरिका की सीधी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडन के बीच कई मुद्दों पर सीधी बातचीत हुई। जापान में क्वाड नेताओं की मीटिंग बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। क्या बयान जारी होता है इस पर भी नजर थी। इस संयुक्त बयान में यूक्रेन का जिक्र तो था लेकिन कहीं रूस का नाम नहीं था। कूटनीति के लिहाज से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारत ने जो चाहा वैसा ही हुआ। भारत और रूस के बीच कैसे संबंध है यह बात किसी से छिपी नहीं लेकिन भारत का शुरू से ही इस पूरे मामले पर क्लियर स्टैंड रहा है और संयुक्त राष्ट्र के मंच तक भी सबने देखा है।

चीन की घेराबंदी क्यों है जरूरी, कड़ा संदेश

क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हिन्द प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों और साझा हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। क्वाड समूह के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बिना किसी उकसावे के और एकतरफा तनाव बढ़ाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया। साथ ही किसी तरह की धमकी के बिना शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का निपटारा करने का आह्वान किया। क्वाड समूह के नेताओं ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच अंतरराष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बरकरार रखने का संकल्प व्यक्त किया।

बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि किसी किसी भी बलपूर्वक, उकसाने वाली या एकतरफा कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं, जिसके जरिये यथास्थिति को बदलने और तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाए। बयान के अनुसार, हम अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन करने के हिमायती हैं, जैसा समुद्री कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र संधि में है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की पृष्ठभूमि में, भारत, अमेरिका और विश्व की कई अन्य शक्तियां स्वतंत्र, खुला एवं संपन्न हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दे रही हैं। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप एवं सैन्य अड्डे भी बनाए हैं।

हम स्वतंत्रता, कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता, बिना बल प्रयोग के विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने का पुरजोर समर्थन करते हैं। विमानों की उड़ान संबंधी स्वतंत्रता को बनाये रखने के पक्षधर हैं। सभी हिन्द प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में शांति, स्थिरता व समृद्धि के लिये जरूरी हैं।

यूक्रेन का हुआ जिक्र लेकिन रूस का नाम नहीं

क्वाड समूह के नेताओं ने यूक्रेन जंग के बाद पैदा हुए हालात चर्चा की और इसके हिन्द प्रशांत क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया। इसमें कहा गया है कि वे आसियान की एकता एवं इसकी केंद्रीयता के लिये अपने समर्थन तथा हिन्द प्रशांत आसियान दृष्टि को व्यावहारिक रूप से लागू करने की पुन: पुष्टि करते हैं। बयान में चारों देशों ने कहा कि वे हिन्द प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिये यूरोपीय संघ की रणनीति पर उसकी संयुक्त विज्ञप्ति का स्वागत करते हैं, जिसकी घोषणा सितंबर 2021 में हुई थी ।

समूह के नेताओं ने उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास व प्रक्षेपण

क्वाड सम्मेलन

क्वाड के नेताओं की यह पहली 'इन-पर्सन' मुलाकात है। पांच साल पहले इसके गठन के बाद से दो बार इसके नेताओं का वर्चुअल सम्मेलन हुआ है लेकिन पहली बार चारों नेता आमने-सामने मिल रहे हैं। क्वाड यानी 'क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग' या 'क्वाड्रिलेटरल इनीशिएटिव' का सुझाव देने वाले शिंजो आबे अब जापान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनकी जगह प्रधानमंत्री बने फूमियो किशिदा पहले 'इन-पर्सन' क्वाड सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। आबे ने सबसे पहले 2016 में इस तरह के एक समूह के गठन का सुझाव दिया था। वे चीन की विस्तारवादी नीतियों और हिंद-प्रशांत का सैन्यकरण करने के उसके प्रयासों से चिंतित थे। उनके प्रयास का नतीजा था कि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने 2017 में एक समूह बनाया।

क्वाड का गठन एक बड़ी वैश्विक परिघटना थी और इसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा था। यह माना गया था कि चार बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाएंगे, हिंद-प्रशांत को चीन के सैन्य अड्डे में बदलने से रोकेंगे और इसे एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे। क्वाड के कई घोषित मकसद में से मुख्य मकसद हिंद-प्रशांत को सुरक्षित क्षेत्र बनाना है। सवाल है कि क्या पिछले पांच साल में क्वाड अपने इस मकसद में कामयाब हुआ है? या कोई ऐसी ठोस पहल हुई है, जिससे लगे कि चारों देश इस दिशा में आगे बढ़े हैं?

हिंद-प्रशांत के चार बड़े देशों की पहल के बावजूद उसका आश्वस्त होना सिर्फ इस कारण से है कि ये चारों देश कारोबार के लिए चीन पर निर्भर हैं। चीन के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का कारोबार कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन चार देशों के साथ चीन का ट्रेड सरप्लस सालाना करीब सात सौ अरब डॉलर का है। यानी ये चार देश मिलकर चीन को जितना निर्यात करते हैं उससे सात सौ अरब डॉलर ज्यादा का आयात करते हैं। यह चीन की असली आर्थिक ताकत है, जिसके दम पर वह हिंद-प्रशांत में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी अपना सैन्य विस्तार कर रहा है। इसमें अकेले अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस चार सौ अरब डॉलर का है। चीन के कुल ट्रेड सरप्लस में करीब 60 फीसदी हिस्सा अकेले अमेरिका का है। भारत के साथ भी उसकी सालाना कारोबार अधिकता बढ़ कर 80 अरब डॉलर हो गई है।

चीन की विस्तारवादी नीतियों का सबसे बड़ा और पहला शिकार भारत है। उसने मध्य एशिया के देशों से अपना सीमा विवाद निपटा लिया है और पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया में उसका विवाद ज्यादातर समुद्री सीमा को लेकर है। दक्षिण एशिया में भारत अकेला देश है, जिसकी सीमा चीन खा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले आठ साल में चुमार से लेकर डोकलाम और अब पूर्वी लद्दाख में चीन ने सीमा विवाद और सैन्य टकराव बढ़ाया है। इसके बावजूद चीन के ऊपर भारत कोई आर्थिक दबाव नहीं डाल पाया है। पूर्वी लद्दाख में दो साल से चल रहे सीमा विवाद और गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बावजूद चीन के साथ भारत का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अब तक के इतिहास में पहली बार भारत ने चीन के साथ एक सौ अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार किया है। सोचें, एक तरफ चीन का सैनिक विस्तारवाद है और उसे रोकने के लिए क्वाड पहल है तो दूसरी ओर चीन के साथ कारोबार का विस्तार है। जाहिर है भारत का नेतृत्व मुंह जबानी जो पहल करे लेकिन हकीकत में वह वास्तविक खतरे से मुंह मोड़े हुए है। जब तक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चारों देश चीन के ऊपर आर्थिक दबाव नहीं डालेंगे, तब तक उसके सैन्य विस्तार को रोकना नामुमकिन होगा।

कम से कम अभी तो इसकी संभावना नहीं दिख रही है कि अमेरिका या भारत कोई आर्थिक दबाव देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो चीन को राहत देनी ही शुरू कर दी है। चीन ने अमेरिका के साथ हुए कारोबार समझौते के पहले चरण की शर्तों को 2020 की तय समय सीमा तक पूरा नहीं किया, इसके बावजूद बाइडेन प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई। उलटे चीन की बड़ी तकनीकी कंपनी हुआवे के संस्थापक की बेटी को फ्रॉड के आरोपों से मुक्त कर दिया। कोरोना की उत्पत्ति और उसके प्रसार में चीन की घोषित भूमिका होने के बावजूद अमेरिका ने उस पर दबाव नहीं बनाया। आने वाले दिनों में चीन के साथ अमेरिका के कारोबार में कमी आने की बजाय बढ़ोतरी हो तो हैरानी नहीं होगी क्योंकि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने चीन से आयातित 352 वस्तुओं पर शुल्क से छूट फिर से बहाल कर दी है। पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन वस्तुओं पर शुल्क लगाया था, जिसे बाइडेन प्रशासन ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन चीन से आयातित असैन्य वस्तुओं पर शुल्क में और छूट देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन इस प्रयास में है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चीन किसी तरह से रूस से दूरी बनाए। चीन को रूस से दूर रखने के लिए अमेरिका उसके साथ कारोबार भी बढ़ा रहा है और उसे रियायत भी दे रहा है।

क्वाड का एक मकसद इस समूह के चार देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने का भी था। लेकिन इसके उलट चीन के साथ ही कारोबार बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत और दूसरे देशों के साथ कारोबार बढ़ाने या अपने बाजार तक इन देशों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल नहीं की है। तभी क्वाड की सफलता पर संदेह किया जाने लगा है। अगर ये चारों देश मिल कर स्पष्ट और ठोस एजेंडा तय नहीं करते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा।

स्वीडन-फिनलैंड को चाहिए NATO मेंबरशिप तो पूरी करनी होंगी दो शर्तें! दोनों देशों से आखिर क्या चाहता है तुर्की?

यूक्रेन में भीषण युद्ध लड़ रहे रूस के लिए टेंशन बढ़ रही है। यूरोपीय देश फिनलैंड और स्वीडन भी अब नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कहा था कि वह स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो को पूरा विश्वास है कि तुर्की दोनों यूरोपीय देशों की नाटो सदस्यता का विरोध नहीं करेगा। तुर्की ने रविवार को बर्लिन में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर अपनी मांगें रखीं।

अल जजीरा की खबर के अनुसार तुर्की ने कहा कि वह चाहता है कि दोनों नॉर्डिक देश अपने क्षेत्र में मौजूद कुर्द समुदाय के लिए अपने समर्थन को खत्म कर दें। इसके अलावा तुर्की को कुछ हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दें। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने कहा कि बर्लिन में स्वीडिश और फिनिश समकक्षों के साथ उनकी बातचीत मददगार रही है। तुर्की की चिंताओं को दूर करने के लिए दोनों देशों ने अपने सुझाव दिए हैं जिस पर विचार किया जाएगा।

नॉर्डिक देशों में 'आतंकवादी' होने के सबूत दिए

कावुसोग्लू ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में `आतंकवादियों' के मौजूद होने के सबूत मुहैया कराए हैं। उन्होंने स्वीडन का जिक्र करते हुए कहा कि कुर्दिश समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके), जिसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से आतंकवादी के रूप में प्रतिबंधित किया गया है, ने इस हाल ही में स्टॉकहोम में बैठकें की थीं। हालांकि उन्होंने कहा कि तुर्की ने गठबंधन की उस नीति का विरोध नहीं किया जिसके तहत गठबंधन के दरवाजे सभी यूरोपीय देशों के लिए खुले हैं जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं।

सदस्यता में देरी नहीं चाहता नाटो

नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम तुर्की की ओर से जाहिर की गई सभी चिंताओं को जल्द से जल्द दूर कर पाएंगे ताकि सदस्यता में देरी न हो। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बर्लिन में इस मुद्दे पर बंद दरवाजे के पीछे हुई बातचीत के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही आम सहमति पर पहुंचेंगे। ब्लिंकन ने कहा कि `नाटो संवाद का एक मंच' है।

फिनलैंड और स्वीडन को NATO की सदस्यता तुर्की को मंजूर नहीं, एर्दोगन ने धमकाया, रूस को नो प्रॉब्लम!

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कहा है कि वह स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया कि अंकारा की आपत्तियों पर बात करने के लिए जल्द ही प्रतिनिधि तुर्की जाएंगे। इसपर एर्दोगन ने कहा कि डिप्लोमेट्स को तुर्की आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, `जो लोग तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनके नाटो में शामिल होने पर हम कभी हां नहीं कहेंगे।' तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि स्वीडन या फिनलैंड, दोनों में किसी देश का आतंकी संगठनों के खिलाफ साफ स्टैंड नहीं है। उन्होंने स्वीडन को `आतंकियों का पालन गृह' करार दिया। फिनलैंड के बाद, स्वीडन ने भी सोमवार को ऐलान किया कि वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) की सदस्यता के लिए अनुरोध करेगा। वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के आवेदनों से कोई दिक्कत नहीं है।

फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों में जनता की राय 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले NATO में शामिल होने के खिलाफ थी, लेकिन उसके बाद दोनों देशों में NATO सदस्यता के लिए समर्थन तेजी से बढ़ा है।

रूस के लिए झटका है स्वीडन का ऐलान

स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना ऐंडरसन का ऐलान इस मायने में अहम है कि यह नॉर्डिक देश (स्वीडन) 200 से अधिक वर्षों से किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं था। उसके इस ताजा कदम को रूस के लिए झटका माना जा रहा है। इससे पहले यूरोप के एक और देश फिनलैंड ने भी रविवार को घोषणा की थी कि वह 30 देशों वाले सैन्य गठबंधन NATO में शामिल होने के लिए अनुरोध करेगा। सोमवार को स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने राजधानी में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वीडन को औपचारिक सुरक्षा गारंटी की जरूरत है जो NATO में सदस्यता के साथ आती है।

फिनलैंड को NATO मेंबर क्यों नहीं बनाना चाहते एर्दोगन? पुतिन बोले दिक्कत नहीं, विदेश मंत्री के तेवर गरम

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि रूस को NATO की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले स्वीडन या फिनलैंड से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूस को इससे सीधा खतरा नहीं है। हालांकि इन देशों में किसी भी सैन्य विस्तार पर उसकी प्रतिक्रिया आएगी। वहीं

पुतिन के उलट रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन ने NATO सैन्य गठबंधन में शामिल होने के अपने इरादे को लेकर 'गंभीर गलती की है'। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने से यूरोपीय महाद्वीप में सैन्य तनाव का सामान्य स्तर बढ़ जाएगा।

फिनलैंड-पोलैंड को NATO मेंबर क्यों नहीं बनाना चाहते एर्दोगन? तुर्की और रूस का कनेक्शन

रूस-यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा तुर्की उठा रहा है। नाटो का सदस्य होने के कारण तुर्की का यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। वहीं भू-राजनीतिक हालात के कारण तुर्की और रूस की दोस्ती भी काफी मजबूत है। बस इसी बात का फायदा तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन उठा रहे हैं। एर्दोगन ने एक दिन पहले ही कहा कि तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। नाटो सदस्य होने के नाते तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों को नाटो का सदस्य बनने से रोक सकता है। तुर्की के इस कदम से सीधा फायदा रूस को होगा, लेकिन इससे अमेरिका के नाराज होने का डर भी है। अमेरिका चाहता है कि समान विचारधारा वाले रूस के सभी पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बनें।

स्वीडन और फिनलैंड पर क्या बोले एर्दोगन

एर्दोगन ने कहा कि हम स्वीडन और फिनलैंड के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं, लेकिन हमारा रुख पक्ष में नहीं है। उधर, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बदले सुरक्षा परिवेश में नार्डिक देशों के समक्ष चुनौतियों पर केंद्रित स्वीडिश सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि नाटो में स्वीडन के शामिल होने पर मास्को नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और वह कई जवाबी कदम उठा सकता है। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडर्सन की कैबिनेट देश को नाटो में शामिल होने को लेकर क्या फैसला लेगी, यह स्वीडन की सरकार की उस रिपोर्ट पर तय होगा जिसमें सुरक्षा नीति का विश्लेषण किया गया है। सरकार ने यह रिपोर्ट सांसदों को शुक्रवार को सौंप दी।

फिनलैंड भी नाटो मेंबर बनने को तैयार

इसके पहले फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा था कि वह नाटो की सदस्यता के लिए तेजी से आवेदन करने के पक्षधर हैं। इससे फिनलैंड के आने वाले दिनों में नाटो में शामिल होने का ऐलान करने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही फिनलैंड को नाटो की तरफ से आवश्यक शर्तों को पूरा करने की लिस्ट सौंपी जाएगी। जिसको पूरा करने के बाद सभी 30 सदस्य देशों की सहमति से फिनलैंड को नाटो में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में महीनों से लेकर साल तक का समय लग सकता है।

नाटो मेंबर होते हुए रूस का साथ क्यों दे रहा तुर्की

रूस की तरह तुर्की का विस्तार भी आधा यूरोप और आधा एशिया में है। भू राजनीतिक हालात के कारण नाटो का सदस्य होते हुए भी तुर्की की मजबूरी है कि वह रूस से दोस्ती करे। दरअसल, गृह युद्ध और इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहे सीरिया की सीमा तुर्की से सटी हुई है। सीरिया के राष्ट्रपति बसर अल असद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी नेता हैं। वहीं, तुर्की और सीरिया के संबंध ठीक नहीं हैं। ऐसे में तुर्की की मजबूरी है कि वह रूस के जरिए सीरिया में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे। इससे तुर्की को सीरिया में रूस जैसा एक ताकतवर साथी मिल रहा है। दोनों देशों की जुगलबंदी अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रही है।

ग्रीस से तनाव भी तुर्की-रूस को ला रहा साथ

भूमध्य सागर में द्वीपों को लेकर तुर्की और ग्रीस में पिछले कई साल से गतिरोध जारी है। पिछले दो साल में कई ऐसे मौके आए हैं, जब तुर्की और ग्रीस की सेना आमने-सामने आ गई हैं। ग्रीस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और अमेरिका का काफी करीबी है। ऐसे में अमेरिकी विदेश नीति का झुकाव ग्रीस की तरफ ज्यादा रहता है। बस यही कारण है कि अमेरिका मांगने पर भी तुर्की को एफ-35, पेट्रियट मिसाइल जैसे घातक हथियार नहीं बेंच रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए तुर्की ने रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की है। इसी खरीद के कारण अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया था।

करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करने की निंदा की तथा कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इन देशों ने म्यांमार के संकट पर चिंता व्यक्त की और देश में तत्काल हिंसा समाप्त करने, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने तथा लोकतंत्र बहाल करने का आह्वान किया ।

मुंबई हमला, पठानकोट सहित आतंकवादी हमलों की निंदा

क्वाड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के सभी रूपों की स्पष्ट तौर पर निंदा करते हैं। चारों नेताओं ने आतंकी समूहों को साजो-सामान, वित्तीय या सैन्य सहयोग नहीं देने के महत्व पर जोर दिया क्योंकि इनका इस्तेमाल सीमा पार से आतंकी हमलों सहित इसकी साजिश रचने में किया जा सकता है। नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा, हम 26/11 मुंबई हमलों, पठानकोट हमलों सहित आतंकवादी हमलों की फिर से निंदा करते हैं।

क्वाड ने बनाया 'चक्रव्यूह'

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच मंगलवार को अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश का संकल्प जताया। क्वाड नेताओं ने कमियों को पाटने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने के वास्ते भागीदारों तथा क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसे हासिल करने के लिए क्वाड अगले पांच वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता और निवेश की कोशिश करेगा।

साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड ने बड़े फैसले किए हैं। इस क्षेत्र में चीन पर लगाम लगाने के लिए क्वाड ने कई फैसले किए हैं। क्वाड की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चीन को ताकीद की गई है कि साउथ चाइना सी में वह कोई ऐसी हरकत न करे जिसका पड़ोसी देशों पर असर पड़े। जापान में खत्म हुए क्वाड बैठक (Quad

रूस-यूक्रेन युद्ध : किस तरफ झुकेगा पलड़ा?

यूक्रेन में रूस का अभियान दिनों दिन थकाने वाला साबित हो रहा है। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं।

युद्ध की शुरुआत को करीब तीन महीने हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को थकाने में लगे हैं। दोनों ने हाल के दिनों में अपनी बढ़त का ऐलान किया है लेकिन सच ये है कि नुकसान दोनों पक्षों को हुआ है।

मोटे तौर पर रूस को बढ़त हासिल है क्योंकि उसकी सैनिक ताक़त काफी ज्यादा है। लेकिन रूस ने जैसी योजना बनाई थी, उस हिसाब वह फौरी जीत हासिल करने में नाकाम रहा है। यहां हम कुछ हालातों पर गौर करेंगे, जो युद्ध का पलड़ा किसी भी तरफ झुका सकते हैं।

हार और जीत

उत्तर में जवाबी हमले के जरिए यूक्रेन रूस को खारकीव से दूर रखने में सफल हुआ लेकिन दक्षिण में रूस का पलड़ा भारी था। अब रूस ने मारियुपोल पर फतह हासिल कर बढ़त बना ली है। खारकीव और मारियोपोल दोनों जगह की लड़ाइयों में बड़ी तादाद में सैनिक और नागरिक मारे गए। लेकिन दोनों जगह की जीत किसी एक पक्ष में निर्णायक साबित होती नहीं दिखती।

मारियुपोल और खारकीव में जो हुआ है वह इस जंग के अब तक के उतार-चढ़ाव को दिखाता है। अब उत्तर में महंगी हार और जीत का पैटर्न दोहराया जा रहा है।

रूस को डोनबास में थोड़ी ही लेकिन बढ़त मिल रही है। अब वहां उसने अपना फोकस और मजबूत किया है। लेकिन उसे वहां नुकसान भी हुआ है। सिवरस्की डोनेट्स नदी को पार करते हुए रूस की दर्जनों हथियारबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है।

रूस के पास हैं ज्यादा हथियार

पूर्वी हिस्से में रूस और यूक्रेन दोनों ओर से तोपों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में ब्रिटिश आर्मी के पूर्व ब्रिगेडियर बेन बेरी कहते हैं कि डोनबास की लड़ाई में ये हालात बने रहेंगे।

उनका कहना है कि तोपों से होने वाली ये लड़ाई हफ्तों और महीनों तक दोनों ओर जनहानि की वजह बनी रहेगी। पश्चिमी अधिकारियों ने रूसी पक्ष को हुए अच्छे-खासे नुकसान का जिक्र किया है । लेकिन वो यूक्रेनी पक्ष को हुए नुकसान को बताने में हिचक रहे हैं।

पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद यूक्रेन के पास हथियारों की कमी बनी है। फिलहाल उसे यूएस एम 777 तोपें मिल रही हैं। उसे काउंटर-आर्टिलरी रडार सिस्टम भी मिल रहा है ताकि रूसी आर्टिलरी लाइन को खोज कर उस पर हमला किया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत यही है यूक्रेन के पास अब भी रूस की तुलना में हथियार कम हैं।

दांवपेंच

रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से खूब गोले बरसा रहे हैं। उन पर रॉकेटों से भी हमला हो रहा है। रूस इस वक्त दो तरफ से हमला कर रहा है। उत्तर में आइजम और पश्चिम में सेवर दोनेत्स्क से। हालांकि उसे दोनों ओर आगे बढ़ने में थोड़ी ही सफलता मिली है।

ब्रिगेडियर बेरी का कहना है, 'ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेनी सैनिकों को वहां मारना चाहता है, जहां वो सबसे बुरी हालत में फंसे हों। यहां पर उन पर तोपों से धुआंधार हमला हो सकता है।'

सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इससे यूक्रेन के सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है लेकिन यूक्रेन अभी भी रूसी सैनिकों को रोकने के लिए डोनबास के शहरी इलाकों का इस्तेमाल कर सकता है। शहरों में लड़ाइयां यूक्रेन की सेना के लिए मददगार रही हैं।

रूसी सेना एक बार फिर मारियुपोल की ही तरह यूक्रेनी सेना के विरोध को कुचलने के लिए पूरा जोर लगाएगी। इसके लिए ये अपनी पहले से ही आजमाई रणनीति के मुताबिक चलेगी। यानी तोपों का जबरदस्त इस्तेमाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि रूसी हमले में पूर्वी डोनबास पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और वहां जिंदगी नरक बन गई है।

स्टील फैक्ट्री से निकले एक हजार यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर, रूस का मारीपोल जीतने का दावा

रूसी सेना ने मारीपोल इलाके को जीतने का दावा किया है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक मारीपोल की अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में रहकर कई हफ्ते लड़ाई लड़ने के बाद करीब एक हजार यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है।

मारीपोल की अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में रहकर कई हफ्ते लड़ाई लड़ने के बाद करीब एक हजार यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सैनिकों को रूसी कब्जे वाले स्थान पर ले जाया गया है और वहां उनसे पूछताछ चल रही है। उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। सैनिकों को लड़ाई खत्म करने का आदेश देने वाली यूक्रेन सरकार ने उनसे जान बचाने के लिए कहा लेकिन बाहर जाकर आत्म समर्पण करने के लिए नहीं कहा था।

स्टील फैक्ट्री की स्थिति को लेकर अभी भी सब कुछ साफ नहीं है। फैक्ट्री के भीतर कितने लोग बाकी हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। जिन सैनिकों ने बाहर निकलकर समर्पण किया है उनका भविष्य भी अनिश्चित है। यूक्रेन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि बंदियों की अदलाबदली में स्टील फैक्ट्री से निकले सैनिक रिहा हो जाएंगे लेकिन रूस समर्पण करने वाले कुछ सैनिकों पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने पर विचार कर रहा है।

रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेंकोव ने बुधवार को कहा, सोमवार से अभी तक कुल 959 यूक्रेनी सैनिक स्टील फैक्ट्री से बाहर आए हैं। इनमें घायल सैनिक भी शामिल हैं। रूसी सेना का अनुमान है कि स्टील फैक्ट्री के भीतर से करीब दो हजार सैनिक और विदेशी लड़ाके मुकाबला कर रहे थे। इस लिहाज से करीब आधे सैनिकों ने ही बाहर आकर समर्पण किया है।

करीब एक हजार सैनिकों के फैक्ट्री की सुरंगों और भूमिगत बंकरों में अभी होने का अनुमान है। दोनों पक्ष खुद को हारा हुआ नहीं दिखाना चाहते, इसलिए सतर्कता से बयान दिए जा रहे हैं। रूसी सैनिक सुरंगों में नहीं घुस रहे लेकिन रूसी सेना ने पूरे मारीपोल इलाके को जीत लेने का दावा किया है। कई शहरों से पीछे लौटी रूसी सेना को यह राहत देने वाली खबर है।

यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हाना मालियार ने कहा है कि फैक्ट्री से सैनिकों की निकासी के लिए वार्ता जारी है। वार्ता के आगे बढ़ने पर फैक्ट्री के भीतर मौजूद सैनिकों को बाहर आने के लिए कहा जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि विश्व के सबसे ज्यादा प्रभावशाली मध्यस्थ निकासी के लिए वार्ता में लगे हैं, नतीजा अच्छा निकलेगा।

रूस के लिए कठिन चुनौती

हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का ये मानना है कि पूर्वी इलाके में रूस के पास अहम बढ़त बनाने लिए सैनिकों की कमी है। अगर खारकीव और मारियो पोल के सैनिकों को लाकर यहां फिर तैनात किया जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला।

रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के जैक वैटलिंग का कहना है कि रूस के पास अभी भी सैनिकों की कमी है। खास कर पैदल सेना में। रूस ने बुरी तरह घायल यूनिटों को फिर से व्यवस्थित और खड़ा करने की कोशिश की है। इन यूनिटों को 'फ्रैंकेंस्टीन फोर्सेज' कहा जाता है।

रूस की सेना में तालमेल और हौसले की कमी दिख रही है। उससे उसका प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हालिया आकलन में कहा गया है कि रूसी कमांडर जल्दी नतीजे पाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए वे एक बार सेना को इस तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं ताकि ज्यादा तीखे वार कर अंदर घुसा जा सके।

लेकिन मंत्रालय का कहना है कि इससे सैनिक यूनिट छोड़ कर भाग सकते हैं। यह भी दावा किया जा रहा है हमलावर सैनिकों में रूस एक तिहाई को खो चुका है। साथ ही बड़ी तादाद में उसके सैनिक साजो सामान भी नष्ट हुए हैं।

वैल्टिंग कहते हैं कि रूस इन कमियों को पूरा कर रहा है। वह चालीस से ज्यादा उम्र के सैनिकों को मोर्चे पर लगाने और थोड़ी अवधि के लिए अधिकारियों की भर्ती की कोशिश में लगा है।

यूक्रेन के सामने इसकी सप्लाई लाइन की कमजोरियां भी उजागर हो चुकी है। लेकिन सेना को फिर से व्यवस्थित करने और इसकी ट्रेनिंग कराने में वक्त लगता है। दूसरी ओर यूक्रेन की इस मामले में क्षमता कमजोर लग रही है क्योंकि इसके ज्यादातर सैनिक मोर्चे पर लगे हुए हैं।

QUAD सम्मेलन से क्या मिलेगा ?

शोमैन मोदी हर विदेशी दौरे में छाये रहते हैं। आज कल वे जापान के दौरे पर हैं क्वाड की शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए। चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए बने क्वाड के चारों भागीदारों में अमेरिका के जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अंथनी अलबेनीज के चुनावों में सफलता के पीछे ही चीन ही है। जापान अब अपने नौकरशाह के हाथों में है व अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। मोदी भी बिना नाम लिए चीन को धमकी देने की रस्म निभाते आए हैं और भारत चीन के विरुद्ध सैन्य संगठन,क्वाड में भी शामिल नहीं हुआ है। यद्यपि चीन की विस्तारवादी नीतियों का सबसे बड़ा और पहला शिकार भारत है।

यह माना गया था कि चार बड़े लोकतांत्रिक देश मिलकर चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाएंगे, हिंद-प्रशांत को चीन के सैन्य अड्डे में बदलने से रोकेंगे और इसे एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित करेंगे। क्वाड के कई घोषित मकसद में से मुख्य मकसद हिंद-प्रशांत को सुरक्षित क्षेत्र बनाना है।

ये चारों देश कारोबार के लिए चीन पर निर्भर हैं। चीन के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का कारोबार कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन चार देशों के साथ चीन का ट्रेड सरप्लस सालाना करीब सात सौ अरब डॉलर का है। यानी ये चार देश मिलकर चीन को जितना निर्यात करते हैं उससे सात सौ अरब डॉलर ज्यादा का आयात करते हैं। यह चीन की असली आर्थिक ताकत है, जिसके दम पर वह हिंद-प्रशांत में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी अपना सैन्य विस्तार कर रहा है। इसमें अकेले अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस चार सौ अरब डॉलर का है। चीन के कुल ट्रेड सरप्लस में करीब 60 फीसदी हिस्सा अकेले अमेरिका का है। भारत के साथ भी उसकी सालाना कारोबार अधिकता बढ़ कर 80 अरब डॉलर हो गई है।पूर्वी लद्दाख में दो साल से चल रहे सीमा विवाद और गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बावजूद चीन के साथ भारत का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अब तक के इतिहास में पहली बार भारत ने चीन के साथ एक सौ अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार किया है। सोचें, एक तरफ चीन का सैनिक विस्तारवाद है और उसे रोकने के लिए क्वाड पहल है तो दूसरी ओर चीन के साथ कारोबार का विस्तार है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो चीन को राहत देनी ही शुरू कर दी है। चीन ने अमेरिका के साथ हुए कारोबार समझौते के पहले चरण की शर्तों को 2020 की तय समय सीमा तक पूरा नहीं किया, इसके बावजूद बाइडेन प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई। उलटे चीन की बड़ी तकनीकी कंपनी हुआवे के संस्थापक की बेटी को फ्रॉड के आरोपों से मुक्त कर दिया। कोरोना की उत्पत्ति और उसके प्रसार में चीन की घोषित भूमिका होने के बावजूद अमेरिका ने उस पर दबाव नहीं बनाया। आने वाले दिनों में चीन के साथ अमेरिका के कारोबार में कमी आने की बजाय बढ़ोतरी हो तो हैरानी नहीं होगी क्योंकि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने चीन से आयातित 352 वस्तुओं पर शुल्क से छूट फिर से बहाल कर दी है। पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन वस्तुओं पर शुल्क लगाया था, जिसे बाइडेन प्रशासन ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन चीन से आयातित असैन्य वस्तुओं पर शुल्क में और छूट देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन इस प्रयास में है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चीन किसी तरह से रूस से दूरी बनाए। चीन को रूस से दूर रखने के लिए अमेरिका उसके साथ कारोबार भी बढ़ा रहा है और उसे रियायत भी दे रहा है।

ऐसे में QUAD का यह शिखर सम्मेलन कोई निर्णायक या ठोस पहल कर पाएगा , इसकी उम्मीद कम ही है।

- अनुज अग्रवाल

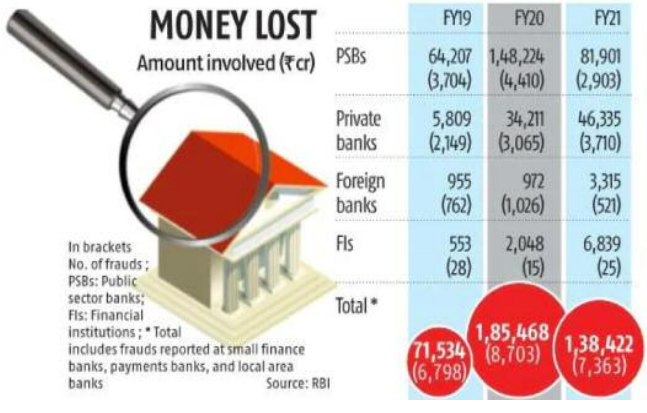

	FY19	FY20	FY21
PSBs	64,207 (3,704)	1,48,224 (4,410)	81,901 (2,903)
Private banks	5,809 (2,149)	34,211 (3,065)	46,335 (3,710)
Foreign banks	955 (762)	972 (1,026)	3,315 (521)
FIs	553 (28)	2,048 (15)	6,839 (25)
Total *	71,534 (6,798)	1,85,468 (8,703)	1,38,422 (7,363)

Summit) में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) बनाने का फैसला किया गया है। इसके जरिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा।

चीन को ताकीद

इसके अलावा समुद्र में चीन के गैरकानूनी तरीके से मछली मारने को लेकर पर नजर रखने के लिए एक सर्विलांस सिस्टम बनाने पर भी जोर दिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान वाले क्वाड समूह ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को लेकर भी बात की। इन देशों ने अगले पांच वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है।

क्वाड देशों ने चीन पर निशाना साधते हुए संयुक्त बयान

नाटो का विस्तार और भारत

'नाटो' नामक सैन्य संगठन में अब यूरोप के दो नए देश भी जुड़नेवाले हैं। ये हैं- फिनलैंड और स्वीडन। इस तरह 1949 में अमेरिका की पहल पर बने 15 देशों के इस संगठन के अब 32 सदस्य हो जाएंगे। यूरोप के लगभग सभी महत्वपूर्ण देश इस सैन्य संगठन में एक के बाद एक शामिल होते गए, क्योंकि शीतयुद्ध के जमाने में उन्हें सोवियत संघ से अपनी सुरक्षा चाहिए थी और सोवियत संघ के खत्म होने के बाद उन्हें स्वयं को संपन्न करना था। फिनलैंड, स्वीडन और स्विटजरलैंड जान-बूझकर सैनिक गुटबंदियों से अलग रहे लेकिन यूक्रेन पर हुए रूसी हमले ने इन देशों में भी बड़ा डर पैदा कर दिया है। फिनलैंड तो इसलिए भी डर गया है कि वह रूस की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। रूस के साथ उसकी सीमा 1340 किमी की है, जो नाटो देशों से दुगुनी है। फिनलैंड पर हमला करना रूस के लिए यूक्रेन से भी ज्यादा आसान है। यूक्रेन की तरह फिनलैंड भी रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को जितनी दूर है, उससे भी कम दूरी (400 किमी) पर फिनलैंड है। द्वितीय महायुद्ध के बाद फिनलैंड तटस्थ हो गया लेकिन स्वीडन तो पिछले 200 साल से किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। अब ये दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं, यह रूस के लिए बड़ा धक्का है। उधर दक्षिण कोरिया भी चौगुटे (क्वाड) में शामिल होना चाह रहा है। ये घटनाएं संकेत दे रही हैं- नई वैश्विक गुटबाजी के! रूस और चीन मिलकर अमेरिका को टक्कर देना चाहते हैं और अमेरिका उनके विरुद्ध सारी दुनिया को अपनी छतरी के नीचे लाना चाहता है। यदि फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए अर्जी डालेंगे तो भी उन्हें सदस्यता मिलने में साल भर लग सकता है, क्योंकि सभी 30 देशों की सर्वानुमति जरुरी है। नाटो के महासचिव ने इन दोनों देशों का स्वागत किया है लेकिन मास्को ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी है। रूसी प्रवक्ता ने कहा है कि नाटो का यह विस्तार रूसी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। रूस चुप नहीं बैठेगा। वह जवाबी कार्रवाई करेगा। वह फौजी, तकनीकी और आर्थिक कदम भी उठाएगा। रूस ने धमकी दी है कि वह फिनलैंड को गैस की सप्लाय बंद कर देगा। वह बाल्टिक समुद्र के तट पर परमाणु प्रक्षेपास्त्र तैनात करने की भी तैयारी करेगा। इन सब धमकियों को सुनने के बावजूद इन देशों की जनता का रुझान नाटो की तरफ बढ़ रहा है। इनकी 70-80 प्रतिशत जनता नाटो की सदस्यता के पक्ष में है, क्योंकि नाटो चार्टर की धारा 5 कहती है कि नाटो के किसी एक सदस्य पर किए गए हमले को सभी तीसों सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो रूस की हिम्मत ही नहीं होती कि वह उस पर हमला करे। यूक्रेन की फजीहत इसीलिए हो रही है कि वह नाटो का सदस्य नहीं है। ऐसा लगता है कि अब विश्व राजनीति फिर से दो गुटों में बंटनेवाली है। यह खेल जरा लंबा चलेगा। भारत को अपने कदम फूंक-फूंककर रखने होंगे। भारतीय विदेश नीति को अपना ध्यान दक्षिण और मध्य एशिया के पड़ौसी देशों पर केंद्रित करना होगा। इन देशों को गुटीय राजनीति में फिसलने से बचाना भारत का लक्ष्य होना चाहिए।

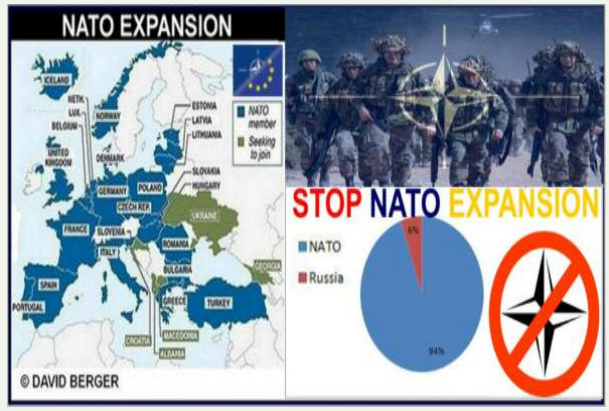

डॉ. वेदप्रताप वैदिक
(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं)

जारी कर कहा कि पूर्व और दक्षिण चाइना सी में अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानने वाले नियमों का पालन होना चाहिए। बयान में चीन को घेरते हुए कहा गया है कि इन इलाकों में किसी एकतरफा कार्रवाई, यथास्थिति बदलने की कोशिश या उकसाऊ कार्रवाई का जिससे तनाव बढ़ने की आशंका हो, उसका ये देश सख्ती से विरोध करते हैं।

चीन के खिलाफ सख्त भाषा का प्रयोग

दूसरे प्रत्यक्ष क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन के खिलाफ पिछले सम्मेलन की तुलना में सख्त भाषा का प्रयोग किया गया है। बयान में कहा गया है कि इन इलाकों में सैन्यीकरण करना। तटरक्षक बलों का बेजा इस्तेमाल और दूसरे देशों को परेशान करने के तरीके का क्वाड देश सख्त विरोध करता है।

क्वाड की बैठक ये बड़े फैसले

- आधारभूत ढांचा बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश का फैसला।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। क्वाड क्लाइमेट चेंज ऑडप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज की घोषणा।
- क्वाड फेलोशिप की घोषणा। इसमें चारों देशों के 100 छात्र STEM फील्ड में हर साल अमेरिका में अपनी ग्रेजुएट डिग्री पूरी करने जा सकते हैं।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में गैरकानूनी मछली मारने से रोकने के लिए इंडो-पैसिफिक फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस अभियान की लॉन्चिंग।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी आपदा से निपटने के लिए सहयोग करने का फैसला। ■

महंगाई से राहत
कोशिश है, पूरी नहीं

● संपादन - अनुज अग्रवाल

गेंहू,पेट्रोलियम पदार्थ, के बाद अब सरकार ने खाद्य तेल खरीद रहे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, परिणाम प्रतीक्षित हैं। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान किया है। यह सेस अभी 5 प्रतिशत है। फैसले से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद है।

ऐसे वक्त में जब वैश्विक संकट के बीच देश की जनता कमरतोड़ महंगाई से जूझ रही है, केंद्र सरकार द्वारा शुल्क घटाकर जनता को राहत देने का फैसला वक्त की मांग ही थी। पिछले आठ साल की सबसे अधिक खुदरा व नौ साल की सर्वधिक थोक मुद्रास्फीति झेल रही जनता को इससे कुछ न कुछ राहत अवश्य मिलेगी। इससे जहां मालभाड़ा कम होगा, वहीं खाद्य महंगाई में कुछ कमी की भी उम्मीद जगी है।

देश के केंद्रीय बैंक ने भी संकेत दे दिये थे कि पेट्रो उत्पादों की कीमत में कमी के बिना महज मौद्रिक उपायों से महंगाई पर काबू पाना मुश्किल होगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर में भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। उसके बाद भाजपा व एनडीए शासित राज्यों ने भी पेट्रो उत्पादों पर से वैट घटाया था। लेकिन विपक्ष शासित राज्यों ने इसका अनुकरण नहीं किया। इस बार केंद्र सरकार द्वारा की गई कटौती के बाद राजस्थान, ओडिशा व केरल ने अपने राज्यों के लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। विश्वास है कि अन्य राज्य भी महंगाई से हलकान जनता का

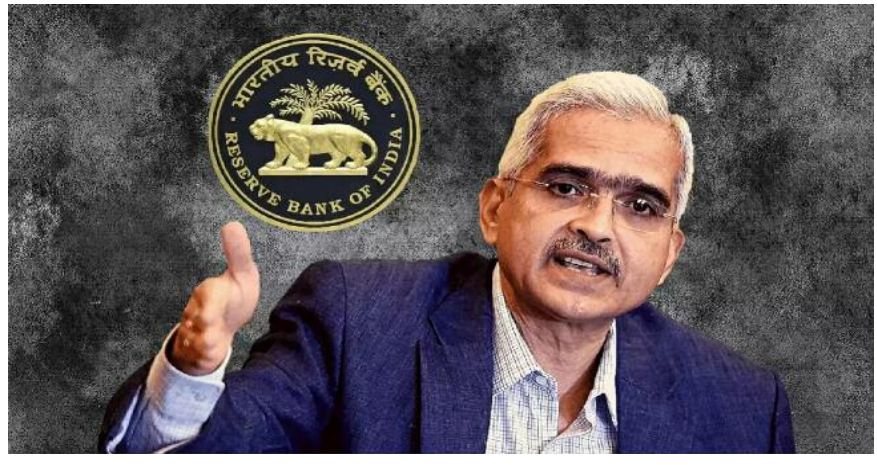

बोझ कम करने का प्रयास करेंगे। निस्संदेह, सरकारी खजाने पर सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा, लेकिन वक्त की मांग थी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से जनता को राहत दी जाये। वैसे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष व परोक्ष करों में जो वृद्धि हुई है, उससे सरकार के घाटे में कमी हो सकेगी। मौजूदा वैश्विक संकट में महंगाई का ताप कम करना हर सरकार का नैतिक दायित्व होना चाहिए क्योंकि दो साल के कोरोना संकट की वजह से देश के अस्सी करोड़ से अधिक लोगों की आय का संकुचन हुआ है। ऐसे में जख्मों पर मरहम जरूरी था।

केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमों को राहत देने का प्रयास किया है। सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों, लोहे व स्टील पर कस्टम ड्यूटी कम करने की पहल भी की है। साथ ही वायदा किया है कि निर्माण उद्योग के लिये प्रचुर मात्रा में सीमेंट की उपलब्धता कराई जायेगी। दरअसल, देश के तमाम सेक्टर उत्पाद लागत में वृद्धि व आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न होने से संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार के इस कदम से इन क्षेत्रों के उद्यमों को राहत मिलेगी। महंगाई के इस दौर में कोरोना संकट से उबरती अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतरती दिख रही है। ऐसे में आय का संकुचन होने से बाजार में मांग कम हो सकती है जिससे आखिरकार अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है।

इस संकट के मूल में जहां कोरोना दुष्काल के जख्म हैं, वहीं इस तपिश वाली आग में घी डालने का काम रूस-यूक्रेन युद्ध ने किया है। जिसके चलते पूरी दुनिया में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। जाहिर है इस संकट से सारी दुनिया जूझ रही है और कई पड़ोसी देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गये हैं, लेकिन अपना घर संभालने की जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। इन तमाम मौद्रिक उपायों के साथ ही सरकार को महंगाई कम करने के लिये कुछ और अतिरिक्त उपाय करने चाहिए। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को भी संबल देना ही होगा। ऐसे में विश्वास किया जाना चाहिए

विश्व का सबसे विषम देश भारत

नये- नये अध्ययन और अनुमान सामने आ रहे हैं, ये ही भविष्य की वैश्विक समृद्धि संरचना के आधार होंगे। आज जहां विश्व में एक तरफ 26 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भुखमरी के हालात हैं, तो वहीं विश्व को हर 33 घंटे में एक नया अरबपति मिल रहा है। यह निष्कर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संगठन ऑक्सफैम ने एक विस्तृत अध्ययन के बाद विश्व को दिया है। परिस्थिति कैसे बदले ? कौन बदले ? इस पर कोई सोच विचार चलता नहीं दिखाई दे रहा है।

वो कहावत गलत साबित हो गई कि बीमारी का वायरस कभी भेदभाव नहीं करता। कोई बीमारी जब फैलती है, तो अमीर-गरीब सबको अपना शिकार बनाती है, लेकिन जो बीमारी के वायरस का अर्ध सत्य है, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था का सच नहीं है। तमाम रिपोर्टें बताती हैं कि कोरोना दुष्काल के कारण पैदा हुए हालात ने अलग-अलग वर्ग और समाज को अलग-अलग तरह से प्रभावित किया है। इसने कुछ लोगों को नए अवसर दिए, तो कई सारे लोगों के अवसर लंबे समय के लिए छीन लिए। इस सिलसिले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संगठन ऑक्सफैम ने एक विस्तृत अध्ययन के बाद यह बताया है कि महामारी के बाद के दो साल में दुनिया में आर्थिक गैर-बराबरी काफी तेजी से बढ़ी है। इस दौर ने जहां विश्व में एक तरफ 26 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भुखमरी के हालात हैं, तो वहीं विश्व को हर 33 घंटे में एक नया अरबपति मिल रहा है। पिछले दो साल में महामारी और लॉकडाउन वगैरह से पूरी दुनिया की विकास दर काफी ज्यादा गिरी है। परंपरागत आर्थिक सोच यही कहती है कि इसका नुकसान सभी को होना चाहिए था7 अमीरों को भी और गरीबों को भी, लेकिन तमाम अध्ययन और शोध यही बताते हैं कि नुकसान का ज्यादातर हिस्सा गरीबों के पाले में ही आया है, जबकि अमीर इससे तकरीबन बच ही गए, बल्कि कुछ को तो इस हालात ने और अधिक मालामाल कर दिया।

इन हालातों में यह भी सही है कि भारत ने हालात का मुकाबला जिस तरह से किया, उसने एक बहुत बड़ी आबादी को भुखमरी का शिकार होने से बचाया। 80 करोड़ लोगों को लंबे समय तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का कोई दूसरा उदाहरण विश्व में शायद नहीं है। पिछले दिनों विश्व मुद्रा कोष तक ने इसके लिए भारत की तारीफ की थी। लेकिन, इससे आगे के जो हालात हैं, काफी उलझे हुए हैं। कुछ दिनों पहले आई 'वर्ल्ड इनिक्वैलिटी लैब' की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सबसे ज्यादा विषमता अगर कहीं है, तो वह भारत में ही है। तकरीबन यही बात अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने भी कही है। इस दौरान भारत में हर 11 दिन में एक नया व्यक्ति अरबपति बना है। 2020 में अरबपतियों की फोर्ब्स पत्रिका की सूची में 102 भारतीयों के नाम थे, पर 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई। अरबपतियों के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। गरीबों की संख्या के मामले में तो यह पहले नंबर पर है ही।

एक नजर कोरोना दुष्काल के पहले पर - जब कोरोना वायरस ने एक दुष्काल के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किया था। गरीबी तब भी थी और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आर्थिक विषमता भी बढ़ रही थी। महामारी से एक सीधा फर्क यह पड़ा कि समाज की बहुत सारी सच्चाइयां, जिनसे हम मुंह फेर लेते थे, कोरोना दुष्काल ने उन्हें हमारी आंखों के सामने ला खड़ा किया। मसलन, इस वैश्विक महामारी ने बताया कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अक्षम व अपर्याप्त हैं और संकट के समय लोगों को सीधी मदद देने में ये असमर्थ हैं। इसी तरह, महामारी ने यह भी बताया कि हमारी वे आर्थिक नीतियां कितनी अक्षम व अपर्याप्त हैं, जिनके सहारे हम गरीबी-उन्मूलन के सपने देखते हैं! जब बड़ा आर्थिक संकट आया, तब उन तमाम नीतियों के बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान गरीब वर्ग को ही उठाना पड़ा। दुर्भाग्य यह है कि विश्व अब भी अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं है। वह अब भी पुरानी लकीर पर ही चल रहा है।

कि केंद्र सरकार के हालिया कदम से लोगों की मुश्किलों में कुछ कमी आयेगी। इस संकट में भारतीय कृषि क्षेत्र हमारी ताकत बना है। सरकार ने समय रहते गेहूं के निर्यात पर रोक लगाकर घरेलू बाजार में आम आदमी की प्राथमिक जरूरत आटे की कालाबाजारी पर रोक लगाने की सार्थक पहल की है। महंगाई कम करने के लिये केंद्र व राज्यों के साझे प्रयास जरूरी हैं। संकट के दौर में कम से कम राजनीति तो नहीं होनी चाहिए।

जून में फिर हो सकती है ब्याज दरों में बढ़ोतरी

पिछले चार महीने से लगातार तय स्तर से ऊपर जा रही महंगाई दर को काबू में लाने के लिए एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक जून की शुरुआत में ब्याज दरों में इजाफा करने जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। दास ने कहा कि ब्याज दरों में इजाफा होने वाला है। यह कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। लेकिन ब्याज दरों में कितना इजाफा होगा यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों के बढ़कर 5.15 फीसदी हो जाने का आकलन बहुत सटीक नहीं है।

आरबीआई ने किया ब्याज दरों में इजाफा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अगली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 6-8 जून को होनी है। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में दो साल में पहली बार ब्याज दरों में बदलाव किया है और लगभग चार साल में पहली बार अपनी ऑफ साइकिल बैठक में आकर रेपो रेट में 0.40 फीसदी की बढ़त कर इसे 4.40 फीसदी कर दिया।

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर

मंदी की चपेट में लगभग आ चुका है अमेरिका

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सॉक्स के बाद अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी अपने देश के मंदी में घिरे होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कुछ गलत कदम की वजह से महंगाई बढ़ी और अब मंदी को दावत दे रही है।

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला व स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने भी अमेरिका के मंदी में घिरे होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगभग मंदी की चपेट में आ चुका है।

मियामी बीच में चल रहे समिट में मस्क ने कहा, 'अर्थशास्त्रियों और आंकड़ों की गणित पर न जाएं। अमेरिका करीब-करीब मंदी से घिर चुका है। कंपनियों को अभी अपनी लागत और कैश फ्लो पर ध्यान देना चाहिए। यह मुश्किल समय भी जल्द बीत जाएगा और दोबारा इकॉनमी में बूम दिखेगा।' उन्होंने कहा कि मुझे यह तो नहीं पता कि ये कब तक चलेगा लेकिन फिलहाल संभावित मंदी का यह दौर अगले एक साल या 18 महीने तक चलने की आशंका है। गौरतलब है कि इससे पहले गोल्डमैन सॉक्स ने अमेरिका में मंदी आने का जोखिम बताया था।

इसलिए उठने लगी मंदी की बात

अमेरिका में मंदी की आशंका हाल मे फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बाद जतायी जाने लगी है। फेड रिजर्व ने मई की शुरुआत में ब्याज दरों को 0.50 फीसदी बढ़ा दिया था, जो 22 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। दरअसल, उसकी मंशा अमेरिका में 40 साल के शीर्ष पर पहुंच चुकी खुदरा महंगाई की दर नीचे लाना है। इस साल की पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर शून्य से 1.4 फीसदी नीचे रही है। इस पर उपभोक्ता खर्च घटने, बिजनेस के लिए निवेश में कमी आने का असर दिखा है। हालांकि, दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 1.8 फीसदी रहने का अनुमान है।

मंदी को बुरा नहीं मानते मस्क

एलन मस्क ने कहा कि मंदी हमेशा एक बुरी चीज नहीं होती है। अगर आप लंबे समय तक बाजार और इकॉनमी में बूम देखते हैं तो अपनी पूंजी बिना सोचे-समझे निवेश करने लगेंगे। इससे तो ये होगा कि बाजार मूल्यों पर भी धन की बारिश करने लगेगा। ऐसे में आई मंदी हमें दोबारा सोच-समझकर निवेश करने और बाजार को ज्यादा गहराई से समझने का मौका देती है।

महंगाई बढ़ने का ये है कारण

अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की तरह मस्क ने भी बेतहाशा महंगाई बढ़ने का कारण सरकार की ओर से असीमित संख्या में नोट छापने को बताया। दुनिया के नंबर एक और नंबर दो अरबपतियों ने अमेरिकी सरकार को दोष देते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में नोटों की छपाई करने से महंगाई को काबू करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने वेनेजुएला का उदाहरण है, जिसने इसी नक्शे कदम पर चलकर खुद को बर्बाद कर लिया। आप जानते ही होंगे कि यह कितना उलझाऊ है। मस्क ने ई-कार सहित कई नीतियों को लेकर अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की है।

आर्थिक कंगाली की कगार पर दुनिया, संकट के पीछे ये कारण जिम्मेदार

दुनिया भर में एक बार फिर से आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे से अर्थशास्त्रियों की नींदें तो उड़ी ही हैं, साथ ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क को भी कंगाली का डर सता रहा है। मस्क समेत कई लोगों का मानना है दुनिया खासकर अमेरिका जैसे विकसित देश इस समय मंदी की कगार पर खड़े हैं। कई ऐसे फैक्टर हैं, जिनसे लग रहा है कि एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था का आर्थिक मंदी की चपेट में आना लगभग तय है। कोरोना महामारी- पूरी दुनिया 2019 से कोरोना महामारी की मार झेल रही है, इस महामारी ने दुनिया भर में स्वास्थ्य संकट से ज्यादा आर्थिक संकट ला दिया है।

Recession 2022 दुनिया भर में एक बार फिर से आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे से अर्थशास्त्रियों की नींदें तो उड़ी ही हैं, साथ ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क को भी कंगाली का डर सता रहा है। मस्क समेत कई लोगों का मानना है दुनिया खासकर अमेरिका जैसे विकसित देश इस समय मंदी की कगार पर खड़े हैं। कई ऐसे फैक्टर हैं, जिनसे लग रहा है कि एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था का आर्थिक मंदी की चपेट में आना लगभग तय है।

कोरोना महामारी

पूरी दुनिया 2019 से कोरोना महामारी की मार झेल रही है, इस महामारी ने दुनिया भर में स्वास्थ्य संकट से ज्यादा आर्थिक संकट ला दिया है। अब फिर से चीन महामारी की नई लहर से जूझ रहा है। शंघाई जैसे इंडस्ट्रियल हब इस समय सख्त लॉकडाउन में हैं। इसके कारण कई कंपनियों के प्लांट फिर एक बार बंद हो गए हैं।

रूस-यूक्रेन जंग

रूस और यूक्रेन फरवरी के अंतिम सप्ताह से जंग

में उलझे हुए हैं। लंबी तनातनी और सैन्य तनाव के बाद रूस ने फरवरी के अंतिम दिनों में यूक्रेन पर हमला कर दिया। पहले माना जा रहा था कि रूस कर यूक्रेन की ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और रूस को कुछ ही सप्ताह में जीत मिल जाएगी। हालांकि सारे अनुमान गलत साबित हुए और महीनों बीत जाने के बाद भी दोनों देशों का युद्ध जारी है। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में कई आवश्यक चीजों की कमी का संकट खड़ा हो गया। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश गेहूं और जौ जैसे कई अनाजों के बड़े निर्यातकों में से है। युद्ध के चलते निर्यात भी प्रभावित हुआ है, कई देश तो ऐसे हैं को इस समय फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं।

दशकों की सबसे ज्यादा महंगाई

बहुत सालों से महंगाई खबरें सुर्खियों में नहीं थी, लेकिन अब फिर से पुराना दौर लौट रहा है। भारत की ही बात करें तो बीते महीने थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उच्चतम लेवल पर रही। अप्रैल में सालों बाद थोक महंगाई 15 फीसदी के पार निकली और नवंबर 1998 के बाद सबसे ज्यादा रही। वहीं, खुदरा महंगाई की बात करें तो खुदरा महंगाई पहले ही मई 2014 के बाद के सबसे उच्च स्तर पर है।

महंगा होता कर्ज

महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ने इसी महीने आपातकालीन बैठक की और रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ा दिया। भारत में ब्याज दरें दो साल से स्थिर थीं और 4 साल में पहली बार इसे बढ़ाया गया है, जानकारों की मानें तो इस कदम से महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी।

क्रूड ऑयल में उबाल

पिछले कुछ महीने से कच्चे देल के दामों में आग लगी हुई है, यह लगातार 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड 01 फीसदी उछलकर 113.08 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। दरअसल क्रूड ऑयल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रूस के ऊपर अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसी में रूसी तेल व गैस पर प्रतिबंध भी शामिल है।'

अप्रैल में आरबीआई ने रूस-यूक्रेन के जारी युद्ध के कारण पनपे जियोपॉलिटिकल टेंशन का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.5 प्रतिशत के पहले के अनुमान से बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत कर दिया और 2022-23 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमान को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया।

सरकार ने उठाए कई सारे कदम

दास ने आगे कहा कि RBI और सरकार ने मुद्रास्फीति (Inflation Rate) को कम करने के लिए समन्वित कार्रवाई के दूसरे चरण में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई (RBI) ने पिछले 2-3 महीनों में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, उन्होंने कहा कि दूसरी ओर सरकार ने गेहूं निर्यात प्रतिबंध और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती सहित उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी का मूल्य वृद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हुआ। डीजल भी 7 रुपए सस्ता हुआ।

PM उज्जवला योजना वाले सिलेंडर पर इस साल 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एक परिवार को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। इसका फायदा 9 करोड़ परिवारों को मिलेगा।

प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के कच्चे माल पर भी एक्साइज ड्यूटी कम की जा रही है। जहां आयात पर हमारी निर्भरता अधिक है।

कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के कच्चे माल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी। वहीं, कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ली जाएगी।

सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। बेहतर लॉजिस्टिक्स से सीमेंट के दाम भी कम किए जाएंगे।

चिंता का सबब बनता गिरता हुआ रुपया

- सत्यवान 'सौरभ'

रुपये के मूल्यह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कम मूल्यवान हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.44 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। सख्त वैश्विक मौद्रिक नीति, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और जोखिम से बचने, और उच्च चालू खाता घाटे से भारतीय रुपये के लिए गिरावट चिंता का विषय है।

भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के पीछे विभिन्न कारक देखे तो वैश्विक इक्विटी बाजारों में एक बिकवाली जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व (केंद्रीय बैंक) द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, यूरोप में युद्ध और चीन में कोविड-19 के कारण विकास की चिंताओं से शुरू हुई थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ, वैश्विक बाजारों में बिकवाली हुई है क्योंकि निवेशक डॉलर की ओर बढ़ गए हैं। डॉलर का बहिर्वाह उच्च कच्चे तेल की कीमतों का परिणाम है और इक्विटी बाजारों में सुधार भी डॉलर के प्रतिकूल प्रवाह का कारण बन रहा है।

भारत में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कोटक के आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लगभग 5.8 बिलियन डॉलर की निकासी की है, जिससे मुद्रा पर दबाव बढ़ गया है। बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा

करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से भी मूल्यह्रास हुआ है। बढ़ते व्यापार घाटे के कारण भी दबाव है - अप्रैल में घाटा मार्च में 18.7 अरब डॉलर से बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया। दरअसल, विश्लेषकों के मुताबिक, चालू खाता घाटा 2013 के संकट के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर रहने की संभावना है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति की आशंका, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कमजोर घरेलू इक्विटी से निवेशकों की धारणा प्रभावित होने के कारण सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.43 के ताजा निचले स्तर पर आ गया। वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने, डॉलर की मजबूती ने जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों की मांग को प्रभावित किया, जिससे स्थानीय इकाई कम हुई। ग्रीनबैक के मुकाबले रुपया 0.7 प्रतिशत गिरकर 77.43 पर आ गया, जो इस साल मार्च में 76.98 के पिछले सर्वकालिक निचले स्तर को छू गया था। विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय संपत्तियों की लगातार बिक्री को लेकर चिंता का भी मुद्रा पर असर पड़ा। फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रुपये पर दृष्टिकोण खराब हो गया है क्योंकि संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।

रुपये में गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा; चालू खाता घाटा बढ़ने, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और रुपये को कमजोर करने के लिए बाध्य है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अन्य महत्वपूर्ण आयातों के साथ, अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से लागत-मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रही है। कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन जिसे मजदूरी-पुश इन्फ्लेशन के रूप में भी जाना जाता है; तब होता है जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतों में वृद्धि (मुद्रास्फीति) होती है। कंपनियों को उच्च लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर पूरी तरह से डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो बदले में, सरकारी लाभांश आय को प्रभावित करती है, बजटीय राजकोषीय घाटे के बारे में सवाल उठाती है।

मजबूत अमेरिकी मुद्रा के साथ-साथ निराशावादी वैश्विक बाजार की भावना रुपये के मूल्यह्रास का कारण बन रही है। बाजार की धारणा भी आहत हुई है क्योंकि निवेशक बढ़ती मुद्रास्फीति, दुनिया के प्रमुख देशों में मौद्रिक नीति के सख्त होने, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से चिंतित हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक व्यापार बिल के रूप में देश अपनी तेल जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात करता है, ने निवेशकों को हिला दिया है। बाजार सहभागियों को डर है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारत के व्यापार और चालू खाते को नुकसान होगा।

रुपये में गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए दोधारी तलवार है। कमजोर रुपये को सैद्धांतिक रूप से भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में, रुपये के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में तब्दील नहीं हो सकती है। मुद्रास्फीति आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा करता है, और केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है। भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकताओं का दो-तिहाई से अधिक आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत खाद्य तेलों के शीर्ष आयातकों में से एक है। एक कमजोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और बढ़ाएगी और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी।

मूल्यह्रास का मुकाबला करने के लिए गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने से डॉलर की मांग कम होगी और निर्यात को बढ़ावा देने से देश में डॉलर के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी, इस प्रकार रुपये के मूल्यह्रास को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मसाला बॉन्ड सीधे भारतीय मुद्रा से जुड़ा होता है। यदि भारतीय उधारकर्ता अधिक रुपये के मसाला बांड जारी करते हैं, तो इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी या बाजार में कुछ मुद्राओं के मुकाबले रुपये के स्टॉक में वृद्धि होगी और इससे रुपये का समर्थन करने में मदद मिलेगी।

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) विदेशी मुद्रा में एक प्रकार का ऋण है, जो अनिवासी उधारदाताओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, ईसीबी की शर्तों को आसान बनाने से विदेशी मुद्राओं में अधिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे रुपये की सराहना होगी। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की स्लाइड को नरम करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है - इसके विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से पता चलता है कि यह गंभीर मामला है। यह मुद्रा की अस्थिरता को कम करता है।

यह देखते हुए कि रुपये का मूल्य अधिक है, केंद्रीय बैंक को मुद्रा को फिसलने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे वह अपने स्तर का पता लगा सके, केवल अतिरिक्त अस्थिरता को कम करने के लिए हस्तक्षेप कर सके। मुद्रा मूल्यह्रास एक स्वचालित स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करेगा। यह आयात पर अंकुश लगाकर चालू खाते के दबाव को कम करने में मदद करेगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा समय में देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण चालक के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ■

मौलिक भारत विचार श्रृंख्ला-10

अजय सिंह 'एकल'

मजबूत बुनियादी ढांचा उन्नति की राह बनाता

● अजय सिंह 'एकल'

देश के सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नीतीश गडकरी जी कहते है की अमरीका के राजमार्ग इसलिए नहीं अच्छे है की वह एक उन्नत देश है बल्कि राजमार्ग अच्छे है इसलिए अमरीका एक उन्नत देश है। यह मंत्र एनडीए सरकार के प्रथम मुखिया अटल बिहारी बाजपेई ने समझा और देश में उन्नत राजमार्गों की श्रंखला बनने की शुरुवात हुई। सबसे पहले देश के चार प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए चतुर्भुज स्वर्णिम सड़क योजना शुरू की गई जिसमे दिल्ली, मुंबई कोलकाता और चेन्नई राष्ट्रीय राज मार्ग बना कर जोड़ा गया। हालांकि कतिपय कारणों से काम में देरी हुई है परंतु देश में 2021-22 में 37 कि.मी. प्रति दिन राजमार्ग का निर्माण हुआ है। इस वर्ष 50 कि.मी. प्रति दिन के लक्ष्य पर काम हो रहा है। इसी तरह के नव निर्माण अन्य क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश में तीन नए एयर पोर्ट, डिफेन्स कोरिडोर, फ्रैट कॉरिडर इत्यादि का निर्माण चल रहा है। रेलवे में तेजी से होता हुआ आधुनिकीकरण बुनियादी ढ़ाचे को मजबूती दे रहा है। करीब 25 शहरों में मेट्रो या तो चलाई जा चुकी है या चलाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। अगले पांच वर्षों में कम से कम 25 और शहरों मेट्रो शुरू करने की योजना है। स्वास्थ्य से संबंधित अस्पतालों का बड़ा संजाल देश में बनाया जा रहा है। साथ ही मेडिकल कालेजों का भी बड़ा नेटवर्क चिकित्सा की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दृष्टि से

बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पूरे देश में इस समय 19 एम्स कार्य कर रहे है इसमें से 11 एम्स 2014 के बाद बने है। अभी 3 नए एम्स और बन रहे है। इतना ही नहीं हर प्रदेश में नए मेडिकल कालेजों का निर्माण किया जा रहा है। इस क्रम में भारत माला, सागर माला योजना, उड़ान योजना जैसी अनेक योजनाएं सरकार ने शुरू की है। इस तरह भारत में मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने की शुरुवातमोदी सरकार पार्ट 1.0 में हो गई थी परंतु मोदी सरकार पार्ट 2.0 में इसमे तेजी आई है। अमृतकाल वर्ष 2022 में घोषित वित्तीय बजट में अगले 25 वर्षों की योजना का खाका तैयार करके देश के सामने मजबूत बुनियादीढांचा बनाए जाने की रूप रेखा को देश के सामने पेश कर दिया है ।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है पी एम गतिशक्ति योजना का शुभारंभ। इस योजना के अंतर्गत एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत एक डिजिटल प्लेटफार्म बनाया गया है इसकी सहायता से 16 मंत्रालयों और विभागों के कामों का समन्वय किया जा रहा है। इसमे यातायात के विभिन्न साधन सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल, हवाई परिवहन, समुद्री परिवहन के बीच मल्टीमोडल परिवहन व्यस्था लागू करना संभव हो सकेगा। मान लीजिए दिल्ली से किसी वस्तु को यूरोप या अमरीका समुद्री मार्ग से भेजा जा रहा है। इसके लिए सामान पहले सड़क मार्ग से नजदीकी रेलवे फ्रैट कारीडोर के स्टेशन को भेजा जाएगा वहां से बिना समय गवाएं और अतिरिक्त मेहनत के इसे रेल वैगन मुंबई ले जाने के लिए तैयार रहेंगे और ट्रेन के पहुचने के समय पर ही शिप तैयार मिलेगा ताकि इंतजार में समय खराब होने से बचे। यह

सुविधा होने से समय, ईंधन और लागत में बचत करके भारतीय समानदुनिया के बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा से टक्कर ले सकेगा। पिछले दो दशको में दुनिया के दो छोटे देश सिंगापुर और दुबई ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बना कर और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू कर के व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए है । इस व्यवस्था के शुरू होने से दोनों देशों की अर्थ व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। देखते ही देखते दोनों देश दुनिया भर के लोगों के लिए पसंदीदा व्यापार का केंद्र बन गए है। भारत को अग्रणी देश बनने के लिए भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है इसकी शुरुवात मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पी. एम. गति शक्ति योजना की घोषणा करके कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर का काम करेगा।

इस योजना के अंतर्गत देशभर मे टेक्सटाइल, डिफेन्स , फार्मा कृषि, मत्स्य पालन, इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों का जाल बिछाने और वहां से उत्पादन को देश में या विदेशों में भेजने के लिए मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध करवाने से देश के विदेश व्यापार, आयात और निर्यात क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। उत्पाद की लागत कम होने सेभारतीय सामानों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। देश और विदेश के बाजारों से ज्यादा मांग निकलेगी और देश में अधिक उत्पादन की आवश्यकता पड़ेगी। उत्पादन बढ़ने से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा और रोजगार के भी अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। वास्तव में इस परिवर्तन का कैस्कैडिंग प्रभाव होगा और यह अर्थव्यवस्था के कई आयामो को प्रभावित कर सकारात्मक परिणाम लाने में सहयोग करेगी। इसरो की मदद से समान को ट्रैक और ट्रैस करने की टेकनालजी का इस्तेमाल कर सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और समयबद्ध से पूरी करने में भी मदद मिलेगी।

पी.एम. गतिशक्ति योजना के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारण का कार्य हो गया । प्रमुख लक्ष्यों के अवलोकन से देश में अगले कुछ वर्षों में किस तरह का परिवर्तन बुनियादी ढांचे में दिखाई पड़ने वाला है इसकी एक झलक मिल जाएगी।

- दूर संचार के क्षेत्र में 35,00,000 कि. मी. का आप्टिकल केबिल 2024-25 तक डालना तथा देश की सभी 2,50,000 गावों की पंचायतों को 4जी नेटवर्क से जोड़ना।
- अक्षय ऊर्जा की क्षमता 87.7 गीगा वाट से बढ़ा कर 2024-25 तक 225 गीगावाट करना ताकि ऊर्जा जरूरत का 50 प्रतिशत तक मांग अक्षय ऊर्जा द्वारा पूरी की जा सके।
- विद्युत प्रेषण की क्षमता को 4,25,500 सर्किट कि.मी. से बढ़ा कर 2024-25 तक 4,54,200 सर्किट कि.मी. किया जाना साथ ही विद्युत प्रेषण तकनीक को बेहतर बना कर प्रेषण हानि को कम से कम किया जाना है ।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में 17000 कि.मी लाइन को 2024-25 तक 34,500 कि.मी. किया जाएगा ताकि सभी प्रदेश सीधे पाइप लाइन से जुड़ सके और इसको एक जगह से दूसरी जगह सड़क या रेल परिवहन से भेजने की जरूरत न पड़े यह श्रम, समय और धन तीनों को बचाने में सहायक होगा।
- समुद्री परिवहन और जहाज रानी क्षेत्र में सागरमाला योजना के अंतर्गत 1280 MMTPAभार धोने की क्षमता का विस्तार करके 2024-25 तक 1759 MMTPA करना। सभी जलमार्गों पर समान ढोने की क्षमता को 74 MMTPA से 2024 -25 तक 95 MMTPA किया जाएगा ।
- उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की मौजूदा क्षमता को मिलाकर कुल 109 एयरपोर्ट, 51 एयर स्ट्रिप, 18 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तथा 12 वाटर ऐरोड्रोम 2024-25 तक बनाए जाने की योजना है ।
- भारत माला योजना के अंतर्गत 2024-25 तक सड़क परिवहन के क्षेत्र में 200000 कि.मी. सड़को का निर्माण किया जाएगा। साथ ही समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में 5590 कि.मी की छः लेन वाली सड़कों का निर्माण भी 2024-25 तक किया जाएगा ।
- सन 2024-25 तक यात्री रेलों के ट्रैक को 50 प्रतिशत तक माल वाहन से मुक्ति मिलने वाली है। इसके लिए डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर की वर्तमान क्षमता को 1210 मिलियन टन से बढ़ा कर 1600 मिलियन टन किया जाएगा। इससे माल धोने की क्षमता भी बढ़ेगी और समय तथा धन की बचत भी होगी । साथ ही ज्यादा यात्री ट्रेन चलाई जा सकेंगी ।

उपरोक्त लक्ष्य बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए बनाए गए है। यही एक तरीका है जिससे भारत में विदेशी कंपनियां आकर अपनी उत्पाद ईकाइयों को चीन से स्थानांतरित करेंगी। यह विदेशी निवेश को लाने में मदद करेंगी तथा देश में रोजगार की समस्या का सार्थक हल दे पायेंगी। लेकिन सरकार यही नहीं रुक रही है देश में उद्योगों का जाल बिछा कर जीडीपी को बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निम्न योजनाओं को भी पूरा करने के लिए काम कर रही है।

- चार फेज में 11 इंडस्ट्रियल कारीडोर 2024-25 तक निर्माण किए जाएंगे
- कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 तक 90 क्लस्टर और मेगा पार्क निर्माण किए जाएंगे।
- 109 फार्मा और मेडिकल संयंत्र 2024-25 क्लस्टर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है
- इलेक्ट्रानिक समान को बनाने के लिए 38

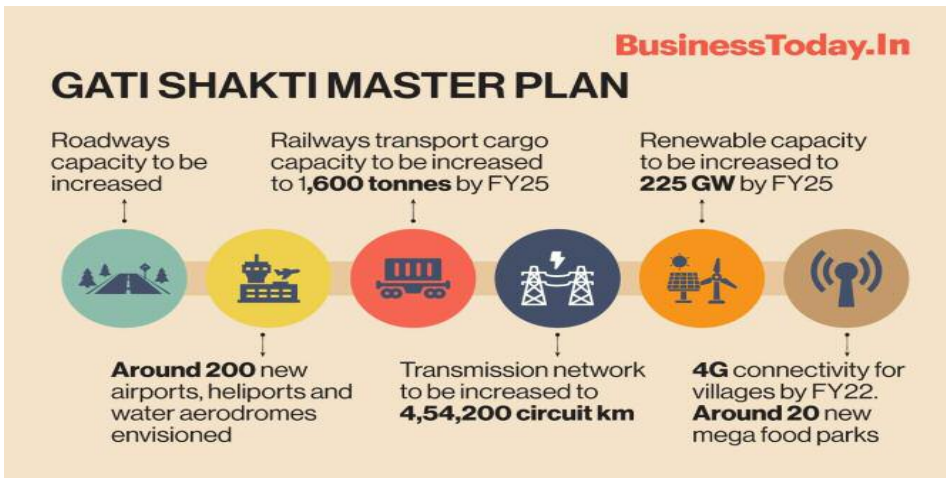

क्लस्टर 2024-25 तक बनाए जाने का प्रस्ताव है ।

- लगभग दस हजार करोड़ रुपयों के इनवेस्टमेंट से दो रक्षा कारीडोर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन कारीडोरों के निर्माण के बाद भारत में रु.170000 करोड़ के रक्षा उत्पाद तैयार किए जाएंगे जिसमे रु. 35000 करोड़ के रक्षा उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 2024-25 तक है ।
- खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग के लिए 197 मेगा पार्क 2024-25 तक बना कर फूड प्रोसेसिंग और प्रेजर्वेशन की उत्पादन क्षमता को 222 लाख टन से 847 लाख टन पहुचाने का लक्ष्य है ।
- मत्स्य पालन के क्षेत्र में वर्तमान क्षमता में 70 लाख टन की वृद्धि कर निर्यात को दो गुना 2024-25 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधान मंत्री की गतिशक्ति योजना के छः प्रमुख अंग निर्धारित किए गए है

व्यापकता- इसके अंतर्गत सभी चालू योजनाओं और भविष्य की योजनाओं का समन्वय सभी विभागों एवं मंत्रालयों के लिए एक पोर्टल बना कर किया जाएगा। ताकि विभागों एवं मंत्रालयों के बीच में समन्वय बना रहे और योजना उसकी और प्रगति की जानकारी बिना किसी देरी के सभी विभागों को हो सके और उससे संबंधित सहयोग एक से दूसरे को समय पर मिल सके।

प्राथमिकता - सभी विभागों और मंत्रालयों के कार्यक्रमों की जानकारी समय से उपलब्ध होने से विभाग अपने कार्यों की प्राथमिकता तय कर पाएंगे और काम निर्धारित समय से पूरा हो सकेगा।

समन्वय - सभी विभागों के बीच में आपसी ताल मेल प्रकल्प को समय से पूरा करने के लिए आवश्यक है। अत: किसी भी प्रकल्प में एक से ज्यादा विभागों के भागीदार होने की वजह से यदि किसी एक के काम में देरी हो तो दूसरे के काम में भी देरी हो जाती है। अत: प्रकल्प के प्रगति की समय से जानकारी के लिए उचित समन्वय बना कर रखने से सभी विभागों का काम समय से पूरा हो सकेगा और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।

विश्लेषणात्मक : तकनीक की सहायता से प्रकल्प के बारे में 360 जानकारी जीआईएस

और उपग्रह से प्राप्त सूचना तथा अन्य तकनीकों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर उपलब्ध डाटा की सहायता से तैयार किया जाएगा। इससे सूचनाओं में गलती की संभावना कम से कम होगी और कार्य सुचारु रूप से प्रगति कर सकेगा ।

गतिशीलता - सभी सूचनाओं में गतिशीलता अर्थात समय से सही सूचनाएं संबंधित विभागों से प्राप्त हो और तुरंत पोर्टल पर अपडेट कर दी जाए ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

राष्ट्रीय महत्व के निर्धारित लक्ष्यों को समय से बिना किसी अड़चन के पूरा करने के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय प्रबंधन की व्यवस्था भी की है।

सचिवों का सशक्त समूह (EGO) - इस समूह का नेत्रत्व कैबिनेट सचिव करेंगे । तथा समूह में सभी संबंधित विभागों के सचिव तथा लजिसटिक प्रमुख शामिल रहेंगे।

नेटवर्क प्लानिंग ग्रूप (NPG) - इस समूह में सभी शामिल मंत्रालयों के योजना प्रमुख शामिल होंगे और श्वरुह की सहायता करेंगे।

तकनीकी सहायता समूह (TSU) - यह समूह गतिशक्ति के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी तथा काम करने के लिए विशेषज्ञ एवं कुशल कार्य करता का प्रबंधन करने का कार्य करेगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने अगले 25 वर्षों में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े लक्ष्य तय करके उन्हे अगले 2 वर्षों से 5 वर्षों में प्राप्त करने के लिए माइल स्टोन तय किए है। इन लक्ष्यों को प्राप्त कर 7-8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर संभव हो सकेगा। बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी हल भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से निकलेगा साथ ही अर्थव्यवस्था को 5 मिलियन तक पहुंचना संभव हो सकेगा।

लक्ष्य बड़े है। सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचे की पूरी क्षमता का उपयोग समय से हो सके इसके लिए सीआईआई, फिक्की तथा इनके जैसे अन्य संगठनों के माध्यम से यह जानकारी सभी रणनीतिक साझेदारों के साथ समय-समय पर साझा करना आवश्यक रहेगा। साथ ही यह भी आवश्यक है की भविष्य में लगने वाले उद्योगों में जिन स्किल के लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है उसका अनुमान लगा कर उन्हे प्रशिक्षण दिया जाए ताकि समय पर कुशल कामगारों की उपलब्धता हो सके इसलिए इसकी व्यवस्था समय रहते करना चाहिए।

केंद्र सरकार ने देश में मजबूत बुनियादी ढांचे को तैयार करने की योजना, योजना को समय से पूरा करने के लिए लक्ष्य तथा काम समय से पूरा हो, निर्धारित योजना के अनुरूप हो इस के लिए स्पष्ट रूप रेखा बना कर तथा जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निर्धारित करके योजना समय पर पूरी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए है। सरकार द्वारा उठाए गए यह कदम देश को निश्चित रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। आशा की जानी चाहिए अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू की गई योजनाएं आजादी के शताब्दी वर्ष तक देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगी और भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार हो सकेगा। ■

मोदी सरकार : आठ साल

● हर्षल ख़ैरनार

साल 2000 का समय था केशुभाई पटेल गुजरात सरकार को ठीक से चला नहीं पा रहे थे, लोगों में और पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा था।

इसी बीच जनवरी 2001 में गुजरात में अब तक का सबसे भीषण भूकंप आया और लगभग 20 हजार लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े, गुजरात घोर निराशा में डूबा हुआ था।

तब स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अनजाने, गुमनाम से आदमी को संगठन से निकालकर गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया, ये अक्टूबर 2001 की बात है।

लेकिन उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी उसने गुजरात को फिर से बनाने में दिन रात एक कर दिया। इसके बाद गोधरा कांड हुआ और उसकी परिणीति में गुजरात मे भीषण दंगे हुए, इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और जान माल का नुकसान हुआ। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। कुछ सांसदों, तथाकथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, फिल्मकारों ने बाक़ायदा अमेरिका को चिठ्ठी लिखी कि इस व्यक्ति को अमेरिका में ना आने दिया जाए।

देखते ही देखते 2002 के चुनाव आ गए और गुजरात की जनता ने इस आदमी पर भरोसा करते हुए फिर से गुजरात की बागडोर संभालने को दे दी।

इन्हीं दंगों में उसने वो कर दिखाया कि वो देश के हर तथाकथित सेकुलर पार्टी, नेता, दलाल पत्रकारों, दलाल अखबारों, न्यूज चैनलों की आंखों की किरकिरी बन गया। उसे मारने के भी कई बार प्रयास हुए और जब गुजरात पुलिस ने उन आतंकियों का एनकाउंटर किया तो आतंकियों के मरने पर रोने वाली एक पार्टी की नेता ने उसे बहुत परेशान किया, उसके एक गृहमंत्री को जेल में डाल दिया स्वयं उसे मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई दफ्तर में घंटों बिठाकर पूछताछ की, परंतु उसने कभी पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

ना उसने किसी की परवाह की, वो गुजरात को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसके काम करने का तरीका भी अजीबोगरीब था। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते समय वो पूरी जानकारी ले लेता कि ये कब तक पूरा होगा, इसकी क्या क्या विशेषता होगी।

इसके बाद वो प्रोजेक्ट पूरा होने की 'डेडलाइन' से कुछ महीनों पहले से ही रेडियो और अखबारों में विज्ञापन देना शुरू कर देता कि फलां तारीख को मैं इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करूंगा। सारा सरकारी अमला, अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार उसे समय पर पूरा करने में जुट जाते और उसमें भी क्वालिटी से कोई समझौता सहन नहीं था।

उसकी साफ सुथरी छवि गुजरातियों के मन को मोहती चली गई और वो एक के बाद एक लगातार तीन बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना।

साल 2013 में उसे पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां भी उसने परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करते हुए मई 2014 में अपनी पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलवाया और देश में लंबे समय बाद अब एक पार्टी की सरकार थी, 'बैसाखियों' के भरोसे वाली सरकार नहीं थी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार विधानसभा पहुंचा था और ऐसे ही सीधा प्रधानमंत्री बनकर संसद भवन में आया था। पहली बार संसद भवन में प्रवेश करने से पूर्व संसद की सीढ़ियों को साष्टांग दंडवत करने का वो दृश्य आजतक देश की जनता को याद है। ऐसा करने वाला वो देश का पहला प्रधानमंत्री था।

उसकी पार्टी के घोषणापत्र में दो मुख्य बिंदुओं का हमेशा उल्लेख रहता था – धारा 370 हटाना और राम मंदिर का निर्माण करना।

वर्षों से जो पार्टी सत्ता में रही उसने राम मंदिर के फैसले को हमेशा लटकाए रखा और उसकी पार्टी पर तंज कसते रही 'मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे'

लेकिन राम को काल्पनिक बताने वाली वो पार्टी नहीं जानती थी कि प्रभु श्री राम को भी सुयोग्य उत्तराधिकारी की खोज थी और वो उसी के हाथों सब कुछ करवाना चाहते थे।

काले धन पर प्रहार करने के लिए उसने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया और पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए बैंकों की लाइन में लगवा दिया। विपक्ष ने उस पर खूब तंज कसे, गालियां दीं, झूठे आरोप लगाए लेकिन वो टस से मस ना हुआ।

गुजरात की ही तरह मई 2019 में देश की जनता ने उस पर पुन: विश्वास जताया और पहले से भी ज्यादा सीटें देकर दुबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाया।

इस बार वो पूरी तैयारी से था और उसने आते से ही अगस्त 2019 के मॉनसून सत्र में धारा 370 और 35ए को हटा दिया और इसके लिये जो योजना उसने बनाई थी उसके बारे में

चुनावी जीत के मिशन में जुटी बीजेपी ने दो प्रमुख रणनीति पर काम करना किया शुरू

आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा ने जोर-शोर से काम करना शुरू कर दिया है। चुनावी जीत के मिशन में जुटी भाजपा ने देश भर में दो प्रमुख रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

एक तरफ जहां भाजपा देश भर में संगठन को और अधिक मजबूत करने को लेकर अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की निगाहें इस तरफ भी लगी हुई हैं कि कई तरह के आपसी अंतर्विरोध और बगावती सुरों से जूझ रहे विरोधी दलों को लगातार कैसे कमजोर किया जाए?

भाजपा हर मौके और हर मंच का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा कर अपने संगठन के विस्तार की मुहिम में लगी हुई है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के मौके पर भी भाजपा 30 मई से 14 जून तक 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' को लेकर विशेष अभियान चलाने जा रही है। सरकार के सभी मंत्रियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को देशभर के 75 हजार स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता योग शिविर लगाने और उसमें शामिल होने जा रहे हैं।

23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उस दिन से लेकर 6 जुलाई तक भाजपा कार्यकर्ता और नेता देश भर में बूथ स्तर तक वृक्षारोपण करते नजर आएंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भाजपा सांसद पहले से ही अपने-अपने क्षेत्रों में 75 तालाब बनाने सहित अन्य कई सामाजिक कामों में जुटे हुए हैं। भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ-साफ नजर आ रही है कि देश के सभी वर्गों के मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जाए, बार-बार किया जाए और लगातार किया जाए।

इसके साथ ही भाजपा बूथ स्तर तक लगातार पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी कार्य कर रही है। भाजपा ने सभी प्रदेशों की कार्यसमिति 10 जून तक, देश के सभी जिलों की कार्यसमिति 20 जून तक और देश के सभी मंडलों की कार्यसमिति को 30 जून तक संपन्न करने का फैसला किया है। इसके अलावा देश के सभी प्रदेशों में जुलाई तक भाजपा के 3 दिन के प्रशिक्षण वर्ग को संपन्न करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सबसे खास बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कमजोर बूथों को लेकर भी खास रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा ने देश भर में ऐसे 73 हजार कमजोर बूथों की पहचान कर, उन बूथों पर पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति के बारे में सुझाव देने के लिए अप्रैल में ही चार वरिष्ठ नेताओं की समिति का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि, इन कमजोर बूथों में से ज्यादातर बूथ दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में है। इस लिस्ट में अल्पसंख्यक समुदाय बहुल ऐसे बूथ भी हैं, जहां फिलहाल भाजपा अन्य दलों के मुकाबले कमजोर है।

अपने आपको मजबूत बनाने के साथ-साथ भाजपा का ध्यान विरोधियों को कमजोर करने पर भी है। इसलिए भाजपा की निगाहें इस तरफ भी लगी हुई हैं कि कई तरह के आपसी अंतर्विरोध और बगावती सुरों से जूझ रहे विरोधी दलों को लगातार कैसे कमजोर किया जाए? इस अभियान के तहत भाजपा खासतौर से ऐसे नेताओं पर फोकस कर रही है जो अपने-अपने इलाके में लोकप्रिय और प्रभावशाली है लेकिन किन्ही वजहों से अपनी वर्तमान पार्टी से नाराज चल रहे हैं।

असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद हाल ही में त्रिपुरा में भी कांग्रेस से आए नेता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक बार फिर से यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो योग्यता, लोकप्रियता और कार्यक्षमता का सम्मान कर उसी अनुसार पद देने में विश्वास करती है।

पंजाब में राहुल गांधी से नाराज चल रहे सुनील जाखड़ को पार्टी में शामिल कर भाजपा ने अपने इरादों को फिर से जाहिर कर दिया है। गुजरात में भी हार्दिक पटेल के भाजपा में शामिल होने की बातें कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस में नाराज चल रहे कई असंतुष्ट नेताओं पर भाजपा की नजरें बनी हुई हैं।

हालांकि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस समेत देश के कई अन्य क्षेत्रीय और परिवारवादी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसलिए वहां की व्यवस्थाओं से दुखी अच्छे नेता विकल्प की तलाश कर रहे हैं।

सारे विरोधी नेता भाजपा का दामन थाम ले या सारे विरोधी नेताओं को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कर ही लें, यह जरूरी नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव और आजम खान जैसा उदाहरण भी मौजूद है जिनके भाजपा में नहीं शामिल होने के बावजूद आपसी अंतर्विरोधों की वजह से प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा कमजोर होती जा रही है। भाजपा के लिए दोनों ही परिस्थितियां फायदेमंद है।

किसी ने सोचा तक नहीं था।

सांसदों का प्रतिनिधि मंडल बनाकर विदेश भेजने की वर्षों पुरानी एक (कु) प्रथा चली आ रही थी उसने इसी को प्रयोग किया। राज्यसभा के विपक्ष के अधिकांश सांसदों एक प्रतिनिधि मंडल उसने 'जल संग्रहण' पर जानकारी जुटाने, अध्ययन करने विदेश भेज दिया।

इसके बाद धारा 370 हटाने का बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया और विपक्ष को पूरा विश्वास था कि ये बिल यहीं औंधे मुंह गिर जाएगा, लोकसभा में जाने का काम ही नहीं रहेगा लेकिन बिल आने के बाद जब नेता विपक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सांसद नदारद थे वो तो जल संग्रहण पर अध्ययन करने विदेश गए हुए थे।

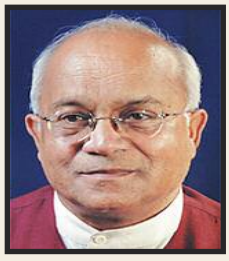

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भाजपा राहुल को दे धन्यवाद

राहुल गांधी ने लंदन जाकर भारत की राजनीति, सरकार, संघवाद, विदेश मंत्रालय आदि के बारे में जो बातें कहीं, वे नई नहीं हैं लेकिन सवाल यह है कि उन्हें विदेशों में जाकर क्या यह सब बोलना चाहिए? भारत में रहते हुए वे सरकार की निंदा करें, यह बात तो समझ में आती है, क्योंकि वे ऐसा न करें तो विपक्ष का धंधा ही बंद हो जाएगा। भारत का विपक्ष इतना टटपूंजिया हो गया है कि उसके पास निंदा के अलावा कोई धंधा ही नहीं बचा है। उसके पास न कोई विचारधारा है, न सिद्धांत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न जन-आंदोलन के कोई मुद्दे हैं। उसके पास कोई दिखावटी नेता भी नहीं हैं। जो नेता हैं, वे कालिदास और भवभूति के विदूषकों को भी मात करते हैं। उनकी बातें सुनकर लोग हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं? जैसे राहुल गांधी का यह कहना कि भारत-चीन सीमा का विवाद रूस-यूक्रेन युद्ध का रूप भी ले सकता है। ऐसा मजाकिया बयान जो दे दे, उसे कुछ खुशामदी लोग फिर से कांग्रेस-जैसी महान पार्टी का अध्यक्ष बनवा देना चाहते हैं। जो व्यक्ति भारत की तुलना यूक्रेन से कर सकता है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई-लिखाई पर कितना ध्यान दिया होगा? कोई जरुरी नहीं है कि हर नेता अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विशेषज्ञ हो लेकिन वह यदि अखबार भी ध्यान से पढ़ ले और उन्हें न पढ़ सके तो कम से कम टीवी देख लिया करे तो वह ऐसी बेसिर-पैर की बात कहने से बच सकता है। भारतीय राजनीति परिवारवाद और सत्ता के केंद्रीयकरण से ग्रस्त है, इसमें शक नहीं है लेकिन उसका विरोध करने की बजाय राहुल ने भारत को विभिन्न राज्यों का संघ बता दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? याने भारत एकात्म राष्ट्र नहीं है। ऐसा कहकर क्या अलगाववाद को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है? इसी तरह पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति की तुलना भारत से करने की तुक क्या है? भारत में कोई सरकार कभी अपनी फौज के इशारों पर नाची है? यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत के अखबारों और टीवी चैनलों पर भारत सरकार का 100 प्रतिशत कब्जा है। क्या आज भारत में आपात्काल (1975-77) जैसी स्थिति है? जो पत्रकार और अखबार मालिक खुशामदी हैं, वे अपने स्वार्थों की वजह से हैं। जो निष्पक्ष और निर्भीक हैं, उन्हें छूने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर घमंडी होने का आरोप भी लगाया जाता रहा है लेकिन यही आरोप तो आज कांग्रेस के नेतृत्व को तबाही की तरफ ले जा रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय के अफसरों पर आक्षेप करना भी उचित नहीं है। वे अत्यंत शिष्ट और उचित व्यवहार के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं। कुछ भाजपा नेताओं ने राहुल के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश भी की है। वह तो जरुरी था लेकिन उससे भी ज्यादा जरुरी यह है कि भाजपा अपने भाग्य को सराहे कि उसे राहुल-जैसा विरोधी नेता मिल गया है, जिससे उसको कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। भाजपा को अगर कभी कोई खतरा हुआ तो वह खुद से ही होगा। भाजपा को चाहिए कि वह राहुल को धन्यवाद दे और उसकी पीठ थपथपाए।

बिल राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में तो होना ही था क्योंकि वहां बहुमत था। विपक्ष के तमाम नेताओं के होश उड़ गए क्योंकि वो तो पानी पी पीकर कसमें खाते थे कि इस देश से धारा 370 कभी हट ही नहीं सकती है।

इसके बाद उसने एक बार सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राम मंदिर मामले की सुनवाई अब रोज होगी और लगभग 50 दिनों तक सुनवाई करने के पश्चात सुप्रीमकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरे देश में 'जय श्रीराम' की धूम मच गई, लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली।

सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी उसने देश का लोहा मनवाना शुरू कर दिया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को सीधा बराक कहकर बुलाया, चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया, जापान के राष्ट्रपति को गंगा आरती में बुलाया।

साल 2020 में जब पूरा विश्व को रोना महामारी की चपेट में आया तो उसने फिर से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में लॉकडाउन

भिवानी परिवार मैत्री संघ 'दिल्ली की शान' नाम से पुरस्कृत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित भारत प्रकाशन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली के लोकप्रिय अशोक होटल (चाणक्यपुरी) में एक मीडिया महामंथन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन को 8 राज्यों के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, श्री पुष्कर धामी, श्री जय राम ठाकुर, श्री भूपेन्द्र पटेल, श्री एन बीरेन सिंह, श्री प्रमोद सावंत, श्री हेमंत बीस्वा सरमा एवं श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने संबोधित किया।

इस महामंथन समारोह में अनेक गणमान्य राजनेता, साहित्यकार एवं समाजसेवी उपस्थित थे। इस समारोह में भारत प्रकाशन ने `दिल्ली की शान' नाम से पुरस्कार श्रृंखला आरंभ की, सौभाग्य का विषय है कि समाजसेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए भिवानी परिवार मैत्री संघ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने संस्था को प्रदान दिया और संस्था की तरफ से प्रधान श्री राजेश चेतन, महासचिव श्री दिनेश गुप्ता, सचिव श्री पवन मोड़ा ने स्वीकार किया। ये सम्मान भिवानी परिवार मैत्री संघ से जुड़े आप सभी बंधुओ को सादर समर्पित है।

संस्था को ये सम्मान देने के लिए भारत प्रकाशन का आभार।

लगा दिया और लगभग दो महीनों तक पूरे देश को उनकी सुरक्षा के लिये घरों में कैद कर दिया। विपक्ष इस समय भी अपनी घटिया हरकतों से नहीं चूका और गाहे बगाहे देश की जनता को भड़काने के तमाम प्रयास करता रहा।

थोड़ी राहत मिलने पर उसने छूट दी लेकिन कुछ ही महीनों बाद को रोना की दूसरी लहर घातक सिद्ध हुई और देश में हाहाकार मच गया। उसकी खूब आलोचना हुई, वो चिंतित और थोड़ा विचलित भी हुआ लेकिन संकटों से पार पाना उसे भली भांति मालूम है। विपक्ष ने इस बार भी लोगों की प्राणों की परवाह नहीं की और उसे बदनाम करने के हरसंभव प्रयास किये।

इन सबसे उबरते हुए उसने वैक्सीन बनाने पर जोर दिया और जब दुनियाभर के तमाम विकसित देश भी वैक्सीन बनाने में नाकाम हो रहे थे, विदेशी कंपनियां मुहमांगे दाम मांग रही थीं तब उसने देश में ही वैक्सीन विकसित करने पर जोर दिया स्वयं एक ही दिन में तीन लैबोरेटरी पर जाकर वैक्सीन निर्माण की जानकारी ली।

जब वैक्सीन बनकर आया तो सबसे पहले को रोना योद्धाओं को वैक्सीन लगवाया, स्वयं ने लगवाया और पूरे देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत की। विपक्ष यहां भी अपनी घिनौनी चालों से बाज नहीं आया और राज्यों ने स्वयं ही वैक्सीनेशन करने की मांग की, उसने भी पूरा अवसर दिया लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हाथपैर फूल गए।

तब उसने दुबारा कमान संभाली और दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीनेशन करके दिखला दिया।

लॉकडाउन, कर्फ्यू ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, महंगाई भी बढ़ी, बावजूद इसके उसने देश को संभाले रखा है। आलोचना करने वालों को केवल महंगाई दिखती है परंतु उसके पीछे के कारणों को वो गोल कर जाते हैं।

उसने देश की बहुत बड़ी आबादी को मुफ्त राशन देने का भी सबसे प्रभावी कार्यक्रम चलाया, आलोचना इसकी भी बहुत हुई परंतु कहीं न कहीं उसने देश में लूटमार, अपराधों की भी रोकथाम कर दी थी।

राम मंदिर का भूमिपूजन का वो दृश्य देश कभी नहीं भूल सकता जब उसने वहां भी साक्षात दंडवत किया था।

उसे भी एक सशक्त जोड़ीदार राम के ही राज्य उत्तर प्रदेश में मिला एक योगी के रूप में, दोनों की जोड़ी की तो राम को भी प्रतीक्षा थी और राम को भी अपने मंदिर निर्माण के लिये सुयोग्य उत्तराधिकारियों की आवश्यकता थी और जब वो मिले तो राम ने भी सारे मार्ग प्रशस्त कर दिये।

प्रभु श्रीराम के जैसे ही महादेव और उनके नंदी को भी प्रतीक्षा थी कि कोई योग्य उत्तराधिकारी आएं और वो ही उनके भी मंदिर पर लगे एक दाग को धोएं।

इस जोड़ी ने पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और उस दाग को बहुत हद तक छिपा दिया। यहां भी महादेव प्रकट होने को व्याकुल थे और आखिरकार वो प्रकट हुए।

इसी तरह प्रभु श्रीकृष्ण भी अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं और शीघ्र ही वहां के द्वार भी खुलेंगे।

हमारे एक वोट ने देश को, हिन्दू समाज को वो दिया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कुछ तो पुण्य हमारे भी रहे होंगे जो हम ये सब होते देख रहे हैं और कुछ अभागे आज भी उन्हें कोस रहे हैं जिन्हें खुद ईश्वर ने उत्तराधिकारी चुना है।

पत्थर, झूठे आरोप, गालियां उसका गहना है इनसे वो देश और हिंदुत्व का निखार और श्रृंगार करता है उस पर विश्वास रखिये, वो हर दर्द का पक्का इलाज करता है, अधूरे में नहीं छोड़ता है!

नरेंद्र दामोदरदास मोदी – वो आदमी जिसने क्रिकेट के दीवाने इस देश में राजनीति को क्रिकेट से भी ज़्यादा दिलचस्प बना दिया ■

नेतृत्व के सामने
लाचार, हताश हैं युवा कांग्रेसी

कांग्रेस का वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्व इस समय इतना लचर एवं लाचार है कि वह न तो युवाओं को दिशा दे पा रहा है और न ही उन्हे प्रोत्साहित कर पा रहा है। कांग्रेस के असन्तुष्ट लोगों का है कि पार्टी में कोई इंटरनल सिस्टम नहीं है और चापलूस लोग गांधी परिवार को घेरे रहते हैं। कांग्रेस में युवा और वरिष्ठों की जंग में अब तक युवा ही कांग्रेस छोडकर जा रहे हैं जबकि राहुल गांधी युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने की बात कहते हैं।

● **अमित त्यागी**

उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया और कांग्रेस के नेता ने फिर से गांधी परिवार में अपनी आस्था व्यक्त की। इधर कांग्रेस का चिंतन शिविर चलता रहा और उधर कांग्रेस की जमीन खिसकती रही। कांग्रेस ने भले ही चुनावी हार से निपटने के लिए चिंतन शिविर में खूब चिंतन किया हो, लेकिन इस महाचिंतन के बावजूद पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तीन दिवसीय चिंतन शिविर के बाद पार्टी के तीन बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। लंबे समय से पार्टी आलाकमान से नाराज पंजाब के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस चिंतन शिविर के बीच ही अपना इस्तीफा दे दिया। सुनील जाखड़ के बाद कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका गुजरात में लगा, जहां पाटीदार नेता और प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ विरोध की राजनीति करने वाली पार्टी बताया, वहीं आर्टिकल 370, राम मंदिर और सीएए-एनआरसी जैसे मुद्दों का जिक्र कर भाजपा सरकार की तारीफ भी की। कांग्रेस को तीसरा बड़ा झटका पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के तौर पर लगा है। सिब्बल ने अचानक खुलासा किया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नाराज ग्रुप जी-23 का हिस्सा थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे।

जब तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तब वह युवाओं को प्रोत्साहित करने वाले पद देने में सक्षम थी। जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर गयी तो कांग्रेस से जुड़े युवा विचारधारा की बात कहकर उससे कटने लगे। केंद्र के बाद एक एक करके राज्य भी कांग्रेस के हाथ से चले गए तो युवाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य कांग्रेस के नेतृत्व पर आ गया। कांग्रेस का वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्व इस समय इतना लचर एवं लाचार है कि वह न तो युवाओं को दिशा दे पा रहा है और न ही उन्हे प्रोत्साहित कर पा रहा है। गुजरात में कांग्रेस छोडकर बाहर आने वाले हार्दिक पटेल का कहना है कि कांग्रेस की हालत उस नए नवेले दूल्हे की तरह है जिसकी नसबंदी कर दी गयी हो। हार्दिक पटेल के इस बयान ने कांग्रेस के अंदर काम करने वाले युवाओं के विचार को आवाज दी है। पिछले दस साल में बहुत से युवा गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल हुये और उनमे कुछ नया कर गुजरने का जज़्बा भी था। लेकिन कांग्रेस ने उनका कोई उपयोग नहीं किया। वह मन मसोस कर रह गए। कन्हैया कुमार एक ऐसे ही नेता हैं। अभी राहुल गांधी ने

भाजपा चिंतन शिविर - खुद से ज़्यादा कांग्रेस की चर्चा

भाजपा के जयपुर चिंतन शिविर में भाजपा ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इस शिविर का सार यह रहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए जन अभियान चलाएगी। दो दिवसीय चिंतन शिविर में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने कहा है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है। चिंतन शिविर में गहलोत सरकार के कामकाज को जमकर कोसा गया। शिविर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन-2023, बूथ, मंडल, शक्ति और पन्ना प्रमुख इकाइयों की मजबूती पर जोर दिया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष कार्ययोजना बनाने पर चर्चा हुयी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जिक्र हुआ।

भाजपा की तरफ से कहा गया कि राजस्थान की भूमि त्याग और तपस्या की भूमि है। इस भूमि का कण-कण वीरता व शौर्य की गाथा गाता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर वन राजनीतिक पार्टी बन गई है तो अब पार्टी को स्थाई और मजबूत बनाने के लिए हम सबको जन भावनाओं के अनुसार कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे और काम भी करना पड़ेगा।

हालांकि राजस्थान की भाजपा गुटबाजी से घिरी है फिर भी भाजपा के शिविर में स्वयं से ज़्यादा गहलोत सरकार पर चर्चा हुयी। भाजपा के नेता पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश में आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और उनकी प्राथमिकता जनता की समस्या के समाधान की नहीं है। उनकी प्राथमिकता अपनी और पार्टी की समस्या का समाधान करना है। आज प्रदेश महिला उत्पीड़न मे नंबर 1 बन चुका है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सरेआम हत्या हो रही है। घटना अलवर की हो या कोटा की कानून का शासन नहीं है। प्रदेश में जंगलराज हो चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने बैठक में जमकर दलित कार्ड खेला। उन्होंने किसानों की दुर्दशा का जिक्र किया। प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसान परेशान हैं। युवा दुखी हैं। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। झालावाड़ और अलवर सहित कई जिलों के मॉब लिंचिंग के मामलों से प्रदेश शर्मसार हुआ है। अशोक गहलोत सरकार किसानों और युवाओं से वादाखिलाफी कर रही है। ढाई साल में ना किसानों का कर्जा माफ हुआ है और ना ही भर्तियां पूरी की गई हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार कोई जन कल्याण के काम नहीं कर रही है।

अपने तेलंगाना दौरे पर युवाओं को कांग्रेस से जुडने के लिए आमंत्रित किया है किन्तु यह एक विडम्बना ही है कि जबसे राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बने हैं तबसे कांग्रेस के बहुत से युवा नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह जैसे अनेकों नाम हैं। सचिन पाइलट भी घुटन महसूस कर रहे हैं। तेलांगना में राहुल गांधी ने कहा कि यदि उन्हे कोई शिकायत है तो वह पार्टी के इंटरनल सिस्टम में शिकायत करे। अब कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा भी कोई सिस्टम है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग दो सालों से गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में जी-23 का वह समूह जो मीडिया में लगातार बयान देता रहा है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुशासन समिति तब नींद से जागी जब पंजाब से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया।

कांग्रेस के असन्तुष्ट लोगों का आरोप ही यही होता है कि पार्टी में कोई इंटरनल सिस्टम नहीं है और चापलूस लोग गांधी परिवार को घेरे रहते हैं। राजीव गांधी के समय में भी ऐसे आरोप लगते रहते थे। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल पर अक्षमता के आरोप लगते रहते हैं। कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि हर

नाकारा सरकारी सिस्टम, लाखों बेरोजगारों का भविष्य अधर में

● रामस्वरूप रावतसरे

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर फिर लीक हो गया है। सरकार ने रीट परीक्षा में हुए पेपर आउट के मामले में कानून बनाया था। उसे लेकर कई प्रकार के दावे किए गये थे। लेकिन 15 मई 2022 को हुई राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में फिर पेपर आउट हो जाने पर परिक्षार्थी का ही नहीं आम आदमी का ही इन सरकारी भर्ती परीक्षाओं से विश्वास उठ गया है। हालांकि मामले में एसओजी ने फरार मुख्य आरोपी मोहन और उसकी पत्नी प्रिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 13 आरोपियों में सीआईडी सीबी का पुलिस निरीक्षक भी शामिल है। आरोपियों से एसओजी टीम पूछताछ कर रही है।

इस सम्बंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि पेपर लीक की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है। उनके अनुसार जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, उसका कारण बेरोजगारी है। उनके अनुसार यह समस्या राजस्थान की नहीं है पूरे देश की है। गहलोत के अनुसार जो क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे है, काफी हद तक उसके पीछे भी कारण होता है कि आदमी जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तो क्राइम करता है, नशा करता है, क्या क्या नहीं करता? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढेगा और पेपर लीक जैसी घटनाएं गैंग बनाकर होंगी, जो कि हो रही है। हर राज्य में होने लगी हैं। राजस्थान में कानून पास किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को रोजगार मिले। कैसे मिले यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार ने नौकरियां निकाली है उसका लाभ बेरोजगारों को लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री गहलोत ने जो ब्यान दिया है वह किस की तरफदारी कर रहा है। राजस्थान में 35 लाख के लगभग युवा बेरोजगारी की कतार में है। वही सरकार द्वारा निकाली गई इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालों घर से अलग रह कर, लाखों रूपयों का खर्चा कर दिन रात लगा हुआ है। लेकिन जब पेपर आउट हो जाता है तो, यह कहा जाता है कि यह सब बेरोजगारी के कारण हैं, हो सकता है। कुछ लोग जो सरकार और समाज विरोधी काम में लगे हुए है, जो संगठित होकर बेरोजगारों से अनाधिकृत रूप से लाखों करोड़ों रूपये लेकर पेपर आउट करते है। वे नीति और नियमों के अनुसार फार्म भरकर परीक्षा देने वालों से भी बड़े बेरोजगार है। यदि ऐसा है तो, सरकार को किसी कानून की दुहाई नहीं देनी चाहिए। और ना ही यह कहना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा। कब करेगा, जब सभी लोग अनैतिक कार्य करने लग जायेंगे। क्यों कि वे बेरोजगार जो है।

सरकार ने परीक्षा विरोधी गतिविधि को रोकने के लिए कानून बनाया है। लेकिन उस कानून को ही पैरों तले रौंद कर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जिम्मेदार लोग इतना भर कहते है कि पेपर आउट हो गया परीक्षा दुबारा होगी। यह सुन कर या पढकर उन परिक्षार्थियों और उनके परिजनों पर क्या बीतती होगी! खैर माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्यान उनकी पीड़ा को कम नहीं करता उस पीड़ा को ओर बढाता है। क्या बेराजगारी के कारण अपराध और क्राइम बढ रहे है, यदि ऐसा है तो फिर सरकार और उसके तामझाम के होने का औचित्य किसके लिए है।

सांसद डॉ0 किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक की सूत्रधार वहीं कंपनी है जिसके पास परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी है। श्री मीणा के अनुसार टीसीएस कपंनी के दागदार इतिहास के बावजूद सरकार ने इसे परीक्षा का जिम्मा सौप कर कई सवाल खडे कर दिये है। कपंनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव कोटा के रहने वाले है। सांसद मीणा ने आरोप लगाया है कि राज्य के एक कैबिनेट मंत्री का उन्हें वरद हस्त है। डॉ0 मीणा के अनुसार जयपुर के झोटवाड़ा के दिवाकर उच्च माध्यमिक विधालय में महज ढाई सौ परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता है, लेकिन यहां पर मिली भगत से 300 से अधिक परीक्षार्थियों को बैठाया गया जबकि यह परीक्षा केन्द्र कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है।

डॉ0 मीणा ने यह आरोप भी लगाया है कि कंपनी ने महज 15 हजार रूपये में परीक्षा से 15 दिन पहले संविदा पर कई कर्मचारियों को हायर कर लिया और आनन फानन में उन्हीं को ऑब्जर्वर और अन्य पदों पर लगाते हुए परीक्षा करवा दी। उनके अनुसार टीसीएस कंपनी ने ही परीक्षा से संबंधित सभी काम किये, सरकार का कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। कंपनी ने ही परीक्षा केंद्रों का चुनाव किया और परीक्षा करवाई। ऐसे में पूरी परीक्षा को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। जो सरकारी निर्णय पर भी सवाल खड़े करता है। डॉ0 मीणा के अनुसार इसी टीसीएस कंपनी ने दिल्ली कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन कराया था। इसमें कोटा के एक परीक्षा केन्द्र हरि ओम कोठारी कॉलेज सेंटर से एक साथ 226 अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। धांधली की जानकारी होने पर इनका चयन निरस्त कर दिया गया और अब सीबीआई जांच जारी है।

डॉ0 मीणा ने जो आरोप लगाए है उनकी भी सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। क्यों कि यह सारा मामला 35 लाख से भी अधिक बेरोजगारों एवं करोड़ों अभिभावको से जुड़ा है। एक अल्प आय वर्ग का पिता अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी का सपना देखता है। उसे जैसे-तैसे परीक्षा की तैयारी के लिए शहर भेजता है। कुछ साल खर्च उठाया। बेटे ने रीट परीक्षा दी, लेकिन पेपर आउट हो गया। बेटे का सपना पूरा होने से पहले पिता चल बसे। अब परिवार की जिम्मेदारी उस बेटे पर थी जो शहर में रहकर तैयारी कर रहा था। ऐसे ही एक किसान ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसे लिए। लेकिन पेपर धांधली की खबर ने

उसे अंदर तक तोड़कर कर रख दिया। उसे तैयारी के लिए और चार महीने शहर में रुकना होगा।

एक तरफ शहर में रहने का खर्च देते-देते आर्थिक रूप से टूटते परिवार की परेशानी, तो दूसरी ओर उम्र की सीमा पार न हो जाने की चिंता। ये स्टूडेंट्स आर्थिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक तौर पर भी टूट जाते हैं। ये बेरोजगारी की वो मार है जो असल में गरीब परिवारों पर अधिक पड़ रही है। रीट, एसआई से लेकर हर बड़ी भर्ती में धांधली की खबर युवाओं के सपनों को ऐसे ही तोड़ रही है। उन परिवारों को झकझोर रही है, जो एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में कर्ज लेकर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। और परिणाम में हताशा अपनों की बेरूखी प्राप्त कर रहे है। सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को इन बेरोजगारों की और उनके परिजनों की पीड़ा को समझ कर सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। अन्यथा पहले आओं, अधिक लाओं और अपनी क्षमता से अधिक पाओं के लिए सारे दरवाजे खोल देने चाहिए। कम से कम कोई गरीब का बेटा या पिता उम्मीद के भरोषे कर्ज में तो नहीं दबेगा।

राजस्थान में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक बेरोजगारी है। सीएमआईई की जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 27 फीसदी बेरोजगारी की दर रही है। खास बात यह है कि प्रदेश में स्नातक और इससे अधिक पढ़े हुए युवाओं में 54 प्रतिशत तक बेरोजगारी है। कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में बोर्ड ने करोड़ों कमाए है। परीक्षार्थियों को रोड़वेज की यात्रा फ्री कर सरकार ने भी अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन पर्चा लीक होने पर फिर भी ठगे गए 35 लाख बेरोजगार। ■

सफलता का श्रेय गांधी परिवार को दिया जाता है और हर असफलता का ठीकरा संगठन के पदाधिकारियों पर फोड़ दिया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश सहित हुये पांच राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की असफलता का ठीकरा प्रदेश अध्यक्षों पर फोड़कर उन्हे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का पांच राज्यों की हार में कोई योगदान नहीं माना गया और ये पाक साफ साबित हुये। कांग्रेस के युवा नेता इस बात से भी ज़्यादा व्यथित दिखते हैं कि प्रियंका और राहुल को वामपंथी और गैर राजनीतिक नेताओं ने घेर रखा है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड रोहण गुप्ता के खिलाफ कांग्रेस के युवा नेता उन्हे हटाने का अभियान चला रहे हैं। वह इसके लिए बड़े नेताओं को लगातार टैग भी कर रहे हैं किन्तु रोहण गुप्ता पर कोई निर्णय कांग्रेस ने नहीं लिया। पांच राज्यों के चुनाव से पहले से यह अभियान चल रहा है। भाजपा से सोशल मीडिया पर पहले से ही बहुत पीछे चल रही कांग्रेस के लिए ऐसे विषयों पर निर्णय न लेना आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। 26 साल की कम उम्र में कांग्रेस का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हार्दिक पटेल के द्वारा कांग्रेस छोडने के बाद कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन बेहद आवश्यक हो गया है। गुजरात कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ नेता हार्दिक पटेल को शुरू से पचा नहीं पा रहे थे।

ऐसा ही कुछ परिदृश्य राजस्थान में सचिन पाइलट के साथ है। राजस्थान में वसुंधरा नहीं चाहती हैं कि सचिन पाइलट भाजपा में आयें। यदि ऐसा नहीं होता तो सचिन कब के भाजपा में आ चुके होते। राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का इतिहास विफलता भरा रहा है इसलिए भाजपा और कांग्रेस ही एक दूसरे के विकल्प बनते रहे हैं। इसी वजह से भाजपा से नार्ज होने पर वॉटर कांग्रेस को विकल्प चुन लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस राजस्थान से साफ हो गयी होती। एक अन्य युवा कांग्रेस कन्हैया कुमार की बात करें तो सीपीआई से कांग्रेस में आए कन्हैया को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन में हैं। कांग्रेस अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह तेजस्वी का विरोध झेल सके। विधानसभा के उपचुनाव में कन्हैया कुमार ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी तब यह चर्चा जोरों पर थी कि उन्हे बिहार कांग्रेस में किसी पद पर बैठाकर उनका उपयोग किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वह राजद से अलग होकर चुनाव लड़ सके। लालू के विरोधी पप्पू यादव भी कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं किन्तु राजद से गठबंधन उनके आड़े आ रहा है। बिहार में लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली चल रही है।

कांग्रेस में युवा और वरिष्ठों की इस जंग में अब तक युवा ही कांग्रेस छोडकर जा रहे हैं जबकि राहुल गांधी युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने की बात कहते हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत, राजस्थान में अशोक गहलौत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, हरियाणा में दीपेन्द्र हुड्डा और आनंद शर्मा और कश्मीर में गुलाब नबी आजाद ऐसे नाम हैं जो युवाओं को पिच पर टिकने नहीं दे रहे हैं। इन लोगों की नजर में युवा या तो इनके पुत्र हैं या इनके इशारे पर काम करने वाले लोग। लगभग सभी प्रदेशों में कांग्रेस का कमोवेश यही हाल है। इंस्टेंट काफी और फास्ट फूड के दौर का युवा कांग्रेस में टिककर तभी काम करेगा जब उसे अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई देगा। चूंकि, अब न कांग्रेस के नेतृत्व के पास न तो प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व है, न ही सरकार में रहते हुये बांटने वाली रेवड़ियां, तो कांग्रेस से जुड़ा युवा हताश है, निराश है, लाचार है। कुछ कांग्रेस छोडने का निर्णय ले चुके हैं तो काफी संख्या में निर्णय के लिए तैयार बैठे हैं। ■

गृह-शांति के लिये आतंक से लड़ाई का सन्देश

● ललित गर्ग

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा उन सभी अलगाववादी नेताओं और आतंकियों के लिए कड़ा संदेश है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, हिंसा एवं आतंक फैलाने एवं राष्ट्रीय जीवन को अस्त-व्यस्त करने में लगे हैं। यासीन मलिक को यह सजा आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे जुटाने और देने के मामले में मिली है। उस पर भारतीय वायुसेना के चार जवानों की हत्या, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री (दिवंगत) मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण और कश्मीरी पंडितों की हत्या जैसे संगीन आरोपों में भी मामले चल रहे हैं। यासीन मलिक ने काफी पहले ही अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। विडम्बना देखिये कि जेल से बाहर आकर यासीन मलिक ने खुद को गांधीवादी कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गांधी के नाम पर राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने वाले तथाकथित राजनीतिक लोग उसे सचमुच गांधीवादी बताने में जुट गए। ऐसी शख्सियतें तो थोक के भाव बिखरी पड़ी हैं, जो स्वांग राष्ट्रनेता होने का करते हैं लेकिन उनकी हरकतें राष्ट्र तोड़क होती है। हर दिखते समर्पण की पीठ पर स्वार्थ चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार हर अभिव्यक्ति में कहीं न कहीं स्वार्थ है, अराष्ट्रीयता है, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने एवं राष्ट्र को आहत करने की ओछी मनोवृत्ति है।

आखिरकार एनआइए की एक अदालत ने आतंकी यासीन मलिक को आतंक से जुड़े विभिन्न मामलों में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि ऐसे गंभीर अपराधों एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में जुड़े लोगों को सजा में क्यों इतना विलम्ब होता है? मलिक को सजा देने में जरूरत से ज्यादा देरी हुई है, वह न्याय व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सवाल आतंकवाद से लड़ने में हमारी प्रतिबद्धता की कमजोरी ही बयान करते हैं। इन्हीं कमजोरियों के कारण देश में आतंकवाद पनपता रहा है। यासीन मलिक ने जैसे एनआइए अदालत के समक्ष आतंकी फंडिंग के मामले में अपने पर लगे आरोपों को स्वीकार किया, वैसे ही एक समय उसने यह माना था कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर के रूप में उसने वायु सेना के चार जवानों को मारा था और वीपी सिंह सरकार के समय गृहमंत्री रहे मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी का अपहरण भी किया था। इन संगीन अपराधों के बावजूद वह कुछ समय ही जेल में रहा। उसे राजनीतिक संरक्षण का ही परिणाम है कि उसके आतंकवादी हौसले बुलन्द रहे।

यासीन मलिक जैसी अराजक, आतंकवादी एवं राष्ट्र-विरोधी शक्तियों को राजनीतिक संरक्षण एवं समर्थन देने वाले लोग भी राष्ट्र के गुनाहगार है, ऐसे लोग जानते नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। उससे क्या नफा-नुकसान हो रहा है या हो सकता है। ऐसे लोग राजनीति में हैं, सत्ता में हैं, सम्प्रदायों में हैं, पत्रकारिता में हैं, लोकसभा में हैं, विधानसभाओं में है, गलियों और मौहल्लों में तो भरे पड़े हैं। आये दिन ऐसे लोग, विषवमन करते हैं, प्रहार करते रहते हैं, राष्ट्रीयता को आहत करते है, चरित्र-हनन् करते रहते हैं, सद्भावना और शांति को भंग करते रहते हैं। उन्हें राष्ट्रीयता, भाईचारे और एकता से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे घाव कर देते हैं जो हथियार भी नहीं करते। किसी भी टूट, गिरावट, दंगों व युद्धों तक की शुरूआत ऐसी ही बातों से होती है। आजादी के पचहतर वर्षों में जम्मू-कश्मीर या अन्य प्रांतों में अशांति, आतंक एवं हिंसा का कारण ऐसे ही लोग रहे हैं। व्यक्ति का चरित्र देश का चरित्र है। जब चरित्र ही बुराइयों की सीढ़िया चढ़ने लग जाये तो भला कौन निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी से देश का नया भविष्य गढ़ सकता है और कैसे लोकतंत्र एवं राजनीतिक मूल्यों के आदर्शों की ऊंचाइयां सुरक्षित रह

सकती है?

सिर्फ सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा ने राष्ट्र की बुनियाद को खोखला कर दिया है। न जिन्दगी सुरक्षित रही और न राष्ट्रीय मूल्यों की विरासत। हिंसा, भय, आतंक, शोषण, अन्याय, अनीति जैसे घृणित कर्मों ने साबित कर दिया कि राजनीतिक स्वार्थों के मैदान में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता से ज्यादा राष्ट्र तोड़क शक्तियां महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जब किन्ही अज्ञात कारणों से 1994 में यासीन मलिक जेल से बाहर आया तो जेल से बाहर आकर उसने खुद को गांधीवादी कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि कई प्रभावशाली राजनीतिक लोग एवं राजनीतिक दल उसे सचमुच गांधीवादी बताने में जुट गए। इनमें सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ सिविल सोसायटी के भी लोग थे और नेता भी। उसे न केवल विभिन्न मंचों पर शांति के मसीहा के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी कहा जाने लगा। यह सब काम खुद को सेक्युलर, लिबरल और मानवाधिकारवादी कहने वाले लोग यह जानते हुए भी बिना किसी शर्म-संकोच कर रहे थे कि यासीन मलिक ने कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम किया और उसके कारण कश्मीरी हिंदुओं का वहां रहना दूभर हो गया।

भारत में एक पाकिस्तान भी बसता है, जो राजनीति में, पत्रकारिता में है, धर्म-संगठनों में है, सत्ता में है, वह पाकिस्तान की जबान में ही सोचता है और वैसे ही देश की एकता एवं अखण्डता को तार-तार करने के लिये उतावला रहता है। हर तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बावजूद यासीन मलिक का जिस तरह महिमामंडन किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी उस पर मेहरबान हो गए। वे उससे मेल-मुलाकात करने लगे। उसके अतीत की अनदेखी कर उसे पासपोर्ट दे दिया गया और पता नहीं किसकी आर्थिक मदद से वह अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान की यात्रा करने लगा। इससे एक ओर जहां कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को बल मिलने लगा, वहीं आतंकवाद से लड़ने में भारत का संकल्प भी भोंथरा होने लगा। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित और पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जैसे लोग मलिक के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन उस समर्थन से क्या होगा। भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, यहां राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता को बलशाली बनाने वाली सरकार का शासन है। मलिक जैसी अराजक एवं आतंकी शक्तियां इसी सरकार के कारण अपने मनसूंबों में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। मलिक को सजा के बाद पाकिस्तान को भी यह समझना चाहिए कि वह भारत के खिलाफ जिन लोगों का इस्तेमाल करेगा, उनसे कानून के दायरे में ऐसे ही निपटा जाएगा।

कश्मीर में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और उसके नेता यासीन मलिक की अलगाववादी गतिविधियां उग्र रही है। वह पाकिस्तान के इशारे पर काम करता रहा। इसके लिए उसे वहां से पैसा व अन्य मदद मिलती रही, जो आज भी जारी है। खुद भी हिंसा के बल पर उगाही करता रहा, कुछ साल पहले कश्मीरी छात्रों को पाकिस्तान के इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर पैसा वसूलने के मामले का खुलासा भी हुआ था। इस पैसे का इस्तेमाल घाटी में आतंकी गतिविधियों, पथराव और दूसरी वारदातों को अंजाम देने के लिए और नौजवानों को आतंकी संगठनों में भर्ती करने जैसे कामों में इस्तेमाल होता रहा है। उसका खमियाजा वहां के बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ा है। पिछले साढ़े तीन दशक में हजारों लोग हिंसा का शिकार हुए। लाखों कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया। सबसे दुखद तो यह कि नौजवान पीढ़ी को आतंकी संगठनों में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया। मलिक एवं उसके अलगाववादी संगठनों को लेकर पूर्व सरकारों का उदार रुख भी समस्या का बड़ा कारण रहा। अगर अलगाववादी संगठनों पर पहले ही नकेल कसने की हिम्मत दिखाई होती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। यासीन मलिक को सजा से यह भी साफ हो गया है कि अगर पुलिस और जांच एजेंसियां ईमानदारी एवं पारदर्शिता से काम करें, पर्याप्त सबूत जुटा कर अदालत के समक्ष रखें और ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई हो तो आतंकवाद में लिप्त लोगों को सीखचों के पीछे पहुंचाने में देर नहीं लगती। वरना अक्सर यह देखा गया है कि सबूतों के अभाव में आतंकी छूट जाते हैं। यासीन मलिक को सजा पर पाकिस्तान के भीतर बौखलाहट पैदा होना भी स्वाभाविक है। ■

मोदी सरकार में भ्रष्ट बाबुओं की खैर नहीं

● आर.के. सिन्हा

किसी भी सरकार का जनमानस में सम्मान तब ही होता है, जब उसके कर्मचारी पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। देखिए सरकार को चलाने वाले नेता तो एक विजेन के साथ सत्ता पर काबिज होते हैं। फिर उनके विजेन को सरकारी बाबू अमली जमा पहनाकर जमीन पर उतारते हैं। मतलब वे ही वस्तुत: समस्त सरकारी योजनाओं- परियोजनाओं को जमीं पर लागू करते हैं। लेकिन, अगर वे ही काहिली और करप्शन के जाल में फंस जाएं तो फिर सरकार और देश का क्या होगा, यह भली भांति सोचा जा सकता है।

दुर्भाग्यवश हमारे यहां अब भी बड़ी तादाद में सरकारी बाबू कायदे से मन लगाकर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही नहीं, वे तो करप्शन करने से तनिक भी बाज नहीं आ रहे। वे चंद सिक्कों में अपना जमीर और देश को बेचने से भी पीछे नहीं हटते।

अब कुछ ताजा मामलों को ही देख लीजिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में अपने चार अफसरों को डिसमिस करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन पर चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन से एक करोड़ रुपए की उगाही करने के आरोप सिद्ध होने के बाद इन पर यह एक्शन लिया गया। सरकार की जीरो टोलरेंस पॉलिसी के तहत यह एक्शन हुआ है। अब जरा सोचिए कि सीबीआई का काम बड़े घोटाले और दूसरे आपराधिक मामलों की जांच करने का है। इससे जुड़े मुलाजिमों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने काम को सही से अंजाम देंगे। लेकिन, यहां पर सही की बात बहुत दूर है, इनके कुछ कर्मी भी करप्शन में बुरी तरह ही लिप्त हैं। वे खुलेआम घूस ले रहे हैं।

बहरहाल, ये मानना होगा कि सीबीआई ने अपने इन शातिर अफसरों को डिसमिस करके सबको एक कड़ा संदेश तो दे ही दिया। सरकार का अब कोई भी महकमा पहले की तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर नहीं चल सकता। पहले तो सरकारी बाबू अपने को सरकार का दामाद समझ कर ही दफ्तर आते थे और अपना रुआब झाड़कर वापस घर चले जाते थे। कुछ सरकारी बाबुओं ने तो अपने को वक्त के साथ बदल लिया। वे अब सही से काम भी करते हैं। लेकिन, कई अब भी बाज नहीं आ रहे। वे करप्शन के किसी भी मौके भी नहीं छोड़ते। उन पर तो चाबुक चलाने की सख्त जरूरत है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मियों की सैलरी में भी तगड़ा उछाल आया है। अब छोटे से छोटे पदों पर काम करने वाले सरकरी बाबू भी ठीक-ठाक ही पगार उठाते हैं। लेकिन, लालच का कोई इलाज नहीं है। महात्मा गांधी बहुत पहले ही कह गए हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं को तो भरसक पूरा किया जा सकता है, लेकिन लालच को नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की तो बुनियादी जरूरतें हैं ढ्ढ फिर भी देख लीजिए, जीवनशैली कैसी होती जा रही है। पृथ्वी से हमें जो कुछ मिलता है, वह हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन, उससे लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। हमलोग पर्यावरण के साथ अन्याय कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन नई-नई टेक्नोलॉजी हमें घेर रही है। लेकिन, इसके प्रतिकूल प्रभावों पर कोई चर्चा तक नहीं होती। आज घरों से गोरैया लुप्त हो गई है। पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण गंगा की अविरलता बाधित हो रही है। यही हाल रहा तो पृथ्वी को बचाना मुश्किल हो जाएगा।

अब वक्त आ गया है कि करप्सन में लिप्त सरकारी बाबुओं को किसी भी सूरत में न छोड़ा जाए। जब सीबीआई के कर्मियों पर एक्शन हुआ, लगभग तब ही झारखंड सरकार की खनन सचिव व आईएएस अफसर पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित कर दिया है। करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक का कैश पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकानों से जब्त किया गया है। पूजा सिंघल को खूंटी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि

पूरी दाल ही काली ....

मित्र ने कहा कि आप झारखंड की ड्रग अधिकारी के यहां पकड़े गए करोड़ों रुपए के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे नहीं। मैंने कहा कि इस जैसे छोटे से मुद्दे पर क्यों बोलना जरूरी है। मित्र बोले कि यह छोटा मुद्दा है, मैंने कहा कि बिलकुल छोटा मुद्दा है। मित्र को अटपटा लगा तो मैंने उनसे आगे कहा –

मैंने कहा कि मुझे झारखंड वाली IAS अधिकारी मूर्ख लगती है या किसी पर विश्वास नहीं करने वाली लगती है।

- भारत में अपवाद छोड़ कर शायद ही ऐसा कोई IAS अधिकारी हो जिसके पास सैकड़ों से हजारों करोड़ नहीं हो। लेकिन सब इतना व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, नेक्सस के द्वारा किया जाता है कि सब खप जाता है।
- बहुत IAS तो अपने आपको इमानदार प्रायोजित किए रहते हैं, कुछ IAS तो लोगों के लिए काम-वाम भी कर देते हैं ताकि महानता की छवि बन जाए जुगाड़ बन जाए तो लगे हाथ कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार झटक लिया जाए, लेकिन कई हजार करोड़ दबाए बैठे होते हैं।
- बहुत तो IAS ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उनके पास घर तक नहीं है। आपको टुटहा सा घर दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में सेटल कर रखा होता है वहां अपने बच्चों के नाम विदेशों अरबों की संपत्तियां खरीद रखी होती हैं।
- मैंने अपने मित्र से कहा कि ऐसा ही बहुत कुछ होता है। अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह एक व्यवहारिक तथ्य है कि खुद को महा-ईमानदार IAS के रूप में प्रायोजित करने वाले IAS अधिकारियों के पास भी झारखंड वाली IAS से अधिक होता है।
- जिन लोगों को भी यह लगता है कि झारखंड वाली IAS के पास पाई

गई रकम बहुत बड़ी रकम है या वह IAS बहुत भ्रष्ट है तो ऐसे लोग खुद को भले ही बहुत बड़ा विद्वान, चिंतक, सिस्टम को समझने वाला मानते हों, लेकिन बकैत के अलावा कुछ नहीं हैं जिनको भारत के सिस्टम की ढेला भर भी समझ नहीं है।

- मेरी तो झारखंड वाली IAS के साथ सहानुभूति है, जिसे इतनी छोटी सी रकम भी सेटल करना नहीं आया। क्या मालूम यह पूरी घटना ही फर्जी हो क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार नोटबंदी के बाद भारत में भ्रष्टाचार व कालाधन पूरी तरह से खत्म हो गया था।
- मैं आशा करता हूं कि जल्द ही झारखंड वाली IAS अधिकारी वाला मामला रफा-दफा हो। ताकि लोग-बाग अपने ढर्रों में लौटें, नए चटकारे का इंतजार करें, स्वाद लें, आनंद लें। जीवन का उद्देश्य ही होता है चटकारे लेना, चटकारे का इंतजार करना।

- विवेक उमराव

के गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूजा सिंघल को कोर्ट के समक्ष पेश किया था। अब जरा सोचिए कि मेरठ के सोफिया स्कूल की छात्रा रही पूजा सिंघल ने 21 साल की उम्र में आईएस की परीक्षा को क्रेक कर लिया था। यानी वह मेधावी तो थी ही । लेकिन वह रास्ते से भटक गई और उसने अपनी खुद ही इज्जत तार-तार कर ली। मोदी सरकार अब निकम्मों और भ्रष्ट अफसरों के पीछे पड़ गई है। अब तो वही सरकारी नौकरी में रहेगा जो काम करेगा। बेकार-कामचोर बाबुओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है।

इस बीच, रेलवे ने भी हाल ही में अपने 19 आला अफसरों को एक ही दिन में जबरन रिटायर कर दिया। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) दी गई है। कामकाज की समीक्षा के बाद इनमें से कई अफसरों को कार्य में अक्षम पाया गया था और उन्हें बार-बार चेतावनी भी दी जा रही थी। रेलवे इससे पहले भी 75 अफसरों को वीआरएस दे चुका है। जिन्हें वीआरएस दी गई हैं उनमें इलेक्ट्रिकल, पर्सनल, मैकेनिकल, स्टोर, सिविल इंजीनियर, सिग्नल इंजीनियर एवं ट्रैफिक सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसमें रेलवे बोर्ड के दो सचिव स्तर के अधिकारियों सहित एक जोनल रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉदर्न सेंट्रल रेलवे, नॉदर्न रेलवे सहित रेलवे उपक्रमों रेल कोच फैक्टरी कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्टरी रायबरेली, डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी और आरडीएसओ-लखनऊ आदि के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

भारतीय रेलवे में अधिकारियों को वीआरएस देने का सिलसिला जुलाई, 2021 से शुरू हो गया था। यानी काहिल अफसरों की तो अब शामत आ गई है। इन्हें अब तबीयत से कसा जा रहा है। देखिए सख्ती होने लगी तो रेलवे के कामकाज में सुधार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं हाल ही में आगरा गया था। इस दौरान नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आगरा कैंट रेलवे स्टेशनों को देखा। सबको देखकर दिल प्रसन्न हो गया। वहां पहले वाली अराजकता और अव्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। इन रेलवे स्टेशनों में रेलव कर्मियों का व्यवहार भी सहयोगपूर्ण मिला। तो क्या माना जाए कि हम सख्ती के बाद ही काम करने लगते हैं? ये सख्ती सभी भ्रष्ट तथा निकम्मे सरकारी बाबुओं पर लगातार जारी रहनी चाहिए। हां, सरकार को ईमानदार तथा मेहनती सरकारी अफसरों तथा कर्मियों को पुरस्कृत भी करते रहना चाहिए ताकि यह मैसेज जाता रहे कि सरकार अपने सच्चे अफसरों को हर तरह से सम्मानित और पुरस्कृत करती रहेगी।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

भारतीय बैंकों मे व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था

भारत बैंक घोटालो से रोज हो रहा है 100 करोड़ का नुकसान

● सुरेश चन्द्र अवस्थी, रेणुका साहू एवं अतुल राठौर

आरबीआई के आकड़े के अनुसार विगत सात सालों में देश को हर रोज बैंक घोटालो के कारण 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा बैंक घोटाले मुंबई में पाये गए है। इसके बाद दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु में जमकर घोटाले हुए है । रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक देश में लगभग 2.5 लाख करोड़ का बैंकिंग घोटाला हुआ है।

भारतीय बैंकों में अराजकता की ओर जाती हुई बैंकिंग प्रणाली। सवाल उठता है, कि क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम पर्याप्त है या बड़े संशोधन की जरूरत है? अगर इसी तरह से चलता रहा तो नामुमकिन नहीं है, कि हिंदुस्तान का बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त हो जाए।

बैंक से संबन्धित लाखों मुकदमे कोर्ट में दाखिल हो गए हैं। जिसका निपटारा मुश्किल हो गया है। छोटे बैंक तो पहले ही नहीं संभल रहे थे । अब बैंक मर्ज होने से समस्या ने और भी भयावह रूप ले लिया है। सरकारी चेतावनीया भी बेअसर हो रही है। दूसरी ओर एक जटिल समस्या ये है, कि बैंक अधिकारियो पर बैंक के लिए प्रॉफिट करने का दबाव बना हुआ है।

गवर्मेंट स्कीम भी बैंक अधिकारियों को कनफ्यूज कर रही है। और इस स्थिति का भरपूर फायदा भ्रष्टाचारी बैंक कर्मचारी उठा रहे है।

प्राइवेट फायनान्स कंपनी, एक्सिस बैंक, हाउसिंग फायनान्स कंपनी इन बैंको में भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अव्वल तो योग्यताओ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

Insurance company में इन्शुरेंस ऐजेंट को काम करने से पहले (I. R. D. A) टेस्ट पास करना होता है । कम से कम उसे दसवी कक्षा पास होना चाहिए। और वहीं हाउसिंग फायनान्स लोन कंपनी में एजेंट और लोन ऑफिसर बनने के लिए कोई विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं होती । इसके अलावा कोई विशेष परीक्षा भी पास नहीं करनी होती। इसके सबूत की बात करे तो हाउसिंग लोन कंपनी में विजिट करने पर हमने पाया, कि अनपढ़, जाहिल, कम पढ़ी लिखी लड़कीया लिपस्टिक पाउडर लगाकर लोन एजेंट का काम करती हुई मिली । उन्हें बकायदा बैंक द्वारा हर महीने पगार और मोटा इन्सेंटिव मिल रहा है।

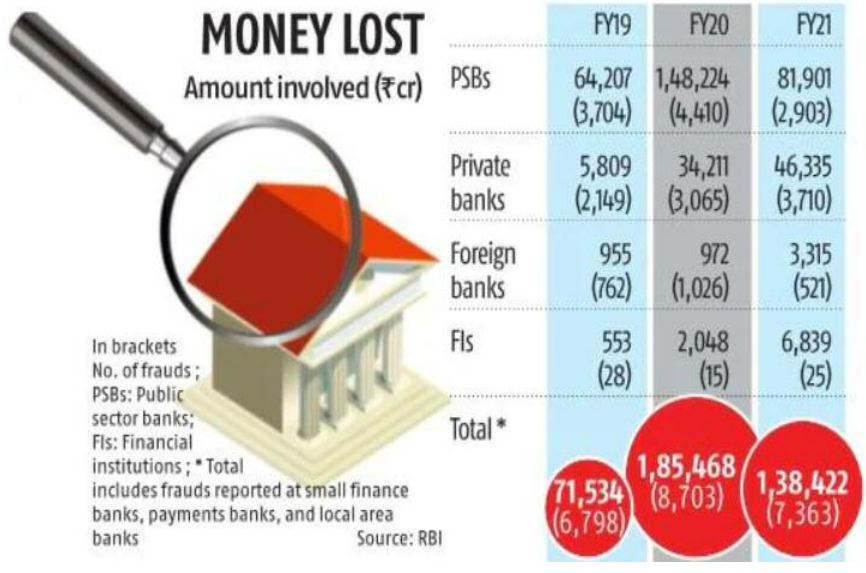

इसी प्रकार इन्हीं बैंको में डिंगडोंग करते हुए मवाली टाइप के लड़के भी दिखाई दिये । जिन्हें बैंक से पगार और इन्सेंटिव दिये जा रहे हैं । मालूम करने पर पता चला कि ये लोग भी लोन एजेंट है। इन लोगों की सिफारिश पर बैंक अधिकारी मोटे मोटे हाउसिंग लोन पास करते हुए मिले। जिसके एवज में ग्राहको से मोटी रिश्वत ली जाती है। फिर आए दिन पार्टिया की जाती है। बैंक के प्रीमाइसेस में ही या आस पास शराब पार्टिया की जाती है। इस प्रकार से ये हाउसिंग फायनान्स कंपनियो के ओफीसर्स सामाजिक अव्यवस्था का कारण बन रहे हैं। जिसकी कीमत आस पास रहने वाले लोगों को चुकानी पड़ रही है।

अगर इसी तरह से चलता रहा तो नामुमकिन नहीं कि हिंदुस्तान का बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाएगा।

इन्श्योरेन्स कंपनी में भरती के लिए नियम है। बैंक कंपनी में भारती के लिए कोई नियम नहीं है। कोई टेस्ट नहीं, कोई मिनिमम क्वालीफिकेशन का नियम नहीं है।

भारतीय बैंकों की भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पराकाष्ठा पर है।

बैंक अधिकारीगण अपने आप को जवाबदेह नहीं समझ रहे हैं। आम जनता तो आम जनता प्रेस प्रतिनिधियों को भी बैंक अधिकारी जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं।

बैंको में भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और लेबर यूनियन, एम्प्लोई यूनियन, ऑफिसर यूनियन, स्टाफ की कमी, सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक स्कीम का बोझ और बैंको का मर्जर

(Murger) बड़े बैंक बनाने के लिए। और बैंक अधिकारियों में व्याप्त असंतोष और हाल ही में हुए बड़े बड़े बैंक घोटाले, चेयर मैन जैसे बैंक शीर्ष अधिकारियों के ऊपर सीबीआई कार्यवाही और सस्पेंशन और उनके खिलाफ मुकदमें क्या इन हालातों में बैंक सुचारु रूप से चल पायेंगे? क्या हिंदुस्तान की बैंकिंग व्यवस्था खतरनाक मोड की ओर जा रही है। क्या संभव है, कि हमारी बैंकिंग व्यवसथा चरमरा जाये। और इन सब चीजों में ध्यान इसलिए जरूरी हो जाता है, कि हमारा देश उन देशों में है, जहां बचत कर पूंजी जमा कर भविष्य बनाना एक महत्त्वपूर्ण आदत है। जिसके कारण उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं और छोटे व्यापारियों को भी उधारी माल लेकर बेच कर धंधा करने का मौका प्राप्त हो रहा है। छोटे छोटे उद्योग धंधे बैंकों की मदद से व्यपारी पैसा लेते थे जिसमें इन्हें सब्सिडी भी मिलती थी। जिसके कारण ये छोटे व्यापारी भी उद्योग धंधे कर पा रहे थे। अब नए माहोल में यहां बैंकों का मर्जर कर बड़े बैंक बनाए जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी हाउजिंग कंपनिया आ रही है। बड़े बड़े बिल्डर इन हाउजिंग कंपनियों में रिश्वत खोरी करके 100 प्रतिशत लोन पर फ्लेट बेच रहे हैं। क्या इस प्रतिस्पर्धा में छोटे लोग, कर्मचारी वर्ग टिक पाएंगे । ऐसा प्रतीत होता है, कि ये सारी व्यवस्था कुछ दिनों में धराशायी हो सकती है। ये बड़े बैंक बड़े व्यपारियों को आसानी से लोन प्रदान करेगे । क्या यही बैंक छोटे छोटे व्यपारीयों के लिए भी सहयोग करेगे।

इस तरह की स्कीम जैसे आशा होम लोन कहीं भ्रष्टाचार का नया बाजार तो नहीं? बैंक में शिकायत करने में बैंक अधिकारियों का कहना है, कि हमारी शिकायत इसलिए नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम उनके बैंक के ग्राहक नहीं है। और बैंक के कोई ग्राहक की शिकायत इस विषय में नहीं है। हमारे द्वारा की गई शिकायत 28\02\2022 तारीख से लंबित है। और हमें आज तक बैंक से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

Asha Home Loan Scheme *इस स्कीम के अंर्तगत किसी भी व्यक्ति को लोन मिल सकता है। किसी प्रकार का* income *रूफ नहीं चाहिये, अब ये तसदीक कौन करेगा कि उक्त व्यक्ति लोनभरने लायक है या नहीं । यह एक जरुरी संदर्भ है।*

RTI 5129/22 **Date : 06/04/2022**

To,
The Public Information Officer
C/o. Managing Director & CEO,
Axis Bank Ltd., Axis House, C-2, Wadia International Centre,
Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai–400 025
Phone : 022-24252525, 022-43252525

Reference : 1) Letter No. Nil dated 28/02/2022
2) Letter No. Ni. dated 05/03/2022
3) Letter No. Bureau M/127/22 dated 11/03/2022

COPIES ENCLOSED

Subject : Information Sought Under RTI Act 2005.
Sir,
Kindly provide the following information –

1) Kindly provide information that the Bank / your office / address mentioned above have received the letters referred above reply in Yes or No.
2) Kindly provide copies of Nothing by your office / officials on the above motioned letters.
3) Kindly provide copies of Communications (Memos, Letters, Communications Oral / In writing) by your office /officials in reference to the above mentioned letters.
4) Kindly provide copies / xerox copies of communications received by your office / officials in reference to the letter mentioned above.
5) Kindly provide any other information in reference to the above mentioned Letters.
6) Kindly provide information that –
   a) An enquiry is pending in reference to the letters mentioned above.
   b) A preliminary Enquiry is pending in above mentioned matter reply in Yes or No.
   c) The above mentioned Letters / complaints has been filed / closed finding it without materials reply in Yes or No.
   d) Provide copies of orders in reference to information sought by me in 6 (a), 6 (b), 6 (c).

Prayed accordingly,
Regards,
Sd/-
(Sureshchandra Awasthi)
(Applicant)

Dialogue India (Magazine)
Mumbai Bureau
1104, Quantum Towers, Chincholi Bunder Road, Nadiyawala
Colony 2, Malad (West), Mumbai – 64.
Mobile : 9930138896
Email – sureshawa@gmail.com

Enclosures : 1) As mentioned above.

To,
The Incharge
Axis Bank Ltd.
Housing Finance Branch,
Unit No. 5/6/7 Gokul Arcade Viva Agashi Rd.
Gokul Township Virar (West) 401 303.

Complaint Against :-

1) Incharge, Axis Bank Ltd. House Finance Branch Virar (W) address mentioned above.
2) So called as team Incharge of team of Mr. Dharmender Yadav and Mr. Akshay at of office of Axis Bank Housing Finance Branch.
3) Mr. Dharmender Yadav Ph. 8850018712.
4) Mr. Akshay Bansode Ph. 8010564603
5) Security Guard at Gate of Office as at 4 pm on 26/02/2022 Photo of Guard attached.

My Complaint / Charges against above.

1) The accused at Sr. No. 1, is responsible for
   a) Allowing its office staff Mr. Dharmender Yadav, Mr. Akshay to accept bribe.
   b) Allowing Mr. Dharmender Yadav to make money by selling flats of Builders making commission / accepting gratification from Builders like M/s. Paramount Builder Palghar in this Case by Diverting Customers willing to buy flats from other Builders by promising sanction of higher amount of Housing Loan and other promises best known to them. Thus allowing his Employees, to misuse their official position for personal gains.
   c) Allowing its senior officials to organise protection from complaints against corrupt employee.
2) Accused at Serial No. 2, is responsible
   a) For providing protection to its corrupt Employee by threatening this applicant when the applicant tried to lodge complaint / provide information about corrupt Employees Mr. Dharmender Yadav and Mr. Akshay.
   b) For providing threat to this Applicant by asking my PAN Card Copy it if I make a Complaint or provide information about their corrupt Employees.
3) Accused No. 3, Mr. Dharmender Yadav
   a) Is responsible for accepting gratification of Rs. 10,000/- through Mr. Akshay.
   b) Is responsible for manipulating papers of Mr. Bablu (who had initially asked for a housing Loan of Rs. 10 Lakhs) to grant him a loan of Rs. 26 Lakhs (Housing Loan of Rs. 26 Lakhs)
   c) Is responsible for misuse of his official position to Lure Mr. Bablu to buy a house with a Builder named Paramount Builder or an another Builder name best known to him, with a housing Loan of Rs. 26 Lakhs. While Mr. Bablu was looking for house worth Rs. 12 Lakhs with a housing Loan of Rs. 10 Lakhs.
   d) Is responsible for organizing a threat to this Applicant through his Gunda elements or Employees of Builder who had threatened to provide physical assault to this applicant. The threat came on mobile of this Applicant's Mobile immediately after when the Applicant left office of Mr. Dharmender Yadav on 26/02/2022. Sometime after 4 pm.
4) Mr. Akshay is responsible for Conniving with Mr. Dharmender Yadav in his Crime.
5) The Accused No. 5 Security Guard is responsible for
   a) Providing protection to the above by not letting this applicant and other Complainants to lodge Complaint against corrupt employee.
   b) Man handling this applicant and trying to Snatch away mobile of this applicant when Applicant had tried to lodge Complaint or had tried to provide information of corrupt Employee to the office incharge.

Sir,

The applicant is a journalist and is working on a story to unearth / syndicate of Builders, Brokers and Employees of Bank involved is Duping Banks by

1) Sanctioning housing loans to in competent.
2) By over Valuing housing properties being mortgaged with Bank.

The present Sanction (Copy enclosed) is clear example of such effort. Kindly provide receipt of the letter for our records / publication.

Sd/-
Tejender Singh
(Applicant)
Email : tejendertejender32@gmail.com
Phone : 9970079609
A-001, Shailphush Building,
Kanchan Universe Vagulsar Palghar
Dist. Palghar 401 404.

April 26, 2022

Sureshchandra Awasthi
C/O Dialogue India (Magazine)
1104, Quantum Towers
Chincholi Bunder Road, Nadiyawala
Colony 2, Malad (West)
Mumbai – 400064

Dear Mr. Awasthi,

This is with reference to your letter (undated) seeking information on a Loan application under RTI Act.

At the onset, we take opportunity to clarify that RTI Act is not applicable for Axis Bank l.td. being a Private Bank.

We also deny the allegations made by Mr. Tejinder Singh in his letter and also like to state that we have contacted our customer and as per confirmation received by him, he has no concerns with regards to his Axis Bank loan application.

Thanking you.

AXIS BANK LTD. VIRAR (W)

Authorised Signatory

Axis Bank Ltd Loan Centre, 2nd Floor, Viva Gokul Arcade, Viva Gokul Township, Agashi Road, Virar (West) Thane-401303
REGISTERED OFFICE : "Trishul" - 3rd Floor Opp. Samartheswar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006. Telephone No. 079-26409322 Fax No. - 079-26409321
CIN: L65110GJ1993PLC020769 Website - www.axisbank.com

AXIS BANK

तब भी इन कर्मचारियों के भर्ती का तरीका आश्चर्यजनक है। उनको भर्ती करने का कोई टेस्ट नहीं होता। ना ही योग्यता का कोई मापदंड होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक लोन बांटे उसे उतनी अधिक वरीयता मिलती है।

आशा होम लोन एक्सिस बैंक द्वारा चलाई गयी एक स्कीम है जिसमें छोटे उद्योग वालों को जो कि किसी प्रकार का इंकम प्रूफ नहीं पेश कर पाते हैं। उनको अधिक ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।

इस संदर्भ में हमारे पत्रकार ने एक शिकायत ऐक्सिस बैंक हाउजिंग फाइनैन्स लिमिटेड विरार ब्रांच में की शिकायत की प्रतिलिपि नीचे संलग्न है । इस शिकायत के संदर्भ में बैंक अधिकारीयो का कहना है कि हम या पत्रकार बैंक का ग्राहक नहीं है इसलिए बैंक हमारी या हमारे पत्रकार की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं कर सकता है। बैंक अधिकारियों ने आज तारीख तक कोई जवाब हमारे पत्र के संदर्भ में नहीं दिया है। लिखित में हमें आज तारीख ऐक्सिस बैंक हाउजिंग फाइनैन्स लिमिटेड से कोई पत्र नहीं मिला है। एक्सिस बैंक हाउजिंग फाइनैन्स कंपनी द्वारा हाउजिंग लोन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की स्कीम और बैंकों में भी चालू की है। (आशा होम लोन जैसी स्कीम)

बैंक घोटाले

बड़े घोटालों के कारण पहले ही बैंक त्रस्त थे। आपको याद होगा विजय माल्या वाला किंग फिशर घोटाला, नीरव मोदी घोटाला और कुछ बड़े घोटाले जो पूर्व में बैंकों में हो चुके हैं, उनकी डीटेल हम पाठकों की जानकारी के लिए निम्न रूप से दे रहे हैं।

अब एक नए प्रकार का घोटाला हाउजिंग लोन कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यह फाइनैन्स कम्पनीज बैंको की सबसीडरी कंपनियां है। किस प्रकार से यह कंपनिया लुटपाट कर रही है। और भ्रष्ट अधिकारीगण मालामाल हो रहे हैं। हम पाठकों को निम्न स्टोरी के द्वारा बता रहे है। इस संदर्भ में हमारे पत्रकार द्वारा कुछ जानकारी ऐक्सिस बैंक हाउजिंग कंपनी विरार वेस्ट ब्रांच के विषय में एकत्रित की गई है। यह जानकारी पाठको के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, कि वे समय रहते उचित कार्यवाही करे ।

देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला ABG SHIPYARD है ।

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष ऋषी अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर संथान मुथुस्वामी और तीन डाइरेक्टर आश्विन कुमार,सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमन नेवेतिया ने 22 हजार 842 करोड़ की धोखाधड़ी SBI बैंक के साथ की । जनवरी 2019 में फोरेंसिक ऑडिट की चर्चा में एबीजी शिपयार्ड को लोन देनेवाले सभी बैंको ने इसे बैंक फ्रौड घोषित कर दिया । एबीजी शिपयार्ड पर लिमिटेड पर 28 बैंको से लगभग 23 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसमें 7 हजार 89 करोड़ रुपए ICICI BAINK, 3 हजार 634 करोड़ IDBI, 2 हजार 925 करोड़ SBI, 1 हजार 614 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा, 1 हजार 244 करोड़ PNB और 1 हजार 228 करोड़ इंडियन ओवरसीज के बकाया है। यानि इन 6 बैंको के

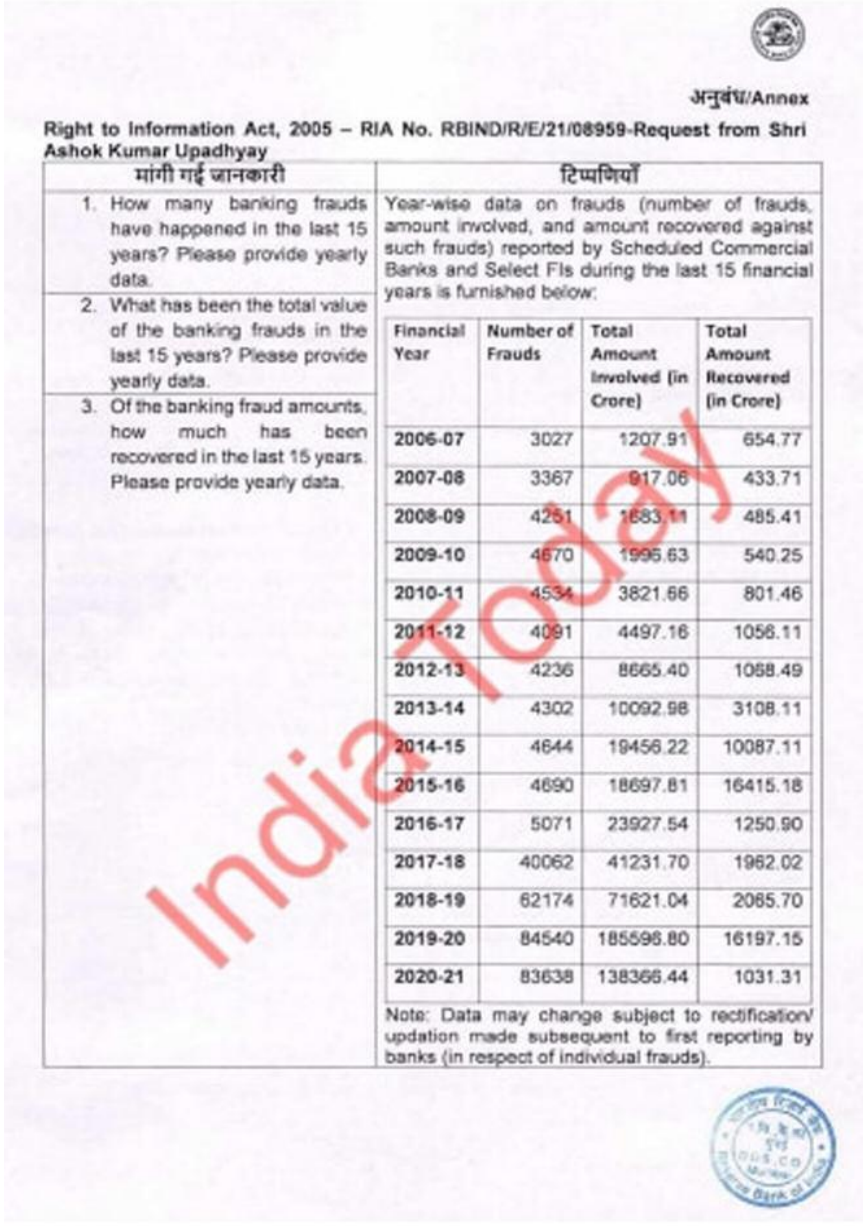

अनुबंध/Annex

Right to Information Act, 2005 – RIA No. RBIND/R/E/21/08959-Request from Shri Ashok Kumar Upadhyay

मांगी गई जानकारी	टिप्पणियाँ
1. How many banking frauds have happened in the last 15 years? Please provide yearly data. 2. What has been the total value of the banking frauds in the last 15 years? Please provide yearly data. 3. Of the banking fraud amounts, how much has been recovered in the last 15 years. Please provide yearly data.	Year-wise data on frauds (number of frauds, amount involved, and amount recovered against such frauds) reported by Scheduled Commercial Banks and Select FIs during the last 15 financial years is furnished below:

Financial Year	Number of Frauds	Total Amount Involved (in Crore)	Total Amount Recovered (in Crore)
2006-07	3027	1207.91	654.77
2007-08	3367	917.06	433.71
2008-09	4251	1483.11	485.41
2009-10	4670	1996.63	540.25
2010-11	4534	3821.66	801.46
2011-12	4091	4497.16	1056.11
2012-13	4236	8665.40	1058.49
2013-14	4302	10092.98	3108.11
2014-15	4644	19456.22	10087.11
2015-16	4690	18697.81	16415.18
2016-17	5071	23927.54	1250.90
2017-18	40062	41231.70	1962.02
2018-19	62174	71621.04	2065.70
2019-20	84540	185596.80	16197.15
2020-21	83638	138366.44	1031.31

Note: Data may change subject to rectification/ updation made subsequent to first reporting by banks (in respect of individual frauds).

India Today

ही 17 हजार 734 करोड़ रुपए बाकी है। इनके अतिरिक्त 22 और बैंको के 5 हजार 108 करोड़ रुपए बाकी है।

Naresh Goyal, Jet airways के पूर्व चेअरमैन नरेश गोयल के खिलाफ CBI FIR लिखनेवाला है (for banking frauds by them.)

नीरव मोदी

जनवरी 2018 में नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार 570 करोड़ रुपए की चालसाजी की थी ।

विजय माल्या

जुलाई 2015 में जगत प्रसिद्ध बिजनेस मेन विजय माल्या ने 9 हजार करोड़ की धोखाधड़ी कुल मिलाकर 17 बैंको के साथ की थी ।

2020 – 21 में 83 हजार से ज़्यादा बैंकिंग फ्रौड हुए है। और रिकवरी का हाल ये कि सिर्फ 1 हजार करोड़ रुपए की ही रिकवरी हो पाई है। ठगी का 1 प्रतिशत भी रिटर्न नहीं हो पाया है। ये जानकारी इंडिया टुडे की RTI में दी गई है।

नोटबंदी के बाद ऑनलाइन धोखाधड़ी बढने लगी है।

नोटबंदी के बाद 2016-17 में 5 हजार धोखाधड़ी हुई, जो कि 2017-18 में बढ़ कर 40 हजार हो गई । वित्त मंत्री की कोशिशों के बावजूद भी इसमें आरबीआई की रिपोर्ट के आंकड़ो के मुताबिक कोई परिवर्तन नजर नहीं आया है।

कोटक महिंद्रा बैंक के लोन विभाग का अधिकारी गिरफ्तार

लोनावाला थाने में एक होटल व्यवसायी अशोक पुरोहित ने आरोप लगाया कि उससे कोटक महिंद्रा के अधिकारी लोन पर उच्च ब्याज दर वसूल कर रहे हैं। शिकायत कर्ता ने बताया कि 2013 में 62 लाख का लोन लिया था। इस केस में बैंक के 7 कर्मचारियों पर आरोप लगा था। जिसमें 10.30 प्रतिशत की ब्याज दर की बात कही गयी थी लेकिन बैंक 12 प्रतिशत ब्याज वसूल कर रहा है । आठ मार्च को भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में बैंक लोन विभाग के अलंकार खरे को गिरफ्तार किया गया है।

Indian Overseas Bank, Sakinaka Branch.

Tribhuvan Singh Yadav the then Branch Manager had connived with Mr. Mubarak Wahid Patel Siphoned Rs. 5 Crores of Mathadi Kamgars defrauding Bank and Mathadi workers in 2016. Mr. Mubarak Wahid Patel The main accused is still active and is planning. Similar kind of Activities from Inside jail and a complaint against him in this regard is pending in Wahiv (Vasai) Police Station of Mumbai.

अव्यवस्था का आलम यह है कि DRT Court में लाखों मुगदमें लम्बित है। Lockdown में सरकार और बैंको ने बहुत सी सहुलियत प्रदान की। बैंक से कर्ज लेकर मकान

अनिता आकाश साहू द्वारा बैंक को दिये Final Notice की प्रतिलिपि

अनिता आकाश साह
(याचिकाकर्ता)

LEGAL NOTICE

Date : 23/04/2022

1) To The Axis Bank Ltd.
Consumer Lending Collection
3rd Floor Gigaplex, Mugalsan Road,
TTC Industrial Area.
Near 1 Gate Patni Airoli,
Navi Mumbai – 400 708.
2) M/s. Aditya Builders
through its Partner
Mr. Akhilesh Abhayraj Singh
Ph. 9930458573
Shop No. 7 & 8, Shivprasad Building, Indralok Bhayander (East) Thane 401105
3) Govt. of India throught Principal Secretary
4) Reserve Bank of India.
through, Governor (RBI).

Final Legal Notice prior to filing petition with DRT Court for legal Redressal

Reference 1 :

1) Copy of one time Restricting Request cum Application letter for self Employed individuals & Non Individual Entities. Provided to Axis Bank Ltd. on 12/10/2020 this format was provided to us by the bank. Enclosed as Annexure - III
2) Request Cum Application form for a resolution plan under Resolution framework 2, Resolution for Covid-19 related stress. Provided to Axis Bank ltd. on 14/07/2021 by this applicant this format was also provided by the Bank.
Enclosed as Annexure - V

Reference 2 :

1. My Letter dated 08/09/2020 Copy enclosed as Annexure (i)
2. My Letter dated 07/10/2020 Copy enclosed as Annexure (ii)
3. My Letter dated 12/10/2020 Copy enclosed as Annexure (iii)
4. My Letter dated 14/05/2021 Copy enclosed as Annexure (iv)
5. My Letter dated 14/07/2021 Copy enclosed as Annexure (v)
6. My Letter dated 12/03/2022 Copy enclosed as Annexure (vi)

Reference 3 :

1. My Loan A/c. No. : PHR 057304836500
2. My Application for Loan Reconstruction with you.
Pending Since : 08/09/2020
Copy enclosed as Annexure I
3. In respect of Flat A-001 Shailpushp Building, Kanchan Universe Vagulsar Palghar (West) 401 404 RERA Number : P99000004216.

Sir,

My Application for reconstruction of Loan is pending with Bank.
Since 08/09/2020

It is most humbly submitted that :

1) The applicant has paid all their Installments in time till start of Covid Lock-down, in March 2020.
2) The applicants application for reconstruction of loan in prescribed format of RBI / Bank is under consideration with bank and has not been replied by the Bank till date.
3) New Corona (Omnicorn) has also come up and there is possibility of another Lock down.
4) Applicant has been severally effected due to slow-down of cash flow in Corona Epidemic.
5) Because of Lock-down Builder has provided loss to the applicant and has provided possession of the flat in incomplete state and Applicant has to spend Additional funds of Rupees four Lakhs for organising Basic facilities like wiring for light and fan, necessary Plumbing and drainage etc.
6) If the Bank doesn't decide application of reconstruction of Loan of this Applicant. The applicant will be subjected to heavy losses in terms of their Emotional and financial stability.
7) By reconstructing Loan and rescheduling the Loan Installment, Bank will help applicant to keep a good repayment history of Applicant with Bank.

Most humbly prayed that the Bank may reconstructed the whole Loan Amount Rescheduling 1st Installment Payable after one Month from the date of

Reschedulment of Loan.

Prayer :

1) Bank may decide on merit the Loan Reconstruction Application of this applicant which is pending consideration with them since 08/09/2020.
2) The Bank may reimburse losses caused to us for not replying our loan. Restructure requests mentioned above. The Applicant had incurred heavy losses Due to this act of Bank not having decided this loan Restructure Application of this Applicant.
   a) Applicants Credit rating fell down,
   b) Arrears of loan Installments has piled up heavily during this pendency of time waiting to hear from the Bank on our loan Restructure request Application.
3) Bank be restrained not to adopt illegal means of Recovery of this Loan.
4) Bank be restrained not to proceed further prior to decision of my Loan restructure request pending, consideration with them.
5) The Builder may compensate losses to the Applicant for not providing proper possession of property with occupation certificate, till today.18/04/2022.
6) The Applicant be given fair opportunity to put forward his side. The Applicant be heard before initiating SARFAESI proceedings against them.

If the Bank does not reply this letter in a period of seven days from receipt of this letter The applicant will be free to avail legal remedy.

Your Truly,

Sd/-
Applicant
(Anita A. Sahu)
House No. A-001, Shailpushp Building Kanchan Universe Vagulsar Mahim Road, Palghar West 401 404.

इस प्रकार के मुकदमें भारी तादात में लम्बित है।

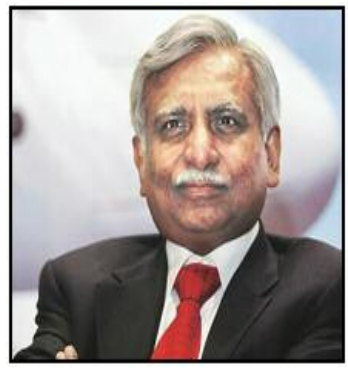

नरेश अग्रवाल

ऋषि अग्रवाल

नीरव मोदी

विजय माल्या

खरीदने वाले एक ग्राहक कि त्रासदी का विवरण यहां दे रहे है। इस ग्राहक को बैंक ने Restructure Scheme के तहत दोबारा फार्म उपलब्ध कराये। ग्राहक ने दोनो बार बैंक को यह फार्म भरकर Loan Restructure Apply किया ग्राहक ने बार बार बैंक को इस विषय मे पत्र लिखा और उचित कार्यवाही के लिए निवेदन किया। बैंक ने आज तारीख तक कोई जवाब उपलब्ध नही करवाया ।

बैंक को मिली ताकत SARFAESI act के तहत ताकत का Misuse

बैंक को SARFAESI act के तहत मिली है Judical Power इस अधिकार के तहत, बैंक अधिकारी Non Judiciously use कर रहें है।

इस प्रकार जब बैंक अधिकारी बिना ग्राहक के पत्र का जवाब दि ही Recovery कर रहे है। Judicial Order for Sale / Possession of Property का ऑर्डर पास कर रहे है। SARFAESI act में इन अधिकारियों को रोकना बहुत मुश्किल है।

समय रहते उचित कार्यवाही करना जरुरी है।

देश के कानून में प्रावधान है कि। किसी भी निर्दोश को सजा ना हो। हर मुजरिम को हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। और हर व्यक्ति को फैसले से पहले अपनी बात रखने को मौका मिलना चाहिए।

इन हलातों में जहां बैंक अधिकारी ग्राहक के पत्र का जवाब ही नहीं दे रहे है । क्या इन हालातो में इस प्रकार की Judicial Power Sarfaesi Act के तहत इस्तेमाल बैंक अधिकारियों द्वारा जायज होगा। ■

अरविंद गौड़ : असाधारण व्यक्तित्व

कल शाम एक विशेष व लंबी भेंट मित्र मयंक मधुर (सिनेमा व कला की दुनिया के लोगों को राष्ट्रवादी दर्शन व मोदी सरकार से जोड़ने के सूत्रधार) के माध्यम से रंगमंच के दुनिया में समकालीन सबसे बड़े नामों में एक अरविंद गौड़ जी से। अरविन्द गौड़ जी अस्मिता थियेटर ग्रुप के निदेशक के रूप मैं कार्यरत है। कुछ प्रमुख सिनेमा अभिनेताओं - कंगना राणावत, दीपक डोबरियाल, शिल्पा शुक्ला, पीयूष मिश्र, लुशिन दुबे, बबलस सबरवाल, ऐशवरया निधि, तिलोत्तमा शोम, राशि बनि, रुथ शेअर्द (ब्रिटिश अभिनेत्री), मनु ऋषि, सीमा आजमी, सुसान बरार (फिल्म-समर 2007), चन्दन आनंद, जैमिनि कुमार, शक्ति आनंद आदि उनसे ही एक्टिंग सीख फिल्मी दुनिया में छा गए। ज्वलनशील व समसामयिक मुद्दों जैसे बाल व महिला शोषण, सांप्रदायिकता, जातिवाद, सामंतवाद, घरेलू हिंसा, राज्य के अपराध, सत्ता की राजनीति, हिंसा, अन्याय, सामाजिक-भेदभाव , जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और नस्लवाद आदि विषयों पर भाव भंगिमाओं, वेदना, संवेदनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति के माध्यम से मंच व नुक्कड़ नाटकों के द्वारा अत्यंत असरकारी प्रभाव छोड़ने वाले अरविंद जी जैसे असाधारण व्यक्तित्व की साधारण जीवन शैली किसी को भी हतप्रभ कर देगी। एक ही भेंट में इस असाधारण व्यक्तित्व के जीवन दर्शन व अनुभवों के अनेक अनछुए पहलुओं को जानने -समझने की अवसर मिला।

अद्भुत आयोजन

एक दूसरे से ही जुड़े हैं संगीत के सात स्वर और और ध्यान के सात चक्र। कल साक्षी बना भारतीय शास्त्रीय संगीत के धुरंधरों के साथ एक सुरमयी शाम का , वह भी आध्यात्मिक गुरु मां मीना ॐ की ऊर्जामय उपस्थिति के मध्य।संगीत व रागों की जुगलबंदी के बीच जब मन झंकृत होता है तो आंतरिक आनंद नए शिखर चूमने लगता है और आपके ध्यान-चक्र जागृत होने लगते हैं व सत-चित्त-आनंद की अनुभूति आपको रसमय और भाव- विभोर कर देती है। कृष्ण कला फाउंडेशन की संयोजिका प्रख्यात कथक नृत्यांगना अनु सिन्हा जी द्वारा गुरु मीना जी के सम्मान में आयोजित संगीत संध्या ने नए आयाम छुए। शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात हस्ताक्षरों ध्रुपद गायक समित मल्लिक जी, सितार वादक उमाशंकर जी, तबला वादक सुनील चौधरी जी व शास्त्रीय गायक इंदू प्रकाश जी की प्रस्तुति ने एक न भूलने वाली शाम की रचना की। सभी रचनाकारों का आभार और नमन।

Anu Sinha Meena Om

समय की कसौटी पर

इस्लाम और इतिहास

भारत इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता तो मिल गयी थी किन्तु भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के प्रतीक चिन्ह जस के तस रह गए थे। तुष्टीकरण की कांग्रेसी राजनीति का आज भरपूर फायदा भाजपा को मिल रहा है। भाजपा लगातार उन मुद्दों को उठाती चली जा रही है जो भारत की चेतना से जुड़े हुये हैं। इस कारण 2014 के बाद से ही जनता ने भाजपा को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया है। पहले आरएसएस हिन्दुत्व का विषय उठाती थी किन्तु अब भाजपा ने फ्रंट फुट पर आकर हिन्दुत्व का विषय जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। राम मंदिर के विषय पर निर्णय और जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद लोगों में भाजपा पर भरोसा बढ़ गया है और राजनीतिक रूप से भाजपा के सामने विपक्ष विकल्पहीन दिखने लगा है। एक तरफ देश में मुग़ल आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के विषय राष्ट्रिय विमर्श बन चुके हैं तो दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों को अरब देशों की तरफ प्रेरित करने वाली जमातों की कलई भी खुलने लगी है। ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद इस सनातन चेतना जागृत होने वाली बहस यकायक तेज हो गयी है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में इस्लाम पर बहस तेजी के साथ चल रही है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप में ईशनिन्दा रोकने के लिए कानून बनाने पर विवाद चल रहा है तो भारत में एतेहासिक धरोहरों पर मुगल आक्रांताओं द्वारा जबरन कब्जे कर मस्जिद बनाने के विषय लगातार उभर रहे हैं। राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ, मथुरा जन्मभूमि, कुतुबमीनार में पूजा की अनुमति और ताजमहल के विषय इस समय सुर्खियों में हैं। अब चर्चा पूजा स्थल कानून 1991 की सीमाओं और उसकी संवैधानिक स्थिति पर हो रही है। राम मंदिर विषय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था किन्तु वर्तमान में वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और कर्नाटक में श्रीरंगपटनम में जामिया मस्जिद का विषय चर्चा में हैं। इतिहास लेखन की त्रुटियों के कारण अब यह कानून भी विवादों में आ गया दिखता है। लोग इस कानून को न्याय वाला कानून न मानकर लीपापोती वाला कानून मान रहे हैं। नब्बे के दशक में घाटी से खदेड़े गए कश्मीरी पंडितों का विषय भी इस समय वातावरण में घूम रहा है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा के बाद न्याय होता भी दिखने लगा है। यह सब ऐसे विषय हैं जो आक्रांताओं के वंशजों को बौखलाने पर मजबूर कर रहे हैं और भारतीय मिट्टी से जुड़े सभी धर्मों के लोग इसे सांस्कृतिक पुनर्चेतना का उदय मान रहे हैं।

● **अमित त्यागी**

भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल बाद आज देश कहां है, इस पर चर्चा हर तरफ चल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ सिर्फ 75 साल का अंकगणित नहीं है बल्कि इन 75 सालों में हम कितना अपनी जड़ों से जुड़ें और कटे हैं, यह चिंतन बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सनातन परंपरा वाला देश रहा है जिस पर कभी मुग़ल आक्रांताओं ने तो कभी अंग्रेजों ने हमला किया। आक्रांताओं का उद्देश्य लूटमार और डर के द्वारा धर्मांतरण था तो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के लिए भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया। 1857 की क्रांति के बाद मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला करते हुये गुरुकुल की तर्ज पर ईसाकुल (स्कूल) खोले। भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा न्यायिक एवं पुलिस तंत्र विकसित किया जिससे मूल भारतीयों का शोषण हो सके। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर चलते हुये आजादी के बाद भी सरकारों ने बहुसंख्यकों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। वामपंथियों के चंगुल में फंसी कांग्रेसी विचारधारा ने मुस्लिम तुष्टीकरण की हद कर दी। आपातकाल के दौरान बिना किसी चर्चा के भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। नब्बे के दशक में कश्मीरी पंडितों के जबरन पलायन का विषय राष्ट्रिय विमर्श का विषय ही नहीं बन पाया। 1991 में पूजा स्थल कानून बनाकर 1947 की स्थिति को यथास्थिति बना दिया गया। यानि कि पूर्व की गलतियों में सुधार का मार्ग भी कांग्रेसी सरकार ने बंद कर दिया।

इसके बाद भारत में अलग से अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का तुष्टीकरण था। कुल मिलकर देखा जाये तो भारत 1947 में आजाद तो हो गया किन्तु उसके बाद भी सनातन को आहत करने के कार्य होते रहे। 2014 के बाद

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ बनाम वामपंथियों के 100 साल - एक अध्ययन

यदि सौ साल पहले के राजनीतिक परिदृश्य पर लौंटे तो अंग्रेजों के शासन के समय आज के कई बड़ी विचारधाराओं का एक साथ उदय हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग बनी जिसका देश के लिये योगदान भारत का बंटवारा था। इस एक्शन के रिएक्शन में 1915 में हिन्दू महासभा बनी। फिर 1925 में कम्यूनिस्ट पार्टी बनी और इसी वर्ष राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा भी सामने आई। एक ओर कम्यूनिस्ट पार्टी एक राजनीतिक संगठन था तो दूसरी तरफ आरएसएस एक वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन तक सीमित था। इसके पहले अंग्रेजों द्वारा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ती के लिये 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गयी थी। इन संगठनों के समय काल और तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से एक बात तो साफ दिखती है कि उस समय के राजनीतिक दलों पर अंग्रेजों का प्रभाव था। अपने हितो को साधने के लिये अंग्रेज कुछ राजनीतिक विकल्प देश के सामने रख रहे थे। उसमे जुड़े लोग भारतीय दिखते थे किन्तु उनके स्वार्थ और लक्ष्य अंग्रेजी नीतियों से पूरे होते थे। चाहे एक अंग्रेज ए ओ ह्यूम के द्वारा शुरू की गयी कांग्रेस हो या जिन्ना की मुस्लिम लीग। इनके द्वारा अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीतियों को राजनीतिक अमली जामा पहनाया। इसके बाद देश का बंटवारा हो गया और अंग्रेज अपने पदचिन्हों पर चलने वाले लोग पीछे छोड़ गए। सनातन धर्म के अंदर की कुरीतियों को उजागर करके उनका समाधान करने के स्थान पर उनका राजनीतिक इस्तेमाल का जिम्मा वामपंथियों के हिस्से आया। वह भारत के सांस्कृतिक गौरव और सनातनी परम्पराओं का विकृत रूप दिखाने लगे।

दलित और पिछड़े वर्ग की जतियों में सवर्णों के प्रति घृणा इनका सुनियोजित अजेंडा बन कर समानान्तर चलता रहा। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उसका अगला पड़ाव था। वामपंथी विचारधारा के लोग सिर्फ उनके दल में ही ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी इसी विचारधारा के लोग बैठे थे जो हिन्दू धर्म की आस्थाओं पर चोट कर रहे थे। आम जनमानस को इसका आभास तब हुआ जब कांग्रेस सरकार द्वारा रामसेतु को मानने से इंकार कर दिया गया। इसके लिये बाकायदा उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दिया गया। वामपंथी विचारधारा ने रामायण को एक काल्पनिक कहानी तक बता दिया। भारत की नस नस में बसे प्रभु राम तब शायद स्वयं आहत हुये। इसके बाद ही कांग्रेस की सरकार के

स्थान पर 2014 और फिर 2019 में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। इसके साथ ही एक बात और समझना बेहद आवश्यक है कि इस विचारधारा और इन दलों के साथ जुड़े लोग कोई विदेशी नहीं हैं। अपने ही लोग हैं। इसी देश के रहने वाले हैं। हमारी तरह ही दिखते हैं। हमारे जैसे ही बात करते हैं। बस विचारधारा राष्ट्रनिर्माण की नहीं रखते हैं। अब जिस तरह से देश में विचारधारा की लड़ाई के नाम वामपंथ और राष्ट्रवाद आमने सामने आ खड़ा हुआ है उसमे दोनों तरफ से आने वाले बयानों का आंकलन करके जनता अब स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुचने लगी है कि वास्तविकता क्या है ? किसका अजेंडा क्या है।

वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों से पूछने का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों भारत का मुस्लिम समाज आज भी दिशा भ्रम की स्थिति में है। उसके भारतीय होने एवं पाकिस्तानी ठप्पा लगाने के लिये कौन सी विचारधारा दोषी है ? उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों पर बनी थी। लोहिया का कहना था कि एक सच्चे समाजवादी को कांग्रेस और वामपंथियों से बराबर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वो कभी भी खुद को मार्क्सवादी कहलाना पसंद नहीं करते थे। लोहिया के अनुसार कम्युनिस्ट अंधों की तरह हर समस्या का हल रूसी पृष्ठभूमि में ढूंढते है अन्यत्र उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता जबकि भारत की समस्याओं का हल केवल भारत के पास ही है। लोहिया ने अपनी पुस्तक भारत माता-धरती माता के पहले अध्याय में ही पृष्ठ 10 पर लिखा है कि 'आनंद, प्रेम और शांति का आव्हान तो रामायण में है ही पर हिंदुस्तान की एकता जैसा लक्ष्य भी स्पष्ट है। राम भारत के उत्तर-दक्षिण की एकता के परिचायक थे और कृष्ण पूर्व-पश्चिम एकता के'। लोहिया जैसा व्यक्तित्व नास्तिक होते हुए भी रामायण और महाभारत के सभी चरित्रों पर विश्वास करते हैं वो कम्युनिष्टों की तरह रामायण और महाभारत के अस्तित्व पर शक नहीं करते थे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली वामपंथी विचारधारा (जिसमे कांग्रेस और सपा भी शामिल है) के द्वारा क्यों मुस्लिमों का उत्थान नहीं हुआ ? यह यक्ष प्रश्न आज भी मुस्लिम समाज के सामने है।

-अमित त्यागी

भाजपा की सरकार आने के बाद जिस तरह से सनातन चेतना को जागृत करने के कार्य नियमित रूप से चल रहे हैं उससे भारतीयता स्थापित होने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। जिस झूंठ और मिथ्या तर्कों आधारित राजनीतिक व्यवस्था को वामपंथियों ने गढ़ा था उसका सच आज जनता तक पहुंच गया है। इसलिए जनता अब स्वयं आगे बढ़कर अपना अधिकार मांग रही है। स्वयं आगे बढ़कर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बनी ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बनी मस्जिद, कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति जैसे विषय अब जनता के द्वारा न्यायालय में उठाए जा रहे हैं। ताजमहल के तेजोमहल होने की याचिका हालांकि खारिज हो गयी है किन्तु उसके जमीन के कागजात जयपुर राजघराने के पास होने के सबूत भी चर्चा में है। जन चेतना से जुड़े यह विषय बताते हैं कि किस तरह मुग़ल आक्रांताओं को महान बताकर और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर भारत के बहुसंख्यकों की भावनाओं से खिलवाड़ किया

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 (Palces of Worship-special provisions Act, 1991) संविधान की मूलभूत रचना, न्याय तथा सत्य के विरुद्ध है। संविधान में भारत को प्रजातन्त्र कहा गया है। किन्तु इससे केवल बहुसंख्यक हिन्दू जनता का दमन हो रहा है। तब इसे प्रजातान्त्रिक संविधान कैसे कह सकते हैं जो बहुसंख्यक मत के अनुसार होता है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के विरुद्ध है जिसके अनुसार बहुसंख्यक हिन्दुओं को भी अपने स्थलों पर पूजा करने का अधिकार है। केवल औरंगजेब के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 30,000 हिन्दू मन्दिरों को तोड़ा गया था जिसके लिए लाखों लोगों की हत्या की गयी थी। इस हत्या, लूट तथा मन्दिर तोड़ने को आदर्श मान कर इस कानून में इसका पालन करने को कहा गया है। 15 अगस्त 1947 सनातन हिन्दू धर्म के आरम्भ की स्थिति मान कर उसे बनाये रखने का कोई आधार नहीं है। उदाहरण के लिए काशी का शिवलिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है जिनकी पूजा भगवान राम के द्वारा भी हुई थी। उसके बाद किसी लुटेरे द्वारा हत्या, लूट आदि करने से वह तीर्थ स्थल समाप्त नहीं हो जाता है। इसके नाम पर लुटेरों के उत्तराधिकारी मन्दिर के अवशेषों को पद-दलित कर हिन्दू आस्था तथा प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। वे अपमान करने के लिए सभी मन्दिर चिह्न रखे हुए हैं। फिर उसे मस्जिद कैसे कह कर इस कानून के अनुसार मस्जिद मान सकते हैं? यह कानून हर प्रकार से सत्य, धर्म, न्याय तथा संविधान की मूल रचना के विरुद्ध है।

पूजा स्थल कानून 1991, कितना वैधानिक ? कितना प्रासंगिक ?

भारतीय पूजा पद्धति में मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां देव की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वह स्वयं निवास करते हैं। यही कारण है कि अगर किसी देवालय को तोड़ भी दिया जाये तो भी वह देवालय ही रहता है। ढांचे का स्वरूप बदलने से देव का स्थान नही बदलता है। यदि मुस्लिम परंपरा की मस्जिद की बात करें तो मस्जिद सिर्फ नमाज अता करने का स्थान है वहां अल्लाह साक्षात विराजमान नहीं होते हैं। अरब में उस मस्जिद को भी तोड़ा जा चुका है जहां स्वयं पैगंबर साहब नमाज पढ़ा करते थे। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने पूजा स्थल (विशेष प्रविधान) कानून 1991 बनाया था जो किसी भी धर्मस्थल के 15 अगस्त 1947 वाले मूल स्वरूप में किसी भी बदलाव को रोकता है। अब इस कानून की वैधानिकता को चुनौती देते याचिका न्यायालय में लंबित है। इस याचिका पर न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी करते हुये उनसे जवाब मांगा है। इस याचिका में कहा गया कि यह कानून आक्रांताओं द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्यों को मान्यता देता है और यह कानून अदालत के जरिये अपने धार्मिक स्थलों और तीर्थों को वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है।

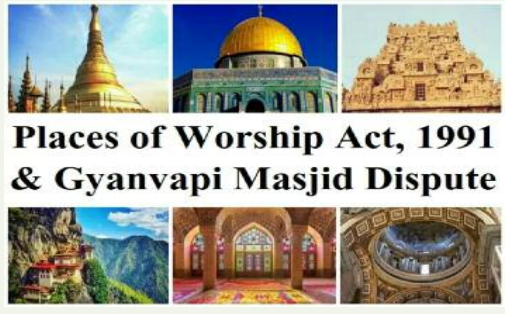

यदि सामान्य बुद्धि से देखा जाये तो क्या किसी स्थान के लंबे समय तक बंद रहने या उसका पूजा के लिए उपयोग न होने से उस स्थान के मालिक का हक़ खत्म हो जाता है। जबकि भारतीय कानून के अनुसार भगवान एक न्यायिक व्यक्ति होते हैं। यह कानून हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिखों को उनके पूजा स्थल और तीर्थों को वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है। यदि मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वक्फ कानून की धारा 7 में उन्हे यह अधिकार प्राप्त है। पूजा स्थल कानून भगवान राम और कृष्ण के बीच विभेद करता है। इस कानून के अंतर्गत राम जन्मस्थान को छोड़ दिया गया है किन्तु कृष्ण जन्मस्थान को नहीं छोड़ा गया है जबकि हिन्दू मान्यताओं के अनुसार दोनों ही विष्णु के रूप हैं। यदि संवैधानिक विषय की बात करें तो अनु0 25 के अंतर्गत हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिखों को उनके धर्म के पालन और उसके प्रचार का अधिकार प्राप्त है किन्तु यह कानून इस अधिकार से भी वंचित करता है। यह अनु0 26 में मिले धार्मिक स्थल प्रबंधन के अधिकार को भी बाधित करता है। संवैधानिक दृष्टि से केंद्र को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार तीर्थ स्थल और ला एंड ऑर्डर का विषय राज्य से संबन्धित है। जिस तरह काशी में ज्ञानवापी में तमाम सबूत प्राप्त हो रहे हैं वह इस कानून की वैधानिकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है।

काशी के साथ ऐसे अनेक स्थान जो इस समय विवादों के घेरे में हैं। यदि लंबे समय तक कोई अपराध करता रहे तो क्या उसे एक कानून के द्वारा वैधानिकता दी जा सकती है? क्या परंपरा के नाम पर अपराध करने दिया जा सकता है? यदि हम परंपरा के नाम पर किसी जाति के उत्पीड़न को असंवैधानिक मानते हैं तो क्या मुगलों द्वारा आदेश देकर मंदिर को ध्वस्त करने और उन्हे मस्जिद के रूप में प्रयोग करने को संवैधानिक ठहरा सकते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो इस कानून की वैधानिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। 1991 का यह कानून न केवल भारत की मूल भावना के विपरीत हैं बल्कि यह एक ऐसी भावना को उचित ठहराता है जिसमे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना गौरव और सवाब का काम समझा जाता है। यह कानून भारत में हुयी हिंदुओं की प्रताड़ना, उनके अपमान और धार्मिक स्थलों को रौंदे जाने को जायज कृत्य बना रहा है। उच्चतम न्यायालय अपने कई निर्णयों में कह चुका है कि व्यक्ति का सम्मान उसके जीवन से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। तो क्या व्यक्तियों के समूह समाज का सम्मान भी उतना ही महत्व रखना चाहिए।

-अमित त्यागी

(लेखक संवैधानिक विषयों के जानकार हैं)

चीनी कम्युनिस्टों द्वारा सुन्नियों का संहार, पीओजेके के गिलगिट पर प्रभाव

विश्व मानव अधिकार आयोग की ताजा रपट के अनुसार कम्युनिस्ट चीन के उइगर प्रांत के सुन्नी मुसलमान अपना मजहब बचाने के खातिर भाग कर कश्मीरी गिलगिट में बस रहे हैं। गिलगिट कभी महाराजा हरी सिंह के राज का भूभाग था। मगर 1947 से पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। उइगर की राजधानी काशगर से चार सौ किलोमीटर दूर पर बसे गिलगिट में इस्लाम महफूज है। वहां इन उइगर मुसलमानों को सुअर का गोश्त जबरन नहीं खिलाया जाता है। वे मस्जिद भी जा सकते हैं। उन्हें बस खतरा है पाकिस्तानी फौजियों से जो रिश्वत पाकर चीन के सैनिकों से उन्हें पकड़वा देते हैं। पाकिस्तानी व्यापारी मिर्जा इमरान बेग की बेगम मलिका मामिति उइगर सुन्नी हैं। मगर 26 सिम्बर 2018 के बाद से बेगम मलिक अपने शौहर से नहीं मिल पायी। शायद उन्हें चीन की जनवादी सरकार ने फौजी शिविर में कैद रखा है। पति–पत्नी ईद साथ नहीं मना पाये। उइगर के कालीन उत्पादक अब्दुल वली इस्लामाबाद में दुकान पर कार्यरत थे। यहां उनके वालिद ने 1960 में विक्रय केन्द्र खोला था। वली ने बताया कि चीन के कम्युनिस्ट पुलिस गिलगिट से उइगर के सुन्नियों को वापस काशगर की जेल में ले जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन उइगर सुन्नियों को गिलगिट से काशगर खदेड़ने के आदेश दिये थे। इमरान खान साफ कहते है कि चीन की सरकार इन सुन्नियों पर कतई जुल्म नहीं कर रही है। तो वास्तविकता क्या है ? पाकिस्तानी पुलिस इन उइगर सुन्नियों पर जासूसी करती है। फिर गिरफ्तार और दरबदर करती है। बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास भी ऐसी ही कारस्तानी करता है। वीजा जारी नहीं करता। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने दस लाख उइगर लोगों को जेलनुमा शिविरों में कैद कर रखा हे। उनके बच्चों पर भी नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं। मसलन कोई भी उइगर

दंपत्ति अपने बेटे का नाम मोहम्मद नहीं रख सकता। एक विशेष कानून बना दिया है। इसके तहत प्रतिबंधित सुन्नी शब्दों में इस्लाम, कुरान, मक्का, जिहाद, ईमाम, सद्दाम, हज, मदीना आदि हैं। कारण यही कि अब ऐसे हरफों से इस्लामी उत्साह बढ़ता है। राजधानी काशगर में अब एक भी मस्जिद नहीं है।

चीनियों ने अब तक 386 बुद्धिकर्मियों को कैद कर रखा है। अथवा गायब करा दिया है। शायद दुनिया से ही उठा दिया हो। उइगर अर्थशास्त्री इल्हाम तोहती आजीवन कारावास में है। प्रमुख नृशास्त्री (एंथ्रोपोलोजिस्ट) राहिल दावत गायब कर दिये गये। प्रो. राहिल ने असंख्य इस्लामी तीर्थस्थलों, अरबी और तुर्की गीतों और जनसंस्कृति को संजोये रखा था। एक पांच सितारा ईमाम थे अब्दुल रहवर अहमद। उन्होंने अपने बेटे को निजी मदरसे में दाखिला कराया था। नतीजन पांच साल की कैद भुगत रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रपट है कि उइगर युवतियों को चीन के फौजी जबरन अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। पुरुषों की बलपूर्वक नसबंदी कर दी जाती है। महिलाओं का गर्भपात आम शिकायत है। उजबेकी महिला अध्यापिका सायरागुल सौयतवे ने बीबीसी को बताया कि महिला कैदियों को बैरक में ठूंस कर बंद किया गया। उनके गुप्तांगों में मिर्ची पाउडर तथा बिजली के छड़ घुसेड़े गये। बाल काट देना और सामूहिक बलात्कार तो आम चलन है। अर्थात ये चीनी जनवादी सैनिक इन उइगर सुन्नियों के साथ जो जुल्म कर रहे उनके सामने तैमूर लंगड़े का दिल्ली की हिन्दू प्रजा पर ढाये अत्याचार भी फीके हैं। हिटलर द्वारा यहूदियों पर, स्टालिन द्वारा सोवियत रुसी किसानों पर, भी इतने अत्याचार नहीं हुए जितने असहाय उइगर सुन्नियों पर कम्युनिस्ट चीन ने ढाया है। मगर त्रासदपूर्ण बात तो यही है कि भारतीय इस्लामी मिल्लत ने इन पड़ोसी अकीदतमंदों से तनिक भी हमदर्दी नहीं दिखायी। रोहिंगिया मुसलमानों, बाटला हाउस मुठभेड़ आदि मसलों पर तो मुस्लिम जमातें (पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी) ओवरटाइम करते है। पर उइगर सुन्नियों की सुरक्षा पर उफ तक नहीं ? क्या मायने हैं ? क्या इसीलिये कि चीन का यार पाकिस्तान इन मजलूम मुसलमानों पर खामोश रहता है? यह बड़ी शर्मसार करने वाली बात होगी। इसको खत्म करना चाहिये, क्योंकि इस्लाम खतरे में है।

– के. विक्रम राव

जाता रहा है।

भारत के अंदर चल रहे इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के मध्य वैश्विक स्तर पर भी वर्तमान में दो तरह की विचारधारा समानान्तर काम कर रही हैं। एक तरफ यूरोप और अमेरिका में राजनीतिक इस्लाम के सिद्धान्त, व्यवहार और इतिहास के प्रति चेतना बढ़ रही है तो दूसरी ओर इस्लामोफोबिया यानि इस्लाम से डराने का आरोप बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया विरोध दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस पर भारत और फ्रांस सहित विश्व के अनेक देशों ने इसका विरोध किया है। अमेरिका और यूरोप के कई बड़े नेता और मीडिया भी इस कदम से पसोपेश में हैं। पूरे विश्व में नियमित तौर पर घटने वाले

जिहादी कांड, कत्लेआम और इस्लाम की आड़ में कई देशों के राष्ट्रिय क़ानूनों के उल्लंघन की घटनाएं जब आम हों तब संयुक्त राष्ट्र का कदम संदेह पैदा करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। यानि कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक वामपंथियों की एक जमात ऐसी भी है जो राजनीतिक रूप से इस्लाम के उपयोग के लिए तरह तरह के तर्क गढ़ते रहते हैं। भारत में ऐसे ही वामपंथियों ने न सिर्फ अपने तर्क गढ़े बल्कि कुछ वर्ष पूर्व राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। रामसेतु को काल्पनिक बता दिया।

राम कृष्ण के प्रति दुराग्रही वामपंथी मानसिकता

राम की जन्मभूमि अयोध्या को अफग़ानिस्तान में बता दिया। वामपंथी विचारधारा सिर्फ यही तक नहीं रुकी थी। इस विचारधारा के लोग राम को भी काल्पनिक पात्र बताने लगे थे। कांग्रेस सरकार में जब रामसेतु का विषय न्यायालय के सामने आया तब वहां बाकायदा हलफनामा देकर रामायण को काल्पनिक बता दिया गया। वर्तमान में सपा से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे कपिल सिब्बल ने 2018 में राम मंदिर विषय की सुनवाई के दौरान न्यायालय से कहा था कि इस विषय पर निर्णय चुनाव के बाद दें ताकि इस पर भाजपा चुनावी फायदा न ले सके। यानि कि राम मंदिर विषय को जितना ज्यादा समय तक लटकाया जा सके इसका प्रयास ये विचारधारा करती रही। उसी समय वामपंथी सीताराम येचूरी ने रामायण और महाभारत को हिंसा से भरा हुआ बताकर तुष्टीकरण की राजनीति में नया छौंका भी मारा था । वामपंथ के बड़े नेता सीताराम येचुरी का कहना था। 'यह कहना गलत है कि हिन्दू हिंसा में विश्वास नहीं रखते। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हिंसा से भरे हुये हैं।' एक बड़े वामपंथी नेता का यह बयान अकारण तो बिलकुल नहीं था।

इसके पीछे वह मानसिकता छुपी थी जिसके प्रचार के द्वारा हिन्दू धर्म से जुड़ी विभिन्न जातियों के बीच यह लोग मतभेद पैदा करते रहे थे। फूट डालो और राज करो की अंग्रेजी मानसिकता का यह वह भारतीय प्रारूप था जिसे विदेशी शक्तियों के द्वारा ईधन दिया जाता था। इस सोच ने कितना नुकसान किया है इसका अंदाजा तो तब लगेगा जब हम पीछे मुड़ कर 70 सालों का मूल्यांकन करेंगे। भारत में इतिहास के पुनर्लेखन की मांग लगातार उठ रही है। मुग़लों और आक्रांताओं को जिस तरह भारत में अकबर महान आदि कहकर लिखा गया है उससे देशभक्तों की भावनाएं लगातार आहत होती रही हैं। यूरोपीय और अमेरिकी नागरिकों ने अपनी वैचारिक स्वतन्त्रता लंबे संघर्ष और सामाजिक विकास के क्रम में हासिल की हैं। जब जब नागरिक जागरूक होते होते हैं तब तब वह अपने अधिकार प्राप्त कर ही लेते हैं। जन चेतना झूंटे इतिहास को पाठ्य पुस्तकों से हटवाने का भी माद्दा रखती है। कनाडा में 1990 के बाद इतिहास दुबारा लिखा गया है। 1990 में में कनाडा की संसद ने संस्तुति दी और वहां पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किए गये।

1990 के पूर्व की पुस्तकों में कनाडाई इतिहास पर्याप्त मात्रा में नहीं था। 1990 के बाद स्थिति बिलकुल बदल गयी और राष्ट्रवादी इतिहास लिखा गया। इससे एक बात तो साफ हो गयी है कि यदि सरकारें जागरूक हों तो वह देश के पुनर्निर्माण का क़दम उठा सकती हैं। मुस्लिम आक्रांताओं के वंशज आज भी भारत में स्वयं को शासक वर्ग समझते हैं और हिन्दू समाज को अपनी प्रजा। उनकी भाषा और शैली में यह स्पष्ट झलकता भी है। जैसे अगर ओवेसी को सुना जाये तो उनका कहना है कि मुगलों ने देश में 800 वर्ष राज किया है। लालकिला और ताजमहल जैसे इमारतें मुगलों की देन हैं। सिर्फ ओवेसि ही नहीं बल्कि तानाजी फिल्म में विलेन बने सैफ अली खान भी फिल्म में अपना किरदार निभाने के बाद फिल्म को एतेहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ वाला बताने लगे थे। इसके बाद उन्हे लोगों ने आड़े हाथों लिया और उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि शायद वह तैमूर नाम के लुटेरे का इतिहास भी नहीं जानते होंगे तभी उन्होने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। शायद यही भारत के लोगों के अंदर का वह आत्मविश्वास है जो 2014 के बाद जाग गया है। वह उन बातों का सार्वजनिक विरोध करने लगे हैं जिन पर बात करने से वह पहले कतराते थे।

वास्तविक भारतीय गौरवशाली इतिहास का हो पुनर्लेखन

इसके साथ भारत में जो इतिहास पढ़ाया जाता है कि भारत पर मुगलों ने शासन किया यह भी भ्रमित करने वाला है। मोहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, लोदी, बाबर आदि लुटेरे थे जो भारत को लूटने का काम कर रहे थे। दक्षिण भारत के राज्यों में कहीं भी मुस्लिम शासन कभी था ही नहीं। उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों, केरल, तमिलनाडू जैसे दक्षिण भारत के राज्यों कभी मुगलों के आधीन रहे ही नही तो कैसे सम्पूर्ण भारत पर मुगलों का राज्य कहा जा सकता है। खिलजी और लोदी दिल्ली तक सीमित रहे। अकबर राजस्थान के कई राज्यों तक भी अपनी पकड़ नहीं बना पाया था। औरंगजेब का शासन आगरा में होने के बावजूद मथुरा उसकी पहुंच से दूर था। इन आक्रांताओं ने भारत की पुरानी इमारतों में परिवर्तन कर उसकी शक्ल मस्जिदों की तरह बनाई। राम मंदिर के फैसले में जिस तरह उच्चतम न्यायालय ने तर्क देकर राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त किया उसके बाद वामपंथियों की कई खोखली थियरी खारिज हो गईं। अब आवश्यकता है उन पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी वास्तविक भारतीय इतिहास को समझ सके।पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास और वास्तविक इतिहास में कितना फर्क है यह बात तो अब समझ आने लगी है। दो साल पहले का एक उद्धारण अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कोलकाता गये थे तो वहां भी उन्होने इस पर चर्चा की थी।

प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के इतिहास, विरासत की दुर्दशा पर की गयी चर्चा अब राष्ट्रिय विमर्श का हिस्सा है। तब उनका कहना था कि 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतन्त्रता के बाद देश का जो इतिहास लिखा गया उसमे कुछ अहम पक्षों को नजर अंदाज किया गया। इतिहास का लेखन एवं विश्लेषण सत्ता और सिंहासन तक सीमित रह गया'। प्रधानमंत्री की बात सही है। जिस समय भारत पर आक्रांता आक्रमण कर लूटपाट कर रहे थे उस समय भारत का शिल्प बहुत ही उच्च स्तर का था। भारत के मंदिर खजानो से भरपूर थे। भारतीय पहाड़ काटकर इमारत बनाने की कला में माहिर लोग थे। इसी भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा 1903 में 'भारतवर्ष का इतिहास' विषय पर रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में दिये गये भाषण की भी याद दिलाई गयी थी, जिस भाषण में गुरुदेव ने कहा था कि भारत का इतिहास वह नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए याद करते एवं

कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया ज्ञानवापी मस्जिद

काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे हो रहे है। इसकी सच्चाई का भी पता चल ही जाएगा पर इस तथ्य से कौन इंकार कर सकता है कि काशी में मुस्लिम शासकों ने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद तो काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर निर्मित है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने 9 अप्रैल, 1669 को इस मंदिर सहित बनारस के तमाम मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया था। इस आदेश की कॉपी एशियाटिक लाइब्रेरी, कोलकाता में सुरक्षित है। मस्जिद का मूल नाम है `अंजुमन इंतहाजामिया जामा मस्जिद'।

मोहम्मद गोरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर औरंगजेब तक काशी के मंदिरों को ध्वस्त करने से बाज नहीं आए। अविमुक्तेश्वर को काशी में शिव द्वारा स्थापित आदि लिंग माना गया है। उनमें एक का स्थान ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे तीन मुस्लिम कब्रों की बीच बताया जाता है, जिनके दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार-शिवरात्रि पर किए जा सकते हैं। शिव के त्रिशूल- जिसपर काशी बसी बताई जाती है-के सबसे ऊंचे बीच वाले फल का यह हिस्सा चौक है, जिसपर यह मंदिर मौजूद था। इस जगह पहुंचकर नीचे झांकिए-यह जगह दो मंजिल से कम गहरी नहीं है। यही है 1194 ईसवी में तोड़े जाने से पहले का विश्वेश्वर मंदिर। रजिया मस्जिद जिसे तोड़कर संभवत: उसी की सामग्री से बना।

काशी के इतिहासकार विमल मिश्र ने अपनी गहन शोध के बाद लिखी किताब `नमामि काशी (काशी विश्वकोश)' में दावा किया है कि

1194 ईसवी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने विश्वेश्वर सहित काशी के तमाम मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। संभवत: दिल्ली की सुल्तान रजिया ने इस स्थान पर जो मस्जिद बनवाई, आज रजिया की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। आपको दिल्ली-6 में तुर्कमान गेट से कुछ ही दूर पर मिलेगी रजिया सुल्तान की कब्र। उसने 1236- 1240 के बीच दिल्ली पर राज किया था। वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के प्रमुख शासक इल्तुमिश की पुत्री थी। इस बीच, 14वीं सदी में शर्की सुल्तानों की फौजों ने भी पहली बार विश्वनाथ मंदिर तुड़वा दिया था।

विश्वनाथ मंदिर 2 सितंबर, 1669 को काशी के बाकी मंदिरों के साथ औरंगजेब के हाथों एक बार फिर ध्वस्त हुआ। क्रुद्ध काशीवासी 10 दिनों तक मुगल सेना से लोहा लेते रहे थे। औरंगजेब के सेनापति तोप ले आए और मंदिर को ढहा दिया। औरंगजेब ने इस जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, जिसके पश्चिम की दीवारों में आज भी प्राचीन मंदिर के विगत वैभव के चिह्न देखे जा सकते हैं।

इस बीच, 18वीं सदी के दौरान काशी को अपने नियंत्रण में लेने के इच्छुक मराठा शासक महादजी सिंधिया, रीवा व मेवाड़ के राजाओं और पेशवाओं के दीवान फणनवीस, आदि ने बहुतेरी कोशिशें कीं कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह वाजिब मुआवजा मुसलमानों को देकर वे वहां विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनवा दें, पर खुद काशी के पंचद्रविड़ ब्राह्मण भी 1742 ईसवी में मराठा सरदार मल्हारराव के ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ कर उस जगह विश्वेश्वर मंदिर बनवाने के प्रस्ताव के पक्ष में खड़े नहीं हुए। विमल मिश्र ने यह भी दावा किया है अपनी किताब नमामि काशी (काशी विश्वकोश) में। इसके साथ ही, आए दिन के अत्याचारों से भयभीत काशी की जनता ने भी मंदिर के निर्माण में खुलकर साथ देने से इनकार कर दिया। इस तरह मंदिर का निर्माण जब 120 वर्ष तक आगे नहीं बढ़ पाया, तब यह बीड़ा उठाया इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने।

पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि खरीद लेने और अवध के नवाब से मंदिर निर्माण की अनुमति प्राप्त कर लेने के बावजूद इस कार्य में व्यवधान आते रहे।

बहरहाल, काशी विश्वनाथ धाम के दौरान पुराने मकानों के ध्वस्तीकरण अभियान में तोड़े गए कई मकानों के भीतर मंदिर छिपे मिले। जहां इस बात को मानने के ठोस प्रमाण हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं की नजरों से बचाने के लिए धर्मप्राण नागरिकों ने इन मंदिरों को अपनी चहारदीवारी में घेरा होगा।

पढ़ते हैं। इसमे तो सिर्फ यही बताया गया है कि कुछ लोग बाहर से आए और सिंहासन प्राप्ति के लिए बाप-बेटे और भाई की हत्या करते रहे। यह वास्तविक इतिहास नहीं है। इस इतिहास में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि उस दौरान भारत के लोग क्या कर रहे थे। क्या उस समय उनका कोई अस्तित्व नहीं था? क्या साहित्य, कला, लोककला, स्थापत्य, दर्शन, विज्ञान, शिक्षा, जीवनशैली आदि का इतिहास में स्थान नहीं होना चाहिए।

गौरवशाली इतिहास, अब है राष्ट्रिय विमर्श

गुरुदेव की कहीं बातों को प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने जैसे ही पुनर्जीवित किया वैसे ही जनता ने उसे राष्ट्रिय विमर्श बना दिया। आजादी के अमृत

यहां इस तथ्य का उल्लेख करना समीचिन होगा कि 1022 ईसवी में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी और उनके सिपहसालार मलिक अफजल अल्वी के नेतृत्व में पहला मुस्लिम काफिला बनारस आया था। यहां मुस्लिम बसाहट का सिलसिला बस, यहीं से शुरु माना जाता है। गाजी के इस काफिले में बहुत से ऐसे सिपाही थे, जो तत्कालीन हिंदू शासकों से पराजित होकर परिवारों के साथ यहीं बस गए। इनमें कुछ काशीराज के यहां काम करने लगे। कई मुस्लिम अधिकारियों ने आगे चलकर बनारस के शासकों, सूबेदारों, फौजदारों या दूसरे प्रमुख पदों की जिम्मेदारी संभाली। बनारस के खास इलाके आज तक उनकी याद दिलाते हैं। गाजी का काफिला पहले जिस मोहल्ले में पहुंचा, उसे 'सालारपुरा' और अल्वी के नाम पर 'अलईपुरा' या 'अल्वीपुरा' के नाम से जाना जाता है। अलईपुर के भीतर के तमाम मोहल्ले खुद भी किसी न किसी मुस्लिम शासक के नाम पर ही बने हैं। बनारस में इस्लाम सभ्यता की शुरुआत से जुड़ा तीसरा मोहल्ला है मदनपुरा।

पिछले कुछ समय पहले कुतुब मीनार भी खबरों में था। मशहूर पुरातत्वविद केके मुहम्मद कहते हैं कि कुतुब मीनार कैंपस में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 27 मंदिरों को तोड़कर बनी थी। यह सच है। इसे दिल्ली की पहली मस्जिद माना जाता है। बेशक, कुतुब मीनार परिसर में हिन्दू मंदिरों के चिह्न मिलते हैं और इन्हें छुपाने की या ढकने की कोई कोशिश भी नहीं की गई है। परिसर में ही क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बीचो-बीच चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ खड़ा है जिस पर प्रसिद्ध महरौली प्रशस्ति गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। मस्जिद के खंभों पर अनेक देवी देवता यक्ष यक्षिणियां उत्कीर्ण हैं।

एक बात तो सबको समझ ही लेना चाहिए कि सेक्युलर बिग्रेड कितने ही पिलपिले दावे करे कि औरंगजेब बहुत दयालु था पर सच्चाई यह है कि उसने और कई अन्य मुस्लिम शासकों ने काशी और देश के विभिन्न भागों में मंदिरों को क्रूरतापूर्वक निशाना बनाया।

आर.के. सिन्हा
(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

महोत्सव के दौरान इतिहास से हुये खिलवाड़ और सांस्कृतिक विरासतों के मस्जिद में तब्दील होने का विषय अब राष्ट्रिय विमर्श है। जिस तरह से कनाडा ने 1990 के बाद राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत नया पाठ्यक्रम अपनाया, जिसमे इतिहास के सकारात्मक बिन्दुओ को उभारा गया इस तरह का विषय 2014 के बाद से भारत में भी अपेक्षित है। इतिहास के पुनर्लेखन विषय पर चर्चा तो प्रारम्भ हुयी किन्तु इस चर्चा के राष्ट्रिय विमर्श बनने में 8 साल लगा दिये गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब पाठ्य पुस्तकों में बदलाव पर काम शुरू हुआ तब अन्य विषयों के बदलाव पर तो आपत्तियां नहीं हुयी। इतिहास लेखन के विषय पर वामपंथी खेमा ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूचाल आने वाला हो। इस खेमे के कुछ इतिहासकारों ने तो ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया कि जैसे इतिहास को तो बदला ही नहीं जा सकता है। वह किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद इतिहास के नए तथ्यों के आधार पर तैयार की गयी नयी पुस्तकों को पूरी तरह नकार दिया गया। ये पुस्तकें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के सुझाए मार्ग पर तो थीं किन्तु वामपंथ से बिलकुल अलग हटकर थी।

इतिहास के पुनर्लेखन में अब जो भी देर हो रही है वह हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद की भावना को आहत कर रही है। अब सबसे पहले तो इस विषय पर राष्ट्रिय विमर्श बनना चाहिए। इसके बाद हमारी संस्कृति, व्यवहार, परंपरा, अनुष्ठान, धार्मिक गतिविधियां एवं कारगर आर्थिक प्रणालियों को हमारी आगामी पौध के बीच पहुंचना चाहिए। चाणक्य की शासन नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत सी वर्तमान समस्याओं का हल प्रदान करता है। हमें इमारतों के निर्माण पर नहीं संस्कृति के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। भूतकाल की बहुत सी इमारतें तो आज नष्ट हो गयी हैं किन्तु उस समय काल की संस्कृति और विचार आज भी जिंदा हैं। बस अब आवश्यकता है उन विचारों को भावी पीढ़ी तक पहुचाने की। इतिहास के संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है कि इतिहास में एक साथ कई समानान्तर गतिविधियां घटित हो रही होती हैं। सिर्फ एक दृष्टिकोण को दिखाकर आप पूरी परिदृश्य का खाका नहीं खींच सकते हैं। समग्रता से विश्लेषण करने से ही वृहद आयाम उभरते हैं। जिस तरह से राम मंदिर के विषय पर उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में वामपंथियों की कई थियरी नष्ट कर दी। और आगे अब यह काशी और मथुरा में भी होने जा रहा है कुछ वैसा ही पाठ्य पुस्तकों के इतिहास में भी करने की आवश्यकता है।

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बनाम धार्मिक कुतर्क

सेकुलर शब्द की आड़ में भी मुस्लिम तुष्टीकरण का एक बड़ा खेल अब तक होता आया है। किसी भी धार्मिक भावना का सम्मान एक तरफा नहीं हो सकता है। शरीयत के अधिकतर कायदे मानवीयता और लोकतान्त्रिक मूल्यों के विरोधी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में किसी भी धर्म

ज्ञानवापी परिसर विश्वेश्वर का आदि स्थान और ज्ञानोद तीर्थ की है भूमि

आज ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो हमारा ही तीर्थक्षेत्र अविमुक्तेश्वर विश्वेश्वर का आदि स्थान और ज्ञानोद तीर्थ की पवित्र भूमि है।

विध्वंस और आलगीर मस्जिद का अस्तित्व हमारे तीर्थ की सत्यता पर भारी आखिर पड़ ही गया जब वहां शिवलिंग का प्राकट्य हुआ।

आज हर एक सनातनी हर्षोल्लास से भरा हुआ है लेकिन इस बीच शायद हम भूल रहे इस धर्म युद्ध के सबसे बड़े योद्धा व्यास परिवार को। आदरणीय पूजनीय स्व. सोमनाथ व्यास को, आदरणीय पूजनीय स्व केदारनाथ व्यास को जिन्होंने 150 सालों से ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई लड़ी है। अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां,ग्रंथों के रचयिता पूजनीय स्व केदारनाथ व्यास।

व्यासपीठ ज्ञानवापी काशी के पिठाधीश, ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मन्दिर (मूल) मुक्ति के प्रणेता व नेतृत्वकर्ता मूरधन्य धार्मिक लेखक विद्वान प. केदार नाथ ब्यास जी का ही ज्ञानवापी की संपत्ति पर मालिकाना हक और स्थापत्य स्व केदारनाथ व्यास के परिवार का रहा है

ज्ञानवापी की संपत्ति पर मालिकाना हक और स्थापत्य स्व केदारनाथ व्यास के परिवार का रहा है

आज इन्ही पूजनीय केदारनाथ व्यास की बदौलत हिंदू पक्ष कानून ज्ञानवापी पर दावा कर सकता है।

इन्ही व्यास परिवार की बदौलत सन् 1936 में दीन मोहम्मद को पूरे ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने के दावे को नकार कर कोर्ट ने बैरंग लौटाया था और ज्ञानवापी परिक्षेत्र को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने के दावे से इंकार किया था।

ज्ञानवापी परिसर और बाबा विश्वनाथ का यह विवाद सैकड़ों साल पुराना है।

साल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद के लोहे की बैरिकेडिंग के पहले यह पूरा इलाका खुला हुआ था, इसकी पुरानी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के पिछले हिस्से में एक मैदान जैसा था, जबकि मंदिर के खंडहर पर मस्जिद का निर्माण साफ दिखाई देता था।

जब यह पूरी मस्जिद खुली थी तब इसका एक हिस्सा मंदिर के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। काफी पहले से यहां विध्वंस के हिस्से में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी जिसके तस्वीर और प्रमाण आज भी मौजूद हैं। हालांकि, तब श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत सिर्फ साल में एक बार ही दी जाती थी।

मगर साल 1991 के बाद जब ज्ञानवापी परिसर को पूरी तरीके से लोहे के बड़े बैरिकेडिंग से घेर दिया गया और वहां सुरक्षा

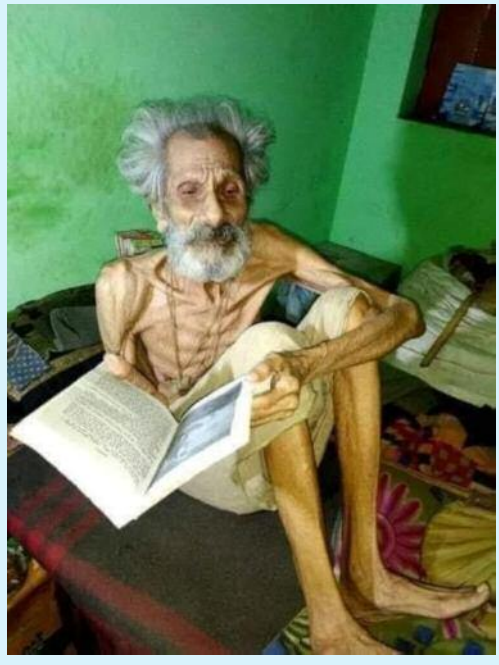

बलों के कैंप स्थापित कर दिए गए उसके बाद ना कोई श्रृंगार गौरी की पूजा कर पाता था और ना ही विध्वंस के उस हिस्से को खुली आंखों से देख पाता था।

इस ज्ञानवापी परिसर को लेकर दो मामले- 1936 में सबसे पहले दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मामला है, जिसमें दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की जमीनों पर अपना हक जताया था। इसका मूवी मुकदमा नंबर 62/ 1936 जोकि एडिशनल सिविल जज बनारस के यहां दाखिल हुई थी, तब की अदालत ने इसे मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद दीन मोहम्मद यह केस लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट गए और 1937 में जब फैसला आया तब हाई कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीनों पर व्यास परिवार का हक बताया और उनके पक्ष में फैसला दिया।

इसी फैसले में बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का वह नक्शा भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया है। तब से आज तक व्यास परिवार ही ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के तहखाना का देखरेख करता है, वहां पूजा करता है और प्रशासन के अनुमति से वही तहखाने को खोल सकता है । आज भी उसमें मंदिर के ढेरों सामान रखे गए हैं।

1937 के इस फैसले में ही इलाहबाद हाईकोर्ट में एक नक्शा भी लगाया और उस नक्शे में बकायदा डॉटेड लाइंस के साथ मस्जिद की सीमा रेखा तय की और उसके अलावा बाकी चारों तरफ की जमीन का फैसला विश्वनाथ मंदिर के व्यासपठ के महंत व्यास परिवार पक्ष में दिया। तब से ही मस्जिद की अपनी सीमा थी, जबकि बाकी आसपास की पूरी जमीन को व्यास परिवार को दे दिया गया। 1937 के बाद 1991 तक इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ।

व्यास परिवार और उनके वकील के पास पिछले पौने दो सौ साल से लड़े गए मुकदमों की फेहरिस्त और फाइलों का पुलिंदा है। 1937 का मुकदमा दीन मोहम्मद का मुकदमा बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच का सबसे अहम मुकदमा माना जाता है। इस मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट तक चली, जिसमें हाई कोर्ट ने बहुत सारी बातें साफ कर दीं। यानी ढांचागत मस्जिद को छोड़कर तमाम जमीने व्यास परिवार की और बाबा विश्वनाथ मंदिर की होगी। मस्जिद के अलावा आसपास की किसी जमीन पर न तो नमाज हो सकेगी ना ही उर्स या फिर जनाजे की नमाज होगी।

बनारस के रहने वाले दीन मोहम्मद ने Civil Suit कोर्ट में दाखिल किया। Civil Suit 62 of 1936 में किया की जो सेटलमेंट प्लाट -9130 को (वास्तविक काशी विश्वनाथ का पूरा एरिया Revenue Record में 9130 के नाम से जाना जाता है) वक्फ प्रॉपर्टी declare किया जाये और उन्हें नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार दे दिया जाये। दूसरा पक्ष इस केस में ब्रिटिश सरकार थी , हिन्दुओ ने जब इस केस में पक्ष बनने की बात की तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने लिखित रूप में कोर्ट में हलफनामा दायर किया और

Paragraph -2 में यह लिखा की यह परिसर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। (यहां आप को जान लेना चाहिए की किसी Valid मस्जिद होने के लिए कोई भी स्थान वक्फ संपत्ति होना चाहिए)

Paragraph -11 में लिखा है की यहां की मूर्तिया मुगलकाल के पहले से यहां है।

Paragraph -12 इस सम्पत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं था। और इस्लामिक law के मुताबिक यह अल्लाह को Dedicate नहीं किया जा सकता। दावेदारों की ओर से सात, ब्रिटिश सरकार की ओर से 15 गवाह पेश हुए थे। सब जज बनारस ने 15 अगस्त 1937 को मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढने का अधिकार नामंजूर कर दिया था।

दीन मोहम्मद इससे खुश नहीं हुए और फिर उन्होंने हाई कोर्ट में Suit दायर किया जिसका Appeal No -466 of 1937 जिसका फैसला आया

1942 SCC OnLine Allahabad/ Page No. 56 के Paragraph-5 में ये HOLD किया है की यहां मंदिर तोड़ी गई है। और Paragraph-16 में HOLD किया है की यह वक्फ सम्पति नहीं है और नमाज पढ़ लेने से किसी स्थान पर आप का उस पर हक़ नहीं हो जाता।

साल 1937 से लेकर 1991 तक दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं हुआ। मुसलमान अपनी मस्जिद में जाते थे, जबकि हिंदू अपने मंदिरों में। हालांकि यह मस्जिद भी 1991 तक विरान ही पड़ी रही, जिसमें इक्के दुक्के मुसलमान ही नमाज अदा करते थे लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद से यहां अचानक नमाजियों की संख्या काफी बढ़ गई और तब से यहां हर रोज नमाज होती भी है।

1991 में व्यास परिवार की ओर से स्वामी सोमनाथ व्यास ने एक मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को 'आदि विशेश्वर मंदिर' कहते हुए इसे मंदिर को सौंपने का मामला दर्ज कराया। 1991 से लेकर यह मामला अभी तक चल रहा है और इसी मामले में सुनवाई करते हुए 1996 में पहली बार अदालत ने कोर्ट कमिशन बनाया था और पहला सर्वे 1996 में किया था।

इस मुकदमे में सोमनाथ व्यास की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी वकील थे। बाद में सोमनाथ व्यास की मृत्यु के बाद वह वादी मित्र होकर इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।

मस्जिद के ढांचे को मंदिर या मूल विश्वेश्वर मंदिर कहकर अदालत में याचिका लगाई गई तो उसमें कई तस्वीरें भी लगाई गईं। वह तमाम तस्वीरें उस विध्वंस किए गए ढांचे की हैं, जो मंदिर दिखाई देता है।

मंदिर के विध्वंस पर बनी मस्जिद की कई तस्वीरें अदालत में सुबूत के तौर पर संलग्न की गईं और उसी को देखते हुए साल 1996 में एक सर्वे कमीशन बनाया गया था। इस केस की सुनवाई के दौरान बनारस की अदालत ने इसमें एएसआई से खुदाई का आदेश दिया था।

आदि विशेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है इसका नक्शा भी 1937 में तत्कालीन बनारस के डीएम ने अदालत में सौंपा था। जिस जमीन पर या जिस ढांचे पर आज ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है उस ढांचे का नक्शा पहली बार अदालत में पेश किया था और उस नक्शे में कई चीजें साफ-साफ लिखी हैं। मसलन यह पहला और एकमात्र ऐसा नक्शा है जो दिखाता है कि मंदिरनुमा कोई ढांचा रहा है जिसके बड़े हिस्से पर मस्जिद बनी है, बकायदा डॉटेड लाइन से इस नक्शे पर मस्जिद के हिस्से को दिखाया गया है।

पूजनीय स्व केदारनाथ व्यास 2020 में इहलोक गमन कर गये। आज भले इन्हें सारा देश ना जानता हो। आज भले स्वयं को सनातनी कहने वाले लोंगों को इनका योगदान और नाम तक ना पता हो। लेकिन महादेव के इस सपूत का, व्यास परिवार का पूरी काशी श्रृणी रहेगी चिरकाल तक। महादेव के लोक में महादेव के पुत्र आज चिर निद्रा में सो रहे।

कोटि कोटि अभिनंदन आपका व्यास परिवार

- आकांक्षा

'ज्ञानवापी'
(ज्ञान का कुआँ) बनारस

मूल श्रीकाशीविश्वनाथ मन्दिर परिसर, वाराणसी में अष्टकोणीय 'ज्ञानवापी' (ज्ञान का कुआं) ठीक उसी प्रकार अवस्थित है जिस प्रकार मक्का के 'मक्केश्वर महादेव मन्दिर' (सम्प्रति 'अल-मस्जिद-अल-हरम') परिसर में 'गंगाजल' ('जमजम') अवस्थित है।

शिवलिंग पर जलाभिषेक हेतु शिवालय में कुएं की व्यवस्था, प्राचीन वैदिक परम्परा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'ज्ञानवापी' का जल श्रीकाशीविश्वनाथजी पर चढ़ाया जाता था।

रिटिश लाइब्रेरी, लन्दन; लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन; जे. पॉल गेट्टी म्यूजियम, कैलिफोर्निया, इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन् 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संगृहीत हैं जिनको देखकर रोमांच हो उठता है।

इन फोटोग्राफरों में फेलिस बीटो (1832-1909), सैम्युअल बर्न (1834-1912), विलियम हैरी जैक्सन (1843-1942), आदि प्रमुख हैं। इन चित्रों में विभिन्न कोणों से ज्ञानवापी, उसके आसपास अवस्थित नन्दी और गणपति आदि की प्रतिमाओं का अवलोकन किया जा सकता है।

के कानून, नेता, संत, पंथ, प्रॉफेट की आलोचना तो शामिल कर ली जाती है किन्तु इस्लाम की आलोचना को इस दायरे से बाहर कर दिया जाता है। बस यही वामपंथियों का खेल है जिसके दम पर आज तक इन लोगों ने गलत इतिहास पढ़ाया है। गलत धारणा बनवाई हैं। लोगों को गुमराह किया है। अब जब जनता इन विषयों पर जागरूक हो गयी है और अपने अधिकार मांगने लगी है तब इन लोगों में खलबली मच गयी है। भारत में इस्लाम की जड़े वैसे ही आधारहीन रही हैं। इसी वजह से पिछले चार दशकों में भारत में अरब के चाल चलन और तौर तरीकों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। अरब की सभ्यता को भारत से बेहतर दिखाया गया। इसकी वजह साफ थी कि भारतीय मुस्लिम स्वयं को अरब से जुड़ा हुआ माने। यदि वह भारत से जुड़ेगा तो उसे भारत में इस्लाम के आधारहीन होने की बात पता चल जाएगी। वह वापस अपनी जड़ों की ओर लौट

शिवलिंग बनाम फवारा विवाद के बीच इस शख्स को भी जानिए

- स्व केदारनाथ व्यास। जिन्होंने 150 सालों से ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई लड़ी है। अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां, ग्रंथों के रचयिता पूजनीय स्व केदारनाथ व्यास।
- आज तक ज्ञानवापी मंदिर (मस्जिद) का खजाना इनका ही परिवार भरते आ रहा है।
- ज्ञानवापी की संपत्ति पर मालिकाना हक और स्थापत्य स्व केदारनाथ व्यास के परिवार का रहा है।
- इन्ही व्यास परिवार की बदौलत सन् 1936 में दीन मोहम्मद को पूरे ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने के दावे को नकार कर कोर्ट ने बैरंग लौटाया था और ज्ञानवापी परिक्षेत्र को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने के दावे से इंकार किया था।
- ज्ञानवापी परिसर और बाबा विश्वनाथ का यह विवाद सैकड़ों साल पुराना है।
- 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद के लोहे की बैरिकेडिंग के पहले यह पूरा इलाका खुला हुआ था, इसकी पुरानी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के पिछले हिस्से में एक मैदान जैसा था, जबकि मंदिर के खंडहर पर मस्जिद का निर्माण साफ दिखाई देता था।
- जब यह पूरी मस्जिद खुली थी तब इसका एक हिस्सा मंदिर के तौर पर भी इस्तेमाल होता था।
- काफी पहले से यहां विध्वंस के हिस्से में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी जिसके तस्वीर और प्रमाण आज भी मौजूद हैं। हालांकि, तब श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत सिर्फ साल में एक बार ही दी जाती थी।
- साल 1991 के बाद जब ज्ञानवापी परिसर को पूरी तरीके से लोहे के बड़े बैरिकेडिंग से घेर दिया गया और वहां सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित कर दिए गए उसके बाद ना कोई श्रृंगार गौरी की पूजा कर पाता था और ना ही विध्वंस के उस हिस्से को खुली आंखों से देख पाता था।
- इस ज्ञानवापी परिसर को लेकर दो मामले- 1936 में सबसे पहले दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मामला है, जिसमें दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की जमीनों पर अपना हक जताया था। इसका मूवी मुकदमा नंबर 62/ 1936 जोकि एडिशनल सिविल जज बनारस के यहां दाखिल हुई थी, तब की अदालत ने इसे मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया।
- उसके बाद दीन मोहम्मद यह केस लेकर इलाहबाद हाई कोर्ट गए और 1937 में जब फैसला आया तब हाई कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीनों पर व्यास परिवार का हक बताया और उनके पक्ष में फैसला दिया।
- इसी फैसले में बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का वह नक्शा भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया है।
- तब से आज तक व्यास परिवार ही ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के तहखाना का देखरेख करता है। वहां पूजा करता है। और प्रशासन के अनुमति से वही तहखाने को खोल सकता है। आज भी उसमें मंदिर के ढेरों सामान रखे गए हैं।
- 1937 के इस फैसले में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक नक्शा भी लगाया और उस नक्शे में बकायदा डॉटेड लाइंस के साथ मस्जिद की सीमा रेखा तय की और उसके अलावा बाकी चारों तरफ की जमीन का फैसला विश्वनाथ मंदिर के व्यासपठ के महंत व्यास परिवार पक्ष में दिया।
- तब से ही मस्जिद की अपनी सीमा थी। जबकि बाकी आसपास की पूरी जमीन को व्यास परिवार को दे दिया गया। 1937 के बाद 1991 तक इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ।
- व्यास परिवार और उनके वकील के पास पिछले पौने दो सौ साल से लड़े गए मुकदमों की फेहरिस्त और फाइलों का पुलिंदा है।
- 1937 का मुकदमा दीन मोहम्मद का मुकदमा बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट तक चली।
- जिसमें हाई कोर्ट ने ढांचागत मस्जिद को छोड़कर तमाम जमीने व्यास परिवार की और बाबा विश्वनाथ मंदिर की कर दी थी। मस्जिद के अलावा आसपास की किसी जमीन पर न तो नमाज हो सकेगी ना ही उर्स या फिर जनाजे की नमाज होगी।
- बनारस के रहने वाले दीन मोहम्मद ने Civil Suit कोर्ट में दाखिल किया। Civil Suit 62 of 1936 में किया की जो सेटलमेंट प्लाट -9130 को (वास्तविक काशी विश्वनाथ का पूरा एरिया Revenue Record में 9130 के नाम से जाना जाता है) वक्फ प्रॉपर्टी declare किया जाये और उन्हें नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार दे दिया

इस द्रश्य में जुदाई है आँसू है करुणा है वेदना है तड़प है इंतजार है 352 साल के बिछड़ने ओर फिर मिलन की बेला है।
ये चित्र नही नन्दी का संघर्ष ओर समर्पण है अपने महादेव के प्रति। इस दृश्य को देखकर मेरी आंखें बार-बार डबडबा रही है।

बाबा मिल गए

जाये। दूसरा पक्ष इस केस में ब्रिटिश सरकार थी।

- हिन्दुओ ने जब इस केस में पक्ष बनने की बात की तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने लिखित रूप में कोर्ट में हलफनामा दायर किया और Paragraph -2 में यह लिखा की यह परिसर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। (यहां आप को जान लेना चाहिए की किसी Valid मस्जिद होने के लिए कोई भी स्थान वक्फ संपत्ति होना चाहिए)
- Paragraph -11 में लिखा है की यहां की मूर्तिया मुगलकाल के पहले से यहां है।
- Paragraph -12 इस सम्पत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं था। और इस्लामिक law के मुताबिक यह अल्लाह को Dedicate नहीं किया जा सकता।
- दावेदारों की ओर से सात, ब्रिटिश सरकार की ओर से 15 गवाह पेश हुए थे। सब जज बनारस ने 15 अगस्त 1937 को मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने का अधिकार नामंजूर कर दिया था।
- दीन मोहम्मद इससे खुश नहीं हुए और फिर उन्होंने हाई कोर्ट में Suit दायर किया जिसका Appeal No -466 श्रद्ध 1937 जिसका फैसला आया
- 1942 SCC OnLine Allahabad/ Page No. 56 के Paragraph-5 में ये HOLD किया है की यहां मंदिर तोड़ी गई है।
- और Paragraph-16 में HOLD किया है की यह वक्फ सम्पति नहीं है। और नमाज पढ़ लेने से किसी स्थान पर आप का उस पर हक़ नहीं हो जाता।
- साल 1937 से लेकर 1991 तक दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं हुआ। मुसलमान अपनी मस्जिद में जाते थे। जबकि हिंदू अपने मंदिरों में। हालांकि यह मस्जिद भी 1991 तक विरान ही पड़ी रही, जिसमें इक्के दुक्के मुसलमान ही नमाज अदा करते थे।
- लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद से यहां अचानक नमाजियों की संख्या काफी बढ़ गई और तब से यहां हर रोज नमाज होती भी है
- 1991 में व्यास परिवार की ओर से स्वामी सोमनाथ व्यास ने एक मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को `आदि विशेश्वर मंदिर' कहते हुए इसे मंदिर को सौंपने का मामला दर्ज कराया।
- 1991 से लेकर यह मामला अभी तक चल रहा है और इसी मामले में सुनवाई करते हुए 1996 में पहली बार अदालत ने कोर्ट कमिशन बनाया था और पहला सर्वे 1996 में किया था।
- इस मुकदमे में सोमनाथ व्यास की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी वकील थे। बाद में सोमनाथ व्यास की मृत्यु के बाद वह वादी मित्र होकर इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।
- मस्जिद के ढांचे को मंदिर या मूल विश्वेश्वर मंदिर कहकर अदालत में याचिका लगाई गई तो उसमें कई तस्वीरें भी लगाई गईं। वह तमाम तस्वीरें उस विध्वंस किए गए ढांचे की हैं, जो मंदिर दिखाई देता है।
- मंदिर के विध्वंस पर बनी मस्जिद की कई तस्वीरें अदालत में सुबूत के तौर पर संलग्न की गईं और उसी को देखते हुए साल 1996 में एक सर्वे कमीशन बनाया गया था।
- इस केस की सुनवाई के दौरान बनारस की अदालत ने इसमें एएसआई से खुदाई का आदेश दिया था।
- आदि विशेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसका नक्शा भी 1937 में तत्कालीन बनारस के डीएम ने अदालत में सौंपा था।
- जिस जमीन पर या जिस ढांचे पर आज ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। उस ढांचे का नक्शा पहली बार अदालत में पेश किया था। और उस नक्शे में कई चीजें साफ-साफ लिखी हैं।
- मसलन यह पहला और एकमात्र ऐसा नक्शा है,जो दिखाता है कि मंदिरनुमा कोई ढांचा रहा है। जिसके बड़े हिस्से पर मस्जिद बनी है। बकायदा डॉटेड लाइन से इस नक्शे पर मस्जिद के हिस्से को दिखाया गया है।
- पूजनीय स्व केदारनाथ व्यास 2020 में इहलोक गमन कर गये।
- आज भले इन्हें सारा देश ना जानता हो। आज भले स्वयं को सनातनी कहने वाले लोगों को इनका योगदान और नाम तक ना पता हो। लेकिन महादेव के इस सपूत का, व्यास परिवार का पूरी काशी श्रृणी रहेगी चिरकाल तक।
- महादेव के लोक में महादेव के पुत्र आज चिर निद्रा में सो रहे।

कोटि कोटि अभिनंदन आपका व्यास परिवार।।

– *अनुराग सिंह*

सकता है। अब मुस्लिमों के बौद्धिकों के चिंतन का गढ़ माने जाने वाले देवबंद में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि मंदिर तोड़कर बनाई गयी मस्जिदों पर उन्हे क्या स्टैंड लेना है। यदि देवबंद इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो यह भारतीय मुस्लिमों के लिए मजबूती का आधार बनेगा।

किन्तु आज ऐसे इस्लामी समूह अधिकता में हैं जिनका मानना है कि उनके रिवाजों, शरीयत आदि की आलोचना नहीं होनी चाहिए। इस आलोचना को ही वह इस्लामोफोबिया या ब्लोस्फोमी कहते हैं। यहां तक कि वह लोग स्वयं प्रामाणिक किताबों का के विवरण का उल्लेख भी रोकना चाहते हैं क्योंकि इससे विश्व में राजनीतिक इस्लाम की असलियत सामने आती है। इस्लामिक राजनीतिक समूह अपना इतिहास बखूबी जानते हैं और वह इस बात से भी बखूबी परिचित हैं कि गैर इस्लामिक नेता उनके इतिहास से अपरिचित हैं। इसी का लाभ उठाकर अब तक वह भारत सहित अनेकों गैर इस्लामिक देशों में अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। चूंकि सत्य शाश्वत होता है और वह सदा रहता है इसलिए सत्य पर समय और काल का प्रभाव नहीं होता है। राजनीति और बाजार से प्रेरित तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सत्य पर परदा डालते रहते हैं। एक अकाट्य सत्य यह है कि भारत में इस्लाम के आने से पूर्व हजारों मंदिर थे। भारत में वास्तुकला उत्कृष्ट थी। हमारे यहां जो कुछ भी उत्कृष्ट है उसे मंदिर कहा जाता है। संसद भवन को मंदिर मंडप कहते हैं।

मंदिर और भारत माता हैं भारतीयता के प्रतीक चिन्ह

बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम में भारत माता की आराधना की है। यानि कि मंदिर और भारत एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। भारतीय जब खुश होते हैं तब मंदिर जाते हैं। जब दुखी होते हैं तो मंदिर में प्रभु की शरण में जाते हैं। इसका अर्थ साफ है कि भारतीयों की सहनशीलता और धैर्य का

मुनाफिकीनों को मस्जिद में जाने का हक नहीं दिया गया है

पवित्र ज्ञानवापी परिसर के जिस हिस्से को अवैध रूप से मस्जिद प्रचारित कर दिया गया है, उसके स्थलीय सर्वेक्षण का न्यायिक आदेश होने पर उसे बाधित करने के लिये अचानक जो भीड़ स्वयं को मुसलमान कहने वालों की उमड़ पड़ी, उसे दंडित करना शासन का कर्तव्य है। क्योंकि हमारा शासन और प्रशासन इस्लाम के प्रति श्रद्धाभाव रखता है और पैगम्बर मुहम्मद साहब तथा उनकी इलहामी किताब जो आसमानी किताब है - कुरान को सुप्रीम कोर्ट ने भी मूल प्रमाण माना है। अत: यह आवश्यक है कि उन सभी लोगों को जो मोमिन होने का दावा करते हैं परन्तु अल्लाताला द्वारा पैगम्बर के जरिये दिखाये गये रास्तों पर नहीं चलते, उन्हें मस्जिद परिसर या मस्जिद घोषित किसी भी परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाये।

क्योंकि स्वयं कुरान के जरिये अल्लाताला ने कहा है, जो बात कुरान शरीफ के सूरा 9 (सूरा अत-तौबा), आयत 17 और 18 में स्पष्ट कही गई है कि 'यह मुशरिकों का काम नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और उसके प्रबंधक हों। अल्लाह की मस्जिदों का प्रबंधक और उसे आबाद करने वाला वही हो सकता है जो अल्लाह और कयामत पर ईमान लाये।'

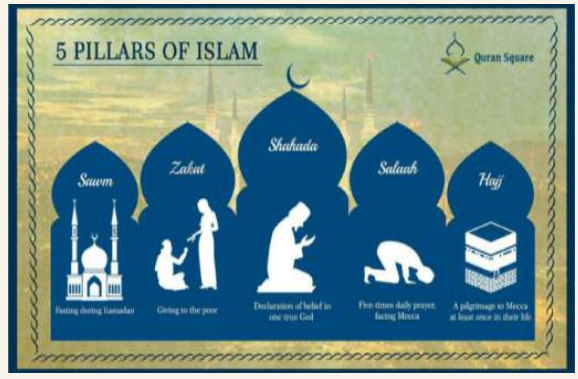

मुशरिक वह है जो नंदी महाराज प्रत्यक्ष विराजमान के परिसर में इबादत का दिखावा करता है। जब वहां भगवान शिव की पूजा का कोई लक्षण या संकेत या चिन्ह मिल जाये तब तो वहां इबादत करना पूरी तरह मुशरिक का ही काम है। क्योंकि वहां एक ही परिसर में अल्लाह का शरीक आप नंदी महाराज को बना रहे हैं।

परन्तु इससे भी बड़ी बात यह है कि मुनाफिकीनों को किसी भी रूप में मस्जिद में प्रवेश का हक नहीं है। मुनाफिकीन वह है जो बाहरी तौर पर स्वयं को मुसलमान कहे परन्तु जो कुरान शरीफ में प्रतिपादित गुनाहों से तौबा न करे। सही: मुस्लिम की हदीस 4226, 4231 कहती है कि शराब पीना या किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करना या उसका व्यापार करना या उसके व्यापार से मुनाफा कमाना - ये सब हदूद गुनाह हैं। हदूद गुनाह का अर्थ है अल्लाह द्वारा तय की गई हद के बाहद जाकर कोई गुनाह करना। ऐसे गुनाह अक्षम्य हैं और इनकी सजा मृत्युदंड है। जो खुद को मुस्लिम कहने वाले लोग वहां उस दिन इकट्ठे हुये थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं या नशे के व्यापार से जुड़े हुये हैं। वे सब मुनाफिकीन हैं और हदूद गुनाह के अपराधी हैं। मुनाफिकीन का मस्जिद में प्रवेश वर्जित है।

इसी प्रकार सही: मुस्लिम की 5255, 5261 एवं 5268 वीं हदीस है कि अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज की नकल करना अर्थात् मनुष्य, पशु-पक्षी आदि किसी का भी चित्र या मूर्ति बनाना या खुद किसी मनुष्य जैसा या पशु पक्षी जैसा अभिनय करना और अल्लाह की बनाई हुई कायनात की किसी भी चीज की नकल करना हदूद गुनाह है जो अक्षम्य अपराध है। स्पष्ट रूप से वहां ऐसे लोग उपस्थित थे। उन मुनाफिकीन को मस्जिद के भीतर जाने का हक नहीं है। क्योंकि जो लोग खुद को मुसलमान कहते हैं और मुहम्मद साहब के कहे गये कथनों पर और कुरान शरीफ पर नहीं चलते, वे सब मुनाफिकीन हैं और कठोरता पूर्वक दंडनीय हैं।

वस्तुत: तो मुहम्मद साहब ने केवल यह कहा था कि हुक्मरान के विरुद्ध किसी भी तरह का विद्रोह करना हदूद गुनाह है और उसकी सजा मृत्युदंड है। जैसा कि सही: मुस्लिम 4543 एवं 4568 में बताया गया है। परन्तु बाद में इसकी व्याख्या यह कर दी गई कि केवल मुस्लिम हुक्मरान के विरुद्ध विद्रोह करना हदूद गुनाह हैं।

स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो कुरान शरीफ में बताये गये आचरण से अलग कोई आचरण करते हैं, वे मोमिन कहे जाने के अधिकारी (हकदार) नहीं हैं। इसलिये उन्हें मस्जिद में प्रवेश का अथवा मस्जिद कही जाने वाली किसी भी जगह में प्रवेश का अधिकार (हक) नहीं दिया गया है। इसलिये उस दिन सच्चे मोमिनों के अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति को स्वयं को मुसलमान कहने के आधार पर यदि ज्ञानवापी परिसर में जाने दिया गया तो यह अल्लाह ताला की, कुरान शरीफ की और पैगम्बर मुहम्मद साहब की तौहीन है और प्रदेश के या वाराणसी के प्रशासकों को इस तौहीन की इजाजत मुनाफिकीनों को नहीं देनी चाहिये थी।

प्रो. कुसुमलता केडिया

आधार मंदिर हैं। जब पश्चिम की तरफ से आक्रांता भारत आए तो उन्होने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ा। चूंकि इस्लाम के अनुसार मंदिरो में जाने वालों को बुतपरस्ती करने वाला कहा जाता है इसलिए इस्लामी परंपरा के अनुसार मंदिर तोड़ने से सवाब (पुण्य) मिलता है। इस्लामिक विचारधारा में एक विषय गज़्वा ए हिन्द का भी है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में इस्लाम तब तक नहीं फैल सकता है जब तक भारत पर यह लागू न हो जाए। मुग़ल आक्रांता यहां सिर्फ मंदिर लूटने आए होते तो उसे लूटकर वापस भी जा सकते थे। उन्होने मंदिरों को लूटा और यही पर रहकर तलवार की दम पर लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। इसी कारण बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक भारत में मंदिर विध्वंश का एक अपमानजनक इतिहास है। इन लोगों ने मंदिर तोड़े और उसी सामग्री से उसी स्थान पर मंदिर बनवाये। यह कुकृत्य इतना स्पष्ट और सपाट दिखता है कि सामान्य बुद्धि से भी समझ आता है। बस वामपंथी विचारधारा से जुड़े बुद्धिजीवियों और नेताओं को यह स्पष्ट संदेश भी दिखाई नहीं देता है। अब सत्य को लंबे समय तक छिपा के नहीं रखा जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर हुये कई आंदोलन हुये। इन आंदोलनों का प्रभाव अखिल भारतीय था और जन का जुड़ाव इन आंदोलन में साफ दिखता था।

इसके बाद न्यायालय ने तार्किक फैसला सुनाकर इस मामले का निस्तारण किया तो जनभावना जुड़ी होने के कारण सरकार ने भी इसको बनाने में जोर शोर से भाग लिया। अब काशी में ज्ञानवापी का विषय न्यायालय के पास है। न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न विषयों पर पड़ताल जारी है। ज्ञानवापी एक ऐसा विषय है जो औरंगजेब के विध्वंश का स्पष्ट साक्षी है। ऐसे ध्वंस किए गए मंदिरों की सूची बहुत लंबी है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, जौनपुर की अटाला मस्जिद, अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर के पास जामा मस्जिद, बंगाल में पंडुआ मंदिर की जगह अदीना मस्जिद, खजुराहो के निकट विजय मंदिर के पास औरंगजेब के द्वारा बनवाई गयी आलमगीर मस्जिद आदि इस विध्वंस के स्पष्ट प्रमाण हैं। 1991 के दौरान आलमगीर मस्जिद की एक दीवार भारी बारिश के कारण गिर गयी जिसके बाद हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियां स्पष्ट दिखाई देने लगीं। अब क़ायदा कहता है कि मंदिर तोड़कर बनाई गयी मस्जिदों पर सर्व मान्य फैसला होना चाहिए और मुस्लिम पक्षों को उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। पर हक़ीक़त यह नहीं है। चूंकि, मंदिरों को तोड़कर उस स्थान पर मंदिर बनाना इस्लामिक प्रक्रिया है इसलिए मुस्लिम पक्ष के लिए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना फक्र की बात है। मुसलमानो के संदर्भ में मिस्त्र के धार्मिक मामलों के मंत्री डॉ मुख्तार मुहम्मद का एक बयान बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज काउंसिल के वार्षिक सम्मेलन में डॉ मुख्तार मोहम्मद कहते हैं कि मुसलमान जिस देश में रहते हैं उन्हे उस देश का सम्मान करना चाहिए।

आक्रांताओं के पक्षधर लोग करते भावनाओं को आहत

एक कट्टर देश के मंत्री की बात को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में मुसलमानों का एक वर्ग भारत के प्रति निष्ठा रखता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग गोरी, गजनी, बाबर, औरंगजेब, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों को अपना आदर्श मानता है। इन हमलावरों की प्रशंसा भारत की मूल भावना को आहत करती है। भारत के मंदिरों को ध्वंस करने वालो की प्रशंसा करने वाले देशभक्त तो नहीं कहे जा सकते हैं। वामपंथी विचारधारा से जुड़े इतिहासकार ही गंगा जमुनी तहजीब का जुमला लेकर आए। इन्ही लोगों के गलत तथ्यों से प्रेरित कांग्रेसी सरकार पूजा स्थल कानून 1991 लेकर आई। यदि मूल समस्या को समझकर इस कानून को समझा जाये तो यह कानून ही असंवैधानिक दिखने लगता है। अपनी पुस्तक राइटिंग एंड स्पीचेस में डॉ अंबेडकर लिखते हैं कि भारत पर पश्चिम उत्तर से मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया। पहला हमला मोहम्द बिन कासिम ने किया था। फिर गजनी के महमूद ने 17 हमले किए। गोरी और चंगेज खान ने धावा बोला। तेमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, बाबर आदि ने आक्रमण किए। अंबेडकर इस पुस्तक में आगे लिखते हैं कि इसमे कोई सन्देह नहीं है कि भारत में मूर्ति पूजा और हिन्दुओ के बहुदेववाद पर प्रहार कर इस्लाम की स्थापना इन हमलों का उद्देश्य था। इस बात को दिमाग में रखना आवश्यक है कि ये सभी एक उद्देश्य से प्रेरित हमले थे। मंदिर ध्वंस एक सच्चा इतिहास और नंगा सच है। इस सत्य को जुठलाकर राष्ट्रिय स्वाभिमान की कल्पना करना व्यर्थ है।

डॉ अंबेडकर ने बहुत सच्चाई से इस सत्य को स्वीकार किया है। मंदिर ध्वंस पुराने कष्ट की तरह बार बार उभरते हैं। उन पर चर्चा पुराने घावों को घोल देती है। अब न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे घावों को ठीक करने की अपेक्षा बढ़ रही है। मंदिरों के ध्वंस का विषय राष्ट्र के सामने आना ही चाहिए चाहें यह कितना ही कड़वा क्यों न हो। राष्ट्र का स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है। हंसी तो तब आती है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राष्ट्र को ही काल्पनिक स्वरूप बता देते हैं। विपक्ष के बहुत से नेता ऐसे हैं जो भाजपा का विरोध करते करते भारत की सनातन चेतना को आहत करने वाले बयान देते हैं और इसी कारण वह लोगों की निगाह में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। कांग्रेस द्वारा 1991 में लाया गया पूजा स्थल कानून एतेहासिक भूलों के सुधार का नहीं बल्कि विषय को टालने वाला कानून था। जबकि उस समय की कांग्रेस को वह काम करना चाहिए था जो आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर निर्माण के द्वारा सरदार पटेल ने किया था। 1991 में पूजा स्थल कानून के स्थान पर यदि कांग्रेस सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर पुनर्निर्माण का कानून ले आती तो वह जनभावना का प्रतीक बनता। न्यायपालिका ने श्रीराम मंदिर का विषय बेहद कुशलता से निपटाया है। अब मुस्लिम विद्वानों को भी सच को स्वीकार करके मिस्त्र के मंत्री की बात मानकर भारत की जन भावना के अनुसार चलना चाहिए।

चर्च पोषित दलित आंदोलन और मुखर होते अभिनेता

अनुपम खेर, अक्षय कुमार, कंगना रानावत जैसे अनेकों नाम हैं जो 2014 के बाद से प्रखर राष्ट्रवादी होकर उभरे हैं। अब कश्मीर फाइल्स के द्वारा कश्मीर का विषय राष्ट्रिय विमर्श का विषय बना गया है। सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी आवाज उठ रही है। भारत की फिल्मों पर इसाइयत और चर्च का प्रभाव एक दूसरे तरीके से भी रहा है। इस संदर्भ में मशहूर अभिनेता रजनीकान्त का बयान महत्वपूर्ण संदेश देता है। रजनीकान्त का कहना है कि पेरियार ने 1971 में सलेम में आयोजित एक रैली में भगवान राम और सीता की वस्त्रहीन तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। पेरियार हिंदू देवताओं के कट्टर आलोचक थे परंतु उस समय किसी ने भी पेरियार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं की थी। अब रजनीकान्त के बयान से दो महत्वपूर्ण प्रश्न उभरते हैं? पहला, कि क्यों उस समय पेरियार के इस तरह के कार्यों का कोई विरोध नहीं हुआ? दूसरा, रजनीकान्त के द्वारा इस समय इस प्रश्न को क्यों उठाया गया? पहले प्रश्न का जवाब है कि पेरियार दलित साहित्य के द्वारा स्वयम उतना लाभ नहीं ले सके जितना उसका फायदा चर्च ने उठाया। चर्च ने विदेशी धन के माध्यम से पेरियार के नाम को स्थापित किया। पेरियार के विरोधियों को दलित विरोधी साबित करने का तंत्र विकसित किया और चूंकि भारत में तर्क सुलभ लोग आसानी से मिल जाते हैं इसलिए उनके माध्यम से अपना तंत्र सुचारु रूप से चलाया। चूंकि उस समय तक दलित और मुस्लिम गठजोड़ भारतीय राजनीति का प्रमुख तत्व होता था इसलिए उस वोट बैंक को छूने का साहस कोई नहीं करता था। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अब जैसे भारत में हिन्दुत्व मजबूत हुआ और दलित समाज मीम-भीम के चक्रव्यूह से निकलना शुरू हुआ तब वामपंथी खेमे का चर्च पोषित यह खेल सतह पर उठने लगा। जो बात लोग दबे जुबान से बंद कमरे में करते थे उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाया जाने लगा। रजनीकान्त का बयान

श्रीकृष्ण जन्मभूमि : सत्य, तथ्य व कथ्य

मैंने वो समय भी देखा है जब उत्तर प्रदेश में 1991 में, मैं व मेरे तमाम छात्रावासी मित्र 'जय श्रीराम' का जयकारा लगाने व गले में भगवा झंडा लपेटने पर सुबह से शाम तक थाने के बंदी गृह में बंद रहे व शाम 5 बजे मुंसिफ साहेब के घर पर निजी मुचलके पर छोड़े गए।

आज वो समय आया जब प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, जहां मुलायम सिंह ने हजारों लोगों की हत्या अपने गुंडों से करवा दिया। वो भी समय आया जब तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद पर रार चल रही है और शत प्रतिशत बाबा आदि विश्वेश्वर विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा।

हिन्दू मंदिरों का विध्वंस मुस्लिम लुटेरों, बलात्कारियों ने जीभर के किया और उन्हीं मंदिरों के मलबे से औना पौना मस्जिदें खड़ी कर लीं। तो ये है 'सत्य'।

आज इन्हीं चोरों,लुटेरों के नाजायज वंशज 30000 से अधिक मंदिरों पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद बना उसके मालिक बने बैठे हैं ये है 'तथ्य'।

कांग्रेस व कांग्रेसी, वामपंथी इतिहासकार, तथाकथित परजीवी से बुद्धिजीवी जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। औरंगजेब सहित गजनी, गोरी, अकबर, खिलजी, तुगलक की शान में कसीदे पढ़ते हैं और उन्हीं राष्ट्र निर्माता बताते हैं, उनके लिए तमाम अवधारणाएं गढ़ते हैं ताकि आम हिन्दू मानस को दिग्भ्रमित कर मलेच्छओं के कुकर्मों को सही साबित किया जाय। इस देश के सनातन हिन्दू धर्म के सबसे बड़े हन्ता व गद्दार यही उपरोक्त लोग हैं। इनके द्वारा बनाये विकृत अवधारणा को कहते हैं 'कथ्य'(Narrative)।

अब बात करते हैं हमारे आराध्य व धर्म संस्थापक लीलाधर प्रभु श्रीकृष्ण जन्मभूमि की।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि अर्थात कंस का कारागार। कालांतर में यहां भगवान श्रीकृष्ण की पूजा शुरू हो गयी और यह कार्य सदियों से होता आ रहा है। इस मंदिर को गजनवी, गोरी, खिलजी व अन्य सुल्तानों ने लूटा और इसको ध्वंस भी करते रहे।

अंततः सन 1618 में बुंदेला राजा बीर सिंह बुंदेला ने 13.37 एकड़ जमीन पर प्रभु कृष्ण जन्मस्थली का भव्य मंदिर निर्माण कराया। उस समय इस मंदिर को बनाने की लागत 33 लाख रुपये आयी थी (ये हिसाब दस्तावेजी है,कोई हवा हवाई नहीं है)। दस्तावेजों में लिखा है कि इस मंदिर के सोने की चमक ऐसी थी कि वह चमक आगरा से दिखाई देती थी।

औरंगजेब 1658 में राजा बना और मथुरा के मंदिर की चमक जब भी दिखती वो आग बबूला हो उठता। 1669 आते आते औरंगजेब का वहशियाना और जालिमाना रुतबा लगभग पूरे भारत पर कायम हो चुका था। हालांकि सुदूर दक्षिण में उसकी बाधा सदैव मराठा बने रहे और उन पर मरते दम तक काबू न पा सका ये बलात्कारी, लुटेरा औरंगजेब।

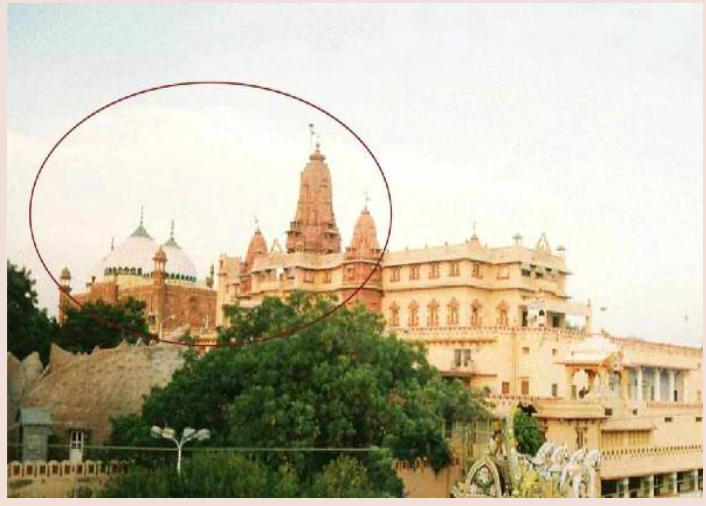

सन 1669 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि, काशी और मथुरा के मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाय और वैसा ही किया गया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि-'औरंगजेब ने ये फरमान भी जारी किया कि, उपरोक्त मंदिर की मूर्तियों को आगरा के जहांआरा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रख दो ताकि नमाजी कुचलते हुए जाएं हिन्दू देवताओं को'।

बहरहाल, सन 1770 के 'गोवर्धन युद्ध' में मरहठों ने मुगलिया सेना को हराया व प्रभु श्रीकृष्ण की जमीन मराठा साम्राज्य की हो गयी। सारे मुस्लिम अतिक्रमणकारी (Encroachers) भगा दिए गए या मार दिए गए। सारा 13.37 एकड़ जमीन मराठा साम्राज्य का हिस्सा हो गयी।

सन 1803 में अंग्रेजों उपरोक्त भूमि को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना दिया और मंदिर का सारा भूभाग बरतानिया हुकूमत के अधीन हो गया।

सन 1815 में, राजा पटनीमल (बनारस से ताल्लुक रखते थे) ने जन्मभूमि की समस्त 13.37 एकड़ जमीन अंग्रेजो से नीलामी में खरीद लिया और यह सम्पूर्ण परिसर उनकी सम्पत्ति हो गयी थी। हालांकि,कुछ मुस्लिम इस भूभाग के कुछ हिस्से पर अब भी अवैध कब्जा किये बैठे थे।

सन 1875 में इन्हीं मुस्लिमों ने दीवानी वाद दायर किया परन्तु हार गए।

सन 1920 में पुनः मुस्लिमों ने दीवानी वाद मथुरा अदालत में डाला जिसमें वो हार गए।

मुस्लिम अपील में उच्च न्यायालय गए और उनकी अपील 1935 में खारिज हो गयी।

8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के प्रपौत्र राय किशनदास ने कृष्ण जन्मभूमि की उपरोक्त 13.37 एकड़ जमीन, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को रु. 13400/- में बेच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि,मालवीय जी ही प्रभु श्रीकृष्ण को पुनः प्रतिष्ठापित करवा पाएंगे। वस्तुतः राय किशनदास जमीन के एवज में कोई पैसा नहीं लेना चाहते थे परन्तु वो कर्जे में थे जो कि उपरोक्त रकम थी। बैनामे का रु.13400/- श्री जुगल किशोर बिड़ला जी ने दिया था।

सन 1946 में मालवीय जी का स्वर्गवास हुआ और *मुस्लिम पक्ष ने 1946 में उपरोक्त सेल डीड या बैनामे की वैधता को चुनौती देते हुए मथुरा कोर्ट में वाद दायर किया कि, राय किशनदास को अधिकार ही नहीं है कि वो रजिस्ट्री कर सकें, लिहाजा, उपरोक्त 1944

की रजिस्ट्री को खारिज किया जाय। कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया और रजिस्ट्री को सही करार दिया। इस हार के बाद मुस्लिम पक्ष कहीं अपील में नहीं गया।

चूंकि,मालवीय जी ने अपने इच्छा पत्रों में उपरोक्त जमीन पर मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की थी। लिहाजा, 21.02.1951 को 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट' बनाया गया और 13.37 एकड़ जमीन को ट्रस्ट में समाहित कर दिया गया। ट्रस्ट का प्रथम लक्ष्य था उपरोक्त भूमि पर दिव्य व भव्य श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण।

अब खेल शुरू हुआ कांग्रेस का। इस समय नेहरू व उनके चमचे जो चाहते वही होता। 1958 आते आते इन चमचों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को निष्क्रिय कर अपना कब्जा जमा लिया।

सन 1958 में इन चमचों ने एक सोसायटी बनाया जिसका नाम था 'श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ'। इसके कर्ता धर्ता थे श्री एम.अनंतशयम अयंगर(बिहार के राज्यपाल रहे) व श्री द्वारका प्रसाद मिश्र (मप्र के मुख्यमंत्री रहे)।

सन 1964 में इस नकली सेवा संघ ने जन्मभूमि से मुस्लिमों को निष्कासित करने हेतु दावा डाला, जबकि न जमीन इनकी न इनका कोई लेना देना।

12.10.1968 को इस फर्जी संस्थान ने आकाओं की मर्जी से ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह से समझौता किया। उसमें लिखा कि 'श्रीकृष्ण जन्म सेवा संघ अर्थात श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट' मुस्लिमों द्वारा कब्जा की गई जमीन पर अपना दावा छोड़ रहा है। 'ये अपने प्रकार का अनूठा जमीन घोटाला था।' जमीन तीसरे की मालिक बन बैठे आप और दूसरे को बिना किसी मालिकाना हक के कब्जा दे दिया। आज भी उपरोक्त जमीन ट्रस्ट की है ना कि फर्जी सेवा संघ या ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की। तो इस प्रकार हिन्दू समाज को इन कांग्रेसियों कितना ठगा व छला यह सप्रमाण है। इनसे घृणा होती है।

साधुवाद है अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी व उनके पुत्र अधिवक्ता विष्णु जैन जी का जिन्होंने कांग्रेसियों, वामपंथियों व लिबरल गैंग द्वारा फैलाये व रचे षड्यंत्र को ध्वस्त कर प्रभु श्रीकृष्ण जन्मस्थली के पुनः निर्माण की ओर हिन्दू समाज को अग्रसर कर दिया है। अब तो इरफान हबीब जैसे इतिहासकार ने भी कह दिया है कि, काशी व मथुरा के मंदिरों का विध्वंस औरंगजेब ने ही किया था। आज अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की त्वरित कार्यवाही जारी है।

कांग्रेसियों ने 'विश्व का सबसे बड़ा कानून घोटाला' करते हुए 'पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम,1991' संसद से पारित किया क्योंकि कांग्रेसियों, वामपंथियों व गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापने वाले हिन्दुओं, परजीवी बुद्धिजीवियों को भान हो चुका था कि हिन्दू मानेंगे नहीं अयोध्या लेकर ही रहेंगे और उनका दुःस्वप्न 6 दिसंबर 1992 को सच हुआ जब बाबरी विध्वंस हुआ। तो ये कानून तो बनाया लेकिन रामजन्मभूमि को अपवाद मान कर इस कानून के दायरे में नहीं रखा।

21वीं सदी के पूर्वार्ध में ही वो सभी हिन्दू मंदिर व स्मारक मलेच्छओं से मुक्त हो जाएंगे जिनको मुस्लिम लुटेरों ने लूटा व उनको ध्वंस कर उनपर मस्जिद बनाया तथा यहां पुनः भव्य मंदिर बनेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। भारतवर्ष अगले 1 दशक के अंदर सर्वग्राही हिन्दू राष्ट्र घोषित हो जाएगा ऐसा मेरा अनुमान है।

नोट- उपरोक्त सभी तथ्य सप्रमाण उपलब्ध हैं तथा माननीय मथुरा अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं।

- संतोष पांडे, एडवोकेट

भी भारत के उस बदले परिदृश्य का उद्धारण है जिसे 2014 के बाद से वातावरण में महसूस किया जाने लगा है।

भले ही भारत 1947 में भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ हो किन्तु भारत के हिन्दू बहुसंख्यकों ने भारत को पंथ निरपेक्ष लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाने पर पूरा जोर दिया। एक विविधतापूर्ण एवं उदार समाज बनाने के भर्तियों के इस प्रयास को न वामपंथी विचारधारा से मान्यता मिली न ही कांग्रेस से। चर्च हिंदुओं को जातियों में विभक्त दिखाकर अपना व्यापारिक और धार्मिक खेल भी खेलती रही। फिल्म और फिल्म से जुड़े लोगों का इसमे उपयोग होता रहा। फिल्मों में दलित उत्पीड़न और हिन्दू परम्पराओं का मखौल उड़ाया गया जिसे आम भारतीय जन मानस उस समय नहीं समझ पाता था। कांग्रेस ने उस समय अन्य धर्मों की निंदा योग्य मान्यताओं पर भी अपनी आंखें बंद रखी और हिन्दू धर्मों से जुड़ी परम्पराओं का मखौल उड़ाया गया। यह तभी दिख गया था जब नेहरू अपने कार्यकाल में हिन्दू कोड बिल को बढ़ाने के इच्छुक और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऐसे ही सुधारों को आगे बढ़ाने के अनिच्छुक दिखे। यह समस्या का वह आरंभिक बिन्दु था जो आज बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया है। यही कारण है आज बहुत से लोग, फिल्मी कलाकार 1947 को नहीं 2014 को आजादी का वर्ष बताने लगे हैं।

चिंतन करें मुसलमान

● **अभिरंजन कुमार**

मेरे प्यारे मुसलमान भाइयो-बहनो, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या यह कलंकित ढांचा एक मस्जिद है? न्याय के तकाजे से बोलिए, क्या यह एक मस्जिद है? क्या कोई समझदार, बुद्धिमान, विवेकशील, न्यायप्रिय, सत्याग्रही व्यक्ति कह सकता है ऐसा?

यदि नहीं, तो इसे बचाने की लड़ाई लड़कर आप स्वयं अपनी स्थिति को कमजोर करते जा रहे हैं। इसके लिए न तो भाजपा जिम्मेदार है, न आरएसएस, न देश के आम हिन्दू। यहां साफ दिखता है कि इस ढांचे को एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर खड़ा किया गया है।

यह उदार और सहिष्णु हिंदुओं का भारत ही है, जहां इस कलंकित ढांचे के नीचे साफ-साफ एक मंदिर के दिखाई देते हुए भी इतनी तरह की जांचें, सर्वेक्षण और खाना-पूर्तियां की जा रही हैं। वरना यह ढांचा मंदिर तोड़कर बनाया गया था ङ्क यह साबित करने के लिए क्या वास्तव में किसी जांच की जरूरत है भी?

मैं तो यहां तक कहता हूं कि मान लीजिए कि इस ढांचे के अंदर कुछ न भी मिले, तो क्या यह ढांचा मस्जिद हो जाएगा? जब बाहर से यह मंदिर के ऊपर बना दिखाई दे रहा है, तो कोई भारी मूर्ख या महादुष्ट ही तो कह सकता है कि यह अंदर से भी मंदिर पर ही नहीं बना है!

इसलिए सच को स्वीकार कीजिए। हम आपसे कुछ छीनने

कुतुबमीनार भी गई...

लो जी मित्रो, अब ASI कुतुबमीनार का भी सर्वे करेगा, केन्द्र सरकार की कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसे हरी झंडी दे दिया है।

केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग को निर्देश दिया है की कुतुबमीनार के साठथ और मस्जिद से 15 मीटर दूरी पर खुदाई का काम शुरू होगा। इसके साथ साथ अनंगताल और लालकोट किले पर भी खुदाई का काम होगा। अब वामपंथी लिब्राइुओं की दिन का चैन और रात की नींद हराम होने वाली है। अब मोदीजी पूरे देश में विवादित स्थलों की जांच कराकर खुदवा के ही मानेंगे।

चलिए अब पूरा माजरे को समझते हैं....

दिल्ली में स्थित कुतुबमीनार को लेकर कई दशकों से चली आ रही सच्चाई का पता लगाने की मांग अब मान ली गई है! कुतुबमीनार के इतिहास का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने परिसर की खुदाई और वहां स्थित मूर्तियों की Iconography कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर अधिकारियों ने परिसर का दौरा किया। खुदाई के बाद इसकी रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को सौंपी जाएगी।

ASI के अधिकारियों का कहना है कि कुतुबमीनार में साल 1991 के बाद से और खुदाई नहीं हुई है।

इसके अलावा कई रिसर्च भी पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है।

कुतुबमीनार के अलावा अनंगताल और लाल कोट किले में भी खुदाई होगी। माना जा रहा है कि कुतुबमीनार के दक्षिण में स्थित और मस्जिद से 15 मीटर की दूर खुदाई का काम किया जाएगा! इसकी खुदाई के निर्णय से पहले संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने 12 लोगों की टीम के साथ परिसर का दौरा कर निरीक्षण किया! इस टीम में ASI के चार अधिकारी, 3 इतिहासकार और शोधकर्ता भी थे। सचिव द्वारा निरीक्षण करने के बाद खुदाई का फैसला लिया गया है।

कुतुबमीनार के परिसर में स्थित विवादित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर लगी हिंदू मूर्तियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी देने के लिए नोटिस बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस स्थल पर पहले क्या था और उसका प्रयोग किस काम के लिए होता था? इस मस्जिद के परिसर में एक लौह स्तंभ भी है जो चौथी शताब्दी का है और इसे विष्णु स्तंभ कहा जाता है। लोहे के इस स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगा है!? इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी चकित हैं। इस स्तंभ को लेकर मान्यता है कि यदि इसे बांहों में भर कुछ मांगी जाए, तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हालांकि अब यहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं है! कुतुबमीनार को लेकर, ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने कहा था कि ये कुतुबमीनार सूर्य स्तंभ नामक एक वेधशाला है। उन्होंने ने बताया कि इसे इस्लामी आक्रांता कुतुबद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि उसके आने से 700 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था व इसे विष्णुपद पहाड़ी पर बनाया गया है और इसलिए इसे झुकाया गया है कि सूर्य का अध्ययन किया जा सके।

शर्मा जी ने दावा किया था कि कुतुबमीनार को लेकर अभी शोध जारी है और इसके पूरा होने पर चौंकाने वाले नतीजे आएंगे ! उनका कहना है कि यह पूरा परिसर एक हिन्दू आर्किटेक्चर है, और इसमें से एक भी चीज इस्लामिक नहीं है। इस्लामिक शासकों ने पत्थरों को रीयूज करके महिमामंडन के लिए अपना नाम चिपका दिया था।

बता दूं कि, हाल ही में कुतुबमीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के रूप में जाने वाले इस विवादित ढांचे के एक खंभे में एक प्राचीन मूर्ति की पहचान हुई है! इसे वर्षों से पहचानने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन पुरातत्वविद धर्मवीर शर्मा जी ने इसकी पहचान नरसिंह भगवान और उनके भक्त प्रह्लाद की मूर्ति के रूप में की है।

ASI के क्षेत्रीय निदेशक रहे धर्मवीर शर्मा का दावा है कि यह मूर्ति आठवीं-नौवीं सदी में प्रतिहार राजाओं के काल की है। सालों से इसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही थी और काफी प्रयासों के बाद इसको पुरातत्वविद ने इस मूर्ति की पहचान कर ली है! कहा जा रहा है कि यह मूर्ति 1200 साल पुरानी है और ये प्रतिहार राजाओं या राजा अनंगपाल के समय की है। प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज सबसे प्रतापी राजा हुए हैं। इस मूर्ति की तस्वीरें देश भर के विशेषज्ञ पुरातत्वविदों को विशेष अध्ययन के लिए भेजी गई हैं। उनका कहना है कि यह नरसिंह भगवान की दुर्लभ मूर्ति है, किसी और जगह इस तरह की मूर्ति नहीं मिलती है।

इसपर सर्वे कराने की आदेश मिलने के बाद म्लेच्छो और वामपंथियों के बीच हाहाकार मचना तो लाजमी है।

- शनीस अघोर

की बात नहीं कर रहे। यह मंदिर जो तोड़ा गया था, वह जितना हमारा था, उतना ही आपका भी था! हमारे पूर्वजों की तरह आपके पूर्वज भी इसमें पूजा करते थे। इसलिए हमसे और आपसे दोनों से हमारे पूजा-स्थल को तब छीना गया था, जब इस मंदिर को तोड़ा गया था।

जरा सोचिए तो सही कि जो विदेशी लुटेरे और हमलावर चुन-चुन कर हिन्दू धर्मस्थलों को तोड़ रहे थे, उन्होंने आपके पूर्वजों को क्या पुचकार कर और टॉफियां चुसवा कर धर्मांतरित कराया होगा? क्या यह संभव है?

इसलिए आप जिस मजहब को अपने माथे की टोपी बनाए घूम रहे हैं, सच्चाई यह है कि वह आपका मजहब है ही नहीं। आपका मजहब भी वही है, जो हमारा है। आपके पूजा स्थल भी वही हैं, जो हमारे हैं। आपकी संस्कृति भी वही है, जो हमारी है। आपका देश भी वही है, जो हमारा है। आप भी हमारे ही हैं। हम भी आप ही

के हैं।

इसलिए लुटेरों और हमलावरों के मजहब को अपना मजहब कहने से पहले इस ढांचे और देश भर में फैले इस जैसे अनेक ढांचों को देखिए और खुद ही खुद से सवाल कीजिए कि इन मंदिरों को इस तरह से तोड़ने वालों ने आपके पूर्वजों को कितना तोड़ा होगा। तन से, मन से, धन से, संपत्ति से, जो वे मुसलमान बनने को मजबूर हुए होंगे!

इसलिए अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए आप लोगों को स्वयं आकर कहना चाहिए कि यह कोई मस्जिद नहीं, बल्कि हमारे आराध्य देव शिव का मंदिर है और हम लोग कोई मुसलमान नहीं, बल्कि हिन्दू ही हैं, जिनके पूर्वजों को विदेशी लुटेरों और हमलावरों ने जबरन मुसलमान बना लिया था।

यह नैरेटिव कितना शरारतपूर्ण है कि हिंदू समाज में फैली अस्पृश्यता के कारण आपके पूर्वज मुसलमान बने। यदि ऐसा होता तो

1. हिंदुओं की केवल कथित अस्पृश्य जातियां ही मुसलमान बनी होतीं। राजपूतों सहित बड़ी संख्या में ऊंची जातियों के लोग भी कैसे मुसलमान बन गए?
2. भारत के सारे दलित-पिछड़े लोग मुसलमान क्यों नहीं बन गए? ऐसा तो नहीं था कि जो दलित-पिछड़े मुसलमान बने, केवल वही अस्पृश्य थे और जो नहीं बने, वे अस्पृश्य नहीं थे।
3. जब मुगलों का शासन कमजोर पड़ गया और उनकी जगह अंग्रेजी राज कायम हो गया, तब हिन्दू से मुस्लिम धर्मान्तरण लगभग बंद कैसे हो गया? अगर अस्पृश्यता के कारण ही कुछ हिंदू जातियां मुसलमान बन रही थीं, तब तो धर्मान्तरण की यह प्रक्रिया आजादी के कई दशक बाद तक जारी रहनी चाहिए थी न!

इसलिए मुसलमान भाइयो-बहनो, सत्य को समझिए। आप लोगों को लगातार बरगलाया जा रहा है। कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के लिए आप इंसान नहीं, वोट बैंक हैं; और कुछ के लिए महज मजहबी लड़ाके। वे अपने फायदे के लिए आपको भीड़ की तरह इस्तेमाल करते हैं, डराकर रखते हैं, लगातार असुरक्षित वातावरण में धकेले रखना चाहते हैं।

इसलिए आज बहुत साफ दिल से आप लोगों से यह अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपनी मुक्ति और अपने पीड़ित पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए ईस देश पर आक्रमण करने वाले लुटेरों और हमलावरों के मजहब से मुक्ति पाइए, घर वापस लौटिए, और यहां पर स्वयं भगवान महादेव के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कीजिए।

ऐसा करके यहां जो मंदिर बनेगा, केवल उसमें ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया के तमाम मंदिरों में आप भी हमारे साथ पूजा कीजिए। हम आपसे कुछ छीनने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे जितना ही आपका भी है और जो इतिहास के एक बुरे दौर में आपसे छिन गया था, उसे ही आपको वापस लौटाने की बात कर रहे हैं।

एक बात याद रखिए। कोर्ट के जरिए तो हिंदुओं ने अयोध्या भी ले ली। एक न एक दिन काशी और मथुरा भी प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन अपने पूर्वजों के हत्यारों, बलात्कारियों और धर्मान्तरण कराने वाले लुटेरे और हमलावरों के पाप से आपको कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी।

इसी पाप से मुक्त नहीं हो पाने के कारण अलग देश हासिल करके भी पाकिस्तान और बांग्लादेश आज नर्क बने हुए हैं। जरा सोचिए कि आज यदि वे भारत का हिस्सा होते, तो भी क्या वे ऐसी ही बदहाली भोग रहे होते? और यही पाप है, जिसकी सजा भुगतते हुए आप लोग भी भारत में पिछड़ी बदहाल जिंदगी जी रहे हैं।

इसलिए, आज एक बेहद कड़वी हकीकत आपको बता रहा हूं, जो इतनी सादगी और साफगोई से कोई भी कभी भी नहीं बताएगा। जब तक आप अयोध्या, काशी, मथुरा समेत भारतीय तीर्थस्थलों को छोड़कर मक्का-मदीने में अपने आराध्य को ढूंढते फिरेंगे, तब तक आप इस देश की मिट्टी, मूल संस्कृति और मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएंगे।

और जब तक आप इस देश की मिट्टी, मूल संस्कृति और मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस संविधान और कथित धर्मनिरपेक्षता के तमाम वादों और दावों के होते हुए भी आप दोयम दर्जे के नागरिक ही बने रहेंगे। तब तक हर कोई आपको डराएगा, कट्टरपंथी और आतंकवादी कहेगा, आपसे नफरत करेगा।

लेकिन जैसे ही आप वापस अपनी संस्कृति और परंपरा में लौट आएंगे, वैसे ही आप तमाम तरह के डर, भय, अलगाव, भेदभाव से मुक्त हो जाएंगे। फिर न आप पर कोई खतरा रहेगा, न आपके मजहब पर कोई खतरा रहेगा। जैसे आज एक आम हिंदू गौरव से इस देश को अपना कहता है और हक जताता है, आप भी वैसे ही गौरव और अधिकार महसूस करने लगेंगे।

इसलिए मैं तो आज आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि इतिहास के इन सबूतों को देखिए, सच्चाई को समझिए और लौट आइए वापस... अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति, अपने ही समाज में। बहुत से लोग आपसे नफरत करते हैं। मैं प्यार करता हूं। मेरा दिल साफ है। इसलिए कह रहा हूं।

वह इतिहास का एक बुरा अध्याय था, जब आप जैसे कुछ लोगों के पूर्वज हमलावरों का शिकार बन गए और हम जैसे कुछ लोगों के पूर्वज बचे रह गए। अब वह दौर बीत चुका है। न कोई डर है, न कोई खतरा है, न कोई दबाव है।

इसलिए आइए, हम सभी एक ही धारा... इस देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर मिल-जुल कर तरक्की करें और विश्व में मानवता का परचम लहराएं।

मुसलमानों के अलगाव के लिए कुछ औरंगजेब-छाप नेता ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज और हमारे कुछ कथित राष्ट्र निर्माता भी रहे हैं जिम्मेदार!

मुसलमान भाइयों बहनों के नाम चिट्ठी से आगे...

ओवैसी बंधु वोटों के लिए इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि अपने पूर्वजों के सम्मान, स्वाभिमान, तन, मन, धन, धर्म और आत्मा को रौंदने वाले पापी को अपना पापा बनाने के लिए भी तैयार हैं। औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए कलंकित ढांचों को मस्जिद कहना और इन्हीं विवादों के बीच जाकर औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकना इस बात का सबूत है।

ऐसे आत्महीन लोग भारत में केवल औरंगजेब-छाप गुलाम मुसलमानों के ही प्रतिनिधि हो सकते हैं, भारत के आम मुसलमान इन्हें घास भी नहीं डालेंगे। इसीलिए पूरे देश में इनकी पार्टी के केवल 2 सांसद (लोकसभा और राज्यसभा के 788 सांसदों में से) और 16 विधायक (4036 विधायकों/विधान पार्षदों में से) हैं।

यह अलग बात है कि बिना किसी जनाधार वाले इस औरंगजेब-छाप को भारतीय मीडिया ने अपना दामाद बना रखा है और जबरन इसे आम

कण कण में है जिनकी महिमा

डॉ कामिनी वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर

तन को विभिन्न प्रकार के रंगों से सराबोर करके, मन मे नवजीवन सा उल्लास जगाता , समाज मे समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करके बुराई पर अच्छाई की और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देकर होली पर्व के जाते ही कानो में माता के जयकारे गूंजने की आहट सुनाई देने लगती है । नवरात्र के 9 दिनों में घण्टों और घड़ियालों के नाद से देश का कोना कोना घनघना उठता है । ऐसे श्रद्धामय परिवेश में मन में अकुलाहट हो रही है मां के दिव्य दर्शन और विराट स्वरूप से भिज्ञ होने की। देश भर में जिनके आयतन, आस्था और श्रद्धा का केन्द्र हुआ करते है ।

मन की इस अकुलाहट को दूर करने के लिए पुरातात्विक और आभिलेखिक साक्ष्यों पर दृष्टि डालने पर ज्ञात हुआ कि हिन्दू धर्म मे देवी की उपासना प्रागेतिहासिक युग से ही हो रही है। सैन्धवकाल में शक्ति सम्पन्न मातृदेवी की आराधना के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते है।

वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधानता की ओर अग्रसर होने लगा। यद्दपि इंद्र वरुण, रुद्र आदि देव प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित हो गए तथापि ऋग्वेद में उषा, अदिति और वाग्देवी की स्तुति के प्रमाण मिलते है व वाग्देवी का ओजस्वी रूप भी प्रदर्शित होता है। ब्राह्मण ग्रंथो पर दृष्टिपात करने पर शतपथ ब्राह्मण में `अम्बिका' नाम की देवी का रुद्र की बहन तथा तैत्तरीय आरण्यक में रूद्र की पत्नी पार्वती के रूप में उल्लेख है।

महाकाव्य काल मे देवी का पूर्ण रूप से शक्तिसंपन्न रूप प्रतिष्ठित है। महाभारत में अर्जुन तो रामायण में राम युद्ध में विजय प्राप्ति की आकांक्षा से इनकी उपासना करते दिखाई पड़ते है । मन की इस अकुलाहट को दूर करने के लिए पुरातात्विक और आभिलेखिक साक्ष्यों पर दृष्टि डालने पर ज्ञात हुआ कि हिन्दू धर्म मे देवी की उपासना प्रागेतिहासिक युग से ही हो रही है। सैन्धवकाल में शक्ति सम्पन्न मातृदेवी की आराधना के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते है।

वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधानता की ओर अग्रसर होने लगा। यद्दपि इंद्र वरुण , रुद्र आदि देव प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित हो गए तथापि ऋग्वेद में उषा, अदिति और वाग्देवी की स्तुति के प्रमाण मिलते है व वाग्देवी का ओजस्वी रूप भी प्रदर्शित होता है। ब्राह्मण ग्रंथो पर दृष्टिपात करने पर शतपथ ब्राह्मण में `अम्बिका' नाम की देवी का रुद्र की बहन तथा तैत्तरीय आरण्यक में रूद्र की पत्नी पार्वती के रूप में उल्लेख है।

महाकाव्य काल मे देवी का पूर्ण रूप से शक्तिसंपन्न रूप प्रतिष्ठित है। महाभारत में अर्जुन तो रामायण में राम युद्ध में विजय प्राप्ति की आकांक्षा से इनकी उपासना करते दिखाई पड़ते है । महाभारत में इसी संदर्भ में उल्लिखित है प्रातःकाल शक्ति का स्त्रोत का पाठ करने वाला युद्ध क्षेत्र में विजयी होता है तथा एकांतिक रूप से लक्ष्मी को प्राप्त करता है । वर्तमान में इनकी उपासना शिव की पत्नी शिवा पार्वती, उमा गिरिजा के रूप में होने के साथ साथ वह स्वतन्त्र रूप से भी पूजित हैं। यह शिव की शक्ति, भक्तों की रक्षिका तथा शत्रुओं की विनाशिका है।शिव की सहचरी के रूप में इनका सौम्य रूप तथा दुर्गा के रूप में यह उग्र रूप में पूजित हैं, इनकी चरण धूल को लेकर ब्रह्मा विश्व का सृजन, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते है। कामप्रधान रूप में वह `त्रिपुर सुंदरी' की संज्ञा में विभूषित है और अलौकिक सौंदर्य शालिनी है।

भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर दिन-रात पेश करता रहता है, ताकि आम भारतीय मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और उनके प्रति हिंदुओं की नफरत को बढ़ावा दिया जा सके।

लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आम भारतीय मुसलमान इस औरंगजेब-छाप के साथ नहीं, बल्कि हमारी मुसलमान भाइयों बहनों के नाम चिट्ठी में की गई अपील के साथ हैं और वापस इस देश की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समस्याएं केवल मुसलमान भाइयों-बहनों में ही नहीं, अन्य कई स्तरों पर भी हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं।

1. समाज में ऐसे न्यायप्रिय और सत्याग्रही लोगों की बहुत कमी है, जो किसी भी समस्या को तटस्थ रहकर सुलझाने के प्रयास कर सकें।
2. किसी भी मुद्दे को स्वयं ठीक से समझते हुए सामने वाले को ठीक से समझाने वाले धैर्यवान, सहिष्णु और समझदार लोग भी आज कितने हैं?
3. राज करने के लिए राजनीति का जोर एकता की बजाय फूट डालने के सिद्धांत पर अधिक रहता है।
4. ज़्यादातर हिन्दू संगठन भी अपनी ऊर्जा मुसलमान भाइयों-बहनों की आलोचना करते रहने में ही खपाते हैं। नफरत की बातें जरूरत से ज़्यादा हो रही हैं, प्यार की बातें जरूरत से काफी कम।
5. मुसलमान भाइयों-बहनों को वापस मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक लाने के लिए हिन्दू समाज, संगठन, नेता, बुद्धिजीवी क्या प्रयास कर रहे हैं?
6. गरीब-अशिक्षित हिंदुओं का धर्मान्तरण कराने के लिए चर्च और मस्जिदों की आलोचना करने वाले हिन्दू मठाधीश बताएं कि इस धर्मान्तरण को रोकने और धर्मांतरित पीड़ितों को

वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हिन्दू मंदिर, मठ, साधु, महात्मा, संत, संन्यासी क्या कर रहे हैं?

मैं इस बात पर कायम हूं कि आज हमारे जो भाई-बहन हमारी मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इतिहास के एक अंधेरे कालखंड में विदेशी लुटेरों, हमलावरों, हत्यारों, बलात्कारियों ने तलवार के जोर से उन्हें मजबूर कर दिया हमसे अलग होने के लिए। कुछ लोग तो हमारे समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत जैसी कुरीतियों के कारण भी हमसे अलग हो गए।

भारत के आजाद होते ही इन सबकी सम्मानजनक वापसी का रास्ता बनाना हमारा ही दायित्व था, लेकिन यह रास्ता बनाने की बजाय पिछले 75 साल हम इनसे नफरत करने और गालियां देने में बर्बाद कर चुके हैं।

हमारे कुछ कथित महान नेताओं ने भी भारत की आजादी को केवल एक भूखंड को आजाद कराए जाने की संकीर्ण सोच तक ही सीमित रखा। नागरिकों को बुद्धि, चेतना और सोच की गुलामी से आजाद कराए जाने के लिए कोई पहल नहीं की गई।

विभाजन और आजादी के समय जो मुगल-पीड़ित मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उनका हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो 3.5 करोड़ (1951 की जनगणना के अनुसार) पीड़ित आबादी भारत में रह गई, उसके कल्याण और मुक्ति की कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई? यह जानते हुए भी कि यह वह हिंदू आबादी है, जो पहले आक्रांताओं से पीड़ित रही और बाद में छुआछूत का शिकार हो गई, उसे हिंदुओं से अलग मानकर हमारी नफरत, गरीबी और अशिक्षा का शिकार होने के लिए क्यों छोड़ दिया गया?

आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश को चला रहे कुछ अदूरदर्शी और विदेशी संस्कृति से प्रभावित नेताओं ने समस्या को लगातार विकराल होने दिया। उन्हीं के कारण आज दुनिया का वह भूभाग भी कट्टरता और आतंकवाद का डेरा बनता जा रहा है, जहां से पूरे विश्व को 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिन:' की संकल्पना दी गई थी।

भारत वह अभागा देश है, आजादी के साथ ही जिसका न केवल धर्म के नाम पर बंटवारा स्वीकार किया गया, बल्कि सत्ता के लिए समाज में जातिवाद की जड़ें और भी गहरी कर दी गईं। कर्म-आधारित 4 वर्णों की आलोचना करने वालों ने देश को जन्म-आधारित लगभग 4 हजार जातियों के चंगुल में फंसा दिया। अंग्रेजों ने तो जो किया, सो किया, इस काम में हमारे कुछ संविधान निर्माताओं का रोल भी अत्यंत अदूरदर्शिता-पूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण रहा।

हमारे कुछ संविधान निर्माता इस बात को भांप नहीं पाए कि सांप्रदायिकता और जातिवाद को मिटाने की व्यवस्था करने की बजाय वे जिस तरह से इसे पुख्ता करने की व्यवस्था किये जा रहे हैं, उससे यह देश और इस देश के नागरिक लगातार पीड़ित रहेंगे और उनकी समस्याओं का कभी अंत नहीं हो सकेगा। ऊपर से इसी कारण से इसपर और भी कई विखंडनों का खतरा मंडराता रहेगा।

स्पष्ट है कि आजादी के समय से आज तक राजनीति कभी इतनी सक्षम नहीं हो सकी कि वह भारत और इसके नागरिकों के लिए स्थायी रूप से न्याय, मुक्ति और विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसलिए इस देश में राजनीति से इतर अब एक ऐसे सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से समाज को तोड़ने की बजाय जोड़ने पर काम हो। और जोड़ने का यह काम निश्चित रूप से मुसलमान भाइयों-बहनों को छोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें भी जोड़कर ही हो।

जो लोग इन विचारों के साथ हैं, उनसे अपील है कि इन्हें असंभव मानकर चुपचाप बैठ न जाएं, बल्कि अपने-अपने स्तर से प्रयास करना शुरू करें। यह कोई दो-चार दिन या दो-चार साल का काम नहीं, बल्कि कई दशकों का काम है। इसमें यदि हमारा-आपका जीवन खप भी जाए, तो कोई बात नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला होना चाहिए। धन्यवाद।

भारत में हिंदू मुस्लिम समस्या के समाधान के लिए अभिरंजन कुमार के विचार

काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन से जुड़े सभी तपस्वियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। इस मौके पर सभी भाइयों-बहनों से मेरी 3 अपीलें हैं-

1. स्पष्ट रूप से मंदिर तोड़कर बनाए गए इस कलंकित ढांचे को भूल से भी मस्जिद न कहें, 'कलंकित ढांचा' ही कहें। जो सत्य है, उसे किसी भी संकोच का शिकार मत बनाइए। अब तो माननीय न्यायालय के आदेश पर कराए गए सर्वेक्षण में शिवलिंग मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है।

2. ओवैसी बंधु औरंगजेब-छाप उन्मादी मुसलमान हैं। उन्हें आम भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने की भूल न करें। भारतीय मीडिया पर दबाव बनाएं कि वह ओवैसी बंधुओं को अपना दामाद मानना बंद करें। यह केवल मेरी अपील से नहीं होगा। आप सभी के दबाव की जरूरत होगी। भारतीय मीडिया को इन उन्मादी औरंगजेब-छाप बंधुओं का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए।

3. भारत में हिंदू-मुस्लिम समस्या के समाधान के लिए मेरे विचार बेहद स्पष्ट हैं, इसलिए मेरी अलग-अलग टिप्पणियों और लेखों को अलग-अलग न देखकर समग्रता में देखें। बहुत सोच-समझकर ही हमने यह नीति बनाई है-

- सभी घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए। यदि भारत सरकार हफ्ष्ट लाएगी, तो मैं उसका पूर्ण समर्थन करूंगा। चाहता हूं कि CAA को लागू करने में भी अब वह और देर न करे।
- सभी औरंगजेब-छाप उन्मादियों, अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ पूर्ण सख्ती बरती जाए। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति।
- मुगल-पीड़ित आम मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक-सांस्कृतिक अभियानों की शुरुआत की जाए।
- सभी वर्गों और समुदायों पर एक जैसी जनसंख्या नीति लागू की जाए। देश के किसी भी हिस्से की जनसांख्यिकी बिगड़ने न दी जाए।

मुस्लिम भाइयो-बहनों की मुक्ति अब सुनिश्चित लग रही!

मुस्लिम भाइयों-बहनों को मेरा शत शत प्रणाम। उन्होंने बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपने ऊपर मुगलों के अत्याचार का गिन-गिन कर बदला लेने की ठानी है। उन्हें पता है कि हिंदू एक सहिष्णु समुदाय है। इतना सहिष्णु कि कायरता की हद तक पहुंच जाता है। इसे ललकारे बिना जगाया नहीं जा सकता। इसके देवी-देवता तक बिना ललकार के नहीं जागते थे।

भगवान श्रीराम की करबद्ध प्रार्थना को

विनीत
नारायण

मंदिरों पर मस्जिदें क्यों खड़ी रहें ?

क्या भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में एक भी मंदिर ऐसा है जो किसी मस्जिद को ध्वस्त करके बना हो ? अगर है तो ये बात मुसलमान समाज सामने लाये, हिंदू उस मंदिर को वहां से हटाने को सहर्ष राजी हो जाएंगे। जबकि देश में लगभग 5000 मस्जिदें ऐसी हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके भग्नावेशों के उपर बनाई गयी हैं।

1990 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में एक व्याख्यान देने मैं गया तो वहां के लोग मुझे शर्की वंश के नवाबों की बनवायी इमारतें दिखाने ले गये। जिनमें से एक मशहूर इमारत का नाम था अटाला देवी की मस्जिद। नाम में ही विरोधाभास स्पष्ट था। देवी की मस्जिद कैसे हो सकती है ?

जो धर्मनिरपेक्षतावादी ये कहते आये हैं कि इतिहास को भूल जाओ आगे की बात करो उनसे मैंने अपने इसी साप्ताहिक कॉलम में पिछले दशकों में बार-बार ये कहा है कि ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। हम ब्रजवासी हैं और बचपन से श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ईदगाह की इमारत खड़ी देखकर हमें वो खौफनाक मंजर याद आ जाता है, जब किसी धर्मांध आततायी मुसलमान आक्रामक ने वहां खड़े विशाल केशवदेव मंदिर को ध्वस्त करके ये इमारत तामीर की थी। हर बार हमारे सीने में यही जख्म दुबारा हरा हो जाता है।

यही बात उन 5000 मस्जिदों पर भी लागू होती है जो कभी ऐसे ही आक्रांताओं द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनायी गयी थीं। इनमें से हरेक मंदिर से उस नगर के भक्तों की आस्था सदियों से जुड़ी है। फिर वो चाहे विदिशा, मध्यप्रदेश में मंदिरों को तोड़कर बनाई गयी बिजमंडल मस्जिद हो, रुद्र महालय को तोड़कर बनाई पाटन गुजरात की मस्जिद हो, भोजशाला परिसर में सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाई गयी मस्जिद हो, या बंगाल में आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गयी मदीना मस्जिद हो। जिसे आज भारत की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान राम की विशाल मूर्ति दबी पड़ी है। जिस पर चलकर नमाजी जाते हैं।

मेरे पुराने पत्रकार मित्र व भाजपा के दो बार सांसद रहे बलबीर पुंज जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लाहौर गये थे तो एक प्रसिद्ध होटल में खाना खाने गये। जहां जगह-जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के सिर पर गड्ढे बनाकर उनमें मेहमानों द्वारा सिगरेट की राख झाड़ने का काम लिया जा रहा था। ऐसे अपमान को देखकर कौन और कैसे अपने अतीत को भूल सकता है ?

ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991' की याद दिलायी जा रही है। ये ऐक्ट अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद बनाया गया था ताकि आगे किसी और मस्जिद को लेकर ऐसा विवाद खड़ा ना हो। पर क्या इस क़ानून को बनाने से वो सब जख्म भर गए जो सदियों से हर शहर के हिंदू अपने सीने में छिपाए बैठे हैं ? जिन शहरों में उनकी आस्था, संस्कृति, ज्ञान और भक्ति के केंद्रों को ध्वस्त करके उन पर ये मस्जिदें बना दी गयीं थीं ? न भरे हैं न कभी भरेंगे। बल्कि हर दिन और ताजा होते रहे हैं। आप हमारी पिटाई करो और उसकी फोटो खींच कर रख लो। फिर रोजवो फोटो हमें दिखाओ और कहो कि भूल जाओ तुम्हारी कभी पिटाई हुई थी। तो क्या हम भूल पाएंगे ?

धर्मनिरपेक्षवादी, साम्यवादी और मुसलमान, भाजपा व आरएसएस पर ये आरोप लगाते हैं कि ये दल और संगठन हिंदुओं की भावना भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते आए हैं। उनका ये आरोप भी है कि भाजपा की मौजूदा सरकारें रोज बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर से ध्यान बटाने के लिये ऐसे मुद्दे उछलवाती रहती हैं। उनके इस आरोप में दम है। पर क्या इस आरोप को लगाकर वो पाप धुल जाता है जो इन मस्जिदों को देखकर रोज आम हिंदू को याद आता रहा है और वो लगातार अपमानित महसूस करता आया है ? नहीं धुलता।

इसीलिये आज हिंदू समाज योगी और मोदी के पीछे खड़ा हो गया है, इस उम्मीद में कि ये ऐसे मजबूत नेता हैं जो सदियों पहले खोया उनका सम्मान वापिस दिला रहे हैं। पर इसमें भी एक पेच है। भाजपा के राज में भी जहां कहीं भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की तरह आधुनिकीकरण के नाम पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, उससे वहां के स्थानीय हिंदुओं को वही पीड़ा हुई है जो सदियों पहले मुसलमानों के हमलों से होती थी। इसी तरह भाजपा शासन में मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित पौराणिक संकर्षण कुंड व रुद्र कुंड का अकारण विध्वंस 2018 में घोटालेबाजों के इशारे पर हुआ। उससे भी सभी ब्रजवासियों को भारी पीड़ा हुई है। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि योगी राज में हिंदू धर्म व

संस्कृति पर ऐसा वीभत्स हमला क्यों किया गया ?

यहां भाजपा व संघ के लिए एक सलाह है। अगर वे केवल मंदिर-मस्जिद और मुसलमान के मुद्दे में ही उलझे रहे और आम जनता की आर्थिक परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया तो यहां भी श्रीलंका जैसे हालात कभी भी पैदा हो सकते हैं। खासकर तब जन मुफ़्त का राशन मिलना बंद हो जाएगा।

प्रेस का गला दबाकर, इन सवालों को उठाने वालों को अपनी ट्रोल आर्मी से देशद्रोही या वामपंथी कहलवाकर, उन पर एफआईआर दर्ज करवाकर आप कुछ समय के लिए तो आम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, पर लम्बे समय तक नहीं। वो तो कोई मजबूत और विश्वसनीय विकल्प अभी खड़ा नहीं है वरना इन भीषण समस्याओं के चलते अब तक विपक्ष हावी हो जाता। जैसा कई राज्यों में हुआ भी है। इसलिये कोई मुग़ालते में न रहे। अगर भरे पेट वाले हिंदुओं के लिये मंदिर-मस्जिद का सवाल जरूरी है तो खाली पेट वाले करोड़ों हिंदुओं के लिये मंहगायी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का सवाल उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इनका समाधान नहीं मिलने पर यही लोग आक्रोश में सड़कों पर भी उतरते हैं और पुलिस की लाठी-गोली झेलकर भी वहां डटे रहते हैं। इनके ही सैलाब से सरकारें क्षणों में अर्श से फर्श पर आ जाती हैं। इसलिए उन सवालों पर भी ईमानदारी से खुलकर बात होनी चाहिये। जिस उत्साह से मंदिर-मस्जिद की बात आज की जा रही है।

जहां तक भाजपा व आरएसएस की मंदिर राजनीति का प्रश्न है, जिसे लेकर धर्मनिरपेक्ष दल आए दिन उनके ख़िलाफ बयान देते हैं, तो इसका सरल हल है। हर वो मस्जिद जो कभी भी हिंदुओं के मंदिर तोड़कर बनायी गयी थी उसे खुद-ब-खुद मुसलमान समाज आगे बढ़कर हिंदुओं को सौंप दें। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वैसे भी खाड़ी के देशों की आर्थिक मदद से पिछले 30 वर्षों में देश भर में एक से बढ़कर एक भव्य मस्जिदें खड़ी हो चुकी हैं, जिनसे हिंदुओं को कोई गुरेज नहीं है। तो फिर हिंदुओं के इन प्राचीन पूजास्थलों पर बनी मस्जिदों को लेकर इतना दुराग्रह क्यों ?

समुद्र ने जब तीन दिनों तक अनसुना किया, तब जाकर उन्हें गुस्सा आया। हनुमान जी को उनकी शक्ति का अहसास दिलाने के लिए जामवंत जी को क्या-क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े। भगवान श्रीकृष्ण ने तो जन्म ही तब लिया, जब कंस ने उनके 7 भाइयों-बहनों को मार डाला। इसके बाद भी शिशुपाल की 100 गलतियां उन्होंने बर्दाश्त कीं और तब जाकर सुदर्शन चक्र चलाया। स्वयं भगवान शिव तो अपनी तीसरी आंख ज़्यादातर बंद ही रखते थे। जब परिस्थितियां बिल्कुल असहनीय हो जातीं, हर तरफ हाहाकार मच जाता, तीनों लोकों में त्राहिमाम की स्थिति बन जाती, तब जाकर धीरे से वे अपनी तीसरी आंख खोलते थे।

सो मुस्लिम भाइयों-बहनों ने समझ लिया कि हिंदू तो अयोध्या, काशी, मथुरा लेकर मान जाएंगे। लेकिन अत्याचार तो हमारे पूर्वजों ने सहा है। जाति हमारी गयी। धर्म हमारा गया। सम्मान हमारा गया। स्वाभिमान हमारा गया। हत्याएं हमारे पूर्वजों की हुईं। बलात्कार हमारी माताओं का हुआ। हम कैसे छोड़ देंगे उन पापियों को? गिन-गिन कर बदला लेंगे। एक-एक मंदिर को मुगलों के अतिक्रमण से खाली कराएंगे। विध्वंस और अतिक्रमण केवल अयोध्या, मथुरा, काशी में ही थोड़े हुआ? हिन्दू तो छोड़ देंगे, हम क्यों छोड़ें? पीड़ित तो हम हैं!

इसीलिए वे कायरता की हद तक सहिष्णु और सुषुप्त हिन्दू समुदाय को ललकार रहे हैं, जगा रहे हैं। उसे अहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे भीतर भी तो एक हनुमान जी बैठे हैं। तुम भी तो शिव के ही अंश हो। तुम भी तो राम-कृष्ण के ही वंशज हो। हमें मुक्ति दिलाना तुम्हारा धर्म है। आक्रांताओं के मजहब में हमारा दम घुट रहा है। पहले हमारे सारे पूजा-स्थलों को मुक्ति दिलाओ। फिर हमें भी मुक्ति दिलाओ। वापस हमें हमारे मूल धर्म में शामिल करो। हमें अछूत मत समझो। हमें म्लेच्छ मत समझो। हम तुम्हारे ही हैं। तुम हमारे ही हो।

इसीलिए ये सब जो बातें की जा रही हैं न कि शिवलिंग मिल गया तो क्या हुआ, हम तो वजू करते रहेंगे, इत्यादि, उसके पीछे मंशा केवल इतनी है कि हिंदुओं को जगाना है। जागो। नहीं जागोगे तो पहले हमारे सम्मान-स्वाभिमान को कुचला गया। अब आंच तुम तक भी पहुंचेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यदि इसकी परवाह तुम न भी करो, तो कश्मीर में, बंगाल में, असम में, केरल में क्या-क्या तमाशे हुए हैं और हो रहे हैं, यह तो देखो।

दरअसल ईश्वरीय लीला होती ही ऐसी है कि जो भिन्न-भिन्न राक्षस होते हैं, वे भी ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई मति से ही संचालित हो रहे होते हैं। ईश्वरीय लीला की हर स्क्रिप्ट में अंत में सत्य, न्याय और मानवता की जीत सुनिश्चित होती है। वह तो बस दर्शकों के रोमांच के लिए बीच-बीच में वे थोड़ी मार-धाड़-एक्शन-प्यार-मोहब्बत भी डाल दिया करते हैं।

तो ईश्वर की यह वाली स्क्रिप्ट भी ऐसी ही है। अंत में मुस्लिम भाइयों-बहनों को भी इसी मुख्य धारा में आना है, जिससे मध्ययुगीन/मुगलिया आक्रमण के कारण आत्मरक्षा के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ा। वे भी हिंदू ही थे, हिन्दू ही हैं, हिन्दू ही रहेंगे। ओवैसी वगैरह भी हमें इसी तरफ ले जाने के लिए बस कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में रोमांच हाई होना चाहिए, सो है।

ईश्वर के एक बार पलक झपकने में भी मनुष्य की सदियां बीत जाती हैं। इसीलिए यह फिल्म थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन सब कुछ तय स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रहा है। एक-एक दृश्य अपने तय समय पर ही आ रहा है।

विधाता ने जो लिख दिया, उसे कौन बदल सकता है? इसलिए पहले मैंने कहा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा पर विराम दीजिए, लेकिन अब विधाता की इस स्क्रिप्ट को समझकर अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद भी जो-जो जैसे-जैसे होता रहेगा, उसे देखने का फैसला किया है। बढ़िया सीन आएगा, तो ताली भी पीटूंगा। कोई दृश्य मन के अनुकूल नहीं लगेगा तो यह भी कहूंगा कि इस फिल्म में इस दृश्य की क्या जरूरत थी! लेकिन इतना समझ आ गया है कि यह एक आवश्यक फिल्म है और हमारे मुसलमान भाइयों-बहनों की इच्छा के अनुसार उनकी मुक्ति और कल्याण के लिए ही चल रही है। हिंदुओं को तो बस अपने धर्म/कर्तव्य का पालन करना है और मुगलिया कैद में सदियों से छटपटा रहे अपने मुस्लिम भाइयों-बहनों को मुक्त कराना है।

जय हो प्रभु! तुम्हारी महिमा अपरंपार है!
मेरा भी समर्पण स्वीकार करो!

स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका पर हुआ अमृत मंथन

● महिमा सिंह

स्वास्थ्य के क्षेत्र में एडवोकेसी का काम कर रही संस्था स्वस्थ भारत (न्यास) के सातवेंस्थापना दिवस पर आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य अमृत मंथन शिविर का आयोजन मेवाड़ इंस्टीट्यूट, गाजियाबाद में किया गया। 'स्वस्थ भारत के निर्माण में भारतीय स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका विशेष संदर्भ कोविड-काल' विषय परविभिन्न हितधारकों ने अपने विचार रखे।

दो दिवसीय स्वास्थ्य अमृत मंथन शिविर में स्वस्थ भारत के निर्माण में जन औषधि, पोषण, आयुष्मान भारत, मीडिया, आयुष, गांधी विचार और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर गंभीरविचार मंथन हुआ। इस अवसर पर जहां देश के तीन बड़े स्वास्थ्य संस्थानों को 'सुशीला नायर स्वस्थ भारत उत्कृष्टता सम्मान' से सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर संस्था के चेयरमैन आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में देश भर में 42000 किमी कीस्वस्थ भारत यात्रा कर स्वास्थ्य का अलख जगाने में सहयात्री रहे 11 यात्रियों को स्वस्थ भारत यात्री सम्मान से सम्मानित किया गया। देश भर में स्वस्थ भारत के विचारों को आगे बढ़ाने वाले 26 स्वयंसेवकों को'स्वस्थ भारत सारथी' सम्मान दिया गया। यह सम्मान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉ. जे.एल.मीणा, लोकसभा टीवी की पूर्व सीइओ सीमा गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ हास्य कवि शंभू शिखर और स्वास्थ्य पत्रकार धनंजयकुमार के कर कमलों से प्रदान किया गया।

उद्घाटन सत्र में अपने अध्यक्षीय संबोधन मेंआध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा ने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि, 'मानव मन अगर स्वस्थ है तो मनुष्य अपने आप खुश रहता है। इंसान मन से परेशान हैं तो फिर शारीरिक स्वास्थ्यखराब हो जाएगा और जीवन में निराशा का वास होगा।'भारतीय स्वास्थ्य

7वां स्थापना दिवस
MEWAR INSTITUTE

MEWA

पारिस्थिकी तंत्र में जनऔषधि की भूमिका विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के सीइओ रवि दाधीच ने कहा कि,'जनऔषधि ने देश के गरीब जनता को सस्ती और गुणवत्तायुक्त दवाइयों का विकल्प दिया है। देश के 750 जिलों में कम से कम एक जनऔषधि की दुकान है। जनऔषधि कोई आयुर्वेद की दवा नहीं है, बल्कि यह भी एलोपैथिक दवा ही है।' आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को क्रियान्वित करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉ. जे.एल.मीणा ने कहा कि, 'गुणवत्ता का विषय मन से जुड़ा हुआ है। यदि सभी लोग अपने-अपने मन में अपने काम में गुणवत्ता लाने को ठान लें, तभी सही अर्थों में धरातल पर गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा उतारा जा सकता है।'

मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉ. अशोक गदिया ने कहा कि, 'स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत काम करने की जरूरत है। जिस तरह मेवाड़ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसी तरह स्वस्थ भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।'

मानसिक स्वास्थ्य एवं समाधान विषय पर बोलते हुए ब्रेन बिहैवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन डॉ. मीना मिश्रा ने कहा कि, 'जीवन में खुशी के लिए दोस्त का होना बहुत जरूरी है जिससे आदमी अपनी बात आसानी से बता सके।'इसी सत्र में अपने अध्यक्षीय संबोधन में सिंपैथी के निदेशक डॉ. आर.कांत ने बताया कि, 'इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए 'इज' यानी सहज रहने की जरूरत है।'

पोषण विषयक सत्र में मुख्य वक्तव्य देते हुए पब्लिक हेल्थ एवं न्यूट्रीशन एक्सपर्ट डॉ. अनन्या अवस्थी ने बताया कि, 'भारत में मिड डे मील और सखी, आंगनवाड़ी आदि ऐसी व्यवस्था है जो गरीब और कुपोषण परिवार और बच्चों को पोषण और संतुलित अहार के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ही काम कर रही हैं। अमेरिका में हुए एक रिसर्च में बताया गया है कि रागी, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज में गेहू से अधिक पोषण है। 1980 के दशक तक यह मोटा अनाज हमारे यहां गरीब का भोजन होता था बाद में उन्होंने भी इसे खाना छोड़ दिया। आजकल इसी को सुपर फूड कहा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें चक्की से पिसा कर खाया जाए।'

मीडिया सत्र की अध्यक्षता करते हुए एनयूजेआई के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकारमनोज मिश्र ने कहा कि, 'कई बार हम अपनी खबरों में

स्वास्थ्य अमृत मंथन सार-01

भारतीय खुश रहना भूल रहे हैं : आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा

स्वस्थ भारत (न्यास) के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर न्यास ने दो दिवसीय स्वास्थ्य अमृत मंथन शिविर का आयोजन मेवाड़ इंस्टिट्यूट, गाजियाबाद में किया। उद्घाटन सत्र में पावन चिंतन धारा के प्रणेता एवं आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा ने शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि, 'अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मानव मन अगर स्वस्थ है तो मनुष्य अपने आप खुश रहता है। अच्छा जीवन जीता है। यदि इंसान मन से परेशान हैं तो फिर शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और जीवन में निराशा का वास होगा। मानसिक बीमारी जैसे अवसाद और तनाव से कई शारीरिक बीमारियों का जन्म होता है जैसे दमा, स्पेनडोलेटिस, कमर दर्द, नसों की समस्या। इस तरह की शारीरिक व्याधी का कारण मानसिक सेहत का बिगड़ना ही है।'

उन्होंने आगे कहा कि, 'अगर मानसिक समस्या से निजाद पाना है तो नृत्य, संगीत, और वादन का सहारा लेना चाहिए। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। उन्होंने आगे कहाकि, 'आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मानसिक स्वास्थ्य कि बात की जाए तो हर 6 वां युवा भारतीय मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सभी को मानसिक स्वास्थ्य की समझ होना जरूरी है। भारत हैपीनेश इंडेक्स में 136वें पड़ाव पर है। इसका मतलब यह हुआ कि हम भारतीय खुश रहना भूलते जा रहे हैं। हमें खुश रहना और जीवन को आनंद में जीना नहीं आता है। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करके हम स्वास्थ्य के जंग में उत्तम हो सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, 'कोविड 19 के काल में यह मानसिक समस्या अधिक बड़ी है। शहर और गांव हर जगह लोग शारीरिक स्वास्थ्य को ही ढंग से नहीं समझते तब वो मानसिक बीमारी को कैसे समझेंगे। लोगों को शरीर और मन के मध्य संतुलन बनाना सिखना होगा। यह काफी मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा कि गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं होते हैं। वो शरीर की बीमारी को नजरअंदाज करते हैं ऐसे

में उन्हें नहीं दिखने वाली मानसिक बीमारी के बारे में समझाना काफी मुश्किल होगा लेकिन अगर अभी पहल नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत (न्यास) ने जेनेरिक मेडिसन को जनता तक पहुंचाने का जो पहल किया है वह सराहनीय है। इस पहल की सुरक्षा के लिए सरकार को लोकपाल निरीक्षण जैसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो निर्धारित करे कि सरकार की कोशिश जनता को फायदा पहुंचा रही है।

श्री सिन्हा ने कहा कि स्वस्थ भारत का लक्ष्य काफी बड़ा है इसे धैर्य के साथ जनता तक पहुंचाना होगा। अभी तक जो भी किया गया है उससे जनता जागरूक हुई है। लेकिन अभी यह यात्रा चलती रहनी चाहिए।

उद्घाटन सत्र का शुभारंभ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डीन प्रो. (डॉ.) महेश व्यास, मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉ. अशोक गदिया, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी एवं ट्रस्ट के संस्थापक श्री आशुतोष कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने किया।

उद्घाटन सत्र में अरविंद कुमार सिंह (वरिष्ठ पत्रकार) ने स्वस्थ भारत (न्यास) के स्थापना के विचार उसके द्वारा किये गए यात्राओं और कार्यो तथा 7 वर्ष के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और पहलुओं से अवगत कराया। वहीं पंकज चतुर्वेदी, अमरनाथ झा, ऋतेश पाठक आदि ने संस्था के कार्यों को रेखांकित करते हुए आने वाले दिनों में स्वस्थ भारत के निर्माण में क्या किया जाना चाहिए इस विषय पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार केशव कुमा ने किया जबकि स्वागत उद्बोधन संस्था के चेयरमैन आशुतोष कुमार सिंह ने किया।

समाज का बहुत नुक्सान कर देते हैं। पत्रकारों को इस बात को समझने की जरूरत है कि वे पत्रकारिता किसके लिए कर रहे हैं।'

दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने कहा कि,'स्वास्थ्य के क्षेत्र में मीडियासमाज की अपेक्षाओं पर खड़ीनहीं उतर पाई है। आज का मीडिया दादी-नानी के नुस्खो को अवैज्ञानिक कह कर खारिज कर देता है, जबकि रस्किन बॉड ने 'रिटर्न टू नेचर' पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को रेखांकित किया है। गांधी जी को लोग सिर्फ आंदोलनकारी के रूप में ज्यादा जान पाए हैं जबकि वे एक कुशल स्वास्थ्य चिंतक एवं पत्रकार थे। कोविड के दौरान स्वास्थ्य पत्रकारिता की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी लेकिन उसी दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे गैर-जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता का स्वरूप उभर कर सामने आया।'

आईआईएमसी में ऊर्दू पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रमोद सैनी ने कहा कि, 'स्वास्थ्य पत्रकारिता में समाधानपरक पत्रकारिता की जरूरत है। भारतीय संस्कृति में इलाज के साथ-साथ बीमारियों को रोकने वाली पद्धति पहले से ही उपलब्ध है यानी कि संपूर्ण आरोग्य की अवधारणा हमारी संस्कृति का स्वास्थ्यगत विरासत है।'

वरिष्ठ स्वास्थ्य पत्रकार धनन्जय कुमार ने कहा कि, 'मीडिया आकर्षक शीर्षक के चक्कर में भ्रामक पत्रकारिता कर बैठता है।' उन्होंने स्वस्थ भारत (न्यास) को सुझाव देते हुए कहा कि अब जरूरत इस बात कि है कि न्यास 'ड्रग लेस भारत' के लिए काम करे और अभियान चलाए ताकि किसी को दवा खाने की जरूरत ही न पड़े।

गैरसरकारी संगठनों की भूमिका विषय पर नोएडा लोकमंच के अध्यक्ष महेश सक्सेना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने में गैर-सरकारी संगठनों की अहम भूमिका रही है। इस सत्र में डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। सुलभ इंटरनेशनल की ओर से पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र सुलभ के कार्यों का विवरण डॉ. नमिता माथूर ने प्रस्तुत किया।

वहीं शम्भू शिखर और दीपक सैनीका हास्य, प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा तिवारी, क्लासिकल गायिका सुमिता दत्ता, उभरती हुई युवा गायिका अनुश्री की गायकी और अदिति के भरतनाट्यम की प्रस्तुति ने इस आयोजन को उत्सवी बना दिया।

इसके पूर्व उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती को माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अनु श्री और उनके साथियों ने गणेश व सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरूवात की। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह ने संस्था के 7 वर्षों की विकास-यात्रा को रेखांकित किया जबकि वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी, अमरनाथ झा, ऋतेश पाठक, डॉ. शशांक द्विवेदी ने संस्था के विजन-मिशन के बारे में बताते हुए आगे की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डिजिटल चित्र प्रदर्शनी के आयोजन के साथ-साथ मेवाड़ इंस्टीट्यूट के छात्रों के बीच पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

स्वस्थ भारत (न्यास) के इस आयोजन को मेवाड़ यूनीवार्सिटी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, कॉसमोस अस्पताल, अग्रवाल होमियो, इंडिया राइज, मस्कट हेल्थकेयर, हिलिंग सब लाइन, मौलिक भारत सहित तमाम संस्थानों का सहयोग मिला। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संस्था के चेयरमैन आशुतोष कुमार सिंह और धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. मनीष ने किया। विभिन्न सत्रों में मंच संचालन की जिम्मेदारी केशव कुमार, संजीव कुमार, महिमा सिंह, संदीप पांडेय, अनिल गोयल,अनुज अग्रवाल, डॉ. शशांक द्विवेदी एवं डॉ. प्रियंका द्विवेदी जैसे देश के जाने-माने पत्रकारों ने किया।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ) महेश व्यास, (डीन, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान), डॉ पंकज अग्रवाल, वरिष्ठ होमियोपैथिक चिकित्सक, श्री आशीष गौतम, (अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन), श्रीमती अलका अग्रवाल, (निदेशक मेवाड़ इंस्टिट्यूट), श्री कुमार कृष्णन, (वरिष्ठ गांधीवादी चिंतक), डॉ. बीएस गर्ग, (सचिव कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी), दीदी ज्ञानेश्वरी एवं डॉ अखिलेश गुमास्ता, (विराट होस्पिस,जबलपुर) और बोन मैरो विसेषज्ञ डॉ. विवेक अग्रवाल आदि की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान किया।

गौरतलब है कि स्वस्थ भारत (न्यास) अपने स्थापना काल से ही भारत में स्वास्थ्य जागरूकता का ध्वज वाहक बना हुआ है। देश के आम जन को स्वास्थ्य के प्रतिजागरूक करने के लिए विविध प्रकार के आयोजन संस्था करती रही है। संस्था का नाम उसके नायाब कार्यों के लिए यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। ■

स्वास्थ्य अमृत मंथन सार-02

30 फीसद वार्षिक बढ़ोत्तरी के साथ खुल रहे हैं जनऔषधि केन्द्र

'जनऔषधि ने देश के गरीब जनता को सस्ती और गुणवत्तायुक्त दवाइयों का विकल्प दिया है। देश के 750 जिलों में कम से कम एक जन औषधि की दुकान है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि जन औषधि आयुर्वेद की दवा नहीं है। यह एलोपैथिक दवा ही है। बस इसकी कीमत कंम होती है। यह सस्ती होती है लेकिन उतनी ही फायदे वाली है जितनी इसकी महंगी वर्जन वाली दवा होती है। यह भी शोध और मानवीय टेस्ट में सफल होने के बाद जारी होती है। बस सरकार और निर्माता इसका दाम कम रखते हैं क्योंकि यह जनता के भले के लिए बनाई जाती है। 350 जनऔषधि केंद्र सिर्फ दिल्ली में हैं।' उक्त बातें प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि दाधीच ने स्वस्थ भारत (न्यास) द्वारा आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य अमृत मंथन शिविर में मुख्य वक्तव्य देते हुए कही।

उन्होंने आगे बताया कि, 'जन औषधि की भंडारण व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि, लोगों तक सस्ती दवाइयां समय तक पहुंच सके इसके लिए चार वेयर हाउस बनाएं गए हैं। दिल्ली, गुडगांव, सूरत और गुहाटी। 38 के करीब जिला स्तर पर डिस्ट्रीबूयटर हैं जो नजदीकी जन औषधि केंद्र पर दवा को पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर सजग है। इसलिए हर साल 1000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। यह योजना प्रति वर्ष 30 प्रतिशत बढ़ रही है।'

सेवा और रोजगार के मूल मंत्र को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि, 'जो व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलता है उसे सरकार 15000 रुपये तक का प्रतिमाह इंसेटिव देती है। 3 साल तक सरकार दुकानदार को सहयोग करती है 5 लाख तक अनुदान दिया जाता है।'

'महिला स्वास्थ्य को बेहतर करने में जनऔषधि की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि,महिलाओं के लिए महामारी संदर्भित स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रख कर 1 रुपये में पैड तैयार किया गया है। 10 रुपये का एक पैक मिलता है। अब तक 23 करोड़ पैक बनाकर मार्केट में बेचा गया है। यह पैड पर्यावरण में खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इनसे प्रदूषण नहीं फैलता है। ये बायोग्रेडिबल पैड हैं।'

जनऔषधि केन्द्र तक पहुंचने के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि, जनऔषधि के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने सुगम एप लॉन्च किया है। जिसकी मदद से आम जनता अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्र तक जा सकती है। दवा जिसकी जरूरत है उसको भी एप पर सर्च किया जा सकता है।'

स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में जनऔषधि की भूमिका पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉ अशोक गदिया ने कहा कि, 'जनऔषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि, 'हमारे प्रधानमंत्री भी स्वास्थ्य और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि भावी युवा पीढ़ी में जो अभी डॉक्टरी पढ़ रहे बच्चे हैं उनके ऊपर अभी कोई व्यवसायिक दबाव नहीं उनका मन अभी साफ पाक है। उन्हें जन औषधि से परिचित कराया जाए और उनको शपथ दिलाया जाए जैसा डॉक्टर लेते हैं। सेवा के लिए वैसे ही उन्हें अपने मरीजों को जन औषधि देने के लिए प्रेरित किया जाए।'

स्वस्थ भारत न्यास के सातवेंस्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य अमृत मंथन शिविर में इस सत्र का संचालन मेवाड़ यूनिवर्सिटी के निदेशक श्री शशांक द्विवेदी ने किया। ■

स्वास्थ्य अमृत मंथन सार-03

माँ, बहन और पत्नी की मानसिक सेहत का ध्यान रखना घर के पुरुषों की जिम्मेदारी है : डॉ. मीना मिश्रा

मानसिक डिसऑडर से पीड़ित व्यक्ति में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे यह पता ही नहीं चलता है कि वो इससे पीडित है लेकिन समय रहते अगर इसे डाईगनोस कर लिया जाये तो इस समस्या से असानी से पार पाया जा सकता है।

स्वस्थ भारत के निर्माण में मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां और समाधान विषय पर मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए ब्रेन बिहैवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन डॉ. मीना मिश्रा ने कहा कि यदि हम स्वयं में कुछ विशेष लक्षण जैसे अगर हमको टीवी देखना पसंद है और अचानक उसे देखना बंद कर दें, खेलना पसंद है और खेलने का मन नहीं हो रहा है या पढ़ना पसंद है लेकिन पुस्तकों की ओर देखना की इच्छा भी नहीं हो रही है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमें तनाव घेर रहा है या हम अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम अपनी बातें अपने किसी खास विश्वास पात्र दोस्त, रिश्तेदार या निकट संबंधी से साझा करें या अपने को किसी अपनी मनपंसद हॉबी संगीत, नृत्य या लेखन में व्यस्त करें ऐसा करने से हम अपनी उलझन का हल पा सकते हैं और तनाव से निकल सकते हैं। ऐसा करने में एक से चार हफ्ते का समय लग सकता है।

दो दिवसीय स्वास्थ्य अमृत मंथन शिविर में डॉ. मीना मिश्रा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यदि कभी कोई मानसिक तनाव और अवसाद हो तो मनोवैज्ञानिक के पास अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि, 'कोरोना काल में हमने रिश्तों और परिवार के महत्व को देखा समझा और हम सभी को दोस्तों रिश्तेदारों की अहमियत समझ में आई।

डॉ. मीना मिश्रा ने शिविर में, 'घरेलू महिलाओं में तनाव और अवसाद' विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि घरेलू महिलाएं अपनी बात किसी से कह नहीं पाती इसलिए उनका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। वो शरीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखती हैं। पूरा परिवार उनके ऊपर निर्भर होता है। उनको भी दोस्त और अपनेपन की जरूरत होती है। मां, बहन और पत्नी की मानसिक सेहत का ध्यान रखना घर के पुरुषों की जिम्मेदारी है।

इसी सत्र की अध्यक्षता कर रहे सिंपैथी के निदेशक डॉक्टर आर.कान्त ने कहा कि, मानसिक तनाव और अवसाद से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इज यानि चैन से जीवन जीये। दिखावे और स्टैटस के चक्कर में न फंसे। कोई आपको सम्मान दे तो भी खुश न दे तो भी खुश रहें। खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें।' इस सत्र का संचालन वरिष्ठ लेखक व पत्रकार अनिल गोयल ने किया। ■

स्वास्थ्य अमृत मंथन सार-04

पोषित बच्चों और स्वस्थ माँ से ही होगा स्वस्थ भारत का निर्माण : डॉ. अनन्या अवस्थी

'सरकार की ओर से मां और बच्चों के पोषण पर कई योजनाएं लायी गयी है। भारत में मिड डे मील और सखी, आंगनवाडी सहित तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो गरीब और कुपोषण परिवार और बच्चों को पोषण और संतुलित अहार के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ही हैं। अमेरिका में हुए एक रिसर्च में यह पाया गया है कि रागी, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज में गेहूं से अधिक पोषण होता है। 1980 के दशक तक यह मोटा अनाज हमारे यहां गरीबों का भोजन होता था, फिर उन्होंने भी इसे खाना छोड़ दिया। आजकल इन्हीं मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सुपर फूड कहा जा रहा है।' उक्त बातें हावर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ी पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. अनन्या अवस्थी ने स्वस्थ भारत (न्यास) द्वारा आयोजित स्वास्थ्य अमृत मंथन शिविर में स्वस्थ भारत के निर्माण में पोषण का महत्व विषय पर बोलते हुए कही।

डॉ अवस्थी ने घर में काम करने वाली एक सहायिका का उदाहरण देते हुए कहा कि, वो अपने बच्चे को चिप्स के पैकेट खिलाने को तैयार है लेकिन फल और पोषण वाला अनाज उसे महंगा लगता है। यह सच भी है आंकड़ों के नजरिए से। लेकिन 5 रुपये के 4 पैक चिप्स और 20 रुपये के केले देने में क्या बेहतर है यह उन्होंने उसे समझाया। पोषण पैकेट वाले फूड में नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया की यहां मदद काफी अहम है जिससे मां और उनके बच्चों को पोषित भोजन और संतुलित थाली के बारे में समझाया जा सकता है। भारत में निचला तबका जिसके पास भोजन के लिए पैसे कम है उनकी सोच को भी बाजार के बड़े ब्रांड का प्रचार प्रभावित करता है। जबकि उनके लिए सरकार ने सखी और आंगनवाड़ी वाटिका का भी इंतजाम किया है, जहां से फल और सब्जी इनको और बच्चों को दिया जाए जिससे उनका शरीर का पोषण हो। बस ये वर्ग इन योजनाओं से परिचित नहीं है। भोजन की जरूरत घर से पूरी होती है इसमें मां के साथ पिता की जिम्मेदारी भी बनती है ताकि बच्चा कुपोषित न हो।

उन्होंने आगे कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अगर भोजन के कारण बीमार होगी तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण अधूरा रहेगा। सखी और आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब परिवार की मां और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए बहुत सी योजना इंतजार कर रही। यहां बच्चों का अन्नप्रासन संस्कार भी कराया जाता है। 2 से 6 साल तक के बच्चों को उचित पोषण मिलना आवश्यक है। इसपर सरकार बहुत काम कर रही है। स्वस्थ भारत का निर्माण पोषित बच्चों और स्वस्थ मां से ही होगा।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में मेवाड़ इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉ. अल्का अग्रवाल ने डॉ. अनन्या अवस्थी के बताए सुझाओं को अमल में लाने पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में हम पोषणयुक्त भोजन पर कम ध्यान दे रहे हैं यहीं कारण है कि तमाम तरह की बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे शरीर को जकड़ रही हैं। इस सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार महिमा सिंह ने किया।

स्वास्थ्य अमृत मंथन सार-05

आयुर्वेदग्राम की अवधारणा पर सरकार कर रही है काम : प्रो. (डॉ) महेश व्यास

स्वस्थ भारत (न्यास) द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डीन प्रो. (डॉ) महेश व्यास ने कहा कि,आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा ग्रंथ ही नहीं अपितु स्वयं में एक सम्पूर्ण जीवन शास्त्र हैं। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण हैं, जो आज के स्वास्थ्य तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने AYUSH Health&Wellness Centre के बारे में बताते हुए कहा कि, आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National HealthMission) की तर्ज पर राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSHMission) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2019 से चरणबद्ध तरीके से आयुष्मान भारत योजना के तहत लक्षित कुल स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) का 10 प्रतिशत,जिनकी संख्या 12,500 है। इसे प्राप्त करने का लक्ष्य 2023-24 रखा गया है। आयुष HWC ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित आयुष HWC मुख्य रूप से आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, जो स्वस्थ आहार, योग और जीवन शैली में संशोधन जैसे निवारक और प्रोत्साहन उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आयुर्वेदग्राम की अवधारणा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा किइस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के प्रत्येक ग्राम को आयुर्वेद ग्राम घोषित कर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य तंत्र को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

आयुष दीप समिति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम जिला स्तर पर आयुष की सुविधाओं को सुनिश्चित करता हैं। आयुष के क्षेत्र में सरकार द्वारा कुए जा रहे कार्यों के बारे रेखांकित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि, इसके अलावा जन जागरण विकास समिति बनाई गई है इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणी या जिन्हें 'Traditional healer'भी कहा जाता हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता हैं।

स्वस्थ भारत के निर्माण में आयुष की भूमिका विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखते हुए वरिष्ठ होमियोपैथिक चिकित्सक डॉ. पंकज अग्रवाल ने कहा कि, 'आयुष विभिन्न बीमारियों के उपचार प्रणालियों का एक गुच्छा है। आधुनिक वैज्ञानिक मापदण्डों के कारण अब तक जानबूझकर इसकी उपेक्षा की जाती रही है। लेकिन यह कठिन समय की कसौटी पर खरा उतरा है और यह भी सत्य है की यह प्राचीन काल से मौजूद है। क्या आपको नहीं लगता कि इसको दबा कर रखने के पीछेकोई साजिश है?'

उन्होंने आगे कहा कि,आयुष प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान मानकों पर आंकना अंग्रेजी व्याकरण के साथ संस्कृत सीखने जैसा है। आयुष को अपने स्वयं के विशेष अनुसंधान प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। क्या हम इस पर काम कर रहे हैं? शायद नहीं! इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है।

आयुष प्राथमिक स्तर पर ही बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है, इसलिए इसे बिना किसी देरी के पीएचसी (PHCs) में पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी प्रणालियों को 'डाउन मार्केट सिस्टम' के रूप में देखना गलत अवधारणा है और हर एक को इसके प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। मेरी आशा यही है कि आयुष घर-घर में इलाज करने की पहली पंक्ति में शामिल होगा। ■

इस अवसर पर स्वस्थ भारत (न्यास) की ओर से आयोजित स्वस्थ भारत यात्रा में शामिल रहे यात्रियों को स्वस्थ भारत यात्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जिनके नाम हैं-

1. श्री प्रसून लतांत, दिल्ली
2. डॉ. सोम शेखर, उत्तराखंड
3. श्री कुमार कृष्णन, बिहार
4. श्रीमती प्रियंका, बिहार
5. श्री संतोष कुमार सिंह, दिल्ली
6. श्री संभू कुमार, झारखंड
7. श्री विनोद रोहिल्ला, हरियाणा
8. श्री पवन कुमार,हरियाणा
9. श्री धर्मेन्द्र उपाध्याय, बिहार
10. श्री विवेक कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश
11. श्री आशुतोष कुमार सिंह, बिहार
12. स्व. अशोक प्रियदर्शी (मरणोपरांत), दिल्ली

साथ ही स्वस्थ भारत के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर के 26 स्वास्थ्य-सेवकों को स्वस्थ भारत सारथी सम्मान भी दिया जाएगा। उनके नाम निम्नवत है:

1. श्री देबाशीष मजूमदार, त्रिपुरा
2. श्री केशव आचार्य,चेन्नई
3. श्रीमती अल्का अग्रवाल सिगतिया, मुंबई
4. श्री विनित कुमार ज्ञा, जबलपुर
5. श्री पंकज पाठक, रांची
6. श्री संदीप पांडेय, पटना
7. श्री अभिषेक कुमार (दिल्ली)
8. डॉ. एन.के.आनंद, बिहार
9. डॉ. गणेश राख, पुणे
10. श्री बी.एन.शिन्दे, कर्नाटक
11. श्री अतुल मोहन सिंह, लखनऊ
12. श्री सरोज सुमन, मुंबई
13. श्री अमित त्यागी, उत्तर प्रदेश
14. श्री देवेन्द्र माधोपुर, राजस्थान
15. श्री सचिन अरोड़ा, कपूरथला, पंजाब
16. श्री अमित कुमार, दिल्ली
17. श्री शिवकरण मील, राजस्थान
18. श्री रिजवान रज़ा, दिल्ली
19. श्री नलिनी रंजन, दिल्ली
20. डॉ. विवेक अग्रवाल, कोलकाता
21. श्री मणिशंकर, दिल्ली
22. श्री समर मंडलोई, इंदौर
23. श्री संजीव कुमार, दिल्ली
24. श्री संजय बेंगाणी, गुजरात
25. पंचदेव शुक्ल (दिल्ली)
26 पुष्कर शर्मा (नोएडा, यूपी)

स्वास्थ्य अमृत मंथन सार-06

स्वस्थ भारत के निर्माण में गैर-सरकारी संगठन निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका

स्वास्थ्य भारत निर्माण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका विषय पर बोलते हुए नोएडा लोकमंच के अध्यक्ष महेश सक्सेना ने कहा कि, मेरे आदर्श विवेकानंद और मालवीय जी है। सेवा कार्य जो समाज के लिए किया जाता है उसे गैर-सरकारी संगठन करते हैं। मैंने शिक्षा के लिए काम किया है। COVID-19 काल में हमने लोगों को दवा, भोजन , शिक्षा सब कुछ दिया। हमने अपने संगठन में तीन नियम बनाया जो आज भी है। राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। भवन नहीं बनाएंगे। सरकारी और कंपनी की सहायता नहीं लेंगे। 24 साल से लोग हमें मदद कर रहे समाज, अपनी मदद खुद कर रहा है। नेपाल का भूकंप हो, कोई राष्ट्रीय आपदा हो, हम वहां जाते है सेवा करते है। ईश्वर हमारी मदद करता है। केवल एलोपैथी नहीं सभी अन्य चिकित्सा विधि को मौका देना चाहिए। डाक्टर ध्यान नहीं देते एक केमिकल जो किसी बीमारी का इलाज है, वही शरीर के अन्य अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद और अन्य को जीवन का हिसा बनाया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य में सामजिक संगठनों का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि समाज का कार्य गैर-सरकारी संगठन बखूबी निभा रहे हैं।

इस सत्र में सुलभ इंटरनेशनल कीमानद उपाध्यक्षडॉ. नमिता माथुर, ने सुलभ इंटरनेशनल द्वारा COVID-19 में दी गई सुविधा और अपने संगठन द्वारा स्वच्छ भारत की मुहिम को सफल बनाए के लिए किए प्रयास की चर्चा की। सुलभ इंटरनेशनल ने COVID-19 समाधान के लिए covid रिलीफ हब बनाया। कार्यशाला से लोगों को बताया कि हाथ धोना कैसे लाभदायक है। वृंदावन में असहाय महिलाओ के लिए इलाज और उतम जीवन की व्यवस्था की। इस अवसर पर प्रेषित अपने वीडियो संदेश में सुलभ इंटरनेशन के संस्थापक डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने कहा कि गांधी जी ने हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने आत्मसात किया और इसे एक आंदोलन बना दिया। उन्होंने स्वस्थ और स्वच्छ भरत का सपना देखा। जिसे पूरा करने में हम सब गैर सरकारी संस्था लगे हैं। मोदी जी ने महिलाओ और बच्चियों की सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए शौचालय की व्यवस्था पर जोर दिया। उनके आह्वान के बाद सारे स्कूल औए कॉलेज में शौचालय बने। गांव-गांव में मुफ्त में शौचालयों का निर्माण हुआ। यह शुद्धता का विषय है।

इससे शरीर और मन स्वस्थ होता है। गैर-सरकारी संगठनो ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्र पिता गांधी के सपने को जनता तक पहुंचाया है। यह सेवा भाव से चलता है। इसे और बढावा देने की जरूरत है।

इस अवसर पर स्वस्थ भारत यात्री और गांधीवादी चिंतक विचारक कुमार कृष्णन ने गांधी और स्वास्थ्य विषय पर बोलते हुए कहा कि, गांधी जी ने स्वास्थ्य पर मौलिक चिंतन दिया है। उसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग, स्वच्छ जीवन शैली काफी अहम है। आज के समय में जीवन शैली को बदल कर काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जिन्होंने ऋषिकेश में योग संस्थान खोला जबकि वो एलोपैथी के डॉक्टर थे। मुंगेर का योग विश्वविद्यालय 1963 में खुला जिसे सत्यानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया। वहां अनेक शोध हुए जैसे ओम का गायत्री मंत्र का मानव मन और शरीर पर प्रभाव आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भारत की योगिक परम्परा में योग और आयुर्वेद ऐसे नगीने हैं जो जीवन को सरल और शांत बनाते है। बीमारी दूर करते है। इन्हें अपना कर जीवन आसानी से निर्वाह होता है। दवा रहित भारत का यही भविष्य हैं। इस सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं डॉयलॉग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल ने किया। ■

स्वास्थ्य अमृत मंथन सार-07

पत्रकार यह समझें कि वे पत्रकारिता किसके लिए कर रहे है : मनोज मिश्र

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एनयूजेआई के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र ने कहा कि, कोरोना काल ने स्वास्थ्य पत्रकारिता की जिम्मेदारियों को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमे सूचना देने के प्रति सचेत रहना चाहिए। कोविड काल में कुछ समय ऐसा भी रहा कि काफी लोगों ने अखबार पढ़ना तक छोड़ दिया था। ऐसे वक्त पर सोशल मीडिया ने सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई। कई बार हम अपनी खबरों में समाज का बहुत नुक्सान कर देते हैं। मीडिया संगठनों एवं पत्रकारों को इस बात को समझने की जरूरत है कि वे पत्रकारिता कर किसके लिए रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चित्रकूट में समाजसेवी नाना जी देसमुख ने दादी मां का बटूवा नाम से एक प्रकल्प चलाया था। इस बटूए में देसी इलाज कि सभी सामग्री होती थी। नाना जी ने महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शिल्पी दंपत्ति तैयार किए थे जो समाज के बीच जाकर स्वास्थ्य संबंधी जन-जागरुकता बढ़ाते थे। इस प्रयोग ने महिला स्वास्थ्य को ऊपर उठाने में कारगर सिद्ध हुआ।

इस विषय पर मुख्य वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष उमेश चतुर्वेदी ने कहा कि पत्रकारिता की प्रकृति आलोचनात्मक मानी जाती है लेकिन दुर्भाग्य है कि यह केवल राजनीति और प्रशासन तक ही सीमित रह जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसकी यह भूमिका उस तरह से उभर कर सामने नहीं आई है जिस तरह की अपेक्षा समाज करता है। आज का मीडिया दानी-नानी के नुस्खो को अवैज्ञानिक कह कर खारिज कर देता है जबकि रस्किन बॉड ने रिटर्न टू नेचर पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को रेखांकित किया है। गांधी जी को लोग सिर्फ आंदोलनकारी के रूप में ज्यादा जान पाए हैं जबकि वे एक कुशल स्वास्थ्य चिंतक एवं पत्रकार थे। कोविड के दौरान स्वास्थ्य पत्रकारिता की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी लेकिन उसी दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे गैर-जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता स्वरूप उभर कर सामने आया था।

भारतीय जनसंचार संस्थान के ऊर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रमोद सैनी ने कहा कि, स्वास्थ्य पत्रकारिता में समाधानपरक पत्रकारिता की जरूरत है। भारतीय संस्कृति में इलाज के साथ-साथ बीमारियों को रोकने वाली पद्धति पहले से ही उपलब्ध है यानी कि संपूर्ण आरोग्य की अवधारणा हमारी संस्कृति का स्वास्थ्यगत विरासत है। जिसे हमें स्वस्थ जीवन शैली के रूप में जानते हैं।

आज की जो स्वास्थ्य पत्रकारिता हो रही है उसमें प्रमुख रूप से दवाइयों का प्रचार और डॉक्टरों का साक्षात्कार प्रकाशित किया जाता है जिसे वास्तव में स्वास्थ्य पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता है। तमाम उपायों के बावजूद अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हमारे समाज में स्वास्थ्य का मूल मंत्र रहा है सच्चा सुख निरोगी काया।

वरिष्ठ स्वास्थ्य पत्रकार धनन्जय ने कहा कि स्वास्थ्य की बारीकियों को मीडिया में स्थान दिया जाना चाहिए। मीडिया आकर्षक शीर्षक के चक्कर में भ्रामक पत्रकारिता कर बैठता है, जबकि उसकी जिम्मेदारी इस मामले में बहुत अधिक है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई खबर न छपने पाए, क्योंकि एक भ्रामक खबर करोड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। उन्होंने स्वस्थ भारत न्यास को सुझाव देते हुए कहा कि अब जरूरत इस बात कि है कि न्यास ड्रग लेस भारत के लिए काम करे और अभियान चलाए ताकि किसी को दवा खाने की जरूरत ही न पड़े। इस सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं युगवार्ता के संपादक संजीव कुमार ने किया। ■

ऑर्गेज्म
चरम सुख बनाम चरित्रहीन स्त्रियां

● अनामिका चक्रवर्ती 'अनु'

एक लेखिका के विचार से कि जिन 70 प्रतिशत स्त्रियां को ऑर्गेज्म नहीं मिलता वे कहीं न कहीं तो तलाशेंगी। क्या नैतिकता सिर्फ स्त्रियों के लिए है

अजीब है कि उन्होंने यह तय कर लिया कि औरतें ऑर्गेज्म तलाशती रहती हैं। यानी हद दर्जे की बकवास लिखा है ।

अब जबकि हर सोशल साइट्स पर हर तरफ लिखा जा रहा है पढ़ा जा रहा है लेकिन कितने दिन ?

फिर कोई नया विषय आ जाएगा और फिर हर तरफ उसका हो हल्ला होने लगेगा ।

सबसे पहले तो यही बता दूं कि इसे पढ़ने वाले बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि इस पर लिखा ही क्यों कुछ और नहीं मिला लिखने को जबकि मजेदार बात ये रहेगी इसे सब पढ़ेंगे ।

बल्कि पढ़ना ही चाहिए और पढ़कर अपनी राय भी रखनी ही चाहिए

अब जब हर तरह के विषय और विचारों इच्छाओं पर बातें होने लगी है तो ये भी क्यों नहीं।

देखा जाए तो इस विषय को लेकर सबसे बड़ा पाखंड हमारे ही समाज में है और इसके दुष्परिणाम कयी रूपों में हमारे समाज घर परिवार और रिश्तों पर निरंतर पड़ रहे हैं।

लेकिन उससे पहले कि आखिर चरम सुख की परिभाषा है क्या

जबकि कोई चीज जब अपने चरम पर पहुंच जाती है तब वहां से वह खत्म हो जाती है। कोई इच्छा चाह सबसे मुक्त हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है लेकिन यह चरम सुख हर बार संभोग करते हुए शुरू से शुरू होता है हर बार संतुष्टि की वही मांग होती है।

एक बार मन भरपेट भोजन की तृप्ति या संतुष्टि के बाद भी दोबारा उतनी ही भूख लगती है और जब तक जीवन है भूख लगती रहेगी, हर बार पूरी हो होकर भी।

तलाश एक गलत वक्तव्य है जबकि सच तो ये है कि लगभग 70 बल्कि इस आंकड़े को और अधिक रूप में भी देखा जा सकता है कि भारतीय महिलाएं संतुष्ट नहीं हैं ये अलग बात है कि वे इससे लोक लाज से बचने के लिए इंकार भी करती हो या तो कुछ समझ ही नहीं पाती कि वे उस सुख से वंचित है या ये कि यह भी एक सुख की चीज है।

ऑर्गेज्म शारीरिक सुख आनंद और खुशी की उत्तेजना से भरी वह की भावना है, सेक्स या संभोग करते हुए दोनों पार्टनर को मिलना चाहिए या मिलता है।

ऑर्गेज्म यौन उत्तेजना का चरम है। अधिकतर पुरुष स्त्री को उस चरम सुख से वंचित रखता है क्योंकि वह इस सुख को केवल स्वयं के लिए महसूस करता है' जाने या अंजाने ही सही और स्त्रियां इस बारे में बोलना पाप समझती है या जानती ही नहीं ।

अधिकतर स्त्रियां इसे केवल पति को सुख देने का कर्तव्य मान लेती हैं और अपनी उठती कामनाओं को चुपचाप दबा जाती हैं।

लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा है क्यों

हम जिस सामाजिक संस्था में रहते हैं यहां हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमारे जीवन के हर एक जगह दखल देते हैं या यह कह लिजिए कि हमारे जीवन की सामाजिक और मानसिक गतिविधियों पर नैतिकता के नियमों का शासन है ।

लेकिन इसकी जरूरत से हम इंकार नहीं

बैडरूम में सौतन और संतानोत्पति में बाधक बनते मोबाइल और लैपटॉप

बैडरूम में देर रात तक मोबाइल फोन और लैपटॉप पर कार्य करने से पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ रहें है। आधुनिक युग के दम्पति साइको सेक्स डिसऑर्डर के शिकार हो रहें है। शरीर में डाई हाइड्रोक्सी इथाइल अमाइन नामक रसायन का स्तर तेजी से घट रहा है। जिसकी वजह से पुरुष व महिला का हॉर्मोन साइकिल प्रभावित हो रहा है जो अब बच्चे पैदा करने में मुश्किल खड़ी कर रहा है, संतानोत्पति में बाधक बन रहा है।

इंडियन मेडिकल एजुकेशन के रिसर्च के अनुसार कुदरत ने लड़कियों को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन एवं लड़को को टेस्टोस्ट्रोन हॉर्मोन तोहफे में दिया है ताकि वो अपनी वंश बेल को आगे बढ़ा सके। मगर बदलती दिनचर्या और आधुनिक उपकरणों की लत के कारण इन होर्मोनेस का स्तर गड़बड़ा रहा है। जिस से आधुनिक दम्पति बांझपन की समस्या से लड़ रहें है। इस से बचने के लिए हमें मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनानी होगी, लगातार शाम को पैदल चलने की आदत बनानी होगी। ऐसा करने से हॉर्मोन स्तर सही रहेगा और दांपत्य में खुशियां आएगी।

आंकड़े बताते है कि तलाक के मामलों में युवा पीढ़ी आगे है। इसके पीछे मुख्य कारण पति-पत्नी के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता का न होना है। पोर्न साइट्स दाम्पत्य जीवन में खलल डाल रही है। तलाक के मामलों में नव दम्पति अधिक है। इंटरनेशनल फेडरेशन के अनुसार विवाह के लिए बेहतर उम्र युवती के लिए 22 और युवक के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। विलम्ब से विवाह विवाद का कारण बनते है। ऐसे में सन्तानोपत्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाता।

पिछले एक दशक में मोबाइल फोन के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है और मानव स्वास्थ्य पर इन उपकरणों द्वारा उत्सर्जित रेडियो - फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संभावित खतरनाक प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रारंभिक अध्ययन सेल फोन के उपयोग और बांझपन के बीच एक संभावित लिंक का सुझाव देते हैं। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि सेल फोन का उपयोग शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता, व्यवहार्यता और आकारिकी को कम करके वीर्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पुरुष प्रजनन क्षमता पर मोबाइल फोन के हानिकारक प्रभाव के साक्ष्य अभी भी समान हैं क्योंकि अध्ययनों ने संभावित प्रभावों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का खुलासा किया है, जो मामूली प्रभावों से लेकर वृषण क्षति की परिवर्तनशील डिग्री तक है। हालांकि पिछले अध्ययनों ने पुरुष बांझपन में सेल फोन के उपयोग की भूमिका का सुझाव दिया था, पुरुष प्रजनन प्रणाली पर सेल फोन से उत्सर्जित ईएमडब्ल्यू की क्रिया का तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं है. रेडियो-फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक विशिष्ट प्रभाव, थर्मल आणविक प्रभाव या दोनों के संयोजन के माध्यम से प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है।

मानव कामुकता स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण घटक है लेकिन जब मोबाइल और लैपटॉप बेडरूम में रहेंगे तो इनका नशा दम्पतियों के वैवाहिक जीवन पर असर डालने लगते हैं। नयी टेक्नॉलजी के साथ विवादों की घटनाएं लगातार जन्म ले रही हैं। आपत्तिजनक साइटें दाम्पत्य जीवन में खलल पैदा करने लगीं हैं। साइको सेक्स डिस्आर्डर पैदा हो रहे हैं। डिस्आर्डर से ग्रसित दम्पतियों के विवादों के कारण हर महीने तलाक हो रहे हैं। यह तलाक नवविवाहित जोड़ों में ज्यादा हैं लेकिन 40 पार दम्पतियों में भी हो रहे हैं।

दिन में करीब 4 घंटे तक सेल फोन को सामने की जेब में रखने से भी अपरिपक्व शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यह पुरुषों में उनकी प्रजनन क्षमता को कम करने वाले डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है. ओहियो (अमेरिका) के क्लीवलैंड क्लिनिक फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, सेल फोन के इस्तेमाल से शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता, व्यवहार्यता और सामान्य आकारिकी को कम करके वीर्य की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसके अलावा, कई शोधकर्ताओं द्वारा यह पाया गया है कि उच्च और मध्यम आय वर्ग के 14 प्रतिशत जोड़ों को गर्भधारण करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

दरअसल, गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही महिलाओं के लिए सेल फोन रेडिएशन का लगातार संपर्क बहुत हानिकारक माना जाता है। लंबे समय तक संपर्क और सेलुलर विकिरण से निकटता महिलाओं में बांझपन की ओर ले जाती है क्योंकि यह अंडाशय की सामान्य गतिविधि को प्रभावित करती है। डॉक्टर और विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए अपने दैनिक सेल फोन के उपयोग की आदतों को बंद करने की सलाह देते हैं। सेल फोन द्वारा उत्पन्न विकिरण और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को भ्रूण के विकास को प्रभावित करने के लिए भी जाना जाता है।

बेडरूम में मोबाइल-लैपटॉप सौतन बन गए हैं और सेक्स लाइफ को बिगाड़ रहे हैं। नए परिदृश्य में इसे साइबर विडो भी कहा जा रहा है। मोबाइल-लैपटॉप दम्पतियों के बीच विवाद के कारण बनते जा रहे हैं और तेजी से तलाक की वजह बन गए हैं। पति-पत्नी के बीच के विवाद धीरे-धीरे साइको सेक्स डिस्आर्डर के रूप में पनप रहे हैं जिसमें मारपीट तक की नौबत आ रही है। ऐसे में इन विवादों के बढ़ने से पहले ही दम्पतियों को नीम-हकीमों के पास नहीं जाना है। उन्हें मनोचिकित्सकों के पास जाकर अपनी समस्या का निदान कराना होगा।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि तकनीक ने हमें पहले से कहीं ज्यादा काम करने के सक्षम बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इसने लोगों को सकरात्मक और रचनात्मक सोच में भी बाधा पैदा करने का काम किया है। दुर्भाग्य की बात ये है कि बहुत से लोग शारीरिक रूप से भी तकनीक के लती हो गए हैं, जो सीधे तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है।

बहुत से लोगों ने टाइम पास करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपना पसंदीदा ऐप बना लिया है, जिससे परिवार से उनका ध्यान बंट गया है। सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करने में समय बर्बाद करने के बजाय आप एक नया शौक आजमाएं जैसे कि किताब पढ़ना या फिर क्राफ्ट बनाना। इससे आपके ज्ञान चक्षु भी खुलेंगे औरआपकी समस्या का निदान होगा।

- प्रियंका सौरभ

परिवार या समाज – किसके लिए कितना करें?

परिवार के लिए उतना ही करना चाहिए, जितना आपका अनिवार्य कर्तव्य है, जैसे पालन-पोषण और विपत्ति में सहायता... बस! क्योंकि परिवार के लिए किया हुआ सब कुछ एक दिन पानी में ही बह जाना है। परिवार में कोई भी आपका कृतज्ञ नहीं रहता। ऊपर से अंतिम दिन तक हर सदस्य आपका एक-एक बूंद खून निचोड़ लेना चाहता है।

आदमी जो आज भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी बन रहा है, वह भी परिवार की तृष्णाओं और शोषण के ही कारण। आप जीवन भर परिवार के लिए करते हैं, फिर भी परिवार आपसे एक-एक इंच जमीन, एक-एक पैसे के लिए झगड़ा करता है।

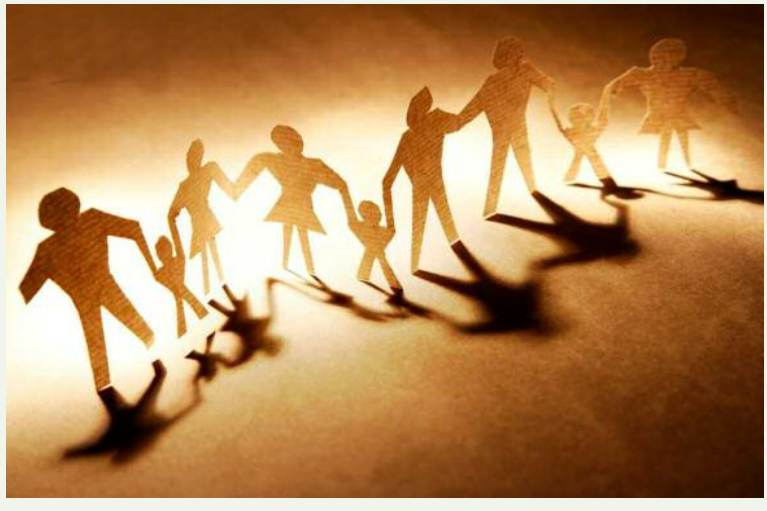

परिवार आपकी कोई बात नहीं सुनता, मनमानी करता है, आपको अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता है। ऊपर से परिवार के लोग यदि नासमझ और जिद्दी हैं, तब तो वे आपकी तरक्की के रास्ते के ऐसे रोड़े बन जाते हैं कि उन्हें ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना भी आपके लिए संभव/आसान नहीं होता। गलतियां परिवार के लोग करते हैं, सजा आपको भी भुगतनी पड़ती है। परिवार में सब कुछ करके भी आपको अपमानित होना पड़ेगा। परिवार के लिए सारी कुर्बानियां देकर भी आपको लांछित होना पड़ेगा।

इसलिए, यदि आप कुछ सार्थक करना चाहते हैं, आपमें कुछ बेहतर करने का पुरुषार्थ है, तो समाज के लिए कीजिए। समाज के लिए किया हुआ ही टिकाऊ होता है और यही आपको यश दिलाता है। समाज हमेशा कृतज्ञ रहता है और जीवन भर एवं जीवन के बाद भी आपको सम्मानित करता रहता है।

भाइयों का वश चले तो आपके घर का रास्ता तक रोक लें, लेकिन समाज अपनी जमीनें देकर अपनी चिंता करने वालों के नाम पर बड़ी-बड़ी सड़कें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय बनवा देता है। बेटे-बेटियां आपके गुजरने के बाद आपकी यादों को सहेजकर रखने के बजाय आपके घर-मकान के एक-एक हिस्से पर कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन समाज आपके योगदान को सम्मान देने के लिए अपने संसाधनों से आपके नाम पर स्मारक, संग्रहालय, चौक-चौराहे बनवा देता है।

आपके न रहने के बाद घर-परिवार के लोग आपको जल्दी ही भूल जाते हैं, आपके विचारों पर तो शायद ही चलते हैं, लेकिन समाज न सिर्फ आपको और आपके विचारों को याद रखता है, बल्कि उसके प्रचार-प्रसार के लिए काम भी करता है और उसे अपने हृदय में बसाए हुए अपने जीवन में भी उतारने के प्रयास करता है।

परिवार ने भगवान राम को जंगल भेज दिया, भगवान कृष्ण की बार-बार हत्या करने की कोशिशें कीं, लेकिन समाज ने उन्हें देवता बना दिया। भगवान बुद्ध इस बात को समझ गए, इस लिए मध्यरात्रि में अपने बीवी-बच्चों को छोड़कर निकल लिए।

जीवन में एक ऐसा वक़्त आ सकता है, जब मां-बाप भी धृतराष्ट्र और गांधारी बन जाते हैं। भगवान राम को तो बीवी के चक्कर में बाप ने ही जंगल भेज दिया। बेटे ने जो भी मर्यादा निभाई हो, लेकिन बाप ने क्या किया? ययाति ने अपनी अय्याशी के लिए बुढ़ापे में भी अपने बेटों की जवानी छीन ली। कुंती ने अपने कम्फर्ट जोन में बने रहने के लिए मां होकर भी बेटे कर्ण को पानी में बहा दिया। उसकी लोक-लाज की चिंता बेटे के प्रति उसकी ममता और दायित्व पर भारी पड़ी।

कुछ पुराने प्रसंगों का जिक्र मैंने केवल आपके समझने में आसानी के लिए किया है, लेकिन सच यह है कि लगभग हर परिवार में यही होता है। मैंने जितनी दुनिया देखी है, उसमें यही नोट किया है कि जन्म देने वाले मां-बाप और सहोदर भाई-बहन भी आपको अपने सुख-सुविधा-सम्मान के लिए केवल इस्तेमाल ही करते हैं। आपका इस्तेमाल खत्म, आप कूड़ेदान में।

परिवार कभी आपको नहीं समझेगा, हमेशा आपको उल्टा ब्लेम करेगा– यह बात लगभग तय मानकर चलिए।

आजकल तो बड़ी संख्या में लोगों को परिवार से एक नई तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है। यदि आप मां-बाप, भाइयों-बहनों के ही चाहने पर पढ़ाई करने या नौकरी करने के लिए बाहर निकल गए और बाहर रहते हुए लगातार उनकी सहायता भी करते रहे, इसके बावजूद जब कई वर्षों के बाद किसी भी कारण से आप अपने घर लौटना चाहेंगे या वहां कोई सीमित गतिविधियां भी चलाना चाहेंगे, तो यह आपके लिए अत्यंत दुरूह हो जाएगा, क्योंकि अब आपके घर-परिवार के लोग ही नहीं चाहते कि आप लौटें, क्योंकि अब उनका अपना कम्फर्ट जोन बन चुका है, जिसमें वे आपको बाधक महसूस करने लगे हैं। इसलिए अब यदि आप केवल सालाना पर्यटक के रूप में आते-जाते रहें, तब तक तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही आप वापसी की इच्छा प्रकट करेंगे, आपको तगड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा।

हमारे बिहार में एक कहावत है– 'जे

बेटा परदेस गेल, देवता-पितर सबसे गेल।'

हालांकि परिवार अनेक खुशकिस्मत लोगों के लिए सहायक भी सिद्ध होता है। अनेक मां-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी, बेटे-बेटियां अपनों के लिए जान तक दे देते हैं। मैं ऐसे परिजनों को भी जानता हूं, जिन्होंने अपनी किडनी तक दे दी, अपने किसी परिजन को बचाने के लिए। इसलिए जो बातें मैंने ऊपर लिखीं, उनके अनेकानेक अपवाद भी आपके इर्द-गिर्द हो सकते हैं।

चूंकि यह एक अत्यंत जटिल विषय है, इसलिए इसपर नियम की तरह कुछ प्रतिपादित करना आसान नहीं। फिर भी अब तक जितना अनुभव किया है और समझ पाया हूं, उसी के हिसाब से यह लिखा है। हो सकता है कि आपमें से कई लोगों के अनुभव अलग हों और आप इससे सहमत न हों। फिर भी जैसे-जैसे समय मिलेगा, इस विषय पर थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा और इन विचारों की कमियों को दूर करने के प्रयास करूंगा।

अभी के लिए बस इतना ही कि परिवार और समाज के लिए अपने कर्तव्यों को ठीक से समझिए और हमेशा एक लक्ष्मण रेखा खींचकर चलिए। उस लक्ष्मण रेखा को लांघकर न तो आप परिवार के लिए कुछ कीजिए, न ही परिवार को वह लक्ष्मण रेखा लांघने दीजिए। हालांकि ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा खींचकर चलना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि यह भी परिवार में टकराव और असंतोष का कारण बन सकता है।

परिवार का वश चले, तो वह आपको रत्नाकर डाकू बना डाले, लेकिन आप भी जानते हैं कि जीवन की सार्थकता इसमें नहीं, बल्कि महर्षि वाल्मीकि की तरह बनने और निखरने में है।

- अभिरंजन कुमार

कर सकते क्योंकि यही नैतिकता हमें एक परिवार और सुगठित समाज प्रदान करता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन इन सबके बीच स्त्रियों की हर तरह की स्वतंत्रता की डोर पुरषों ने अपने हाथ में ले रखी है और वे इसका अपने मनमाफिक और सहुलियत से इस्तेमाल करते हैं ।

स्त्रियों की सभी तरह की स्वतंत्रता के बीच उनके शारीरिक सुख की चाह को सबसे अधिक दबाया गया यहां तक कि उस बारे में बोलना भी उनके चरित्र से जोड़ा गया, जिसका असर आज हम परिवारों में समाज में एक विकृत रूप की तरह देख रहे हैं।

आखिर कितने पुरुष अपने सेक्स पार्टनर के साथ सहवास को एक आनंद के रूप में लेते हुए अपने साथी को अपनी हर इच्छा जाहिर करने की सहजता और स्वतंत्रता देते हैं कितने पुरुष ?

सच यह है कि वे इसे सही मानते ही नहीं। वे स्वयं स्खलित होने तक ही स्त्रियों पर अपना आनन्द दिखाते जताते हैं।

अधिकतर स्त्रियां पुरुष की मांग अनुसार सपोर्ट करती हैं, अपनी इच्छा और अधिक सुख पाने की चाह के अनुसार नहीं । और अगर कभी स्त्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर भी दिया तो पुरुष उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगता है।

बहुत जरूरी है इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना इसके मन मस्तिष्क और शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को समझने की मानसिक तनाव का भी यह एक बड़ा कारण होता है स्त्रियों के साथ। इसे संगीत की तरह समझिए शोर की तरह नहीं, लेकिन क्यों देखता है पुरुष क्यों ?

क्यों उसे एक सुख की प्राकृतिक प्रकृति पर संदेह होने लगता है ?

क्या इच्छाएं स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग बनी है ?

क्या स्त्री पुरुष की जीभ में स्वाद लेने या उसकी चाह अलग अलग होती है ? क्या स्त्री पुरुष की ग्रंथि एक ही चीज के लिए अलग अलग होती है ?

नहीं बिल्कुल भी नहीं।

हां स्त्रियां ऑर्गेज्म की तलाश नहीं करती लेकिन चाह रखती है और उसे दबा जाती है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को समाज ने चरित्रहीन माना है समाज ने अनैतिक माना है। जबकि पुरुष भी इससे बच नहीं पाए उन्हें भी लम्पट और चरित्रहीन माना गया है लेकिन पुरुष की प्रकृति इस मामले में बेपरवाह है, तभी तो पुरुष एक ही बार में कयी औरतों से खुल्लमखुल्ला संबंध बनाकर भी लज्जित नहीं होता और तो और उसे अपने पौरुष पर गर्व होता है अक्सर तो वे इसके चर्चे भी बड़े मजे ले लेकर करते हैं।

लेकिन सवाल अब भी वहीं है क्या करें स्त्रियां कहां जाएं किसके पास जाए और क्या गारंटी है कि कोई दूसरा उसे ऑर्गेज्म दे सकेगा इस तरह तो एक के बाद एक यही सिलसिला चलता रहेगा और अंत में एक मानसिक रोगी की तरह हो जाएगा ।

सांसारिक व्यस्तता और जरूरतों और हर

शराबी बनाने का सरकारी अभियान

भारत में राज्य सरकारों को लगता है कि देश में बहुत कम लोग शराब पी रहे हैं और जो पी रहे हैं वे भी कम पीते हैं। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक शराब पीने का दुनिया का प्रति व्यक्ति औसत 6.2 लीटर का है, जबकि भारत का औसत पांच लीटर का है। देश में सिर्फ दो ही उत्पाद ऐसे हैं, जिनको वन नेशन, वन टैक्स के सिस्टम से बाहर रखा गया है। उनमें एक शराब है और दूसरा पेट्रोल-डीजल। भारत में अभी साल में पांच अरब लीटर शराब की खपत है, जिसे 2024 तक सवा छह अरब लीटर तक ले जाना है।

इसके लिए शराब खरीदने और पीने की उम्र सीमा कम की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खोल कर लोगों को बिल्कुल घर के नजदीक शराब उपलब्ध कराई जा रही है। बार और रेस्तरां में देर रात तक शराब परोसने की छूट दी जा रही है। राजधानी दिल्ली में इसकी समय सीमा बढ़ा कर तड़के तीन बजे तक कर दी गई तो पड़ोसी राज्य के मिलेनियम शहर गुरुग्राम में 24 घंटे शराब उपलब्ध कराने का नियम बन गया। राजधानी दिल्ली में किसी जमाने में साल में 27 ड्राई डे होते थे यानी साल में 27 दिन शराब नहीं मिलती थी। इसे घटा कर अब दो दिन कर दिया गया है। इतना ही नहीं शराब और बीयर के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर 50 से सौ फीसदी की छूट भी दी जा रही है। इस तरह भारत में सरकारें शराब का उपभोग बढ़ा कर राजस्व बढ़ा रही है।

भारत में राज्य सरकारों को सालाना 1.75 खरब रुपए की कमाई शराब पर मिलने वाले राजस्व से हो रही है। 2018-19 में राज्य सरकारें हर महीने साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए की कमाई करती थीं, जो 2020 में बढ़ कर 15 हजार करोड़ रुपए हो गई। अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री से साढ़े 17 हजार करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। लेकिन 2017 में आई भाजपा कीसरकार के नियमों और प्रयासों से शराब की बिक्री ऐसी बढ़ी की चार साल में सरकार का राजस्व 74 फीसदी बढ़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार को 2021 में शराब की बिक्री से 30 हजार करोड़ रुपए की कमाई हुई। सो, शराब कंपनियों के आक्रामक विज्ञापन व कीमत नीति और राज्य सरकारों के अथक प्रयास से भारत में शराब का कारोबार सबसे फलने-फूलने वाला कारोबार बन गया है।

कौन है भारत का धनपति एस्कोबार?

पिछले साल सितंबर में देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के नियंत्रण वाले मुंदरा बंदरगाह पर तीन टन हेरोइन पकड़ी गई थी। इसकी कीमत कोई 21 हजार करोड़ रुपए थी। बताया गया था कि टेल्कम पाउडर बता कर इसे भारत भेजा गया था। यह भी खबर आई थी कि यह खेप पकड़े जाने से पहले ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से टेल्कम पाउडर की कई खेप और आ चुकी थी। जून 2021 में एक और बड़ी खेप उसी बंदरगाह से भारत में उतरने की खबर आई थी, जिसके बाद देश के कई बड़े शहरों में नशीले पदार्थों की जब्ती में अचानक तेजी आ गई थी। बहरहाल, तीन टन हेरोइन की जब्ती के अलावा भी पिछले साल गुजरात में नशीले पदार्थों की जब्ती का नया रिकार्ड बना। इस 21 हजार करोड़ रुपए के नशीले पदार्श के अलावा गुजरात पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने 1,617 करोड रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए, जो 2020 में हुई जब्ती के मुकाबले आठ सौ फीसदी ज्यादा था। 2020 में गुजरात में 195 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त हुए थे, जो 2021 में बढ़ कर 1,617 करोड़ हो गई। इसके अलावा एक जब्ती 21 हजार करोड़ रुपए की थी।

उसके बाद नए साल में अभी चार महीने बीते हैं और गुजरात में चार हजार करोड़ रुपए के करीब के नशीले पदार्थ जब्त हो चुके हैं। हेरोइन की दो खेप फरवरी और अप्रैल में पकड़ी गई, जिसकी कीमत साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए है। इस साल 11-12 फरवरी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने 760 किलो नशीला पदार्थ पकड़ा, जिसकी कीमत दो हजार करोड़ रुपए बताई गई। इसके बाद 25 अप्रैल को दो सौ किलो नशीले पदार्थ की एक खेप और पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए बताई गई।

इस तरह सिर्फ दो खेप साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए की है। इसके अलावा छोटी-छोटी जब्ती अलग हो रही है। दूसरी जो डेढ़ हजार करोड़ रुपए की जब्ती हुई यह हेरोइन भी ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से आई थी। यानी जिस रास्ते से पिछले साल 21 हजार करोड़ रुपए की हेरोइन आई थी वह रूट अब भी काम कर रहा है। सोचें, जब इतनी बड़ी मात्रा में नशीली वस्तुएं जब्त हो रही हैं तो इससे कितनी बड़ी मात्रा में सरकुलेशन में जाती होंगी? एक साधारण अनुमान के मुताबिक कोई भी प्रतिबंधित वस्तु जितनी मात्रा में जब्त होती है उससे 10 गुना ज्यादा मात्रा में सरकुलेशन में होती है। इसका मतलब है कि अगर हजारों करोड़ रुपए की जब्ती हो रही है तो नशे का कारोबार लाखों करोड़ रुपए का होगा।

मोटा मोटी पिछले दो-तीन सालों से धरपकड, बरमादगी की जितनी खबरें पढ़ने को मिली है उनका दो टूक अर्थ है कि भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता ड्रग्स बाजार है। पंजाब

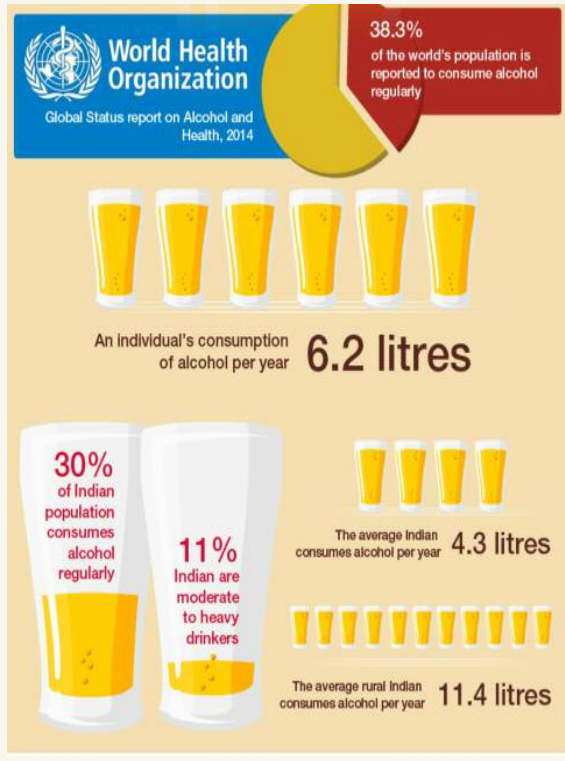

के नौजवानों के ड्रग्स के आदि होने की बाते अब पुरानी है। भारत के सभी राज्यों में तेजी से बढ़ी नौजवान आबादी शराब, ड्रग्स, गांजा आदि की ऐसी आदी बनी है कि दुनिया के ड्रग माफियाओ के लिए भारत बढ़ा बाजार हो गया है। पाकिस्तान की सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स आने के कयास हो या म्यांमार से उत्तर-पूर्व के जरिए या समुद्री रास्ते, बंदरगाह और ह्वाई अड्डो से चोड़े-धाडे कंटेनरों, कुरियर सेवा आदि से नशीले पदार्थो के आने और उनमें कुछ के पकड़े जाने की तमाम खबरों का अर्थ है भारत में डिमांड सुरसा की तरह बढ़ी है। भारत अब अमेरिका और योरोप की तरह नशीले पदार्थों की खपत, डिमांड का ऐसा बड़ा बाजार हो गया है कि आसियान, अफगानी, पाकिस्तानी, अफ्रीकी नेटवर्क से भारत की और खैप पहुंचाने में भारी मुनाफा बना है। अन्यथा टनों की तादाद में कंटेनर से पाउडर के नाम पर हेरोइन की खैप के बदंरगाह के रास्ते पहुंचने का भला क्या अर्थ ?

दो-तीन सप्ताह पुरानी बात है। मुझे एक नौजवान ने ज्ञान दिया कि आपको पता है ऑनलाइन सट्टे में नौजवान लोग कैसे बरबाद हो रहे है। मैं पूरी तरह बेखबर था। उसने अपना नुकासन और आदत बताई तो मालूम हुआ कि मोदी राज में क्रिकेट अब नौजवानों के सट्टे का वैधानिक खेल हो गया है। पूरे देश के नौजवानो को सपना देखों, जुआ खेलों का आदी बनाया जा रहा है। लडकों की सट्टे की आदत बन रही है। एमएम रेडियों, सोशल मीडिया पर इतनी तरह के प्रचार से बहला-फुसला कर बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग की आदत बनवाई जा रही है।

तभी सोचे, हम लोग कैसा बेसुध जीवन जीते हुए है!

- हरिशंकर व्यास

भारत की बड़ी समस्या, जनसंख्या ?

इस खबर को क्या कहें? कुछ वर्षों में भारत की आबादी में युवाओं का अनुपात कम होने लगेगा। भारत में अभी औसत उम्र 28 वर्ष है, जो 2026 तक बढ़ कर 30 वर्ष और 2036 तक 35 वर्ष हो जायेगी। इस अनुपात के अपने अर्थ है।वैसे भारत में कुल प्रजनन दर घटी है।संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया की आबादी बढ़ कर 7.7 अरब हो गयी है, जबकि 2018 में यह आबादी 7.6 अरब थी। पिछले एक दशक में भारत की जनसंख्या में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, या यूं कहे कि देश के विकास की राह में यह सबसे बड़ी बाधा है।

भारत की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से संसाधनों का विकास संभव नहीं है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़े अलबत्ता राहत देने वाले हैं। इस सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल प्रजनन दर में कमी आयी है और यह 2.2 से घट कर 2.0 रह गयी है। यह दर महिला से होने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापी जाती है और उसमें गिरावट दर्ज की गयी है। सबसे खास बात मुस्लिम समुदाय में भी प्रजनन दर घट कर 2.36 प्रतिशत हो गयी है, सबसे तेज गिरावट इसी समुदाय में आयी है। यह बात महत्वपूर्ण है इस विषय को राजनीतिक मुद्दे के रूप में जब तब इस्तेमाल किया जाता है।

आंकड़े कहते हैं देश में गर्भनिरोधक उपायों को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से इन आंकड़ों को उत्साहजनक माना जा सकता है। जनसंख्या में बढ़ोतरी की रफ्तार को संतुलित रखने के लिए प्रति महिला औसत जन्म दर 2.1 होनी चाहिए। प्रति महिला औसत जन्म दर के दो तक आ जाने का अर्थ है कि देश की जनसंख्या जितनी है, उतनी बनी रहने के लिए भी जरूरी जन्म दर मौजूद नहीं रही। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों के 707 जिलों से लगभग 6.37 लाख परिवारों से सैंपल लिये गये थे। इसमें 7.24 लाख महिलाओं और 1.01 लाख पुरुषों को शामिल किया गया था । विशेषज्ञों ने पाया कि बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम को लेकर लोग अधिक जागरूक हुए हैं। देश में केवल पांच राज्य ऐसे हैं, जो 2.1 के प्रजनन दर के ऊपर हैं। इनमें क्रमशः बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35) और झारखंड (2.26) और मणिपुर (2.1) शामिल है। खास बात पिछले चार वर्षों में भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आयी है। जो बताता है कि बच्चों के पोषण और देखभाल में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। सर्वे के अनुसार बढ़ता मोटापा एक नयी चुनौती बन कर उभर रहा है। महिला और पुरुष, दोनों में मोटापा तेजी से बढ़ा है।

भारत में महिलाओं में मोटापा 21 प्रतिशत से बढ़ कर 24 प्रतिशत और पुरुषों में 19 प्रतिशत से बढ़ कर 23 प्रतिशत हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दर को काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब और चंडीगढ़ में एक तिहाई से अधिक महिलाएं अधिक वजन से ग्रस्त पायी गयी हैं। सारा देश अब यह भली-भांति जानने लगा हैं कि बढ़ता मोटापा कई प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है और इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि भारत की आबादी से तेजी से बढ़ी है।भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी और उस समय देश की आबादी 36 करोड़ थी। इसके बाद हुई जनगणना में देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई । वर्ष 1961 में हुई जनगणना में देश की आबादी बढ़ कर लगभग 44 करोड़ हो गयी। वर्ष 1971 मे देश की जनसंख्या बढ़ कर 55 करोड़ हो गयी। वर्ष 1981 की जनगणना में पता चला कि देश की आबादी 68 करोड़ हो गयी है और 1991 यह आबादी बढ़ कर 85 करोड़ दर्ज हुई। 2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ पार कर गयी, तो 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ आंकी गयी थी। अब माना जा रहा है कि भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास है।

बढ़ती आबादी का असर बहुआयामी है। बढ़ती जनसंख्या का देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है, बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना लगभग नामुमकिन है। इसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं भी दिख रहीं हैं। जमीन पर बोझ बढ़ा है, जिसने पारिवारिक संघर्ष को जन्म दिया है। जनसंख्या के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि इसने हमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना दिया है, जिस कारण हर विदेशी कंपनी भारत में आना चाहती है और निवेश करना चाहती है.

लंबे समय तक देश के विमर्श से जनसंख्या नियंत्रण गायब रहा। जनसंख्या पर नियंत्रण रखना नागरिकों की जिम्मेदारी है, जागरूकता फैलाने में केंद्र और राज्य सरकारें पहल कर सकती हैं, लेकिन एक सीमा के आगे इस संवेदनशील विषय पर सरकार की भूमिका सीमित हो जाती है।

- राकेश दुबे

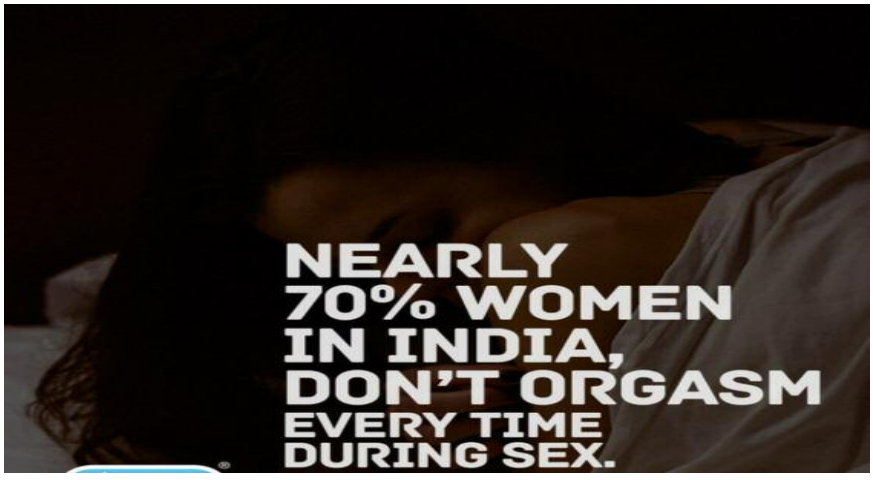

पल भागम-भाग की जिंदगी के बीच में ऑर्गेज्म एक दवा भी है और जहर भी।

और यही कारण है लेट नाइट पार्टीज में शराब शबाब और .....

छोटी छोटी बच्चियां भी इसकी गिरफ्त में आती जा रही हैं। लड़कों में शीघ्र पतन जैसी समस्या आम हो चली है। शादी के बाद बच्चे न होने का भी ये एक बड़ा कारण है। शादियां जल्द जल्द टूटने की कगार पर खड़ी हो जाती है।

पार्टनर अपनी असंतुष्टि का समाधान आपस में खोजने की बजाय गलत हाथों में चले जाते हैं जिसका अधिक नुक्सान स्त्रियों को ही उठाना होता है। अ ौ र बलात्कार जैसी घृणित कर्म भी कहीं हद तक इसी का नतीजा है।

जहां यह कई तनावों से मुक्त कर मनुष्य को रीफ्रैश करती है, वहीं इसके पूरे न होने पर इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव हर काम पर पड़ता है और स्त्रियां जानती है। यह सुख इतना आसान नहीं इसलिए वे अपना ध्यान दूसरी चीजों में लगाती है जिसमें अध्यात्म सबसे अधिक है। और कुछ इस सुख को पाने के लिए एक क्षणिक मुलाकात पर भी आसानी से सहवास कर लेती है लेकिन यह सुख नहीं क्षणिक आनंद होता है। कुछ समय का रिलेक्सेशन होता है और दोबारा इसकी प्यास और चाह अधिक तीव्रता के साथ उठती है और यही कारण है कि स्त्रियां किसी के भी संपर्क में थोड़ा प्यार अपनापन पाकर आसानी से सबकुछ सौंप देती है, जिसका परिणाम अक्सर उन स्त्रियों को चरित्रहीन के नाम के साथ मिलता है।

ये एक ऐसा ड्रग्स है जो इस खोज में एक बार निकल गया वो वापसी नहीं कर पाता और समाज उसे हमेशा ग़लत नजरों से ही देखता है।

सबसे जरूरी है पुरुष साथी इस बात को समझे और अपनी पार्टनर को वह सहजता प्रदान करें जिससे वे खुल सकें।

एक बूढ़ी महिला से पूछने पर जिसके दस बच्चे हैं, उन्होंने बताया हमें तो कभी समझ भी नहीं आया कई बार कि कब हुआ, हम आधी नींद में होते थें और हमारा आदमी आता, करता और चला जाता। और ऐसे ही बच्चे कब पेट में आ जाते पता ही नहीं चलता, कभी होश में भी रहते तो घूंघट रहता चेहरे पर।

क्या बोलें ऐसी ही कितनी महिलाएं ढेर बच्चे पैदा करके भी इस सुख का आनंद तक नहीं ले सकी तो इसका जिम्मेदार कौन है?

स्त्री केवल पुरुष को स्खलित करने की एक टूल या पात्र नहीं हैं वे जीती जागती आपकी तरह ही एक इंसान है उसकी भी कामनाएं आपकी कामनाओं की तरह तृप्त होने के लिए तीव्र होती है। उन्हें समझिए और उन्हें उस सुख की अनुभूति लेने के लिए उन्मुक्त कीजिए ।

यही वो चरम सुख बन जाएगा जिसके लिए कभी शरीर भटकता है कभी मन भटकता है भीतर ही भीतर मन में कहीं। और इस तरह प्रेम और भी मजबूत होगा।

हां सब सुख का अपना अलग अलग आनंद होता है। रोटी की भूख जैसे शरीर नहीं मिटा सकता वैसे ही शरीर की भूख रोटी नहीं मिटा सकता।

ऐसे उदाहरण एकदम बकवास हैं कि भूखे पेट कुछ नहीं सूझता। रोज दिन की सारी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं ।

वरना कोई गरीब दिन भर कड़ी मेहनत कर थका मांदा कभी इस तरफ सोचता ही नहीं लेकिन वो इसे अपनी थकान मिटाने का सबसे अच्छा विकल्प भी मानता है केवल सुख और आनंद ही नहीं।

क्योंकि गरीब से गरीब रोटी के लिए कड़कती धूप बारिश ठंड में में कांपने वाले लोग भी सहवास के आनंद की सुखद अनुभूति का अनुभव करता है।

इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए इधर उधर भटकने से अच्छा है वे एक दूसरे की कामनाओं की जरूरत को समझे और कोई समस्या है तो काउन्सलर से मिले। या अपने किसी ऐसे मित्र से जो इसके बारे में सही सलाह दे सकें।

ऑर्गेज्म एक तलाश को एक सुख में तब्दील कीजिए। स्त्रियों को चरित्रहीन कहने से पहले अपनी पौरूष हीनता पर गौर कीजिए मालिक नहीं मनचाहा साथी बनिए। आनंद लेना नहीं देना भी सीखिए ।

ध्यान रहे स्त्री की योनि में आप पेशाब करने नहीं गये हैं। अपनी कामनाओं को स्रावित करने गये हैं इसलिए स्त्रियों को भी स्त्रावित होने तक का सबर रखिए। उन्हें स्पर्श प्रेम से करें, मन से करें, वासना से नहीं ।

इसके आगे भी जीवन में सुख है यही सुख सब सुख का अंत नहीं। अपनी कामनाओं को संयमित करना भी सीखिए। क्योंकि भूख चाहे कितनी भी हो श इंसान का मांस तो नहीं खाना चाहिए न।

जीवन और मन और शारीरिक सुख की चाह से जुड़ी हर इच्छा हर कामना को पूरा करने का स्त्रियों का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुष का। भले ही स्त्रियां जानती है हर चाह को बांधना परन्तु पुरुष भी समझे उनकी चाहना।

नोट-इस बारे में मेरी हर उम्र और कयी तरह के महिलाओं से भी बात हुई है उनके विचार सुने हैं, बहुत ही भयावह और दुखद स्थितियां हैं हमारे समाज में इस विषय पर। ■

वरदान है आम लोगों के लिए गाजियाबाद का वरदान अस्पताल

कोविड के समय के अनुभवों के बाद बड़े अस्पतालों के नाम से ही डर लगने लगा है। लगभग हर व्यक्ति को ये ऊंची दुकान फीके पकवान ज्यादा लगने लगे। झूठ धोखे व लूट के अड्डे। इन अनुभवों के बीच कल ग़ाजियाबाद में स्थित 'वरदान आई हॉस्पिटल व वरदान मल्टीस्पेशीऐलिटी अस्पताल' के भ्रमण का अवसर वहां के न्यासी अशोक सिंघल जी द्वारा विशेष निमंत्रण दिए जाने पर मिला। मौलिक भारत से जुड़े 'स्वस्थ भारत न्यास' के अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह के साथ एक पूरा दिन इन तीनो अस्पतालों की कार्यप्रणाली , गतिविधियां व उपलब्ध सुविधाएं देखने में बिताया। और बेझिझक कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य का वरदान है, वरदान नेत्र अस्पताल एवं वरदान मल्टीस्पेशियलीटी। आशुतोष जी अपने आंखों का चेकअप कराया, ओपीडी चार्ज 10 रुपये, वह भी हमसे नहीं लिया गया। वरदान सेवा समिति का प्रबंधन देख रहे अशोक सिंघल जी राजनगर स्थित नेत्र चिकित्सालय और उसके बाद वरदान मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल जो गढ़ी सिकरोड़, मेरठ रोड, गाजियाबाद दोनो के भ्रमण में हमारे साथ रहे।नेत्र चिकित्सालय में लाखों लोगों को निशुल्क व किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को देने के कारण अस्पताल की बहुत प्रतिष्ठा है। वही स्तरीय व किफायती व ईमानदारी से सेवाओं को देने के लिए विशालकाय व सभी अत्याधुनिक सुविधाओं व मशीनो से युक्त मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल भी अब मैदान में है। पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे सस्ता व विश्वसनीय अस्पताल बनता जा रहा है वरदान। बहुत ही किफायती रेट (लगभग आधे दाम पर) पर बेहतर उपचार करने का संकल्प वरदान ने लिया है।

वरदान के संस्थापकों का विचार 'स्वस्थ भारत' के विचार के अनुरूप है व हम लोग अस्पताल को हर संभव मदद देने की कोशिश भी करेंगे।वरदान सेवा समिति द्वारा संचालित स्वास्थ्य के इस वरदान का लाभ दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ देश के मध्यमवर्गीय व गरीब लोगों को भी मिले ऐसी कामना करते हैं। आप भी लाभ उठा सकते हैं।

- अनुज अग्रवाल
(अध्यक्ष, मौलिक भारत)

थामस कप

● रचित सतीजा

हमारे एक सीनियर का IIT में सिलेक्शन हुआ था। उन दिनों लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। STD बूथ से उन्होंने मेरे लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। मैंने फोन उठाया, दूजी और से आवाज आई 'हो गया', आवाज इतनी जानी पहचानी थी के आंखें नम हो गई। जवाब देते देते जुबान लडखडा गई। मैं उन्हे प्यार से MOGAMBO कहता था।

उस समय लगा के मोगेंबो को शुभकामनाएं प्रेषित करू लेकिन STD booth पर मिनट के हिसाब के पैसे कटते थे, मोगेंबो जानता था उसके सिलेक्शन से अगर उसके बाद कोई खुश हुआ है तो उसके मां बाप और छोटी बहन के बाद मैं हूं, एक मिनट से पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मोगेंबो खुश हुआ और मोगेंबो के बाद, खुश होने वालो की फेहरिस्त में मैं था।

अगले दिन रोड़वेज की बस पकड़ी भाई के घर पहुंचा, गले से लगाया तो कंधे पर ओस की कुछ बूंदे टपकती दिखाई दी।

उस क्षण में एक खुशी थी, एक उल्हास था, एक उमंग थी।

हम मोगेंबो के घर पहुंच, घर में हलवा बना हुआ था, यही उनकी सेलिब्रेशन थी। यही उनकी पार्टी थी।

हलवा बनाया गया। मंदिर में बजरंग बलि के श्रीचरणों में चढ़ाया गया और पार्टी हो गई।

मैंने मोगेंबो के पिता से पूछा? कि गाम के कितने लड़के हैं जो आई आई टी में सिलेक्ट हुऐ हैं? असल में सवाल गलत नहीं था? जिससे सवाल पूछा गया इस आदमी तो यह मालूम तक नहीं था कि आईआईटी किस बला का नाम है?

सवाल के जवाब में बाह्मण बापू ने मुझे करडाई से कहा के जो पूछना है सीधा पूछ लड़के, यों घूमा फिरा के बात ना कर। मैंने कहा बापू, छोरा राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित कालेज में सिलेक्ट हुआ है। कम से कम एक छोटी मोटी पार्टी तो कर दे? मने घर के बाहर डीजे लगवा दे, गाम के लोगों का खाना पीना कर दे।

इस बात पर अंकल बिगड़ गया। बोला कैसी पार्टी, हो गई पाटी, घर मैं हलवा बना दिया, मंदिर में दान कर दिया, बस हो गई पार्टी। मुझे भी महसूस हुआ मोगेंबो के बापू से अगर फालतू बात की तो क्या पता था मेरे ही कान पर दो धर दे।

उस रात मैं मोगेंबो के घर में रुका। रात सोने लगे तो डीजे की आवाज आने लगी। सोने का प्रयास किया तो नींद ना आये। मैंने मोगेंबो से पूछा के गाम मैं कोई ब्याह शादी है?

ऊन्ने कहा ना, गाम के एक जमींदार के छोरे की कम्पार्मेंट आ गई थी। वो कंपार्टमेंट के पेपर में उत्तीर्ण हो गया, आज उसका जन्मदिन भी था, दोहरी खुशी थी और इस खुशी के मौके पर बापू ने पार्टी रख दी।

एक ओर राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट में सिलेक्शन पर पार्टी के नाम पर हलवा बनाया गया और पार्टी संपन्न हो गई। और दुजि ओर, कंपार्टमेंट में उत्तीर्ण होने पर बाक्यादा, जश्न मनाया गया।

तो निष्कर्ष क्या है, क्या कॉमपार्टमेंट में पास होने वाला लौंडा हमारे जिगरी से आगे था... नहीं...कदापि नहीं।

मोगेंबो खुश हुआ, क्यों खुश हुआ, क्योंकि ऊन्ने राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट का क्म्पिटीशन क्रैक किया था। उसकी खुशी वास्तविक थी। रियल थी।

आज एक अर्से बाद आखें भर आई

14 बार ....

14 बार इंडोनेशिया के थॉमस कप जीता है और आज हिंदुस्तानियों ने इंडोनेशियाई खिलाड़ियों को मारा नहीं ह, तोड़ा है।

मने टूर्नामेंट एक तरफा जीता है। पहले तो लक्ष्य सेन ने इंडोनेशियाई सुपर स्टार विश्व स्तरीय खिलाड़ी जिंटिंग को हराया। फिर सात्विक और चिराग ने इंडोनेशियाई प्लेयर को पेल दिया। आखरी कील श्रीकांत ने ठोकी और इंडोनेशियाई सुपर स्टार क्रिस्टी को जमींदोज कर दिया।

मने इंडियन टीम का स्कोर रहा 3 और विपक्षिओं का स्कोर रहा '0'। इंडियन बैडमिंटन टीम का थॉमस कप जीतना!

शब्द नहीं हैं, वैश्विक पटल पर जब जब तिरंगा लहराता है तो उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिऐ शब्दों का आभाव हो जाता है।

इस बात का दु:ख भी नहीं है के इस वैश्विक विजय पर एक सामान्य जनमानस खुश क्यों नहीं है, आनंदित क्यों नहीं है, उल्हासित क्यों नहीं है।

मोगेंबो आई आईटी में सिलेक्ट हुआ तो गाम मैं कौन जानता था के आई आई टी क्या बला है।

वह तो जमींदार के लडके के कॉमपार्टमेंट में पास होने पर धुत्त होकर नाच रहे थे। किसी से कोई शिकायत नहीं है। अधिकतर लोगों को क्या पता के थॉमस कप क्या है?

हां, उम्मीद जरूर है।

उम्मीद है के वह दिन आएगा जब इस राष्ट्र का बच्चा बच्चा किसी वैश्विक उपलब्धि पर खुश होगा।

जब आठ दस राष्ट्रों में खेले जाने वाले क्रिकेट को राह चलता कुत्ता नहीं पूछेगा और वैश्विक स्तर पीआर लोहा ले रहे हमारे एथलीट्स, हमारे पहलवानों, हमारे हॉकी प्लेयर्स, हमारे वेट लिफ्टर्स हमारे बॉक्सर्स, हमारे आर्चर्स, हमारे शटलस, इस राष्ट्र के असली हीरो होंगे।

बरहाल, थॉमस कप में विश्व भर के समक्ष हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ साबित कर बैडमिंटन खिलाड़ियों ने इस राष्ट्र को जो गर्व के क्षण दिए हैं, उनके लिये मेरे जैसा एक साधारण स्पोर्ट्समैन आप सभी को केवल अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर सकता है।

आप सब पर गर्व है। बेशक इस राष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा आपकी उपलब्धि को ना पहचाने लेकिन जो पहचान रहे हैं, उन्हे आप पर गर्व है।

विश्व के धुरंधरों को पछाड़ विश्व विजयी होने पर गर्व है।

जय हिंद।।

भूगोल
GEOGRAPHY
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)

ONLINE - OFFLINE For WEEKEND COURSES

IAS/PCS
By S.M.Zaki Ahmad
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

Career Plus Online
visit us CAREER PLUS online.com

इतिहास
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)

ONLINE - OFFLINE For WEEKEND COURSES

IAS/PCS
By करुणेश चौधरी सर
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

Career Plus Online
visit us CAREER PLUS online.com

ANTHROPOLOGY

By K Mukesh Sir

FREE SEMINAR
14th April Time: 4 PM
The best optional strategy for UPSC and all state PCS

New batch starts from
18th APRIL
Registration & admission started.

UPSC online classroom programme

COURSE FEATURES
- Classes starts from basic and Focus on concept building
- Reference notes to strengthen your Preparation.
- Focus on writing skills development.
- 15 Tests and discussion.
- Prior registration and admission is must.
- To join classes download our app CAREERPLUSONLINE

Offline: 45000/-
Online: 29999/-

Offline & Online courses offered :
- Anthropology foundation
- Anthropology Main 2022
- Anthropology crash course.
- Anthropology Test Series
- Correspondence course
- Q & A personalize guidance.

Career Plus EDUCATIONAL SOCIETY
A Legacy of 25 Years

44 SELECTIONS IN IAS 2020

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Contact : 9310151465,9891186435, 9811069629,011-27654588
Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com

IAS PCS

Career Plus Online CAREER PLUS online.com

संस्कृत साहित्य
द्वारा- आर.सिंह

अद्यतन नोट्स, दो माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम

नया बैच प्रारंभ
दो दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला के साथ
(21 एवं 28 मार्च, समय 3 बजे से)

Quality Improvement Program for Old Students
Test Series Available

Career Plus EDUCATIONAL SOCIETY

301/A, 37,38,39,3rd Floor, Ansal Building Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

लोक प्रशासन
Public Administration
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)

ONLINE - OFFLINE For WEEKEND COURSES

IAS/PCS
By HARUN SIR
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

Career Plus Online
visit us CAREER PLUS online.com

POLITICAL SCIENCE
राजनीति विज्ञान
एक वैकल्पिक विषय (हिंदी माध्यम)

ONLINE - OFFLINE For WEEKEND COURSES

IAS/PCS
By SUDHIR SIR
(Classes Every Friday & Saturday)
Register now and Avail 50% discount
Call @ 9310151465, 9891086435,9811069629

Career Plus Online
visit us CAREER PLUS online.com

This issue Published on 1st June, 2022 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2020-22, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089

Career Plus People - Born to Lead

2022 IAS/PCS 2023

PRELIMS • MAINS • PRELIMS CUM MAINS

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi Medium

SUBJECTS AVAILABLE

GEN. STUDIES (for Prelims/Mains), CSAT & ESSAY

HISTORY | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY

POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION

SANSKRIT "LITERATURE" | HINDI "LITERATURE"

By Most Renowned & Competent Facilities under the Leadership & Direction of

Mr Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha

Silver Jublee Year (Since 1997)

Career Plus

English / हिन्दी Medium Hostel Facility

EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

Study Material & Test Series

44 SELECTIONS IN IAS 2020

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Mukherjee Nagar, Delhi-9

9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com